राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] तेरहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का अट्ठहवां दिवस [संख्या : 8

गुरुवार,

11 मार्च, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री भवानी सिंह राजावत।

राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत बकाया राशि का भुगतान

86. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारण्टी योजना मंत्री) यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत 13 माह में राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के कितने प्रकरण कहां-कहां दर्ज किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है? यदि हां, तो अब तक किन-किन के विरुद्ध कार्यवाही की गई और कुल कितने मामले दर्ज कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना में काम कर रहे मजदूरों को गत 13 माह का पूरा भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां पूरा भुगतान कर दिया गया और कहां-कहां मजदूरों का भुगतान करना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : (1) प्रदेश में नरेगा योजना के क्रियान्वयन में गत 13 माह में 192 अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के प्रकरणों की जानकारी प्राप्त हुई है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री)

(2) हां। यह सही है कि भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस में गत 13 माह में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) नरेगा में काम कर रहे मजदूरों को किये गये कार्य की मजदूरी का पाक्षिक भुगतान पखवाड़ा समाप्ति के पश्चात् 15 दिवस में किया जाता है। तकनीकी व स्थानीय कारणों से कुछ स्थानों पर निर्धारित समयावधि में देय भुगतान नहीं किया जा सका, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब के खण्ड-एक में माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि नरेगा में भ्रष्टाचार की 13 माह में लगभग 192 शिकायतें सरकार को मिली हैं। मैं समझता हूं कि यह आंकड़ा न केवल सदन को गुमराह करने वाला है बल्कि राजस्थान की जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है, क्योंकि जिस पैमाने पर नरेगा में भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर समाचार पत्र रंगे हुए आ रहे हैं पिछले 13 महीने से, उस पैमाने पर यह आंकड़ा बहुत कम है। खण्ड-दो में माननीय मंत्री महोदय ने जहां-जहां एफ.आई.आर. दर्ज हुई, उसका ब्यौरा जो मुझे दिया है उसमें लगभग 156 एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं नरेगा में भ्रष्टाचार को लेकर। मेरा पूरक प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है, मुझे यह बताने की कृपा करें कि 156 एफ.आई.आर. में से कितने में एफ.आर. लग गई, कितने मामलों में न्यायालय में चालान पेश हुए? और अगर कहीं सज़ा भी हुई हो भ्रष्टाचारियों को तो वह भी सदन को बताने की कृपा करें। कई मामले राजनीतिक दबाव से एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद भी सी.आई.डी. को ट्रांसफर कर दिये गये, यह भी बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सूची देखकर बहुत दुःख हुआ, मैंने पूरी सूची देखी कि एफ.आई.आर. किस-किस के खिलाफ दर्ज हुई, तो अधिकांश मेट हैं, रोजगार सहायक हैं, सरपंच हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, भाषण नहीं, स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न के सन्दर्भ में पूछ रहा हूं, अलग से नहीं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, भूमिका की आवश्यकता नहीं है, सीधा प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): मैं सीधा ही पूछ रहा हूं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेट, रोजगार सहायक, सरपंच के अलावा भ्रष्टाचार के बड़े मामले भी राजस्थान की धरती पर पिछले 13 महीने से हुए, उसमें बड़े अधिकारी भी हैं, आई.ए.एस. भी हैं, आर.ए.एस. भी हैं, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कोई एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, यह बताने की कृपा करें?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): तीसरा, खण्ड तीन का भुगतान को लेकर मामला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी गम्भीर मामला है। मुझे संतोष है कि बहुत जिलों में समय पर भुगतान हो रहा है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं, जैसे सिरोही है, 13 महीनों से कई पंचायतों में भुगतान नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये। सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, लाडपुरा से आये माननीय सदस्य ने तीन बातों पर ध्यान दिलाया है। एक तो इन्होंने जो आंकड़ा भ्रमित करने वाला बताया, माननीय अध्यक्षजी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि सरकार को आंकड़े छुपाने में, तथ्यों को दबाने में कोई रुचि नहीं है। सरकार पूर्व में ही अनेक बार इस बात को कह चुकी है कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी प्रकरण सरकार के समक्ष आएंगे, उनको गम्भीरता से लिया जाएगा और कोशिश यह की जाएगी कि जो इसमें जिस भी स्तर के आदमी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। माननीय सदस्य ने इस बात पर भी चिन्ता जाहिर की कि इसमें छोटे-छोटे स्तर के लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। यह सही है कि इसमें अधिकांश लोग-बाग़ जिन पर कार्यवाही हो रही है, वे मेट और निचले स्तर के कर्मचारी हैं, मगर जिस तरह की गतिविधि सामने आती है उस स्तर के लोगों पर कार्यवाही होती है। जहां तक बड़े अधिकारियों का प्रश्न है, तो सरकार की इस बात में बिलकुल रुचि नहीं है कि बड़े अधिकारियों को बचाया जाए और छोटे कर्मचारियों को दण्डित किया जाए। आपके पास जो हमने सूचना भेजी है, उसका आप अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि इसमें एक्स.ईएन. लेवल के अधिकारी और आर.ए.एस. अधिकारी,

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

उनको भी हमने दण्डित किया है। दो आर.ए.एस. अधिकारियों को निलम्बित किया गया है और उनको सज़ा दी गई है। इसलिये किसी को बचाने का प्रश्न नहीं है। कुछ हमारे पास शिकायतें कलक्टर स्तर के अधिकारियों की भी आई हैं, जांच चल रही है, अगर वे दोषी पाये जाएंगे तो कोई कलक्टर भी उसमें दण्ड का भागीदार होगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी।

जहां तक भुगतान के विलम्ब की बात आपने की है, निश्चित रूप से मैं इसको स्वीकार करता हूं कि 15 दिन में भुगतान की होने की व्यवस्था है, और जैसा कि आपको हमने जानकारी दी है, विलम्ब हो रहा है, सरकार प्रयास कर रही है। उसमें काफी कमियों में सुधार करने के प्रयास किये हैं, आप चाहेंगे तो मैं डिटेल में उनकी जानकारी सदन को अभी अवगत करा सकता हूं।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी हमने कार्यवाही की है, दो आर.ए.एस. अधिकारियों के लिये भी आपने कहा। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी और सदन को भी बताना चाहूंगा, और पूरे राजस्थान को ज्ञात है, कि डूंगरपुर की तत्कालीन कलक्टर आरुषि मलिक ने, ऊंची दरों पर पेड़ों की खरीद की। टौंक के तत्कालीन कलक्टर सुधीर कुमार, ट्री-गार्ड की खरीद में लाखों का घोटाला हुआ। ऐसे ही करौली कलक्टर, दौसा कलक्टर, इन कलक्टर ने करोड़ों का घोटाला किया। सरकार ने, मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि मेट और सरपंच को तो दोषी मानकर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है, एफ.आर.आर. भी दर्ज हुई है, लेकिन इतने बड़े अधिकारी, सरकार मछलियों को मारना चाहती है, मगरमच्छों को क्यों नहीं मारना चाहती है? इसका संदेश पूरे राजस्थान में गलत जा रहा है। इनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं हुई, जो भ्रष्टाचार का बड़ा मामला और बड़े घोटाले इन्होंने किये? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब आपने कलक्टर कांफ्रेस की तो उस कलक्टर कांफ्रेस में करौली के जिला कलक्टर नीरज पवन ने आपसे कहा कि जॉब-कार्ड 3-3 हजार में बिक रहे हैं। आपकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि 20-25 हजार जॉब-कार्ड फर्जी हैं करौली जिले में।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका, पूरक प्रश्न?

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): प्रश्न यही कर रहा हूं कि यह भ्रष्टाचार है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये, पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): यह भ्रष्टाचार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे टोकें, मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन यह पूरे राजस्थान की पीड़ा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और माननीय मुख्य मंत्रीजी को कलक्टर कांफ्रेंस में कलक्टर कह रहे हैं कि फर्जी जॉब-कार्ड बन रहे हैं। उसके बाद में, एक तो राजस्थान आज आश्चर्यचकित है कि केन्द्र के हमारे... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो न। पूरक प्रश्न पूछिये, भाषण नहीं।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, एक तो है कि इनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं हुई, यह बताएं? आज ये कलक्टर दोषी होते हुए कलक्टर लगे हुए बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): एक चित्तौड़ की कलक्टर हैं और दूसरे कलक्टर दूसरी जगह लगे हुए बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने सदन में आपके माध्यम से पहले ही अवगत करवाया है कि कितना भी बड़ा अधिकारी हो अगर वह दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। आपने उल्लेख किया है डूंगरपुर के कलक्टर के बारे में जो वर्तमान में चित्तौड़ के कलक्टर हैं और आपने उल्लेख किया है करौली के कलक्टर के बारे में, इन दोनों के बारे में आप चाहें तो मैं दो मिनट में बता दूं कि क्या कार्यवाही हम कर रहे हैं।

जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा नरेगा योजना के तहत 2010 कम्प्यूटर, 2010 प्रिंटर तथा 2010 यू.पी.एस. की आपूर्ति करने के लिए क्रय आदेश दिनांक 19.5.2009 को ग्लोबल कम्प्यूटर नैटवर्क, जयपुर को दिये गये थे। यह क्रय आदेश लगभग 85 लाख रुपये का था। क्रय आदेश यद्यपि डी.जी.एस. एण्ड डी. दरों पर था लेकिन क्रय आदेश जिस फर्म को दिया गया था वह फर्म डी.जी.एस. एण्ड डी. द्वारा अधिकृत नहीं थी। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं डी.जी.एस. एण्ड डी. की दर-संविदा प्रावधानों के अनुसार उक्त क्रय डी.जी.एस. एण्ड डी. द्वारा अधिकृत दर-संविदा-धारक से ही किया जाना होता है। प्रकरण में यह क्रय आदेश जारी करने के उपरान्त जिला कलक्टर द्वारा क्रय आदेश को निरस्त भी कर दिया गया था लेकिन फर्म द्वारा उपरोक्त सामग्री की

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

सप्लाई कर दी गयी। जिला स्तर से भुगतान प्राप्त नहीं होने पर फर्म ग्लोबल कम्प्यूटर नैटवर्क, जयपुर द्वारा जिले से भुगतान दिलवाये जाने बाबत् पत्र विभाग को भिजवाया गया जिस पर विभाग द्वारा प्राथमिक परीक्षण करवाये जाने पर प्रथम दृष्टया वित्तीय नियमों का उल्लंघन पाया गया है। साथ ही फर्म द्वारा सप्लाई की गयी सामग्री, क्रय आदेश के अनुसार मात्रा एवं गुणवत्ता के अनुसार है अथवा नहीं, इस संबंध में तकनीकी जांच हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि सहित एक जांच समिति का गठन किया गया है। वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भिजवाये जा रहे हैं। यह तो रहा एक कलक्टर के बारे में।

रहा दूसरा, अपराध निरोधक संगठन, राजस्थान द्वारा नरेगा कार्यों में क्रियान्वयन में उच्च अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में एक शिकायत पत्र दिनांक 27.7.2009 को आयुक्त, नरेगा को प्राप्त हुआ, जिसकी जांच मुख्यालय के अधीक्षण अभियंता, ई.जी.एस. से करवायी गयी। जांच अधिकारी ने अवगत करवाया कि जिला करौली में 51 लाख रुपये के पौधे, बीज क्रय के मामले में वित्तीय अनियमितता पायी गयी है। उक्त क्रय सक्षम समिति के माध्यम से नहीं कराना, न्यूनतम दर के मुकाबले उच्च दर पर क्रय करना, क्रय किये गये पौधे, बीजों की सप्लाई के स्तर पर सत्यापन नहीं करना तथा न्यूनतम निविदादाता के विपरीत उच्च निविदादाताओं से नैगोशिएशन करना पाया गया है। प्रकरण की विस्तृत जांच सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर से करवायी जा रही है। अभी जांच विचारणीय है, वह आएगी तो निश्चित कार्यवाही होगी।

सरकार ने इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार मेटने के लिए विभिन्न जो प्रयास किये हैं, सदस्य चाहें तो उसकी भी जानकारी मैं दूं और आप चाहें तो ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बताना कि ...(व्यवधान) अधिकारियों को बचाने की लीपापोती है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : केवल मूल प्रश्नकर्ता एक सप्लीमैंट्री कर लें। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मूल प्रश्नकर्ता की इजाजत से ही पूछ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। केवल मूल प्रश्नकर्ता को एक सप्लीमैंट्री की इजाजत दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल):×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल):×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय):×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। केवल मूल प्रश्नकर्ता एक प्रश्न कर सकते हैं। माननीय सदस्य, बैठ जाएं। कृपया आप विराजें। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): बड़े अधिकारियों के मामले कार्मिक विभाग में भेजना, यह बड़े अधिकारियों को बचाने की एक ... (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय):×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण):×××

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। केवल एक प्रश्न मूल प्रश्नकर्ता का। अंकित नहीं हो रहा है। मंत्रीजी को जवाब देने दीजिए। माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): जो कार्मिक विभाग के मंत्री हैं वह बताएं इस सदन को। अपराधी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक राजनैतिक कार्यकर्ता अगर चक्का जाम करता है तो उसके खिलाफ तुरन्त चालान पेश किया जाता है और ...(व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): और बड़े अधिकारियों को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये, नहीं। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। माननीय मंत्रीजी, उनके एक पूरक प्रश्न का जवाब देकर छुट्टी करें। 15 मिनट निकल गये एक प्रश्न में। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मूल प्रश्न भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, मैं आंकड़े सहित जब से यह योजना लागू की है, उस पर आपका ध्यान दर्शाऊंगा तो आपको पूरी बात समझ में आएगी।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप एक मिनट शांति से सुनें। (व्यवधान) इस योजना में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य की रुचि केवल भ्रष्टाचार में है, उससे सम्बन्धित आप जवाब दें। उसका जवाब दे दीजिए, खतम बात। भ्रष्टाचार का ही तो जवाब दिलवाना है। भ्रष्टाचार का जवाब दिलवा रहा हूं, बैठिये आप। भ्रष्टाचार का जवाब दिला रहा हूं, बैठिये आप। अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल):×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आ जाने दीजिए। जवाब आ जाने दीजिए। अंकित नहीं होगा। आप जवाब दीजिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का पूरा ध्यान भ्रष्टाचार मेटने पर है। सदस्य का ध्यान किस पर है, मुझे यह जानकारी नहीं, मगर सरकार का पूरा ध्यान भ्रष्टाचार को मेटने पर है। पिछले 15 महीने में, आपने 13 महीने कहा, इस सरकार को 15 महीने हुए हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुनिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह योजना वर्ष 2006 से चालू हुई है, कुल दर्ज एफ.आई.आर., उनकी संख्या मैं सालवार बताता हूं, 2006 में 1 भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई, 2007 में 9 एफ.आई.आर. दर्ज हुईं, 2008 में 54 हुईं और 2009 में 216 एफ.आई.आर. दर्ज हुईं।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): यह भ्रष्टाचार का प्रमाण है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिए। जवाब तो आने दीजिए। आप जवाब ही नहीं सुनेंगे? जवाब सुनिये ...(व्यवधान)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप सुनिये। (व्यवधान) और अभी तक 28 एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं। कुल एफ.आई.आर. 307 अभी तक, एफ.आर. लगायी संख्या-69, कोर्ट में चालान 91 ...(व्यवधान) सी.आई.डी. में नहीं है। गिरफ्तारी हुए प्रकरणों की संख्या 87 और सज़ा हुई चार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो प्रयास किये हैं, क्योंकि इस योजना में जितनी बड़ी राशि खर्च हो रही है, 13 हजार करोड़ रुपये इसमें अब तक खर्च हो चुके हैं और लाखों की संख्या में जहां काम चल रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें कमियां हैं। उनको मिटाना आप और हम सबका कर्तव्य है। हर महीने नरेगा से सम्बन्धित एक संवाद इंदिरा गांधी भवन में होता है, जिसको भी जो कोई राय अपनी देनी है, आप उसमें शामिल होकर इसमें योगदान दे सकते हैं। इस सरकार ने जो प्रयास किये हैं, उस ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा ताकि इस व्यवस्था के अन्दर नियंत्रण हो और भ्रष्टाचार मिटे। राज्य सरकार द्वारा ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। माननीय सदस्य, विराजें। जवाब आ गया, विराजें। बैठें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय):×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):×××

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। अगला प्रश्न पुकार चुका हूं। ये प्रश्न मुझे लेने हैं। अगला प्रश्न पुकार चुका हूं। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। आप विराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): प्रश्न संख्या-87 ।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल):×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, जवाब दें। अंकित नहीं होगा। ऊर्जा मंत्रीजी।

परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु अनुसंधान

87. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में विद्युत की वर्तमान मांग कितनी यूनिट है? मांग के सापेक्ष में सभी इंतजामों से विद्युत उपलब्धता की स्थिति क्या है?

(2) विद्युत उपलब्धता में से कितनी यूनिट राज्य में किस व्यय दर पर उत्पादित होती है? विद्युत उत्पादन इकाईवार एवं लागत प्रति यूनिटवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा कितनी यूनिट दूसरे राज्यों से किस-किस दर पर खरीदी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विद्युत वितरण के दौरान छीजत का अनुपात क्या है? इसको रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये? किये गये प्रयासों और उपलब्धियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(5) क्या यह सही है कि राज्य में वैकल्पिक संसाधनों यथा सूर्य ऊर्जा, सौरतापीय ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की प्रचुर सम्भावना है? यदि हां, तो सरकार द्वारा सूर्य ऊर्जा और सौरतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु कराये जा रहे अनुसंधान पर बजट प्रावधान राशि, अब तक व्यय राशि, कार्यरत इकाइयां, उत्पादित वर्तमान ऊर्जा एवं अनुमानों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): (1) राज्य में विद्युत ऊर्जा की वर्तमान मांग लगभग 1350 लाख यूनिट प्रति दिन है। मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता औसतन 1050 लाख यूनिट प्रति दिन है एवं लगभग 250 लाख यूनिट प्रति दिन विद्युत अनुबंध के अन्तर्गत क्रय की जाती है और 50 लाख यूनिट ओवर ड्रा से प्राप्त की जाती है।

(2) विद्युत उपलब्धता में से वर्तमान में 710 लाख यूनिट औसत प्रति दिन राज्य में उत्पादित होती है जिसकी व्यय दर परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। विद्युत का इकाईवार उत्पादन एवं लागत प्रति यूनिटवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) राज्य में निगम द्वारा Central sector allotted quota एवं अन्य राज्यों से खरीदी गई विद्युत का विवरण परिशिष्ट 3 एवं 4 पर उपलब्ध है।

(4) विद्युत वितरण के दौरान छीजत के अनुपात का निगमवार (वर्ष 2009-10, दिसम्बर, 2009) तक का विवरण निम्न प्रकार है :-

निगम का नाम	छीजत का प्रतिशत
जयपुर	20.36
अजमेर	28.54
जोधपुर	24.72
राज्य भर का औसत	24.20

विद्युत वितरण छीजत को 20 प्रतिशत से नीचे लाने हेतु विद्युत वितरण तंत्र में सुधार किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत उच्च वोल्टेज विद्युत वितरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि कनेक्शनों के लिये छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर कुओं के पास लगाये जा रहे हैं तथा प्रति ट्रांसफार्मर अधिकतम एक

(डा. जितेन्द्र सिंह)

या दो कनेक्शन दिये जा रहे हैं। इस प्रकार 2,92,000 (दो लाख बानवे हजार) छोटे ट्रांसफार्मर्स लगाये गये हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शनों के लिये सिंगल फेस के छोटे ट्रांसफार्मर लगाये जा रहे हैं। अब तक 1,56,000 (एक लाख छप्पन हजार) ऐसे ट्रांसफार्मर्स लगाये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त बिजली चोरी के प्रभावी रोकथाम के लिये राज्य भर में कुल 34 थाने स्थापित किये गये, जो निरन्तर कार्य कर रहे हैं।

उक्त प्रयासों के फलस्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय, छीजत में कमी की उपलब्धि निगमवार निम्न प्रकार है :-

निगम का नाम	**विद्युत छीजत का प्रतिशत**	
	2004-05	**दिसम्बर, 2009 तक**
जयपुर	37.71	20.36
अजमेर	43.58	28.54
जोधपुर	42.38	24.72
राज्यभर का औसत	41.10	24.20

(5) यह सही है कि राज्य में सौर प्रकाश, सौर तापीय ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की प्रचुर सम्भावना है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में विद्युत उत्पादन के वैकल्पिक स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु एक नीति गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति-2004 जारी की हुई है। वर्तमान में इन स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा इस नीति के तहत किया जा रहा है। इस क्षेत्र में अनुसंधान इत्यादि का कार्य सी-वैट एवं एम एन आर ई द्वारा करवाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा अनुसंधान पर इस समय कोई राशि व्यय नहीं की जा रही है।

पूर्व में विण्ड मानिटरिंग स्टेशन पर राज्य सरकार द्वारा रु. 342556 राशि व्यय की गई थी। वर्तमान में पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के माध्यम से स्थापित इकाइयों की सूची परिशिष्ट 5, 6 एवं 7 पर उपलब्ध है। पवन ऊर्जा एवं बायोमास ऊर्जा से उत्पादित ऊर्जा का निगमवार विवरण परिशिष्ट-8 पर उपलब्ध है।

सौर ऊर्जा से उत्पादित विद्युत का विवरण परिशिष्ट-9 पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो उत्तर मिला है बहुत तोड़-मरोड़कर इन्होंने जवाब दिया है। मैं उसका एक एक का विवरण करूं तो मेरे ख्याल से दो बज जाएंगे और कोई काम होने वाला नहीं है। इस तरह से अगर विधान सभा के अन्दर एक जन प्रतिनिधि को, एक एम एल ए को उत्तर दिया जाता है, मैं इसका क्या जवाब दूं, मुझे तो यह समझ में नहीं आता। माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है, मैं उत्तर के खण्ड 4 पर ही जाऊं, आगे जाऊं ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 4 में छीजत सम्बन्धी आंकड़े बिलकुल असत्य बताये गये हैं। इन्होंने जिस तरीके से आंकड़े दिये हैं, अगर इन आंकड़ों को मान लिया जाए तो फिर सदन के नेता को बिजली के ऊपर पैसा बढ़ाने की जरूरत ही क्या पड़ती? कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये दस पैसे क्यों बढ़ाये, मैं यह भी जानकारी चाहूंगी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप इनसे जोधपुर में ही पूछ लेते।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय, बिजली की छीजत इतनी कम हो गयी तो आप गांवों में 24 घण्टे बिजली क्यों नहीं देते? आप अपने खुद के रिकार्ड में, खुद के उत्तर में यह बता रहे हो कि 20 प्रतिशत रह गयी है तो 24 घण्टे गांवों में बिजली क्यों नहीं देते हो? गांव वाले इतने परेशान हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। शहर वाले तो हैं ही, कोई बात नहीं, वे इधर-उधर से काम चला लेंगे। गांव वाले बहुत परेशान हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-4 के आंकड़ों को यदि सही मानें तो क्यों नहीं सरकार बिजली की दरें आधी दर कर रही है? सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? बजट में 10 पैसे यूनिट बढ़ा दी है, क्या सरकार जनता के पसीने की कमाई से मुनाफा कमाना चाहती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से मैं खण्ड-4 की बात कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो दिलवा दूं। पूरा भूल जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मेरी सुन तो लो। मैं खण्ड-4 का ही पूछ रही हूं, मैं तो आगे जा ही नहीं रही हूं। मैं तो पहले वाले का तो कुछ बोल ही नहीं रही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने उत्तर में दिया, छीजत प्रतिशत से नीचे लाने हेतु विद्युत वितरण में सुधार किया जा रहा है। अब क्या सुधार किये जा रहे हैं, इन आंकड़ों को तो देख लो। कृषि कनेक्शनों के लिये छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर कुओं के पास लगाये जा रहे हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर्स कहां-कहां लगाये और

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

किस-किस जगह लगाये, उसकी मुझे थोड़ी जानकारी दे दें? कहां-कहां लगे हैं यह तो बताएंगे, नहीं तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रति ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यदि आप सारे ट्रांसफार्मर्स की सूची चाहेंगे तो खाद्य मंत्रीजी के उत्तर की तरह बड़ा लम्बा उत्तर हो जाएगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, तो अध्यक्ष महोदय, फिर तो प्रश्न पूछें ही नहीं। मेरा इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगी।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, आप पूछिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं तो खण्ड-4 पर ही गयी हूं, आगे गयी भी कहां हूं साहब। मैं तो बहुत नीचे आ गयी हूं। मैं तो बहुत नीचे आकर इनसे यह जानकारी चाह रही हूं। हालांकि मैं शहरी क्षेत्र की हूं। अब सूरसागर में गयी हूं तो कुछ जगह ऐसी आई हैं इसलिये मुझे यह जानकारी करना जरूरी है। विपक्ष के उप नेता बैठे हैं, यह भी बिजली मंत्री रहे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न तो आपको इनसे नहीं करना न, उनसे करिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, मैं तो आपको बता रही हूं। कितने कनेक्शन दिये जा रहे हैं। इसमें 2 लाख 92 हजार छोटे ट्रांसफार्मर्स लगाये, 2 लाख 92 हजार किसको कहते हैं? यह 5-10, 15-20 ही मुझे बता दें तो मैं इनको मान जाऊंगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह तो बताओ। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कनेक्शनों के लिये सिंगल फेस से छोटे ट्रांसफार्मर लगाये जा रहे हैं। कहां लगाये जा रहे हैं, कोई जानकारी तो देओ आप। आपने तो बता दिया, इसके अन्दर देख लो, ऐसे थोड़े ही होता है। आप अपने उत्तर में यह सारा मुझे बताते। आपने बताया, 1 लाख 56 हजार ऐसे ट्रांसफार्मर्स लगाये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त बिजली चोरी की प्रभावी रोकथाम के लिये राज्य भर में कुल 34 थाने स्थापित किये गये। अब कहां रोकथाम की है, क्या किया है, इसकी मुझे आप थोड़ी जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष: आपको जवाब दिलवा रहे हैं। मंत्री महोदय।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने गांवों में बिजली देते हैं, कितने गांवों को 24 घंटे बिजली देते हैं, मुझे इस बात की जानकारी दे दें, मैं ज्यादा कुछ और नहीं पूछना चाहती।

श्री अध्यक्ष: आपने कितने सप्लीमेंट्री पूछे हैं?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैंने तो एक ही पूछा है, साहब। मैंने पूछा ही कहां है? मैंने तो यह सारा छोड़ ही दिया है। मैं खास मुद्दे पर ही आई हूं, इसका ही जवाब दे दो आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। आपको याद हैं न इन्होंने जो सप्लीमेंट्री पूछे हैं?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): याद नहीं हैं तो मैं इनको याद दिला दूं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): आनरेबल अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या हाउस की बहुत सीनियर मैम्बर हैं और इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं आपको इस बारे में अवगत कराना चाहूंगा कि जो टी एण्ड डी लासेज हैं, छीजत है, वह टोटल डिस्काम में इतनी बिजली आई, उसका रिकार्डेड है, माननीय सदस्य, और कितनी बिजली बिकी, यह भी रिकार्डेड है। सारे बिजली के बिल जाते हैं और कितनी बिजली डिस्काम में आई, कितनी बिजली बिकी, इसमें जो डिफरेंस है, इसका जो अन्तर है, उस अन्तर को छीजत कहते हैं, टी एण्ड डी लासेज कहते हैं। अब यह सारा रिकार्डेड है। दूसरा, प्रति वर्ष इसमें डिस्काम अपनी बड़ाई दिखाने के लिये कोई असत्य आंकड़े नहीं दे सकता, क्योंकि इसके ऊपर हमारा रैगुलेटरी कमीशन, हमारा नियामक आयोग है। जो डिफरेंस आया, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी आयी, कितनी खर्च हुई, उसका जो अन्तर है, उसके आंकड़े नियामक आयोग प्रति वर्ष अख़बार में देता है और उसकी हियरिंग करता है। फिर भी यदि माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो, नियामक आयोग एक तरह का कोर्ट है, माननीय सदस्य और न्यायालय पर किसी सरकार का अपना कन्ट्रोल नहीं है, नियामक आयोग is independent body जो बिजली के केसेज को डील करती है और उसके अन्दर कोई भी इस तरह इर्रेगुलरिटी होगी तो नियामक आयोग के सामने रखी जा सकती है। अत: मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, उनके बारे में कभी भी कोई आपत्ति हो तो नियामक आयोग के सामने प्रस्तुत की जा सकती है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि आप इस बारे में सोचती हैं कि यह इर्रेगुलरिटी है तो नियामक आयोग के

(डा. जितेन्द्र सिंह)

सामने अपनी आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। मैं समझता हूं कि नियामक आयोग द्वारा जो उत्तर है वह फाइनल डिसीजन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इनसे जानकारी चाही कि ट्रांसफार्मर्स कहां-कहां लगा रहे हैं, इसका इन्होंने कुछ जबाव नहीं दिया है। जो जानकारी मैं चाह रही हूं, वह तो जानकारी मेरे को देवें, फिर कोई दूसरे एम एल ए साहब पूछना चाहें तो पूछें। ऐसे थोड़े ही चलेगा, साहब? जो मेरे को जानकारी चाहिए वह आप जानकारी देओ। आपने जो छीजत बतायी है, उस छीजत का मैं चाहती हूं कि बाहर का इंजीनियर आकर इसका सर्वे करे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: नहीं। केवल मूल प्रश्नकर्ता।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मेरे को इसका उत्तर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आपको ही दिलवा रहा हूं। वह पीछे खड़े हुए थे, उनको रोका है कि पहले आपका आएगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगी कि जयपुर विद्युत निगम कितने करोड़ के लाभ में चल रहा है?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): यह ओमजी बिड़ला की पर्ची है। ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): चलो, कोई बात नहीं। यह पर्ची नीचे रखी है। मैं खुद ही बोल दूंगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने दो चार सवाल पूछे हैं, उनका उत्तर दिलवा दें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, जयपुर विद्युत निगम कितने करोड़ के लाभ में है?

श्री अध्यक्ष: आपको अलाउ नहीं किया है। मूल प्रश्नकर्ता को अलाउ किया है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): कितनी जगह ट्रांसफार्मर्स लगाये गये और कितनी जगहों पर लोगों ने नहीं लगाने दिये या लगाने दिये, यह सारी जानकारी बताओ?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो हाउस की बहुत सीनियर मैम्बर हैं, उन्होंने जो प्रश्न किया है कि कितने ट्रांसफार्मर्स लगाये गये, मेरे पास सूची है वह मैं अर्ज कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: कितने लगाये गये, के साथ-साथ यह भी पूछा है कि कहां कहां लगाये गये।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो दो लाख बानवे हजार ट्रांसफार्मर्स लगाये गये, मैं एक एक ट्रांसफार्मर का आपके आनर में कम्पैक्टेड माननीय सदस्य को दे रहा हूं। माननीय सदस्य, जोधपुर डिस्काम के अन्दर थ्री-फेस के 8897 ट्रांसफार्मर्स लगाये गये...(व्यवधान) मैं जोधपुर जिले की बात कर रहा हूं। डिस्काम में तो ग्यारह जिले हैं और सिंगल जोधपुर में तो...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में मामा को ब्याह और मां परोसगारी, जोधपुर में लगा लेस्यां।

श्री अध्यक्ष: माननीय तिवाड़जी, आपको एतराज है क्या जोधपुर में लग गये तो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, एतराज नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मामा कौ ब्याह और मां परोसगारी, तो फिर-फिर अपने बेटे को जिमाओ।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सिंगल-फेस ट्रांसफार्मर्स जोधपुर जिले में 5053 लगाये गये। डिस्काम का ही हिस्सा है जालौर। जालौर में 11683 थ्री-फेस के लगाये गये, 3375 सिंगल-फेस के लगाये गये। पाली में थ्री फेज के 1149 लगाये गये, 4220 सिंगल-फेस के लगाये गये। सिरोही में 6589 थ्री-फेस लगाये गये, सिंगल-फेस में 3189 लगाये गये। और बाड़मेर में 1468 लगे...

श्री अध्यक्ष: आप इन्हें डिस्टर्ब नहीं करें।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर में 146 लगे थ्री-फेस के और सिंगल-फेस के लगे 408 । बीकानेर में थ्री-फेस में 4464 और सिंगल-फेस 1051 लगे। हनुमानगढ़ में...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप तो जोधपुर की ही बता दो।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): टोटल जोधपुर का अपना जो डिस्काम है, उसमें, माननीय सदस्य, थ्री-फेस 48307 लगे और सिंगल-फेस में 29725 लगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य सन्तुष्ट हैं, बहुत डिटेल जबाव आ गया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, सरकार ने घोषणा की कि गांवों में 24 घंटे बिजली मिलेगी । आपने कहा कि पांच हजार से कम आबादी के गांवों में दस घंटे बिजली मिल रही है।

श्री अध्यक्ष: यह अलग प्रश्न है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ): नहीं, यह इसी से सम्बन्धित है। दस घंटे जिनको बिजली मिल रही है उनको चौबीस घंटे सरकार के वादे के अनुसार कब तक देने का इरादा सरकार रखती है? अलग नहीं है, इसी में है। इसी में दिया है। पांच हजार से कम की आबादी के तीस हजार गांवों में कब तक चौबीस घंटे बिजली दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया कि 2004-05 के अन्दर 41 प्रतिशत छीजत थी। मेरे पास विभाग के आंकड़े हैं, 42.5 प्रतिशत वर्ष 2003-04 में थी। उसके पश्चात् 8475 फीडर, चार हजार करोड़ रुपये लगाकर हम इस छीजत को 25 परसेंट पर ले आये। अभी ये औसतन बता रहे हैं 24 परसेंट छीजत है, मतलब सवा साल के अन्दर केवल एक परसेंट ही छीजत कम कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज, जो माननीय सदस्य बता रहे हैं, 36 हजार गांवों में बिजली दे रहे थे हम, बीस घंटे अतिरिक्त कितने गांवों को मिल रही है बिजली? आखिर में एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जो सुपर ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, आपके प्रश्न के जबाव में आपने लिखा है कि दो लाख बानवे हजार सुपर ट्रांसफार्मर्स आपने लगाये हैं, अब लगाने कितने शेष हैं, नम्बर एक? नम्बर दो, सिंगल-फेस के आप ने एक लाख छप्पन हजार ट्रांसफार्मर्स लगाये हैं, सिंगल-फेस के अब कितने लगाने शेष हैं? जब तक ये पूरे नहीं लगेंगे, छीजत कम नहीं होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, आपने अपने उत्तर के खण्ड एक के अन्दर खुद यह माना है कि आपके पास जो विद्युत की उपलब्धता है वह मांग के अनुरूप नहीं है। तो मेरा सवाल यह है, क्या यह सही है कि विद्युत उपलब्धता की कमी के कारण आप राजस्थान के किसानों को पांच घंटे बिजली और राजस्थान के गांव के उपभोक्ता को मात्र आठ घंटे बिजली दे पाये हैं? कितना कितना कट आपने पिछले महीने में विद्युत की उपलब्धता कम होने के कारण किया, कृपया यह बताएं, नम्बर एक? नम्बर दो, जो सैन्टल सैक्टर अलाटेड कोटा है, क्या यह सही है कि जितना कोटा हमारा होना चाहिए उससे कम हमें बिजली उपलब्ध हो रही है?

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न के दायरे में रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नम्बर तीन, आप वायलेटर एग्रीमेंट से कितनी बिजली क्रय कर रहे हैं? क्या यह सही है कि आपने कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों-अडानी, रिलायंस और थापर से भी बिजली खरीदी है?

श्री अध्यक्ष: आप इधर मुंह करके बोलें। थापर और अडानी कहां से आ गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसी में है। अध्यक्ष महोदय, विद्युत क्रय करने का सवाल इन्होंने किया है।

श्री अध्यक्ष: थापर, अडानी कहां आ गया। इसी में सीमित रहिए। नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठानों से बिजली खरीदी है या नहीं, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष: नहीं। माननीय सदस्य का जबाव दे दें आप। अडानी कहां से आ गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसी के अन्दर है।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, लोहावट से आने वाले माननीय सदस्य ने, पूर्व में पावर के मंत्री रहे हैं, जो प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जो हमारे दो लाख बानवे हजार ट्रांसफार्मर्स लगे हैं और एक लाख छप्पन हजार सिंगल-फेस के लगे हैं, यह एक सतत् प्रक्रिया है और ये आगे भी लगते रहेंगे। उसके अन्दर वह डिटेल पूछना चाहेंगे तो पर्सनली मैं इनको दे दूंगा। नम्बर दो, आपने जो छीजत का प्रश्न किया है...

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): मंत्रीजी, लगने कितने शेष रह गये हैं, आप उसका जबाव दीजिए न।

श्री अध्यक्ष: आप जबाव आने दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): कितने लगे हैं, वह तो बता दिया कि इतने लग गये हैं। और आपको लोग ट्रांसफार्मर्स लगाने देंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में डिस्टर्ब नहीं। आप इधर देखकर। सुनिए मेरी भी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कृषि कनेक्शन के सम्बन्ध में वर्तमान में जो कृषि कनेक्शन हमने दिये, उसके अलावा हमारे जो पुराने कृषि कनेक्शन थे, पुराने ग्रुप्स के अन्दर ट्रांसफार्मर्स लगे हुए थे- एक एक ट्रांसफार्मर से दस-दस, बीस-बीस कनेक्शन थे, उनको हम शार्ट करके, अच्छी वोल्टेज की बिजली मिले, इसलिए एक और दो में कन्वर्ट कर रहे हैं। जितने भी हमारे पास ओल्ड कनेक्शन थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-एक ट्रांसफार्मर पर बीस-बीस, तीस-तीस थे, उनको वोल्टेज ...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): मंत्रीजी, लगाने कितने शेष हैं, यह बताइये न। फीगर बताएं आप।

श्री अध्यक्ष: छोड़िये, आप तो जवाब दीजिए।

श्री जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): सर, फीगर स्पेसिफिकली मैं आपको ...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): आप कह रहे हैं कि 2 लाख 92 हजार लग गये हैं, अब लगने कितने शेष हैं? What is the balance?

श्री अध्यक्ष: आपस में चर्चा नहीं।

श्री जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): बैलेंस मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैं उपलब्ध करा दूंगा, सर, balance is a long... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत। बैठिये, मंत्रीजी। श्री रामहेत।

एक माननीय सदस्य: जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

कृषि महाविद्यालय लालसोट में डीन के पद पर नियुक्ति हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया

88. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि महाविद्यालय, लालसोट वर्ष 2008 में खोला गया?

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि महाविद्यालय, लालसोट में डीन का पद साक्षात्कार द्वारा भरा गया? कृषि महाविद्यालय, लालसोट में डीन हेतु कितने आवेदकों ने आवेदन किया तथा साक्षात्कार में भाग लिया? यदि नहीं, तो किस नियम के तहत डीन की नियुक्ति की गयी? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कृषि महाविद्यालय, लालसोट में डीन की नियुक्ति प्रक्रिया एवं नियमों का पालन करते हुए की गई है? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि) (श्री मुरारी लाल मीणा): (1) जी नहीं। कृषि महाविद्यालय, लालसोट वर्ष 2007 में खोला गया था।

(2) जी नहीं। कृषि महाविद्यालय, लालसोट (दौसा) में डीन का पद स्वीकृत नहीं है।

(3) महाविद्यालय को चलाने हेतु एक वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत सह-आचार्य को नोडल आफिसर कम विशेषाधिकारी के पदनाम को शैक्षणिक परिषद एवं प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति के पश्चात् डीन पद से नामित किया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुरारीलालजी, डीन के आगे एक शब्द और है, वो भी पढ़ो।

श्री मुरारी लाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): (3) कृषि महाविद्यालय, लालसोट में डीन की नियुक्ति नहीं की गई है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा डीन का पद स्वीकृत नहीं है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या लालसोट महाविद्यालय में सरकार की मंशा डीन की नियुक्ति करने की है? और है, तो कब तक डीन की नियुक्ति हो जाएगी?

(श्री रामहेत सिंह)

इसी में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक बात सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बीकानेर और एग्रीकल्चर महाविद्यालय, लालसोट, इन विश्वविद्यालयों और कालेजों पर सरकार का ध्यान बिलकुल नहीं है। कृषि प्रधान राजस्थान में ...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): प्रश्न यह है कि क्या डीन की नियुक्ति करने की सरकार मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री मुरारी लाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): माननीय अध्यक्ष महोदय, लालसोट कालेज 2008 में खोला गया था, उसके संचालन हेतु नोडल आफिसर के रूप में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की गयी थी। जैसे ही कालेज रैगुलर स्थिति में आएगा और वहां पर पी.जी. की व्यवस्था होगी, डीन का पद स्वीकृति लेकर सैंक्शन कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। थैंक यू। (व्यवधान) श्री सूरजभान। श्री सूरजभान।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): डीन तो सबसे पहले नियुक्त होता है ...(व्यवधान)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ (अलवर) का क्रमोन्नयन

89. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (अलवर) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजगढ़ को 100 शैयाओं का बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजगढ़ की शैयाओं में वृद्धि करने के प्रयास किये जाएंगे।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करूंगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर आने से पहले ही शैयाओं की बढ़ोतरी कर दी गयी है। बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया आप क्वांटिटी और बता दें, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: काम्पीटेंट मंत्री का यही है। श्री अब्दुल सगीर खां।

वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाने हेतु कार्य-योजना

90. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(I) क्या यह सही है कि प्रदेश में वक्फ बोर्ड, आय के स्रोत अत्यन्त सीमित होने के कारण कर्मचारियों को वेतन देने में भी समर्थ नहीं है? क्या सरकार वक्फ बोर्ड की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई विशिष्ट योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और क्या?

(2) क्या यह भी सही है कि वक्फ बोर्ड, आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण अपनी सम्पत्ति पर हुए अतिक्रमणों को हटाने हेतु न्यायालयों में दायर वाद की वकीलों को फीस भी मुहैया कराने में असमर्थ है? क्या सरकार कोई योजना बना कर उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें। कृपया, अगला प्रश्न है, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, विराजो। (व्यवधान) धन्यवाद दे दिया उन्होंने, आप बीच में क्यों? धन्यवाद लेने वाला राज़ी धन्यवाद देने वाला राज़ी, आप बीच में। कृपया शांति रखें।

राज्य मंत्री, वक्फ (राज्य मंत्री, वक्फ): (1) जी हां। वक्फ बोर्ड का आर्थिक प्रबन्धन स्वयं वक्फ बोर्ड द्वारा ही किया जाता है और उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वक्फ बोर्ड की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु राज्य सरकार के समक्ष कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): प्रश्न तो पढ़ दीजिएगा, मंत्रीजी, प्रश्न पढ़ दीजिएगा प्लीज।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, वक्फ): (2) जी हां। वक्फ सम्पत्तियों पर किये गये अतिक्रमणों को हटाने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में पर्याप्त विधिक प्रावधान हैं। अत: अलग से कोई विशेष योजना बनाने का कोई विचार नहीं है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि वक्फ प्रापर्टीज पर अतिक्रमण के कुल कितने केसेज विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं? The total number of cases pending

(श्री अब्दुल सगीर खां)

in different courts. वक्फ इन केसेज में इन्वाल्व वकीलों की फीस नहीं दे पायी है, उसका टोटल अमाउण्ट 31 जनवरी, 2010 तक कितना है?

एक माननीय सदस्य: हिन्दी में बोलो। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): हिन्दी में ही बोला है।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, वक्फ): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मूल प्रश्न नीतिगत है जो स्पष्ट रूप से उनको उत्तर दिया गया है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): What is this answer?

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, वक्फ): वक्फ बोर्ड की हालत नाजुक है, इसमें कोई शक नहीं और आज तक किसी भी ...

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): It is not a specific answer to the question that I have put up.

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिये पूरा।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, वक्फ): हां, क्वेश्चन का जवाब।

आज तक किसी भी सरकार ने इस बोर्ड में एक पैसा भी देने का प्रयास नहीं किया। यह पहली सरकार है, सुनिये, यह पहली सरकार अशोक गहलोतजी की है जिसमें पिछली बार भी 45 लाख रुपये की ग्रांट दी गयी और इस वक्त भी बजट भाषण में 55 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकारी विभागों में जो आंकड़े आप कहो तो मैं पढ़ कर सुना दूं, दो करोड़ रुपये और कुछ ऊपर पैसा अभी तक बकाया है। यह वक्फ बोर्ड की लापरवाही है, बोर्ड आपका है जिसने आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): Hon'ble Speaker Sir, this is not the answer of the question that I have put up.

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले मूल प्रश्नकर्ता। (व्यवधान) माननीय सदस्य, पहले मूल प्रश्नकर्ता।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं, राजनीति की बात कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा स्पेसिफिकली कि आपके कितने केसेज भिन्न-भिन्न न्यायालय में हैं, आपने संख्या नहीं बतायी।

(श्री अब्दुल सगीर खां)

दूसरा, मैंने आपसे पूछा कि आपको टोटल वकीलों की कितनी फीस देनी है, वो आपने नहीं बताया। मंत्रीजी, आप प्रश्न को +++ प्रश्नों का उत्तर दीजिए, भाषण नहीं।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, वक्फ): बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द को एक्सपंज कर दिया जाए। +++

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, वक्फ): माननीय अध्यक्ष महोदय, केसेज जो पैंडिंग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पांच हैं, राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर और जयपुर बैंच में 281 हैं, राजस्थान वक्फ प्राधिकरण में 822 हैं, न्यायालय, वक्फ सम्पदा अधिकारी में 975 हैं और सिविल न्यायालय में 30 हैं। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा, मंत्रीजी, आपके पास मिसएप्रोप्रिएशन, मिसमैनेजमेंट एण्ड करप्शन की कोई भी शिकायत इस 15 महीने में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो आपने क्या कार्यवाही की।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, वक्फ): हमारे यहां पर कोई शिकायत नहीं हुई है। आपके वक्फ बोर्ड की लापरवाही की और स्थानीय कमेटियों में जो 7 प्रतिशत आमदनी वक्फ बोर्ड में आती है, उसमें एक पैसा भी नहीं आ रहा है और वक्फ बोर्ड उसमें कोई कार्यवाही करने नहीं जा रहा है। वक्फ बोर्ड का एक्ट सेंट्रल का है, स्टेट गवर्नमेंट दखल सीधा इसमें नहीं कर सकती।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): क्या यह सत्य है कि सरकार हैल्पलैस है, पावरलैस है हस्तक्षेप करने में?

प्रश्न संख्या-91

श्री अध्यक्ष: श्री ओटाराम देवासी।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री राधेश्याम गंगानगर। श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): आदरणीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं। राधेश्यामजी, एक मिनट, एक मिनट। राधेश्यामजी, बहुत इम्पार्टेंट सवाल है।

श्री अध्यक्ष: हो गया, कुछ है नहीं, जवाब सारा स्पष्ट आ गया। श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि यह सेंट्रल वक्फ एक्ट में आएगा, तो मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इसका जो किराया एक्ट है, क्योंकि वक्फ की सम्पत्तियां हैं वो ...(व्यवधान) किराया आता है।

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): इसलिए सेंटर से इस एक्ट को चैंज कराएं तो इसकी दशा सुधरेगी।

श्रीगंगानगर जिले में राशन सामग्री की कालाबाजारी

92. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला श्रीगंगानगर में कुल कितने ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. कार्डधारक हैं? सरकार द्वारा उन्हें वर्तमान में प्रति कार्ड कितना राशन गेहूं, चीनी आदि उपलब्ध कराया जा रहा है तथा डिपोधारकों द्वारा कितना दिया जा रहा है? वर्ष 2008 से जनवरी, 2010 तक तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले को ए.पी.एल. कार्डधारकों के लिए जनवरी, 2009 से जनवरी, 2010 तक तहसीलवार कितना-कितना गेहूं आबंटित किया गया एवं डिपोधारकों द्वारा कितना-कितना उठाव हुआ है तथा कितना वितरित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर शहर व तहसील में अधिकांश ए.पी.एल. कार्डधारकों को राशन उपलब्ध न करा कर कर्मचारियों ने डिपोधारकों से मिलीभगत कर भारी मात्रा में गेहूं व कैरोसिन वितरण नहीं किया? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) जनवरी, 2008 से जनवरी, 2010 तक जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर व अन्य रसद निरीक्षकों ने कब-कब डिपो का निरीक्षण किया तथा उनमें क्या-क्या खामियां पायी गयीं? निरीक्षण की दिनांक सहित तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री बाबूलाल नागर): (1) जिला गंगानगर में कुल ए पी एल 522446 एवं बी पी एल 44361 कार्ड

(श्री बाबूलाल नागर)

धारक हैं। सरकार द्वारा ए पी एल कार्डधारकों को दस किलो ग्राम गेहूं प्रति कार्ड, बी पी एल कार्डधारकों को तीस किलो ग्राम प्रति माह व 450 ग्राम चीनी प्रति यूनिट कुल उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर समानुपातिक मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है व इसी अनुपात में डिपोधारकों द्वारा वितरण किया जाता है। वर्ष 2008 से जनवरी 2010 तक की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला श्रीगंगानगर के ए पी एल कार्डधारकों के लिए जनवरी 2009 से जनवरी 2010 तक आबंटित व डिपोधारकों द्वारा उठाव कर वितरित गेहूं की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) श्रीगंगानगर शहर में मांग के अनुसार व तहसील में ए पी एल कार्डधारकों को आबंटित मात्रानुसार गेहूं एवं कैरोसिन राशन कार्डधारियों की वर्तमान संख्या के आधार पर उपरोक्तानुसार समानुपातिक मात्रा में उपलब्ध कराया गया है। गेहूं व कैरोसिन के सम्बन्ध में कर्मचारियों व डिपो धारकों की मिलीभगत की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। अत: इस सम्बन्ध में कोई जांच विचाराधीन नहीं है।

(4) जनवरी 2008 से 2010 तक जिला रसद अधिकारी व अन्य रसद निरीक्षकों द्वारा डिपो के किये गये निरीक्षणों, निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियां व की गई कार्यवाही की सूचना तहसीलवार तैयार कर परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी जानकारी यहां मंत्री महोदय ने दी है, मेरे ख्याल में विभाग ने आपको टोटल जानकारी गलत दी है। पहली तो बात यह है कि आप ए पी एल या बी पी एल जो भी उनको देते हो, क्या दस किलो से पेट भर सकता है? दूसरा, आपने इसमें लिखा है कि आबंटन किया है 176, मैंने यह पूछा है कि आपने बांटा कितना है। आपने उठा तो लिया हण्ड्रेड परसेंट, कहीं उठाया आपने पचास परसेंट, कहीं उठाया आपने तीस पर्सेण्ट लेकिन बांटने वाला खाना कहां है? आपने जो बांटना था, डिपो के द्वारा बांटना था, वह किस हिसाब से बांटा, आपने वह कोई आंकड़ा इसमें दर्शाया ही नहीं। मैंने जो पूछा है प्रश्न वह तो प्रश्न इसमें आया ही नहीं। आपको सूचना गलत दी गई है। चारों तरफ बिलकुल अन्धेरा छाया हुआ है। पूरे राजस्थान के डिपो जो हैं वह किस तरह कर रहे है, यह आपकी जानकारी में है, करोड़ों रुपये का गड़बड़ इसमें हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए, पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): पूरक प्रश्न पूछा है न, जी, इसमें जब खाना ही नहीं है तो मैं पूछूं क्या? मैंने पूछा है, आबंटन कितना हुआ। आपने जनवरी, 2008 में 176 उठाया, हण्ड्रेड परसेंट उठा लिया, दिया किसको, कितना बंटा? सारे ट्रक के ट्रक बिक गये ...(व्यवधान) ले गये बाहर। आपने जो चीज है वह तो बताई ही नहीं। मैंने जो प्रश्न पूछा वह कहां है इसकी डिटेल? आपको उन्होंने यह पोथा पकड़ा दिया और आपने यहां बता दिया। यह आपने जो शुद्ध के लिए युद्ध चला रखा है यह लोगों का गला घोंटा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह 2008 का मामला है, 2008 का मामला।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं आगे कैसे बढ़ूं, मेरे को जानकारी ही नहीं दी गयी? आप बताइये, कोई जानकारी तो हो। उठा लिया...

श्री अध्यक्ष: इसीलिए पूछते हैं न पूरक प्रश्न, जानकारी कम रह गयी तो पूछ लो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं वही निवेदन कर रहा हूं। आपने जो आबंटन किया, आपने उठा भी लिया, आपने बांटा तो है ही नहीं। एक भी दाना किसी को नहीं मिला, ट्रक के ट्रक बाजार में बिक गये। और कई बार ट्रक पकड़े गये, यह आपकी जानकारी में है। जब वह चीज आएगी नहीं तो मैं क्या पूछूंगा, कई जगह आपने 350, 2008 को उठाया, उसके अगेन्स्ट 350 अलॉट हुआ 150 उठाया, 42 परसेंट आपने उठा लिया तो कितना दिया? पहले तो उठाया कैसे कम आपने?

श्री अध्यक्ष: ट्रकों से।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आपको अलाट तो हुआ दस हजार मैट्रिक टन, आप उठा रहे हो पांच हजार, पहले कारण बताओ पांच हजार क्यों उठाया? उसके बाद आपने सेंट परसेंट या फिफ्टी परसेंट उठा लिया तो गया कहां, बांटा किसको आपने, सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का है।

श्री अध्यक्ष: विराजें, जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा ......

श्री अध्यक्ष: आपको सारा कल बता दिया था फिर भी आप सन्तुष्ट नहीं हो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): कि 2008 में 176 मैट्रिक टन गेहूं आबंटन हुआ और उठाव 176 मैट्रिक टन किया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने, यह जो गेहूं है गंगानगर में 2008 में खाली ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 2008 से 2010 का भी।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं वह सब बता रहा हूं, 2008 से शुरू कर रहा हूं ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 2008 से पूछा है इन्होंने।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरा मूल प्रश्न यह है कि वितरित किसको किया, वह तो बताओ? आगे मैं बताऊंगा आपको।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): हां, वह नाम ही तो बता रहा हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): कितनी, अध्यक्ष महोदय, इसमें पोल है, यह जानकर सारा हाउस हैरान हो जाएगा। पहले वह तो बताओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गंगानगर का मामला है गंगानगर का।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं माननीय सदस्य को बताना चाह रहा हूं गंगानगर जिले में 2008 से सिर्फ एक तहसील सूरतगढ़ में उसकी भी खाली बीस पंचायतों में उठाव करके वितरण किया है। पूरे जिले में एक क्विंटल का भी वितरण 2008 में नहीं हुआ है ...(व्यवधान) एक क्विंटल का भी वितरण नहीं हुआ है। इसी तरह से 2009 ......

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 2010 की पूछो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 2008, 2009, 2010.

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सब बता रहा हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं यह पूछ रहा हूं आपसे, जिला श्रीगंगानगर में कुल कितने ए पी एल एवं बी पी एल कार्डधारक हैं? सरकार द्वारा उन्हें वितरण-मान से प्रति कार्ड कितना वितरित किया है? कितना दिया है, वह तो आपने इसमें दिया ही नहीं। जब तक आपको यह मालूम नहीं होगा अलाट कर दिया गवर्नमेंट ने .....

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं, माननीय सदस्य, आपको निवेदन कर रहा हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): डिपोधारक ने उठा लिया।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): एक तहसील में बीस गांव के अलावा कहीं एक क्विंटल गेहूं का भी वितरण नहीं हुआ है न उठाव हुआ है, 2008 में आबंटन ही नहीं हुआ है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 2008 की बात करता हूं तो तकलीफ हो रही है माननीय सदस्य को।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आपकी व्यवस्था गड़बड़ है, मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि आपकी व्यवस्था गलत है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): 2008 की बात तो सुनना ही नहीं चाहते। ...(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इसमें वितरण का डिटेल मांग रहे हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, गरीबों को वहां पर राशन का गेहूं नहीं मिल रहा है ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में वितरण का डिटेल पूछा गया है और माननीय सदस्य को ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): भाषण के अन्दर पांच किलो से दस किलो गेहूं कर दिया...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, इनके राज में सारे गरीबों का गेहूं खा गये और अब प्रश्न लगा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सारे गरीबों का गेहूं खा गये ...(व्यवधान) ढ़ाई रुपये ज्यादा ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): पूरी कालाबाजारी हो गयी, माल उनके पास गया नहीं, उठाया ...

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): हमारा राज आया उससे बता दूं ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सारा खा गये, टोटल खा गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): जवाब कहां से देंगे, जवाब इनके पास है ही नहीं। जब इसमें दिया ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष: सुनो तो सही, जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी जवाब दे रहे है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरा आरोप है ...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, समय समाप्त होने जा रहा है, जवाब सुन लें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): पूरी की पूरी चीनी, पूरी की पूरी गेहूं बाजार में बिक गयी, मेरा यह आरोप है। इस बात को सिद्ध करें, पूरा का पूरा घोटाला है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): बिकेगी जब तो उठाव होगा, वितरण करेंगे। उठाव ही नहीं हुआ, आबंटन ही नहीं हुआ, एक तहसील में हुआ खाली।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): कमाल बात कर रहे हो, श्रीमानजी आपको पता ही नहीं है। आप तो ताली पीट रहे हो और कुछ पता नहीं है आपको। (व्यवधान) आप तो भ्रष्टाचार करते हो, भ्रष्टाचार की जीती जागती तस्वीर हो आप। कमाल बात करते हो आप। क्या बात कर रहे हो आप, बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं कुछ पूछ रहा हूं और आप कुछ और बता रहे हो ।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): 2009 से बता रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): झूठा आरोप लगा रहे हैं। 2008 का मामला है, झूठा आरोप लगा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) यह क्या तमाशा कर रखा है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ये जो आरोप भ्रष्टाचार के बाबत लगाये गये हैं, भ्रष्टाचार की जो बात उठाई गई है, यह एक्सपंज होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है, कृपया विराजें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह बंद होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर हैं, कृपया आप विराजें। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, आप कुछ कह रहे हैं, आप फिर से, मैंने सुना नहीं है इसलिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कल भी हाउस की प्रोसीडिंग्स देखी, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी नोटिस के हर कोई आदमी आरोप लगाने को तैयार हो जाता है मन्त्रियों के खिलाफ, जबकि यह नियमों के विरूद्ध है। आज भी यह भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो या तो यह भ्रष्टाचार साबित करें और या सदन से माफी मांगें। और फिर देना है तो बाकायदा नोटिस दीजिए इनको। इस तरीके से नहीं चल सकता हाउस ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम साबित करेंगे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जवाब मांग रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब दिलवाओ इनका।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह अधिकार है इनको, अगर किसी मंत्री के खिलाफ कोई इनके पास आरोप है तो लिखित में ...(व्यवधान) इनको नोटिस दें बाकायदा, लेकिन इस तरीके का आरोप अगर लगता है और एक्सपंज नहीं होगा तो इनको प्रताड़ना नहीं मिलेगी आपकी तरफ से...

(समय : 12.00 बजे)

श्री नगराज (धरियावद): कल भी लगाया और आज भी लगा रहे हैं। आदत बुरी बात है...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ये अच्छी परम्पराएं नहीं होंगी इस हाउस की। आप इनको कहिये न यह बात।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय धारीवालजी, मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। आपकी इस चुनौती को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त। आसन पांवों पर है। प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। आसन पांवों पर है। प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है।

(शेष तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया पृष्ठ सं. 199 पर देखें।)

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

मुख्य मंत्री द्वारा सदन के बाहर वैट (VAT) दर कम करने की घोषणा

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, I am on a point of privilege. अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण...

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रिविलेज। विशेषाधिकार का। माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं तो ठीक रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं। नहीं, कोई आरोप नहीं है। यह प्रश्न मैं न तो किसी पर स्कोर करने के लिये लगा रहा हूं, न मैं यह प्रश्न किसी प्रकार की मानहानिकारकों पर उठा रहा हूं। मैं इस सदन की परम्पराओं के रूप में माननीय मंत्रियों, मुख्य मंत्रीजी से किस प्रकार की गलती करा दी जाती है जिससे हम सारे सदन के जो माननीय सदस्य हैं उनके अधिकार का हनन होता है, इसलिये मैंने नियमों के अन्तर्गत आपके पास यह बात भेजी है।

अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 202 भारत के संविधान का है उस आर्टिकल के अन्तर्गत यह साफ लिखा है, ''The Governor shall in respect of every financial year cause to be laid before the House or Houses of the Legislature of the State a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for that year, in this part referred to as the 'annual financial statement..." तो अनुच्छेद 202 के अन्तर्गत राजस्थान की विधान सभा में 138 नियम आपने जो बनाया है आय-व्ययक, उसमें स्पष्ट आपने उल्लेख किया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राक्कलित आय और व्यय का विवरण जिसे इसके पश्चात् आय-व्ययक कहा जाएगा, सदन में ऐसे दिन उपस्थापित किया जाएगा जैसा कि राज्यपाल महोदय निर्देश दें। आर्टिकल 202 और अनुच्छेद 204, अनुच्छेद 204 है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जिसमें अपन एप्रोप्रियेशन बिल लाते हैं और सदन स्टेट के कंसोलिडेटेड फण्ड से पैसे निकालने के लिये राज्य सरकार को अधिकृत करता है। इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन और परिवर्द्धन विधान सभा के अन्दर ही किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के आदेश पर आर्टिकल 202 के अनुसरण में और नियम 138 के अन्तर्गत 9 तारीख को, दिनांक 9 मार्च, 2010 को चैत्र कृष्ण नवमी विक्रम सम्वत् 2066 को माननीय मुख्य मंत्रीजी जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, ने अपने बजट का भाषण, आय-व्ययक भाषण सदन के पटल पर रखा। उसके पैरा नम्बर 291 में कहा है- सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा वैट अन्तर्गत लोअर टैक्स रेट 5 प्रतिशत रखने की अभिशंसा की गयी है। अन्य कई राज्यों में भी यह दर 5 प्रतिशत कर दी गयी है। अत: हमारे राज्य में भी इस टैक्स रेट को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो राजस्थान की विधान सभा में कोई मंत्री, मुख्य मंत्री या सदस्य सारे सदन को गुमराह करने के लिये नियमों के विपरीत कोई बात कहे, उसके किसी की जिम्मेदारी तो तय होगी। जबकि आपको मैं एक पढ़कर सुनाता हूं भारत सरकार का आदेश सी एस टी के अन्तर्गत Section 4 of CST, जिसमें यह कहा गया है, इसी में है, ''The tax, payable under the law in respect of any sale or purchase of such goods inside the state, shall not exceed 4% of the sale or purchase price there of.'' और उसकी लिस्ट जो उन्होंने जारी की है पैडी, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, कोंडम, कुट्टी, बारले, कोल इत्यादि-इत्यादि। ये 14 वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर राज्य सरकार 4 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकती। इस सदन में इसका उल्लंघन करके माननीय मुख्य मंत्री के मुंह से कहलवाया गया कि 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। यह सदन को गुमराह करने वाला और सदन के विशेषाधिकार का हनन है। एक बात तो यह कहनी है।

इसके बाद में अध्यक्ष महोदय, जब यहां पर चर्चा हुई तो चर्चा के बाद कल एक और उससे बड़ी गलती की। वह गलती यह की गयी कि उसके बारे में एक संशोधन जारी किया गया। संशोधन क्या किया, ''for the existing taxable act'' इसको घटाकर इन्होंने कह दिया, ''declared goods excluding pulses as

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

specified in Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956", और उसको घटाकर उन्होंने उसको 4 प्रतिशत वापस कर दिया। 4 प्रतिशत करने में विभाग से यह फाइल चली, मुख्य मंत्रीजी के पास फाइल गयी। फाइल जाने के बाद में मुख्य मंत्रीजी से दस्तखत कराये गये और दस्तखत कराने के बाद में प्रेस को जारी कर दिये गये। इसको सदन के पटल पर नहीं रखा गया।

मैं, अध्यक्ष महोदय, इसमें दो बड़े प्रश्न आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। पहली बात यह है कि इस विधान सभा में यह नियम है, मैं दो मुद्दों पर, ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा, दो मुद्दों पर आपके सामने निवेदन करूंगा। इस सारे सदन और इसकी मर्यादाओं के रक्षक आप हैं। हम सब आपकी आज्ञा के पालन में हैं।

अध्यक्ष महोदय, दो प्रकार के काम होते हैं। एक होता है सदन चलते समय सदन के किसी मामले की महत्वपूर्ण घोषणा, इसके बारे में तीन बड़ी-बड़ी रूलिंग हैं। मैं उनको बोलकर आपके सामने, आप सब जानते हैं। यह बार-बार पी जी मावलंकर साहब से लेकर, आयंगर साहब से लेकर, रामनिवासजी मिर्धा से लेकर, हरिशंकर जी भाभड़ा से लेकर आप तब सभी माननीय अध्यक्षों ने यह व्यवस्था की है कि सदन के चलते समय कोई भी विशेष घोषणा सदन के बाहर नहीं की जानी चाहिये और लास्ट रूलिंग है उसमें कहा गया है। उसके बाद यह कहा गया है कि इसके बाद सरकार इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करेगी। यह महत्वपूर्ण घोषणा सदन के बाहर की गयी। यह भी सदन के विशेषाधिकार का हनन है। इसको तो अध्यक्ष महोदय, इतना कहकर आप कह सकते हैं कि सरकार आइन्दा नहीं करेगी लेकिन हमारे...

श्री अध्यक्ष: मुझे क्या कहना है, यह आप कैसे कहलवा रहे हो? तो मैं कहूंगा बाद में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, कहेंगे आप, लेकिन दो माननीय अध्यक्षों ने पहले से यह कहा है इसलिये मैं कह रहा हूं और फिर कुछ-कुछ मैं अधिकार भी रखता हूं, थोड़े से आप यह कह दोगे। आप यह कह दो तो क्या दिक्कत है ?

लेकिन मैं दूसरा मामला इसमें पेश कर रहा हूं। यह सामान्य घोषणा की बात है। रोडवेज में स्ट्राइक हो गयी, स्ट्राइक तोड़ने के लिये आप बाहर घोषणा कर दो। आप कह देंगे, यह फाइनेंशियल मैटर है, वित्तीय मामला है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राज्य विधान मण्डल के अलावा वित्तीय मामलों की कहीं हो ही नहीं सकती। राज्य सरकार आदेश जारी करके नहीं कर सकती कोई काम। विधान मण्डलों के बारे में बजट जब पेश कर दिया जाता है उसके बारे में तीन प्रक्रियाएं अपने पास हैं, तीन स्टेज पर चर्चा होती है। आय-व्ययक अनुमान पर चर्चा होती है जो इस समय चल रही है। सैकिण्ड नम्बर की डिबेट आप जब डिमाण्ड पारित करते हैं, उन पर बहस होती है, और तीसरा एप्रोप्रियेशन बिल होता है। आर्टिकल 206 के अन्तर्गत आर्टिकल 256, आपके भारतीय संविधान का आर्टिकल 206 यह साफ कहता है कि एप्रोप्रियेशन बिल के समय जवाब देते समय मंत्री अपने टैक्सों में कम-अधिक करने की घोषणा कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता है। सदन के अन्दर जाकर कोई बात की जा सकती है, लेकिन इन सबके बावजूद वित्तीय मामले अलग हैं। वित्तीय मामलों का अधिकार केवल मात्र सदन को है और एक बार जब मुख्य मंत्रीजी ने सदन में यह प्रस्तुत कर दिया कि मैं वैट दर 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत बढ़ा रहा हूं, उसके बाद में उसको कम करने का अधिकार माननीय मुख्य मंत्रीजी को नहीं था।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सदन के बाहर यह घोषणा की, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 203 और 204 का उल्लंघन किया। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा नियम 138 से लेकर जो बजट के नियम हैं, उनका उल्लंघन किया, वित्तीय मामलों का उल्लंघन किया और, अध्यक्ष महोदय, यह सदन के विशेषाधिकार का खुला-खुला उल्लंघन है।

इस सम्बन्ध में एक नहीं पचास इस प्रकार की बातें हैं इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह जो कार्यवाही की है, वह नियमों के विपरीत, संविधान के विपरीत है, इसके विपरीत है और इसलिये उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का, इस सदन के विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिये। और, अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी को इसके बारे में त्यागपत्र देना चाहिये।

उनकी जिम्मेदारी है सदन के सामने, यह सदन मजाक नहीं है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान) ध्यान तो आकर्षित कर रहा हूं, ध्यान तो आकर्षित कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। क्या हुआ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सरकार कुछ कहना चाहे तो कह दे।

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न रखा है और दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसी सम्बन्ध में एक नोटिस दिया है, मैं पूरे प्रकरण को देखकर इसकी व्यवस्था दे दूंगा। अभी व्यवस्था रिजर्व है, चर्चा नहीं। (व्यवधान) मैं व्यवस्था दूंगा, मैंने आपसे निवेदन कर दिया। अब आगे चर्चा की आवश्यकता नहीं है, कृपया विराजें ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): चर्चा की तो नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है, कृपया विराजें। (व्यवधान) आसन पांवों पर है, कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): इस्तीफा देना चाहिए मुख्य मंत्री को ...(व्यवधान) गांधीवादी मुख्य मंत्री हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अनुपस्थिति के लिये अनुमति।

अनुपस्थिति अनुमति

बीना काक, श्रीमती, सदस्य को 10 से 21 मार्च, 2010 तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि बीना काक, सदस्य विधान सभा ने बर्लिन (जर्मनी) में आयोजित इंटरनेशनल ट्रैवल ब्रोर्स (सेमिनार) में भाग लेने के कारण दिनांक 10 मार्च, 2010 से दिनांक 21 मार्च, 2010 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): यह सदन का अपमान है और आप इस बात को खतम करना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या निष्कर्ष निकला, क्या हुआ यह? (व्यवधान) सदन की क्या सैंक्टिटी रह गयी? (व्यवधान)

सदन में नारेबाजी

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): पूंजीपतियों से मिलकर ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे अधिकारों की हत्या हो रही है। संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, हमारे संविधान की हत्या हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है, कृपया विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इससे बड़ी भूल क्या हो सकती है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: मैं निवेदन कर चुका हूं कि इस पर व्यवस्था दूंगा ...(व्यवधान) सारा प्रकरण देखकर व्यवस्था दूंगा। (व्यवधान) कृपया आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी ...(व्यवधान) आप सुनने को तैयार नहीं होंगे ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):×××

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

सदन में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: जाइए, जाइए, सीटों पर जाइए, अंकित नहीं हो रहा। अपनी-अपनी सीटों पर जाइए ......(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। कृपया, अपनी-अपनी सीटों पर पधारें। अंकित नहीं हो रहा है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

सीटों पर बैठिए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

आपका अधिकार है, महाराज, जैसा आप चाहो। (व्यवधान) सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.36 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 13.36 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

मुख्य मंत्री द्वारा सदन के बाहर वैट (VAT) दर कम करने की घोषणा

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आपके सम्मुख 157 में विशेषाधिकार का प्रश्न विचाराधीन है। यह विशेषाधिकार का प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ कि इस सरकार ने टैक्स प्रपोजल के अन्दर चलते हुए सदन में सदन के बाहर जाकर कटौती की बात की। विशेष बात यह है कि केन्द्रीय बिक्री कर कानून, 1956 में धारा 14 और 15 के अन्दर जिन गुड्स को डिक्लेयर किया है और अन्तरराज्यीय व्यापार के विशेष महत्व के माल पर वैट 4 प्रतिशत से ज्यादा हो नहीं सकता, पर उन सारी चीजों को भूलकर राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने उन सारे नियमों को जो केन्द्रीय बिक्री कर कानून की हिस्सा हैं, उनको धता बताकर पहले इस राजस्थान के लोगों पर महंगाई का मार मारने के लिए गेहूं, चावल, सरसों, मूंगफली पर 5 प्रतिशत किया। मैं उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पुरजोर तरीके से इस सदन के अन्दर जब यह बात रखी तो मजबूर होकर घुटने टेककर सरकार ने उस टैक्स प्रपोजल को वापस लिया। पर, सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, हम पूछना चाहते हैं, हमारा अधिकार है इस सदन में सदस्य के नाते, कि जो वैट पहले 5 प्रतिशत था, जिसको 4 प्रतिशत किया गया, उस पर कितना राजस्व

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इन्वाल्व है, कितना राजस्व व्यय बढ़ेगा, कितनी राजस्व हानि होगी, राजकोष कितना बढ़ेगा? यह सब जानने का हमारा अधिकार है। यह सदन सर्वोपरि है और इस सदन की मान्य परम्पराएं हैं। सभापति महोदय, मैंने कल दो अध्यक्षीय व्यवस्था इस सदन के सामने रखी थीं। रामनिवासजी मिर्धा इस आसन पर विराजे थे, उनके सामने जब यह बात आई उस समय एक बार नहीं दो बार, सभापति महोदय, आप कहें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं, एक बार नहीं दो-दो बार इस तरह की व्यवस्था हुई है कि इस सदन के चलते हुए कोई भी नीतिगत निर्णय सदन के बाहर नहीं हो। इसलिए, सभापति महोदय, मेरी मांग है कि पहले राज्य के मुख्य मंत्रीजी यहां आएं, त्याग पत्र दें, क्षमा याचना करें और उसके बाद सदन की कार्यवाही आप आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, यह सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, यह हमारी संवैधानिक परम्पराओं पर कुठाराघात है, हमारे संवैधानिक सम्मान पर चोट करने का काम किया है, यह इस सदन की अवमामना है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि ये अनुत्तरित सवाल तैर रहे हैं कि किस कारण से सदन के चलते हुए किस शिष्टमण्डल से मिलकर मुख्य मंत्रीजी को अचानक यह सूझा कि जो वैट में 5 प्रतिशत किया था उसको वापस 4 प्रतिशत कैसे कर दिया जाए। यह मैं चाहूंगा..... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पहली बात तो यह है कि आप लोग खुद परम्परा से बंधे हुए हैं, और मैं भी। इसलिए जब तक चेयर की परमिशन नहीं मिल जाए, आप लोगों को सदन के अन्दर अपनी बात रखने का हक नहीं है। जहां तक इस सन्दर्भ में जो बात आ रही है जिसमें माननीय सदस्य बोल रहे हैं, I will make it very clear, Hon'ble Speaker has already given his version that he will get back on this subject. मैं समझता हूं कि आप सब ने अच्छी तरह से सुना है कि माननीय स्पीकर महोदय ने यह कह दिया कि इस सन्दर्भ में वो अपना फैसला, व्यवस्था जल्दी ही देंगे। तो मैं समझता हूं कि अब इस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल केवल राजस्थान की विधान सभा का नहीं है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि बजट को पेश करना और बजट के सत्र के चलते हुए चाहे लोक सभा हो, चाहे राज्य सभा हो, चाहे राजस्थान की विधान सभा हो, बजट से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सम्बन्धित किसी भी प्रकार की अगर कोई घोषणा करना चाहें तो सरकार का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार कम कर सकती है पर इस सदन में आकर अपने प्रस्ताव के द्वारा कम किया जा सकता है, हो सकता है। लेकिन इसके बाहर किसी को करने का अधिकार नहीं है। अगर इस परिपाटी को भी अपन ने हल्के-फुल्के ढंग से लिया तो मैं आपको यह आगाह कर रहा हूं, यह परिपाटी अगर पड़ गई तो बजट की सैंक्टिटी खतम हो जाएगी, बजट का मतलब खतम हो जाएगा। बजट सरकार भले ही पेश कर सकती है लेकिन जब तक हाउस पास नहीं करे, इनको एक रुपया खर्चा करने का अधिकार नहीं मिलेगा। एप्रोप्रियेशन बिल जब तक पास नहीं होता यहां हाउस में, चाहे आप संख्या में बड़े हों या छोटे हों, लेकिन आखिर ठप्पा तो हाउस का लगता है, उसके बाद ही जाकर बजट का उपयोग होता है। मैं सोचता हूं कि यह चाहे भूल हुई है चाहे जाने-अनजाने में गलती हुई है, चाहे किसी भी प्रकार से हुई हो, यह जिद्द का सवाल नहीं है, न प्रतिष्ठा का सवाल है, न पक्ष की प्रतिष्ठा का, न विपक्ष की प्रतिष्ठा का सवाल है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप और हम सब बैठकर अगर ताकत नहीं देंगे और इसको मजाक में उड़ा देंगे या हमने पास कर दिया इसलिए गलत है, आप पास करते हैं जो सही है या हम जो पास करते हैं वह सही है और आप गलत हो, इस मापदण्ड में या इस तरह की दीवारों में नहीं बंधिये। कृपा करके जाने-अनजाने गलती हुई होगी चाहे अधिकारियों ने कराई होगी, कैसे भी हुई होगी लेकिन आखिर इस सदन का महत्व है। इस सदन में आकर के इन सब समस्याओं का निदान है। अगर आप जल्दी चाहें तो भी प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं। आप एप्रोप्रिएशन बिल पर आकर अपना निर्णय बदलना चाहें तो आपको अधिकार है। जब बढ़ाने का अधिकार आपका बजट में है तो घटाने का अधिकार भी आपका है। इस अधिकार से मैं ना नहीं कर रहा हूं लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को अगर तोड़कर करेंगे तो लोकतंत्र के बारे में महत्व नहीं रहेगा... (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य सदन की सैंक्टिटी की बात कर रहे हैं। पिछले दो दिनों में इस सदन के अन्दर सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाया गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...और यह केवल आसन का और आपका सवाल नहीं है। यह केवल आपका और मेरा सवाल नहीं है। यह कोई अध्यक्षजी का सवाल नहीं है। यह कोई राजस्थान की विधान सभा का सवाल नहीं है। यह हिन्दुस्तान के संविधान में दी हुई व्यवस्था का सवाल है। मैं सोचता हूं कि संविधान की व्यवस्था के ऊपर, संविधान के ऊपर कोई नहीं होगा। (व्यवधान) संविधान में जो व्यवस्था दी गई है... (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य सदन की गरिमा की बात करते हैं, लेकिन पिछले दो दिन से सदन के माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य हमारे मंत्रीगण पर भ्रष्टाचार के आरोप बिना तथ्यों के लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देंगे। संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना, हम सब लोकतंत्र के सिपाही हैं... (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय सभापति महोदय, ये वैट कम करने के खिलाफ हैं और वे राजस्थान की जनता को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते। इस तरह का इनका व्यवहार है। यदि ये सदन चलाना चाहते हैं तो सदन के लोग... (व्यवधान) और अध्यक्षजी ने व्यवस्था दे दी है... (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):×××

(व्यवधान)

श्री सभापति: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) देखिये, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। मैं माननीय सदस्यों से एक बार फिर कह रहा हूं, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) मंत्री महोदय, कृपया विराजिये। माननीय सदस्य, कृपया विराजिये, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) अगर आप चर्चा करना चाहते हैं, हाउस को चलाना चाहते हैं तो आगे बढ़िये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

श्री सभापति: इस सन्दर्भ में कोई बात नहीं हो सकती। आसन से व्यवस्था दे दी गई है। (व्यवधान) यह आलरेडी व्यवस्था हो गई है और... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

श्री सभापति: आसन पैरों पर है, कृपया विराजिये। आसन पैरों पर है। (व्यवधान) आप भी बैठिये, आप बैठिये। मंत्रीजी, आप भी बैठिये। कृपया बैठिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, कृपया बैठिये। आप मेरी बात को सुनिये। माननीय सदस्य, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):×××

श्री सभापति: आप बैठिये। मैं विराजूंगा, पहले आप विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप विराजिये। (व्यवधान) आप भी परम्पराओं का पालन करिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):×××

(व्यवधान)

श्री सभापति: आसन पांवों पर है। कृपया आप विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):×××

श्री सभापति: कोई भी व्यवस्था स्पीकर महोदय ने दे दी है। (व्यवधान) वे अपने आप व्यवस्था देंगे।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी):×××

श्री सभापति: वे यह बात सदन के सामने कह चुके हैं। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):×××

(व्यवधान)

श्री सभापति: कोई भाषण नहीं होगा।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण):×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):×××

(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण):×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):×××

सदन में नारेबाजी

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: कृपया अपनी-अपनी सीटों पर विराजिये। कृपया आप अपनी-अपनी सीटों पर विराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) कुछ अंकित नहीं हो रहा है, कुछ अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) कुछ अंकित नहीं हो रहा है। आप अपनी-अपनी सीट पर विराजें, कुछ अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

(सदन में नारेबाजी)

कुछ अंकित नहीं हो रहा है, बैठें अपने स्थान पर। (व्यवधान) विराजें। (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं हो रहा, कृपया, माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। कृपया विराजें, माननीय सदस्य, अपने-अपने स्थान पर। कृपया विराजिये, माननीय सदस्य, कुछ अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) हाउस को सुव्यवस्थित चलने दें...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी):×××

एक माननीय सदस्य:×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):××× (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजिये, माननीय सदस्य।

(लगातार व्यवधान एवं नारेबाजी)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):×××

श्री सभापति: The House is adjourned for another one hour. एक घंटे के लिए सदन स्थगित किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.54 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 14.54 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष: समय कम बचा है इसलिए 295 के जो थे, उनको तो पढ़ा हुआ मान लिया जाए, आपकी इजाजत हो तो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर गतिरोध सदन में है.....

श्री अध्यक्ष: आसन पांव पर हैं, इसको ड्राप कर दूं क्या सारे को? तो फिर? 295 तो पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(पढ़े हुए माने गये विशेष उल्लेख प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

अभी जो विषय चल रहा था और जिसके कारण व्यवधान पैदा हुआ था, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी, उसी के सम्बन्ध में सरकार की ओर से, मंत्रीजी, सरकार की ओर से यदि आप कुछ कहना चाहे तो आपको समय देता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है, मैं इतनी ही बात कह रहा हूं कि जो स्थगन प्रस्ताव और पर्चियां आज की हैं, उन पर चर्चा नहीं हुई, समय हो गया तो आपसे यह प्रार्थना करुंगा कि उनको कल के लिए रख लें तो माननीय सदस्यों ने जिन्होंने लगाई हैं, मेहनत की है, अपनी बात कह सकें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव और पर्चियां जो आज की हैं, कल नहीं लेकर उन्हीं को कल रख दिया जाए, ठीक है।

व्यवस्था का प्रश्न

अनुपस्थित माननीय सदस्य के नाम से सूचीबद्ध प्रश्न भी मौखिक उत्तर हेतु लिया जा सकता है

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इससे हटकर आपकी जानकारी में एक बात ओर लाना चाहूंगा। ये आप ही के आदेश थे, यदि कोई माननीय सदस्य जिनका तारांकित सवाल लगा हुआ हो और वह यहां पर मौजूद न हो तो वह सवाल भी लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: उस पर नहीं, जो अभी माननीय....

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह तो है, मैं दे रहा हूं, उससे अलग एक ओर इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, यह आप ही की दी हुई है। आज यहां 91 पर माननीय ओटाराम देवासी साहब का एक सवाल लगा हुआ था, उस सवाल के कुछ देर पहले तो यहां पर विराजमान थे और जब सवाल ...(व्यवधान) नहीं होंगे, मुझे कह लेने दीजिए, फिर आप कह लेना। उसके बाद जब यह सवाल निकल चुका तो वह उसके बाद में आ गये। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर भी आपकी व्यवस्था आ जानी चाहिए कि क्या ऐसे सवालों को जो पहले आपने बताया था कि अगर वह मौजूद नहीं रहेंगे तो कोई भी या तो उठा लेगा या चेयर अपने आप ही जो है, उस बात को उठवा लेगी। तो आयंदा के लिए इस पर जैसा भी आप व्यवस्था देना चाहें, इसकी भी दे दें।

व्यवस्था

अनुपस्थित माननीय सदस्य के नाम से सूचीबद्ध प्रश्न भी मौखिक उत्तर हेतु लिया जा सकता है

श्री अध्यक्ष: नियमों में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान है। मैं स्पष्ट भी कर चुका हूं, यदि कोई माननीय सदस्य अनुपस्थित रहते हैं, नहीं उपस्थित हो पाते हैं और दूसरे कोई माननीय सदस्य उसको पूछना चाहें तो उसको आसन की इजाजत से परमिशन दी जा सकती है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कई बार यह भी हो सकता है, यह मेरा सुझाव है, आप मानें, न मानें, व्यवस्था देना आपका अधिकार है, पर

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

ऐसा भी हो सकता है कि आसन खुद जो है, मंत्री को आदेश दे दे कि इसका जवाब दीजिएगा। जिसको सप्लीमेंट्री पूछना है, पूछ लेगा।

श्री अध्यक्ष: यह भी सम्भव है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: अभी प्रश्नकाल तो समाप्त हो चुका था, प्रश्नकाल तो समाप्त हो चुका था उस पर तो अब कोई चर्चा होगी नहीं, अब तो जो माननीय सांगानेर से आने वाले....

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

मुख्य मंत्री द्वारा सदन के बाहर वैट (VAT) दर कम करने की घोषणा

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, नहीं होगी। मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं, साहब।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 14 वो आइटम्स हैं जिनमें गेहूं भी हैं, पैड़ी भी हैं, चावल, जौ, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, कपास, कोयला, लोहा, इस्पात, सूती धागा, चमड़ा और जूट इन पर वैट लगाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार का है। यह बात सही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना बजट भाषण लगभग 2 घंटे से भी अधिक समय लेते हुए यहां पर डिलीवर किया था और राज्य के हर वर्ग की भावना को ध्यान रखते हुए

कई ऐतिहासिक घोषणाएं भी अपने बजट भाषण में कीं जो कि करीब-करीब 90 पेज का था। हमें इस बात को भी दृष्टिगत रखना चाहिए कि आखिर बजट भाषण की डिलीवरी के वक्त में आदमी पर कितना स्ट्रेस रहता है ...(व्यवधान) आप मेरी सुन तो लें, साहब कम से कम।

(समय : 15.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप इनकी उससे परिचित हैं तो आप सुनिये तो सही।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): और खास तौर पर, अध्यक्ष महोदय, जब अनिताजी बोलती हैं न, तो ये तो यों हिलने लग जाती हैं। मैंने कई बार देखा, ये अनिताजी भदेल यों हिलने तक लग जाती हैं। तो इतना स्ट्रैस रहता है बोलने वाले पर, जरा यह भी देखो पहले। अध्यक्ष महोदय, मेरा अर्ज करना यह है कि 90 पेज का लम्बा भाषण पढ़ते वक्त कोई बात स्पष्ट न हो, यह भी स्वाभाविक है। सभी बातें स्पष्ट हो जाएं, यह भी कोई अनिवार्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष: जैसे कि कल खाद्य मंत्रीजी के साथ हुआ था। जैसा कि खाद्य मंत्रीजी के साथ महंगाई के स्टेटमेंट के टाइम पर हुआ था।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, इनकी भी बात कल समझ में नहीं आयी लोगों के। ...(व्यवधान) मेरा आपसे करजोड़ निवेदन है कि आप तो मेरी बात ध्यान से सुन लिया करें और मैं आपकी सुन लिया करूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूरा सदन कृतार्थ रहेगा अगर आप दोनों ही सुन लो तो।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी को यह भी जानकारी है कि कौन हिलता है और कौन चलता है और विशेषकर महिलाओं की जानकारी आप रखते हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसलिए, अध्यक्ष महोदय, सभी बातें स्पष्ट हो पाएं, यह कोई अनिवार्य नहीं होता है। जानबूझकर कोई भी बात ऐसी पैदा नहीं की जाती कि जिससे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाए। 4 से 5 प्रतिशत वैट बढ़ा दिया गया, इसकी घोषणा से न तो किसी को नुकसान हुआ और न ...(व्यवधान) मैडम, सुनें तो सही। सुन तो लो मेरी, मैडम। मुझे भी कह लेने दो ...(व्यवधान) मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि मेरा नाम है शांति और खास तौर से अगर कोई महिला मेरे भाषण के बीच में बोल जाए तो फिर मामला ही बिगड़ जाता है।

अध्यक्ष महोदय, 4 से 5 प्रतिशत की घोषणा से न तो किसी को नुकसान पहुंचा है और न ही किसी को लाभ पहुंचाने का कोई इरादा था। यह सम्भव ही नहीं था और न इस प्रकार की बात करना कोई सम्भव था और यही कारण रहा कि जब जानकारी में आ गई यह बात कि ऐसी कोई भ्रांति हो गयी है, जब भी जानकारी में आयी कि इस प्रकार की भ्रांति हो गयी है, उसका स्पष्टीकरण फौरन दे दिया गया। आम आदमी को अपनी खरीदी हुई वस्तु पर ज्यादा वैट न देना पड़े इसलिए स्पष्टीकरण देने में कोई किसी प्रकार की देरी सरकार के द्वारा नहीं की गई तो मेरा प्रतिपक्ष के साथियों से यह निवेदन है कि इस स्पष्टीकरण से कोई विपरीत प्रभाव राजस्थान की जनता पर और यहां के व्यापारियों पर, किसी पर भी चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, किसी पर भी नहीं पड़ा इसलिए इस मामले को, आपने जो सदन का ध्यान आकर्षित किया उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन इस मामले को यहीं समाप्त किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। अंकित नहीं होगा। आसन पांवों पर है। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। आसन पांवों पर है। कृपया विराजें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं निवेदन कर चुका हूं इस प्रकरण पर आसन की ओर से व्यवस्था रिजर्व रखते हुए व्यवस्था दी जाएगी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-11 पर सामान्य वाद-विवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन यह है कि मैंने अपनी बात कही और सरकार की ओर से माननीय गृह मंत्रीजी ने अपनी बात कही है, तो इसमें जो विषय था जिसमें सदन की मर्यादा निहित थी, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, इसलिए आपकी उस पर क्या व्यवस्था, जो सदन के विशेषाधिकार और मर्यादाओं का था उस सम्बन्ध में आपकी क्या व्यवस्था है, वो जरा स्पष्ट करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपसे निवेदन किया कि इस विषय पर रिजर्व रख कर सारी चीज देख कर, पढ़ कर, आपने क्या बताया उसको भी देख कर और नियमों को देख कर व्यवस्था दी जाएगी, इसको मैं रिजर्व रख रहा हूं। श्री श्रवण कुमार। ...(व्यवधान) कल आपका लास्ट था इसलिए इधर से शुरू किया है। मैंने पूछ लिया है इसको कंफर्म कर लिया है, कल लास्ट स्पीकर आपका था इसलिए इधर से शुरू किया है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमें बड़ी खुशी है कि राजस्थान बजट 2010-11 को हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया। बजट का आकार 23872 करोड़ रुपये 2009-10 के बजट से 37 प्रतिशत बढ़ा है। स्वाभाविक बात है, देश की बढ़ती हुई व्यवस्था और जनता और आवश्यकता को देखते हुए हमें इस आकार को बढ़ाना पड़ता है। आज देश के अन्दर महती आवश्यकता है अच्छी व्यवस्था देने के लिए, इसलिए मैं सबसे पहले मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बीपीएल परिवार को 4.70 रुपये के बजाय 2 रुपये में गेहूं देने की घोषणा की है। गरीब के घर में बेटे को रोटी के लिए तरसना पड़ता था, वहां सुख-चैन से रोटी खाने का सुअवसर मिला। धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को जो महती आवश्यकता है मानव की बिजली ...(व्यवधान) बात बताने दो एक बार। पेशेंस नहीं रखोगे क्या? तुम्हारी भी गाथा तो बतानी पड़ेगी न अभी।

(श्री श्रवण कुमार)

बिजली पर जो बजट का 52 प्रतिशत रखा है, हर घर में दीपक जलाने का सरकार ने सोच बदला, बिजली जहां होगी तो दीपक जलेगा, इसमें तो कोई शंका की बात नहीं है। इसी प्रकार अभी धारीवाल साहब मंत्रीजी ने बताया, जो खाद्य पदार्थ महती आवश्यकता है, उसमें से बजट में 4 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत जो टैक्स लगाया था, वो कम कर दिया। इसकी पीड़ा सुबह से चल रही है पर आखिर हुआ तो कम ही न। किसान को आप भी चाहते हो, हम भी चाहते हैं, वो कम हुआ। आपका प्रश्न विधान सभा की प्रक्रिया को लेकर चला है लेकिन बाहर गांव में खेत-खलिहान में रहने वाले व्यक्ति को तो उससे फायदा मिला है। हम सबको पक्ष और विपक्ष के लोगों को मिल कर एक बात की सोच रखनी चाहिए कि जो गरीब किसान के पशु हैं, सबसे पुअर स्थिति में हैं। आज किसान की खल पर जो टैक्स लगाया, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और पक्ष-विपक्ष के दोनों सदस्यों से विनती इस बात के लिए करूंगा कि किसान का अगर आप भला चाहते हैं तो जिस प्रकार से पानी के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष ने पहले वसुन्धराजी के समय में एक संकल्प पास किया था उसी तरह से इस खल के ऊपर भी आपको संकल्प पास करना चाहिए। किसान की महती आवश्यकता है खल। गरीब किसान के आज ग्वार नहीं होता है, खल है। बिनौले की तीसरी फोर्म में आकर तेल और तेल के बाद खल बनता है। 1300 रुपये में खल बिक रही है, अगर आज उसका मूल्य पूरा लगेगा तो 1365 रुपये लगेगा जिसका भार गरीब किसान पर पड़ेगा न कि बनिये पर पड़ेगा।

इसलिए मैं चाहता हूं ...(व्यवधान) बनिये पर कहां से पड़ेगा? बनिया तो केवल भेज देगा टैक्स लगा कर, खरीदने वाले पर भार पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो संकल्प किसान के हित में है, वह प्रत्येक व्यक्ति के दिल में दर्द होना चाहिये।

भरा नहीं भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं

हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें गरीब के प्रति प्यार नहीं।

आज शिक्षा की बात आती है कि हमारी स्कूलें कम खुलीं, मैं कहता हूं कि स्कूल खोलने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बडी पीड़ा का विषय है कि आज 5वीं क्लास का बेटा पहली क्लास की किताब पढ़ कर बता देगा तो हम मान जायेगे कि क्लास पास हो गया। 5वीं क्लास का बेटा अपने साइन नहीं कर सकता, क्लास पढ़ नहीं सकता। उसके बाद शिक्षा में बढोत्तरी होने का प्रश्न

(श्री श्रवण कुमार)

कहां आता है? (व्यवधान) बेटा हो चाहे बेटी हो। बेटी का नाम तो अपने आप आ जाएगा 33 प्रतिशत आ रही है न अभी। बेटी ज्यादा पढ़ती है इसलिए नाम लेने की जरूरत कहां है। मैं कहना चाहता हूं शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। आज 5वीं क्लास तक बगैर पास किये ही पास कर देते हैं। 8वीं क्लास तक भी बिना पास किये ही पास कर देते हैं। यह बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है। हर आदमी को इस पर मनन करना चाहिये, शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना चाहिये। देश का विकास पहिये से हुआ था और देश का विकास शिक्षा से हुआ था, पर देश के विकास का जो अवरुद्ध पाइंट है वह पानी है। इस समय पानी की महती आवश्यकता है। मैंने यह पूरा पढ़ा तो केवल 30 पंचायत समितियां ही ऐसी बची हैं जहां पानी की कमी नहीं है, बाकी सब जगह पानी की कमी है। देश की आर्थिक स्थिति दो मुद्दों पर आकर रुकती है- उत्पादन और वितरण। उत्पादन जिस देश का अच्छा होगा और जिस देश की वितरण प्रणाली अच्छी होगी, उस देश की आर्थिक स्थिति भी बढ़िया होगी। आज हमारे उत्पादन का साधन खेत है। (व्यवधान) हमारे उत्पादन खेत से है। (व्यवधान) आपको पीड़ा किस बात की है? मैं अध्यक्ष महोदय को संबोधित कर रहा हूं न कि आपको। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं न कि इनको, यह मेरे को इंडिकेट कर रहे हैं।

खेत और खलिहान में आज जो व्यवस्था है, पानी के बगैर उत्पादन कम हो रहा है, उन्नत बीज नहीं मिल रहा है, नई टैक्नोलोजी की योजनाओं के हिसाब से यंत्र नहीं मिल रहे हैं, अच्छा पानी नहीं मिलने के कारण हमारा उत्पादन कम हो गया। दूसरा हमारा उत्पादन खनन से है, खनन की हालत बहुत खराब होती जा रही है। बड़े नेताओं और बडे अफसरों के हाथों में खनन है, अगर पट्टा 20x20 का है तो वह खनन करते-करते आज 2000 फीट तक पहुंच गया जिसकी जांच का विषय आज तक नहीं उठा। अगर उनका सर्वे कराया जाए कि जो पट्टा आपको दिया गया था उसमें ही खनन हो रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा राजस्थान को 4 गुणा अधिक प्राफिट और हो सकता है। अवैध खनन कौन कर रहा है, प्रश्न इस बात का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि खनन वही लोग कर रहे हैं जो बडी एजेंसियों के हाथों में हैं। कल प्रश्न था नमक के कुओं का और नमक के क्यारों का। नमक किस के हाथ में है, किसी गरीब आदमी का क्यारा है क्या? किसका है? बड़े नेताओं का है, बड़े अफसरों का है। किसी गरीब आदमी को मालूम है क्या? उन नेताओं का है जिनकी

(श्री श्रवण कुमार)

सीआईडी, सीबी से रेड हो चुकी है और वह टांय-टांय फिस्स हो गई। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के मूल मंत्र जो....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नेता का नाम लेकर सभी को आरोपित कर रहे हैं। या तो स्पेसिफिक कोई नाम आपके पास हो तो आप नाम लीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में नहीं उलझें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपका नाम भी आएगा रुको तो सही। नेता कोई एमएलए ही नहीं होता, नेता बहुत सारे होते हैं। (व्यवधान) आप रुको तो सही, आप जो कहलवाना चाहते हो वह नहीं कहेंगे। आपको भी मालूम है।

(समय : 15.15 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपको पूछता ही क्यों?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो आपकी समस्या है वह सबकी समस्या है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चाहे खनन का हो, चाहे नमक का हो, जिन बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है उसकी जांच निश्चित रूप से कराई जाए, उसके बाद उसके जो पट्टे दिये गये थे उनका नाप-तोल कराया जाये। उसके बाद खनन का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और राजस्थान की आय का स्रोत 4 गुणा बढ जाएगा। यह सारा सिस्टम धूमिल किया जा रहा है।

उसके बाद हमारे कल-कारखानों से उत्पादन होता है, कल-कारखानों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमारा सोच था कि हमारा जो खर्चा हुआ है, उसमें हमारा गरीब का बेटा नौकरी करेगा। सारी एजेंसियों ने बाहर से लाकर मजदूर लगा दिये, हमारे गरीब का बेटा नौकरी नहीं कर रहा है। यह सारा सिस्टम धूमिल हो गया, इस पर नियंत्रण नहीं है, इस पर कमांड नहीं है। यह सारा कमांड हम लोगों को करना पड़ेगा वर्ना राजस्थान की स्थिति धूमिल हो जाएगी और गरीब आदमी और गरीब होता चला जाएगा।

वितरण प्रणाली जिस पर हंगामा करते हैं, यह सोच बदलना पड़ेगा चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आज जो दो रुपये किलो में बीपीएल को गेहूं दिया जाएगा, वह उन डीलरों को और सस्ता पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से

(श्री श्रवण कुमार)

निवेदन करना चाहता हूं कि जो 4 रुपये 70 पैसे वाला गेहूं बाजार में बेच सकता था, वह दो रुपये किलो वाले गेहूं को बड़ी आसानी से बेच सकता है। इसलिए इसको मजाक में नहीं लेना चाहिये, हमें इस पर सख्ती से कार्यवाही करनी पड़ेगी। जब राजस्थान में बाहर से दारू लाने वाली गाडी को बंद करने के बाद छोड़ने में मुश्किल हो जाती है, जब हम बड़े से बड़े शेर को हंटर दिखा कर उससे हां बुलवा सकते हैं, हाथी को फुटबाल खिलवा सकते हैं, सांप को हम गले में डालकर उससे खिलवाड़ कर सकते हैं, तो क्या हम बदमाश और चोर लोगों को नहीं रोक सकते हैं? यह मानव का धर्म नहीं है क्या। जब हम पशु को पढा सकते हैं, हाथी को फुटबाल खिलवा सकते हैं, शेर से चीं बुलवा सकते हैं और सांप को गले में डाल कर खिला सकते हैं तो उन बदमाश लोगों को भी हम मिट्टी चटा सकते हैं। पर सोच बदलना पड़ेगा। सभापति महोदय, इसलिए मैं राजस्थान के 200 विधायकों से कहना चाहता हूं कि हमारी सोच को बदलना होगा। राजस्थान में भ्रष्टाचार 1952 में 1 प्रतिशत से शुरू हुआ था, 1962 में 3 प्रतिशत हुआ, 1972 में 4 प्रतिशत हुआ, 1982 में 7 प्रतिशत हुआ, 1992 में 9 प्रतिशत हुआ, 2000 में 13 प्रतिशत हो गया और 2010 में 27 प्रतिशत हो गया आपकी नाक के नीचे और आप सबको मालूम है। पीडब्ल्यूडी में देखिए, पीएचईडी में देखिए, जिस विभाग में जाएंगे, सरेआम भ्रष्टाचार है। चाहे बीजेपी वाले इस पर नाराज हो चाहे कांग्रेस वाले। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कदम उठाना पड़ेगा वर्ना विकास की गति अपने आप धूमिल हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। आज राजस्थान का 23822 करोड़ का जो बजट है इसका 27 प्रतिशत काट कर राजस्थान की जनता तक जाएगा। इस का आइडिया आप लगा लीजिए कहां जाएगा। इसका भी विस्तार बहुत बड़ा है पर इस विस्तार को रोकने के लिये, आगे बढ़ने के लिये बीच में सब लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, इसमें पक्ष-विपक्ष का कोई प्रश्न नहीं आता है। जब माननीय वसुंधराजी राज में थीं तब भी मैं यह बात कहता था कि आप इसमें सुधार कीजिए। उस समय उनको नशा था, और नशा जब टूट जाता है तो सपना खुलता है, सपना टूटा उसके बाद आज कोई दिखाई ही नहीं देता। माननीय वसुंधराजी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हम प्रत्येक गरीब की बेटी को साइकिल देंगे, कितनी लड़कियों को साइकिल बांटी? (व्यवधान)... झुंझुनूं में तो एक साइकिल है नहीं, सीकर में एक साइकिल है नहीं। बांसवाड़ा में गरीब लोगों को खुश करने के लिये 400-500 रुपये वाली टूटी हुई कोई

(श्री श्रवण कुमार)

साइकिल दे दी हो तो मालूम नहीं। उसके बाद कहा था, ग्रेजुएट बेटे को हम जब तक उसको नौकरी नहीं मिलेगी, 500 रुपये देंगे। कितने लोगों के खाते खुलवाये? केवल धुंए के बादल दिखाने से कितने दिन चलेगा? 52 हजार खाते खुलवाये, झुन्झुनूं में तो एक का खाता दिखा दो, इनाम देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वहां श्रवण कुमार है, उन्हें खाते की क्या जरूरत है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सब जगह इस तरह के श्रवण कुमार हैं- सीकर में घनश्यामजी हैं, तो नागौर में मिर्धा है। फिर आगे? सभापति महोदय यह बहुत सीरियस मैटर है इसको बहुत गहरा लेना चाहिये। आज मैं समझता हूं इस बात को कि लोगों को इस बात का सोच नहीं है। आपको यह मालूम होना चाहिये, जिस गरीब को हम झोपड़ी में छोड़कर आए थे जिस गरीब को खेत और खलिहान में छोड़कर आए थे, प्यासे मरते हुए को, बिजली के दीपक की प्रतीक्षा करते हुए को, उसके लिए कभी किसी का सोच नहीं बदला। इस बात को बदलना पड़ेगा। इस बात की महती आवश्यकता है, पक्ष और विपक्ष को इस बात को गहराई से लेना पड़ेगा। इसलिए हमें हमारा सोच बदलना है। जब भावना बदलेगी तो भाव बदलेगा और भाव बदलेगा तो हमारा विचार बदलेगा और विचार बदलेगा तो गरीब के प्रति हमारी दया जगेगी और दया जगेगी तो हमारा काम करने का अवसर पक्का है। हम काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज पानी की महती आवश्यकता है। मैं बताना चाहता हूं कि फ्लोराइड इतना है कि 25-25 साल के बेटे कुबड़े हो गये, पैर बांके हो गए। 1985 में फ्लोराइड की मशीनें लगाई थीं गांव-गांव में। घनश्यामजी, याद है आपको? तीन सौ करोड़ रुपये की मशीने लगायीं, आज भी गांवों में लगी हुई हैं। किसी के दिल में दर्द आया कि तीन सौ करोड़ की मशीन का उपयोग क्या है? राजस्थान का तीन सौ करोड़ रुपया गांव की जोड़ों में लगा हुआ है, टंकी के पास लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, किसी के दिल में दर्द नहीं आया कि राजस्थान का तीन सौ करोड़ रूपया बर्बाद हो गया। एक भी गांव में फ्लोराइड की मशीन चालू है क्या? फिर क्या है? नारा लगाने से पेट भर जाएगा, मुर्दाबाद कहने से आसमान छू जाओगे? इससे आसमान नहीं छुओगे। आसमान तब छुओगे तब गरीब के दिल को जगाओगे, यह बात मैं आज भी कहना चाहता हूं।

(श्री श्रवण कुमार)

बात करते हैं नरेगा में बहुत ही चोरियां हैं। मैं कहता हूं चोरियां हैं पर दिल में दर्द किसके आया, हमारे सामने नाक के नीचे चोरी हो रही है, बिजली बोर्ड में हो रही है, पीएचईडी में हो रही है, चिकित्सा शिक्षा में हो रही है और पुलिस वाले गरीब के बेटे को लूटकर खां रहे हैं। मुझे बड़ी पीड़ा है, मझे बड़ा दर्द है कि आज ऊपर से लेकर नीचे तक गरीब के साथ अत्याचार किया जा रहा है। किसी को कह भी दिया जाए तो क्या कहते हैं, यह तो प्रोफेशनल हो गया। कभी-कभी तो रोने लग जाते हैं हम कि इस बात का क्या होगा जब हम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो फायदा हमें इस सीट पर बैठने से? इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। सिस्टम को कौन चेंज करेगा? अगर 200 आदमी चेंज नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि चेंज कर दे।

अब तो जोर किसी बात पर है तो आरक्षण पर है। हमें आरक्षण दे दो, महिलाओं को आरक्षण दे दो। आरक्षण तो जब दोगे जब देश सुरक्षित होगा। देश के अन्दर तो सारे का सारा सिस्टम, अंग्रेजों का जमाना था जब अंग्रेज काम करते थे और हमारे काले लोग थे हिन्दुस्तानी, उनके साथ अत्याचार होता था। आज भी वो ही, काले हम हैं और बड़े अफसर गोरे हैं। हमारी कोई सुनता नहीं है, गोरे हैं वो ही काम कर रहे हैं। इस सिस्टम को बदला है क्या, केवल हवा बदली है, समय बदला है सिस्टम नहीं बदला है। सिस्टम वो ही है, गोरे एक तरफ बैठे हैं और काले एक तरफ बैठे हैं। इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। मैं आज भी कहता हूं, क्या हंस रहे हो? कुछ लोग आएंगे कुछ नहीं आएंगे, कुछ आते हैं कुछ चले जाते हैं, कुछ तो चले गये कुछ जाने को तैयार हैं। पर इस बात को याद रखो, जो सदन में बैठा है चार साल साढ़े तीन साल और बैठे हो, अगर आपने सोच नहीं बदला तो राजस्थान की जनता दस साल के बाद, राम तेरी गंगा मैली पिक्चर में बूढे आदमी ने एक लड़की को गलत रास्ता दिखाया था, उस लड़की ने कहा, बाबा आप जैसे बूढे आदमी अगर इस तरह करने लग जाएंगे तो लोग अंधों पर विश्वास करना बंद कर देंगे, तो याद रखो, माननीय सदस्यों, अगर आपने इस चोरी पर, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया तो लोग आप पर विश्वास करना बंद कर देंगे। आज हमें इस बात की बड़ी पीड़ा है।

पीएचईडी हो चाहे शिक्षा हो, आज राजस्थान की शिक्षा बिहार बन गई है, जिसका जीरो पर आकर ग्राफ रूक गया है। मैं ईमानदारी से कहता हूं, एक लड़के को मैंने कहा, बेटा किताब पढ़कर बता। तो बोला, किताब नहीं पढ़नी

(श्री श्रवण कुमार)

आती। मैने कहा, कौनसी में पढ़ता है? तो बोला, पांचवीं में। मैंने कहा, साइन कर, तो बोला साइन भी नहीं आते। मैंने कहा, तो फिर पढ़ता क्या है, बोला मुझे मास्टरजी बोले छठीं में कर देंगे, मैंने कहा छठी में हो जाएगा फिर क्या करेगा, आगे कौन जाएगा? हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का कितना बड़ा सोच है कि गरीब की बेटी, गरीब का बेटा अगर दसवीं में तीन नम्बर में मेरिट में आएगा तो विदेश में भेजा जाएगा। कितना बड़ा सोच है। यह सोच होना चाहिये कि हमारा बेटा पढ़ना चाहिये। सरकारी स्कूल में आज भी एक लड़के के ऊपर 800 रुपये खर्चा आ रहा है, और उसके बाद भी? घनश्यामजी शिक्षा के ऊपर हंस-हंसकर बातें करते थे खूब खींच खींचकर। घनश्यामजी क्या परिवर्तन लेकर आये? कुछ नहीं आया, ढाक के वही तीन पात। चले तो चले और रुके वहीं। अब रुक गये। मैं यह कहता हूं कि आप जैसा शिक्षाविद् चेंज नहीं कर पाया तो हमारे मंत्री तो पढ़े-लिखे ही दसवीं पास हैं तो कहां चेंज लाएंगे? जब आप जैसा एलएलबी नहीं ला पाया तो हमारा मंत्री कहां से लेकर आएगा? मैं कहना चाहता हूं कि सिस्टम को चेंज करने के लिए सोच बदलना पड़ेगा। हमारा सबका सोच एक होना चाहिये देश के विकास के लिए। (व्यवधान) मेरे को मुख्य मंत्री नहीं बनना, मेरे को सदस्य बनना है और सदस्य फिर जीतकर आ जाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है।

मेरा सोच एक बात के लिए है, सबको कहना चाहता हूं कि राजस्थान के इस समय हालात बिगड़े हुए हैं इस भ्रष्टाचार को लेकर के, मैं हरियाणा में गया तो पहाड़ियाजी से मिला, पहाड़ियाजी ने कहा, हरियाणा में तो भ्रष्टाचार नहीं है। मैंने कहा क्यूं, बोले शुद्ध है शुद्ध का मतलब कोई संज्ञा है ही नहीं न। हमारे यहां शुद्ध नहीं है इसलिए मेरी थोड़ी दिल में भावना है कि हम चाहे सब लोग मिलकर तो शुद्ध वैरी शुद्ध कर सकते हैं। हमें सोच बदलना पड़ेगा इसे बदलने के लिए, माननीय घनश्यामजी, आप जैसा ऊर्जावान व्यक्ति, राजेन्द्रजी तो ऊर्जावान नहीं हैं, राजेन्द्रजी तो जैसी हवा आती है वैसे ही बरसाते हैं, इनका तो काम है। कुआ तेरी मां मर गई, बोले मर गई। बोले जीवे है, हां जीवे है। आप ऊर्जावान व्यक्ति हो, ईमानदारी से कहता हूं, आप गहराई में जाइये, पुलिस का इस समय जो आतंक है भ्रष्टाचार का जो मुद्दा चला हुआ है, यह आप लोगों के लिए और हमारे लिए शर्मनाक है। इसलिए मैं कहता हूं कि शर्मनाक मुद्दे पर सबको एकजुट होकर, हमारे मंत्री को, हमारे मुख्य मंत्रीजी को भी इस पर अंकुश लगाना चाहिए। जिस प्रकार यह भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, यह

(श्री श्रवण कुमार)

राजस्थान का नासूर बन जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि देश का विकास पहिये से हुआ था, जिस देश का विकास शिक्षा से जुड़ा हुआ है देश का विकास कम्प्यूटर में फीड हो गया है, देश का दूध थैली में पैक हो गया है, और देश का पानी बोतल में पैक हो गया है और आज जो सबसे बड़ा उजागर हुआ है देश का भ्रष्टाचार पर्दे पर आ गया है। जो चीज पर्दे पर आ गई वह रुकने वाली नहीं है, उसको रोकने के लिए सबको साहस और हिम्मत करनी पड़ेगी। एक शायर ने एक बात कही है, हिन्दुस्तान में भाव तो बहुत बढ़े धान के, पर बेटी विदा न हो सकी किसान की। बड़े नेताओं ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए शौकत बिगाड़ी हिन्दुस्तान की। कुर्सी बचाना चाहते हैं, कुर्सी बचे, न बचे पर हमारे हिन्दुस्तान की शान बचनी चाहिये यह हमारा सपना होना चाहिये। मैं आज भी कहता हूं कि राजनीति में आने के बाद अगर कोई गरीब का पैसा खाकर अपना सोच बदलता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया वह दुनियां का सबसे बड़ा गया-गुजरा व्यक्ति होता है। आज हमें जनता ने क्या नहीं दिया, सबसे बड़ी शौकत दी, 6 करोड़ व्यक्तियों ने 200 आदमियों को चुनकर भेज दिया, मंत्री, वजीर बना दिये, बड़े बड़े नेता, विपक्ष का नेता बना दिया, घर दे दिया, सब कुछ दे दिया अगर अब भी हम भ्रष्टाचार करेंगे तो हमसे बड़ा अन्यायी कोई नहीं हो सकता। हमारा सोच यह होना चाहिये कि राजस्थान का गरीब झोपड़ी का, खेत-खलिहान का बैठा व्यक्ति, आज इस बात की हां भरनी चाहिये कि जिस व्यक्ति को मैंने चुनकर भेजा था वह व्यक्ति आज मेरे लिए रक्षक बनकर बैठा है। वह यह सोचे कि भक्षक बनकर बैठा है तो उस राजनीति से क्या फायदा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज हम यह चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो टैक्स का भार पड़ा है, मैंने गहराई से सारे बजट को देखा है बनियों को काफी फायदा दिया, हो सकता है कांग्रेस ने सोचा होगा कि बनिये हमें वोट दे देंगे। ये लोग वोट देंगे जब मौका आएगा। बीजेपी वालों को देते थे, बीजेपी वालों को निहाल कर दिया अब हमें कोई निहाल करने वाले नहीं है ये । अगर गरीब झोपड़ी का आदमी वोट देगा तो कांग्रेस का पक्का सिपाही वह है, मूल वोटर है हमारा। बिड़लाजी को अगर कोठी बनाकर देते तो कांगेस को वोट दे देंगे क्या, देने वाले नहीं हैं। ये तो खड़े होकर पटल पर रखेगे, पटल पर रखेंगे ये तो, देंगे नहीं वोट। इसलिए क्यों खो रहे हो गरीब

(श्री श्रवण कुमार)

व्यक्ति को? गरीब व्यक्ति को खोने से हमारा नुकसान हो जाएगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री को सबसे पहले एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि सूरजगढ़ विधान सभा हमारे झुन्झुनूं का नाम बहुत कम आया, दुर्भाग्यशाली है।

सभापति महोदय, आप सोल्जर हैं, हिन्दुस्तान की मान और मर्यादा कायम करने में आपका सबसे अग्रणी हाथ रहा है और उसमें झुन्झुनूं जिले का नाम भी अग्रणी रहा है। झुन्झुनूं जिले के शहीदों की संख्या गिनेंगे तो 33 प्रतिशत पूरे राजस्थान के शहीदों की संख्या होगी। आज अगर कहीं बाड़मेर की तलहटी में कोई बेटी पढ़ाती नजर आएगी तो झुन्झुनूं जिले की हमारी बेटी पढ़ती नजर आएगी। अगर मेवाड़ के किसी कोने में कोई सुई लगाती नजर आयेगी तो हमारे झुन्झुनूं जिले की बेटी आएगी। अगर कोई शहीद वीरांगना अपने पति की चिता को जलाती नजर आएगी तो झुन्झुनूं जिले की महिला आएगी। जिस देश के अन्दर देश की मान-मर्यादा कायम करने में, सुरक्षा में, चिकित्सा और शिक्षा में हमारा जिला अग्रणी हो और उस जिले में एक कालेज नहीं खुले तो हमारे लिये एक दुखदायी प्रश्न होगा। इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी से इस बात की मांग करता हूं, बुहाणा, हरियाणा से लगता क्षेत्र है, कालेज है नहीं, डैजर्ट एरिया है, पानी का अभाव है, एक कालेज की घोषणा कर दें, मैं समझता हूं कि उदार दिल होंगे, जिस तरह कल उन्होंने उदारदिलता दिखाई। नम्बर-दो, वहां पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। इस समय पानी की बहुत महत्ती आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, वहां 20-20, 25-25 वर्ष के बेटे कुबड़े हो जाते हैं। पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पहाड़ों में पानी में फ्लोराइड 70 प्रतिशत तक भी हो गया है, पानी जब सुबह गर्मियों में देखते हैं तो सफेद जम जाता है। टौंक को दे रहे हैं, चम्बल का पानी दे रहे हैं, भीलवाड़ा को दे रहे हैं, बांसवाड़ा को दे रहे हैं, अगर 10 प्रतिशत नजर झुन्झुनूं की तरफ भी घुमा दी जाए तो सुन्दरलालजी के तो मौज हो जाए और हमारे भी मौज हो जाए। आपके तो है, जगह देकर आया हूं जो पानी की जरुरत ही नहीं है। वहां तो बना-बनाया पा गये। पर हमें वह जगह दे दी जहां फ्लोराइड ही फ्लोराइड देकर आये हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि इस समय पानी की बहुत आवश्यकता है। पानी राजस्थान का मेन मुद्दा होना चाहिए। आज पशुधन की बहुत बड़ी आवश्यकता है इस किसान को। किसान का अगर रोजी-रोटी का एक सुलभ साधन है तो पशुधन है। पशु को बीमार होने पर ले

(श्री श्रवण कुमार)

जाया नहीं जा सकता। बस में बैठ कर वह जा नहीं सकता, गाड़ी में जा नहीं सकता। प्राइवेट हास्पिटल कोई गांव में होता नहीं है। इसलिये सरकार को सौ उप स्वास्थ्य केन्द्र के स्थान पर दो सौ उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने चाहिए और कम से कम 100 नये हास्पिटल खोलने चाहिए। इस समय किसान की महत्ती आवश्यकता है पशु और पशु के उपचार के लिये गांव में 20 -20 किलोमीटर तक भी कोई उपचार के साधन नहीं हैं। ये सारी महत्ती आवश्यकताएं हैं। हमारे डाक्टरों की हालत यह है कि, स्वास्थ्य की इच्छा करता है, गरीब आदमी सुई लगवाना चाहता है तो टिंचर नहीं है। माननीय सभापति महोदय, ईमानदारी की बात है, हास्पिटल्स में पट्टी बांधने के लिये पट्टी नहीं है। और तो और, 12 बजे बाद डाक्टर भी नहीं है, डेढ़ बजे बाद नर्स भी नहीं है और दो बजे के बाद में वहां कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा, कमरे के ताला मिलेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 65 वर्ष के बाद, माननीय सभापति महोदय, आपके अन्दर भी दिल में दर्द रहना चाहिए कि देश की 65 वर्ष की आजादी के बाद गरीब का बेटा इलाज के लिये चिड़ावा से जयपुर आए और 25 किलोमीटर दूर सोणी का व्यक्ति पिलानी आए। आज हमें इस बात की घोषणा करनी चाहिए, इस बात की महत्ती आवश्यकता है। किसी भी मंत्री के दिल में इस बात का दर्द नहीं आया और कोई भी इस बात का खड़ा होकर मुद्दा नहीं उठा पाया कि गरीब की झोंपड़ी में डाक्टर रहेगा, कम्पाउण्डर रहेगा और नर्स रहेगी, और नहीं रहेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। यह घोषणा करने वाला कोई आज तक नहीं आया। बी.जे.पी. वालों को कह-कह कर हम परेशान हो गये। राजेन्द्रजी को तो 1993 में मंत्री बनाया तो उनको कोई कहते, साहब, डाक्टर पैसे खा रहा है। तो शिकायत कर दीजिए, जांच करवा लेंगे। दोषी पाने वालों को दण्डित कर दिया जाएगा। ये कैसे दण्डित करते हैं, पता नहीं कहां करते हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारे मंत्रीजी ने यह माना, धन्यवाद देना चाहता हूं राजकुमारजी को कि झुन्झुनूं हास्पिटल में गये और वहां के

(श्री श्रवण कुमार)

पी.एम.ओ. के काम के अन्दर मिसअण्डरस्टैडिंग पाई, हाथों-हाथ ए.पी.ओ. कर दिया। धन्यवाद देना चाहता हूं। पर यह सोच सबकी होनी चाहिए। राजकुमारजी अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे। परन्तु राजकुमारजी, घबराने की जरुरत नहीं है। कहा करते हैं, अकेला चना क्या पहाड़ फोड़ सकता है। अकेला चना पहाड़ तो नहीं फोड़ सकता है पर भड़भूजे की आंख फोड़ सकता है। मैं कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, तकलीफ होगी। तकलीफ तेरे सहने की आदत नहीं तो तूफानों से तुझे टकराने की जरूरत नहीं। जो लोग जिगर रखते हैं उन्हें जमाने की जरुरत नहीं। जमाना पैदा किया जाता है। हम वो नहीं, जो तख्त और ताज बदलें तो हम बदलें। हम तो वो हैं कि हम बदलें तो तख्त और ताज बदले। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, जो आदमी आगे बढ़कर काम करेगा, तकलीफ होगी। इस बात की चिन्ता नहीं है। आज हमें इस बात का मालूम है, हमारे सुभाष चन्द्र बोस को मालूम था कि देश आजाद होगा कि नहीं होगा, मुझे देश से जाना पड़ेगा। भगतसिंह को मालूम था, फांसी के तख्ते पर गया, उसको मालूम था कि फांसी पर लटकूंगा और देश आजाद होगा, उसका सुख और कोई उठाएगा। गांधी को मालूम था इस बात का।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें, घंटी आपको सुहाती नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सिर्फ एक मिनट में, माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में कह दूंगा। गांधीजी को मालूम था कि मैं देश की आजादी के लिये लड़ रहा हूं और लन्दन में जाकर कोड़े खाने पड़े। गुरु गोविन्दसिंह के बेटों को दीवारों में चुना गया पर आज वे जिंदा हैं, मरे नहीं। उनका सपना यह नहीं, हमारे गांधी का सपना यह नहीं था कि मेरा गुजरात आजाद हो, भगतसिंह का सपना यह नहीं था कि मेरा पंजाब आजाद हो, सुभाष चन्द्र बोस का सपना भी यह नहीं था कि मेरा बंगाल आजाद हो। उसका सपना था कि मेरा भारत देश आजाद हो। इसलिये मैं पूरे सदन को इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि आपका सबका सपना होना चाहिए कि मेरा राजस्थान खुशहाल हो। सिर्फ आपका सपना एक हो गया कि बी.जे.पी. खुशहाल हो, कांग्रेस खुश हो, इस बात का मोडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसमें शांति से बैठाना पड़ेगा। इस देश को खुशहाल बनाना है तो आपको एक मुद्दा उठाकर भ्रष्टाचार को बंद करना पड़ेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिये हम सब को मिल

(श्री श्रवण कुमार)

कर एकजुट होकर राजस्थान की बहबूदी को कायम करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्य मंत्री को जिन्होंने गरीब के प्रति, हमारे गरीब किसान का बेटा जो प्रमाण पत्र बनवाने जाता था, दस रुपये के लिये तरसता था, अब सिम्पली कागज के ऊपर प्रमाण पत्र बनेगा। कुछ-एक महत्ती आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। इसलिये मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिये हमें सोच बदलनी पड़ेगी और अच्छा सामंजस्य बैठाकर और अच्छे योग्य मंत्री को सुनिश्चित रूप से काम करना पड़ेगा। वर्ना शिक्षा कमजोर हो जाएगी, देश कमजोर हो जाएगा।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): और जिस देश की शिक्षा कमजोर हो, उसकी दीक्षा कमजोर है, वह देश बेहाल हो जाता है, वह कमजोर हो जाता है, उसमें फिर आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती है। इन्टरनेट का जमाना है, इन्टरनेट के जमाने के अन्दर शिक्षा को आगे बढ़ाना हमारा सुनिश्चित कार्य है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया और मेरी बात को सुना, पूरे सदन को बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। कोई गलत शब्द कह दिया तो उसकी माफी चाहते हुए, सदन को पुन: 5 दिन के बाद में अगले ब्रेक के बाद बोलने का मौका मिलेगा, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आदरणीय सभापति महोदय, जब परसों मुख्य मंत्रीजी सदन के पटल पर वर्ष 2010-2011 का बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने बजट की शुरूआत करते हुए कहा, 'मुझे अपनी सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के गत महीनों में सम्पन्न हुए चुनावों के परिणाम पुन: दर्शाते हैं कि राज्य की जनता हमारी नीतियों एवं कार्य पद्धति से संतुष्ट है। इन परिणामों के बाद हमारी नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इस अवसर पर मैं राज्य की जनता का आभार प्रकट करता हूं और सब को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमसे जो अपेक्षाएं और आंकाक्षाएं की गई हैं, उन पर पूरा उतरने की हम पूरी चेष्ट करेंगे'।

माननीय सभापति महोदय, जब उन्होंने यह कहा, प्रदेश की जनता ने लोक सभा में कांग्रेस को जिताया, नगरपालिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को

(श्री कालीचरण सराफ)

जिताया, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में कांग्रेस जीती। कड़ी से कड़ी जुड़ गई, अब तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा। प्रदेश की जनता को यह आशा थी और हमको भी यह आशा थी कि अब तो महंगाई कम होगी, प्रदेश पर जो कर्जों का बोझ है, वह कम होगा। प्रदेश के किसान को, प्रदेश के नौजवान को, प्रदेश की महिलाओं को, प्रदेश के व्यापारियों को, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। परन्तु जब मुख्य मंत्रीजी ने दो घंटे 10 मिनट लम्बा भाषण दिया तो प्रदेश की जनता, हम लोग जो यह आशा कर रहे थे कि इन सब वर्गों को राहत मिलेगी, हमको निराशा लगी। 1985 से मैं लगातार विधायक हूं, एक बार बीच में विधायक नहीं बना, मैं लगातार विधायक बना हूं, परन्तु मैं यह कह सकता हूं और यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 1952 से लेकर आज तक जितने बजट यहां पर प्रस्तुत किये गये, उनमें सबसे बेकार, सबसे नाकारा और सबसे रद्दी बजट यदि इस सदन में पेश किया गया है तो वह मुख्य मंत्रीजी ने जो यहां पर परसों पेश किया, वह बजट है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): चार बार और लगेगा ऐसे आपको। चार साल और लगेगा ऐसे ही।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ऐसे ही ऐसे ही करते हो, हां, ठीक बात है। (व्यवधान) हमें यह उम्मीद थी ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह तो धन्यवाद आपको। माननीय सभापति महोदय, आपने ठीक कहा है चार साल भोगेंगे। फिर आये चार साल, फिर ठीक कर लेंगे।

श्री सभापति: विराजो-विराजो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हमें उम्मीद थी, 20 साल बाद इस प्रकार का सहयोग आया है कि केन्द्र में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी की प्रदेश में सरकार है और हमारे अशोकजी गहलोत तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में सुशोभित हो चुके हैं, उनका केन्द्र में भी बड़ा दबदबा होगा, अपना प्रभाव होगा। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने जब रेलवे बजट प्रस्तुत किया तो राजस्थान के हाथ कुछ नहीं लगा और जब केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने संसद में केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया उस समय भी कहीं पर

(श्री कालीचरण सराफ)

कड़ी से कड़ी जुड़ने की टंकार हमें सुनायी नहीं दी। हमने 12700 करोड़ रुपये, राजस्थान के 27 जिलों में अकाल है, इसके लिए केन्द्रीय सरकार से मांगे थे, एक नया पैसा नहीं मिला। राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है, यहां हर वर्ष अकाल पड़ता है। राजस्थान को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। इस मामले में भी एक नया पैसा और विशेष दर्जा भी राजस्थान को नहीं मिला। हमारे चार-चार मंत्री-सी.पी. जोशी, नमोनारायणजी मीणा, महोदव सिंहजी खण्डेला और सचिव पायलट, जब केन्द्र ने बजट प्रस्तुत किया तो ऐसा लगता है कि इन चारों मंत्रियों ने भी वहां राजस्थान की कोई पैरवी नहीं की और यदि पैरवी की है तो उनका प्रभाव नहीं था, जो राजस्थान को एक नया पैसा नहीं मिला। इससे तो बढ़िया बुंदेलखण्ड रहा जहां कांग्रेस का राज नहीं है। मायावतीजी जो आज उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं, केन्द्रीय बजट में उनको 1200 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मिला और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, केन्द्र में कांग्रेस की सरकार, एक नया पैसा भी राजस्थान को दिलाने में ये सफल नहीं हुए।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं केन्द्रीय सरकार ने एक योजना प्रारम्भ की थी, उन्होंने कहा था कि 25 परसेंट पैसा यदि राज्य सरकार दे, 25 परसेंट पैसा उसमें केन्द्रीय सरकार मुआवजे के रूप में मिलाएगी और किसानों को हम आधी कीमत पर डीजल दे सकते हैं। जिस प्रदेश में अकाल पड़ रहा है वहां यदि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि 25 परसेंट पैसा राज्य दे और 25 परसेंट पैसा केन्द्र दे तो हम आधी कीमत पर किसानों को डीजल दे सकते हैं। इस योजना को यदि प्रदेश में लागू किया जाता तो आज किसानों को, जो अकालग्रस्त प्रदेश के किसान हैं उनको, 17-18 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से डीजल मिल जाता, परन्तु हमारी सरकार ने इस योजना को मंजूर नहीं किया। पंजाब जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां की सरकार ने, वहां पर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने 25 परसेंट मुआवजा देना मंजूर किया, 25 परसेंट केन्द्रीय सरकार का मिला और भरपूर सहायता वहां के किसानों को देने में पंजाब की सरकार सक्षम रही। परन्तु हमारी सरकार का खजाना खाली है। वही रोना जो 1998 से 2003 के बीच तक था, खजाना खाली है, हमारे पास पैसा नहीं है और इन्होंने इस योजना का लाभ नहीं उठाया।

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि इस संबंध में कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय सचिव एस. जानकीरमण ने 3 अगस्त, 2009 को राज्य सरकार को एक पत्र लिखा था और उसमें यह लिखा था कि अगर राजस्थान सरकार 25 परसेंट छूट दे दे तो केन्द्रीय सरकार भी 25 परसेंट छूट देकर राज्य के किसानों को आधी रेट पर डीजल उपलब्ध करवा सकती है। परन्तु हमारी सरकार ने उस पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की और उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कृषि मंत्री बैठे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक तो यह कृषि मंत्री हैं और एक वहां के। वहां से क्यों, साहब, कृषि मंत्रीजी जानकीरमणजी का कोई पत्र आया था? उसके ऊपर आपने क्या कार्यवाही की? आपने उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): फाड़ कर फेंक दिया। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): और जहां तक ...(व्यवधान) हां, यह हो सकता है। और जहां तक ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह वाद-विवाद है, आप मंत्रीजी से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जो हुक्म। जो हुक्म, साहब। और जहां तक महंगाई का सवाल है, बताने की आवश्यकता नहीं है, केन्द्र में जब से यू.पी.ए. की सरकार बनी है, ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, जहां तक महंगाई का सवाल है, बताने की आवश्यकता नहीं है, जब से केन्द्र में यू.पी.ए. की सरकार बनी है, हर चीज की कीमत निरन्तर बढ़ती जा रही है। किसी चीज की कीमत में दुगनी वृद्धि, किसी चीज की कीमत में तीन गुणा वृद्धि और किसी चीज की कीमत में चार गुणा तक वृद्धि हुई है। जब केन्द्रीय सरकार ने यह बजट प्रस्तुत किया, पैट्रोल और डीजल पर जब रेट बढ़ायी गयी तो रातों-रात हर चीज की कीमतों में वृद्धि हो गयी और उस आग में घी का काम किया हमारी राज्य की सरकार ने। बड़ी चतुराई के साथ एक लाइन में इन्होंने कह दिया कि 4 परसेंट से 5 परसेंट वैट किया जाएगा। 1500 करोड़ रुपये का टैक्स इन्होंने एक लाइन में लगा दिया। पिछली बार जब सरकार आयी थी, जब पहला बजट प्रस्तुत किया जो हायर टैक्स स्लैब था 12.5 परसेंट

(श्री कालीचरण सराफ)

का, उसको 14 परसेंट कर दिया, 600 करोड़ रुपये के टैक्स लगाये। डी.एल.सी. की रेट बढ़ा कर अप्रत्यक्ष रूप से स्टाम्प ड्यूटी महंगी कर दी। और इस बार 277 वस्तुओं पर 4 परसेंट से 5 परसेंट टैक्स करके 1500 करोड़ से ज्यादा का टैक्स इन्होंने लगाया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह क्या, यह क्या बात हुई साहब? यानी वे चालीस मिनट बोले और मैं पांच मिनट में ही समाप्त कर दूं? (व्यवधान)

श्री सभापति: बिलकुल। आप देखिये, 16 मैम्बर्स हैं आपकी तरफ के। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं-नहीं, होंगे, पर उन्होंने चालीस मिनट बोला है तो मैं भी चालीस मिनट बोलूंगा।

श्री सभापति: तो ठीक है, फिर देखिये, आसन को काई दिक्कत नहीं है, चाहे रात के तीन बजे तक बोलें आप। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं-नहीं, यह क्या बात हुई? यह क्या है? + + +

श्री सभापति: मैं तो, साहब, यह है कि आपके जो स्पीकर्स हैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। आप टाइम बढ़ाइये, टाइम बढ़ा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): +++

श्री सभापति: नहीं-नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। मैंने जो टाइम अलाटमेंट है उसके हिसाब से कहा है। मेरी व्यवस्था ऐसी नहीं है ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, ऐसा है जब वे चालीस मिनट बोले तो मैं भी चालीस मिनट बोलूंगा। यह क्या बात हुई?

श्री सभापति: फिर सब चालीस मिनट बोलेंगे तो रात के साढ़े तीन बजे तक बैठेंगे फिर सब लोग। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं-नहीं, वे चालीस मिनट क्यों बोले?

श्री सभापति: ठीक है, आसन को कोई दिक्कत नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): फर्स्ट स्पीकर बोलता है हर बार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पहले वक्ता हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): फर्स्ट स्पीकर बोलता है। ऐसा नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जब विधान सभा के चुनाव हुए थे तो हमारे कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव घोषणा पत्र में यह लिखा, पेज नम्बर-29 पर, कि पैट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस पर स्थानीय करों में रियायत दी जाएगी। इस बार जब महंगाई बढ़ रही थी, निरन्तर बढ़ रही थी- दुगनी कीमत, तीन गुणी कीमत, चार गुणा कीमत तो प्रदेश की जनता यह सोच रही थी और हम सबको भी यह आशा थी, मेरे कांग्रेस के मित्र जो बैठे हैं उनको भी यह आशा थी कि अशोकजी गहलोत ने चुनाव में जो वादे किये हैं, उनको पूरा करने में बड़े परफेक्ट हैं। हरियाणा जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां पर डीजल पर 8.8 परसेंट टैक्स है और पैट्रोल पर 20 परसेंट टैक्स है। पंजाब में दोनों चीजों पर, पैट्रोल और डीजल पर 8.8 परसेंट का टैक्स है। दिल्ली में भी टैक्स कम है। तो हमारे मुख्य मंत्रीजी जो 18 परसेंट का डीजल पर टैक्स है और जो 28 परसेंट पेट्रोल पर टैक्स है, उनमें निश्चित रूप से कमी करेंगे और केन्द्रीय बजट के कारण पैट्रोल और डीजल पर जो कीमतें बढ़ी हैं, जिसके कारण महंगाई निरन्तर बढ़ती जा रही है, निश्चित रूप से उस पर अंकुश लगेगा। परन्तु दुर्भाग्य है यह हमारे प्रदेश की जनता का कि चुनावी घोषणा पत्र में किये गये वादे के ऊपर हमारे मुख्य मंत्रीजी कायम नहीं रहे और उन्होंने एक नया पैसा भी अभी पैट्रोल और डीजल टैक्स पर कम नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब राजस्थान के मुख्य मंत्री के रूप में अशोकजी गहलोत ने शपथ ली थी तो उन्होंने अपने पहले उद्‌बोधन में यह कहा था कि मैं राजस्थान की जनता को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि पांच साल कांग्रेस की सरकार में हम एक नया पैसा भी बिजली पर नहीं बढ़ाएंगे।

सबने बड़ी तालियां बजाईं, खुशी जाहिर की। पर इससे ज्यादा विश्वासघात शहरी जनता के साथ नहीं हो सकता कि शहर की जनता जो 100 यूनिट से ज्यादा उपयोग करती है, 95 प्रतिशत लोग इस प्रकार के होंगे शहर में, चाहे वह जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे कोटा हो, चाहे बीकानेर हो, कोई

(श्री कालीचरण सराफ)

भी शहर हो, घनश्यामजी कह रहे हैं 98 प्रतिशत लोग हैं, 98 प्रतिशत जनता 100 यूनिट से ज्यादा उपयोग करती है, उन पर धीरे से 10 पैसे प्रति यूनिट टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, रेडीमेड वस्त्रों का व्यापार और बिजली के बिल, इन पर पहले 4 प्रतिशत टैक्स था, उसको 14 प्रतिशत कर दिया। आज सुबह ही रेडीमेड के व्यापारी मुझसे मिले थे ..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपकी बातें सुनते-सुनते सुन्दर काका चले गये यहां से।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप तो जब आपका नम्बर आए, तब बोल लेना।

बिजली के बिल के लिये व्यापारी मुझसे मिले थे, उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से रेडीमेड कपड़ों का व्यापार राजस्थान में फला-फूला है और यह 4 प्रतिशत से 14 प्रतिशत टैक्स कर दिया। पड़ौस में टैक्स कम है तो यहां का सारा व्यापार समाप्त हो जाएगा। आनन-फानन में 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत टैक्स तो कर दिया, अधिकारियों ने जैसा लिखकर दिया, वैसा हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पढ़ दिया, पर उन्होंने यह नहीं सोचा कि कुछ चीजें जिन पर आप यह टैक्स बढाने की घोषणा कर रहे हैं, इनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं हैं। अभी दो घण्टे तक हंगामा हुआ, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने आनन-फानन में 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया और जिस तेजी के साथ बढ़ाया था, उसी तेजी के साथ बिना विधान सभा की परवाह किये, बिना बजट सैंक्टिटी की परवाह किये, हाउस चल रहा है, यह ज्ञान तो मुख्य मंत्रीजी को भी था, परन्तु प्रेस कान्फ्रेन्स में उन्होंने यह कह दिया कि केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार हम रेटें नहीं बढ़ा सकते, इसलिये हम इन-इन चीजों पर यह रेट वापस ले रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, बजट में एक जगह जिक्र आया है, हमारे कुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, इनका वित्तीय प्रबन्धन जितना कमजोर है, अब तक जितनी सरकारें बनीं, किसी का भी वित्तीय प्रबन्धन इतना कमजोर नहीं रहा। जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 1653 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ छोड़कर गये थे। एक साल के अंदर आपके वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण आज राजस्व घाटा बढ़कर 3,992 करोड़ 87 लाख रुपये

(श्री कालीचरण सराफ)

हो गया है और राजकोषीय घाटा 9,900 करोड़ 12 लाख रुपये और 2010-11 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 8461 करोड़ 10 लाख रुपये अनुमानित है। आपका वित्तीय प्रबन्धन यह दिखाता है।

मैं याद दिलाना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, प्रदेश पर कर्जे की बात जब आती है, गुलाबजी कल बता रहे थे, 1998 में जब भैरोंसिंह शेखावत राजस्थान के मुख्य मंत्री थे और उन्होंने जब सत्ता छोड़ी और गहलोत साहब राजस्थान के मुख्य मंत्री बने, उस समय 24 हजार करोड़ का कर्जा राजस्थान पर था। मुख्य मंत्री बनते ही गहलोत साहब बोले राजस्थान प्रदेश को शेखावत सरकार ने कर्जे में डुबो दिया, प्रदेश की जनता पर कर्जा लाद दिया, 15 हजार करोड़ का कर्जा शेखावत सरकार ने लिया है। उन्होंने इतना ही नहीं किया, एक श्वेत पत्र (व्हाइट पेपर) भी जारी किया और उस समय प्रदेश की जनता से वादा किया कि शेखावत साहब ने 15 हजार करोड़ का कर्जा लिया है, परन्तु मैं कर्जे को कम करूंगा। जब 2003 में हमने सत्ता संभाली थी उस समय कर्जा था 54 हजार करोड़ का। यानि पांच साल में 30 हजार करोड़ का कर्जा लिया, 25 हजार करोड़ से 54 हजार करोड़ हो गया। 120 प्रतिशत कर्जा हमारे गहलोत जैसे काबिल वित्त मंत्रीजी ने बढ़ाया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: उस समय वित्त मंत्री तो प्रद्युम्न सिंहजी थे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): प्रद्युम्न सिंहजी अशोक गहलोत के नीचे ही थे, उनके अण्डर में थे। खैर, कालचक्र फिर घूमा। 2003 में गहलोत साहब चले गये। भारतीय जनता पार्टी का राज आया और वसुन्धरा जी राजस्थान की मुख्य मंत्री बनीं। पांच साल तक वसुन्धराजी ने राजस्थान पर राज किया, भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। हमारे टाइम में कर्जा बढ़कर हुआ 83 हजार करोड़ यानि केवल 30 हजार करोड़ का कर्जा लिया हमने। अब आप फिर सत्ता में आ गये। एक साल के अन्दर अन्दरआज 96 हजार करोड़ का कर्जा है राजस्थान पर और 31 मार्च, 2010 को जब यह साल खत्म होगा तो जिस तेजी के साथ आप कर्जा ले रहे हैं, 1 लाख 03 हजार करोड़ का कर्जा राजस्थान की जनता पर हो जाएगा। आप कौन से वित्तीय प्रबन्धन की बात करते हैं? हमने पांच साल में कर्जा लिया 30 हजार करोड़ और आपने एक साल में 20 करोड़ का कर्जा ले लिया और आप वित्तीय प्रबन्धन की बात करते हैं। (व्यवधान) अच्छा, उसके कारण यह कर्जा हो गया होगा।

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय सभापति महोदय, बताने की आवश्यकता नहीं है, पिछली बार यहां बड़ी घोषणाएं की गयीं। मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि मैं यह कर दूंगा, वह कर दूंगा। हमने भी तालियां बजाईं कि नये-नये मुख्य मंत्री बने हैं, नया-नया जोश है, कुछ करेंगे। परन्तु आज मैं यदि यह कहूं कि उन्होंने जो घोषणाएं कीं, उनमें से अधिकांश घोषणाएं पूरी नहीं हुई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह खाली मैं ही नहीं कह रहा, आपके मुख्य सचिवजी ने सैक्रेटरीज को एक लैटर लिखा है, उसका मजमून मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं – ''Hon'ble CM has taken a serious note of the slow progress in implementation of the budget announcement particularly in the context of the following:- ….of the 10 policies announced, no policy has been brought out so far." एक भी पालिसी का नहीं हुआ। वन नीति अण्डर प्रोग्रेस, ईको ट्यूरिज्म की नीति अण्डर प्रोग्रेस, राज्य पर्यावरण की नीति अण्डर प्रोग्रेस ..(व्यवधान) आप सुनिये। आप बैठिये न, आपका नम्बर आए, तब बोलना। बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: सदन में कृपया शांति बनाये रखें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): भेड़ व पशु प्रजनन नीति अण्डर प्रोसेस, उद्योग व निवेश नीति अण्डर प्रोसेस, नई खनिज नीति नाट पासिबल, नई आवास नीति अण्डर प्रोग्रेस, बायो-मास नीति अण्डर प्रोग्रेस।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): टाइम हो गया, पुराने आइटम पढ़ रहे हो आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, उसकी चिन्ता मत करो आप। ऐसे ही इन्होंने 29 कमीशन ''...bodies to be created in pursuance of the budget announcement; only 7 commissions' bodies have so far been created." इस प्रकार से इन्होंने पांच आइटम्स लिखे। किसी में बजट का काम नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, तो पांच लाख लोगों को हमने रोजगार दिया। प्रति वर्ष एक लाख बेरोजगार नौजवानों को हमने रोजगार मुहैया करवाया। जब विधान सभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के नेताओं ने भी यह घोषणा की थी कि हम हर वर्ष एक लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार देंगे। पहले बजट में घोषणा की, 76 हजार बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाएगा- कांस्टेबलों की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती, आंगनबाड़ी सहयोगिनी की भर्ती, ऐसे 76 हजार भर्ती करेंगे। परन्तु क्या हुआ? 76 हजार में से आप आश्चर्य करेंगे, केवल 6 हजार नौकरियां देने में यह सरकार सक्षम हुई।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है आप समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं 3.40 पर खड़ा हुआ हूं और अभी मुझे केवल 19 मिनट हुए हैं, और +++ माननीय सचेतक महोदय, इनको बताओ। पर +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य, हमारी तरफ से पहले स्पीकर हैं, इसलिये परम्परा रही है कि पहले स्पीकर को थोड़ा समय दिया जाता है। आप तो वैसे ही उदारमना हैं।

(समय : 16.00 बजे)

श्री सभापति: इसका मतलब जो दूसरे स्पीकर्स हैं, उनका टाइम कम हो जाएगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें प्लीज, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है।

श्री सभापति: आप चाहें तो पूरा टाइम ले लें। उप नेता महोदय बैठे हैं। आप पूरा टाइम लेंगे तो बाकी को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इस बार हम यह सोच रहे थे कि पिछली बार नौकरियां नहीं लगीं तो इस बार नौकरियों की घोषणा करेंगे, परन्तु यह पूरा 90-पेज का बोरिंग बजट हमने पढ़ा, उसमें सब छांट छांट कर केवल 6190 नौकरियों के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने बजट में प्रस्ताव किया और उसमें भी अधिकांश नौकरियां ऐसी हैं, जैसे कांस्टेबल की नौकरी, 2300 कांस्टेबल रिटायर होंगे, उनकी जगह 2300 कांस्टेबल और भर्ती किये जाएंगे। एक भी नई नौकरी इस बजट में, कहीं कोई स्थान नहीं है। सभापति महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हर एक किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल, हर दो प्राइमरी स्कूल्स पर एक मिडिल स्कूल और हर पंचायत समिति में एक सैकण्डरी स्कूल, हमने पांच साल में पचास हजार से ज्यादा नयी स्कूलें राजस्थान की धरती पर खोलीं और एक नये पैसे का टैक्स नहीं लगाया। एक लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की और आज...

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): असत्य मत बोलो आप। आपकी पैंट ढीली हो रही है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): और वाह भई, हमारे गहलोत साहब की सरकार 1500 करोड़ से ज्यादा का टैक्स लगाकर राजस्थान के इतिहास में पहला बजट है जिसमें एक नया स्कूल नहीं, एक नया कालेज नहीं।

(श्री कालीचरण सराफ)

और जो राजस्थान विधान सभा में बजट सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय वसुन्धराजी ने तीन विश्वविद्यालयों की घोषणा की थी। एक शेखावाटी विश्वविद्यालय, एक अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय और एक भरतपुर में विश्वविद्यालय, इन तीनों विश्वविद्यालयों का भी अता पता नहीं है। कहां गये? घोषणा ही नहीं गयी। यह पहला बजट होगा जिसमें राजस्थान की सरकार ने राजस्थान में एक भी नया हास्पीटल खोले जाने की घोषणा नहीं की। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का हो नहीं सकता। जहां तक हास्पीटल का सवाल है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जयपुरिया हास्पीटल है, साढ़े चार करोड़ रुपये का हमने खर्चा किया हमारे समय में। जे डी ए से पैसा दिलवाया, कलेक्ट्रेट से पैसा दिलवाया, जन सहभागिता में पैसा दिलवाया और जयपुरिया का जो सेठ है जिसके नाम से हास्पीटल चलता है, उससे पैसे दिलवाये। साढ़े चार करोड़ रुपये से भवन बनकर तैयार हो गया। सालभर से वह भवन बनकर तैयार है परन्तु गहलोत साहब के पास टाइम नहीं है। पिछले बजट भाषण में जयपुरिया हास्पीटल को डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल में क्रमोन्नत किया जाएगा, गहलोत साहब ने घोषणा की थी, मैं पूछना चाहता हूं उस घोषणा का क्या हुआ? क्या जयपुरिया हास्पीटल को डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल में क्रमोन्नत कर दिया गया?

इस बार बजट में उर्जा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में यह कर देंगे, वह कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी तब चौबीस हजार गांवों में हमने बीस से चौबीस घंटे तक घरेलू बिजली दी। ऐसा कोई गांव नहीं था, ऐसी कोई ढाणी नहीं थी, जिसमें आठ घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती हो। आपने बड़े-बड़े प्रोजैक्टस की घोषणाएं की हैं पिछली बार भी और इस बार भी, पर मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि राजस्थान में एक भी गांव ऐसा नहीं है, ऐसी एक ढाणी नहीं है जिसमें चार घंटे से ज्यादा बिजली आ रही हो। मैं पूछना चाहता हूं कि बिजली कहां गयी?

पानी के मामले में यह सरकार गम्भीर नहीं, शिक्षा के मामले में यह सरकार गम्भीर नहीं, बिजली के मामले में यह सरकार गम्भीर नहीं और दलितों के मामले में यह सरकार गम्भीर नहीं, तो मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो बजट यहां पेश किया गया है, यह महंगाई बढ़ाने वाला, कर्ज में डुबाने वाला, दलित विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, बेरोजगार-नौजवान विरोधी, व्यापारी विरोधी और आम-अवाम का विरोधी बजट है, इसकी जितनी निन्दा की जाए उतनी कम है। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोबिन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, सदन में जितने भी लोग मौजूद हैं वे सारे के सारे लोग विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, विभिन्न पार्टियों के बैनर तले जनता में अपनी बात रखकर अपनी पार्टी का घोषणा पत्र रखकर और जो गरीब जनता है, गांवों में बैठी है, उसको सपना दिखाकर कि हम आपके भले के लिए करेंगे, आपके लिए सुख सुविधा जुटाएंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, इस बात को लेकर यहां चुनाव जीतकर आते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं, करोड़पति, अरबपति पूंजीपति लोग हैं, वे न तो हमारे भाषण सुनते हैं और न मत देने के लिए वहां आते हैं। हो सकता है किसी बड़े नेता को केवल चन्दा देते हों। हम उस गरीब जनता के प्रति जबावदेह हैं और इस सदन में आकर उस गरीब जनता का कितना भला कर सकते हैं, हमने उनके सामने जो वादा किया है उसको कितना पूरा कर सकते हैं, इस बात की जिम्मेदारी लेकर हम यहां आते हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदन में हम मौजूद रहते हैं। मैं पूर्ववर्ती सरकार का ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी ने विभिन्न गांवों और ढाणियों में जा-जाकर किसी को भाई बनाया, किसी को बहिन बनाया और विभिन्न प्रकार की चुनड़ियां और कटार-तलवारें भेंट में उनको मिलीं, वे लेकर पांच साल उन्होंने जनता की किस प्रकार सेवा की, यह सब हमें देखने को मिल रहा है। पूरी जनता देख रही है। आपने देखा होगा कि पांच साल भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे मुख्य मंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सब हों, केवल यह जो बजट की बातें करते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा बजट दे दिया, बेकार बजट दे दिया, गरीब को महंगाई की मार मारने वाला बजट दे दिया, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि पांच साल आपने क्या बजट दिये थे? किस प्रकार का बजट दिया था? अगर इन्होंने कोई बजट दिया था तो वह केवल अपना निजी बजट था। कितना बैंक बैलेंस किस साल में बढ़ाना है, यह काम पांच साल किया और उसका परिणाम जनता ने उनको विपक्ष में बैठाकर दिया है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बारह महीने पहले भी बजट दिया था और अब भी बजट दिया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहला काम जो गरीब और झोंपड़ी में बैठा है, बीपीएल का आदमी है, किसान है, गरीब है, नि:शक्तजन है, ये सारे के सारे व्यापारी हैं, चाहे छोटा व्यापारी हो, सारे के सारे लोग जिन्होंने यह मानकर कांग्रेस की सरकार को सरकार सौंपी थी राजस्थान में, कि हमारी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

भलाई के लिए काम करेगा, सबसे पहले बैठते ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उन गरीबों की सुध ली है। पहले बजट में भी ली है और इस वाले बजट में भी ली है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप देखिए, गरीब को दो रुपये किलो का गेहूं मिलेगा, इससे जोरदार और स्वागत योग्य बात दूसरी कोई हो नहीं सकती।

माननीय उप नेता महोदय तालियां धीरे-धीरे बजा रहे थे ताकि ऊपर तक कोई शिकायत नहीं कर दे। ताली बजा रहे थे, मैं देख रहा था। मेरी गारन्टी है कि जब गरीब की बात आयी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इनको, कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब घोषणा की, हाथ तो धीरे थे लेकिन सिर-गर्दन झुकाकर कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम गरीब के लिए किया। जो लोग बीपीएल से छूट गये थे, उनके लिए स्टेट बी पी एल का पिछले बजट में प्रावधान किया। जब इस बात को उनके ध्यान में लाया गया कि नि:शक्तजन, वृद्ध और जितने भी अपंग लोग हैं, वृद्ध हैं, ये लोग सुविधाओं से वंचित रह गये तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में सबसे पहले वृद्धावस्था, बेसहारा, विकलांग, इन लोगों को वे सुविधाएं नि:शुल्क मिलें, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से उनका पूरा का पूरा इलाज हो, इस बात की व्यवस्था की है। हमें इस बात का धन्यवाद देना चाहिए। क्षेत्र में जो विकास करना है, उस बात को लेकर हम आएं। जो गरीब झोंपड़ी में बैठा है, जिसको पानी नहीं मिल रहा है, जिसको बिजली नहीं मिल रही है, जिसके सड़क का साधन नहीं है और कोई साधन नहीं है, जिसको सहकारी बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, मकान बनाने के लिए इन्दिरा आवास का भवन नहीं बन रहा है, उनके लिए बात करें। जबकि प्रतिपक्ष तो कहता है कि अमुक मंत्री ऐसा है, अमुक मंत्री ऐसा है। अगर इस प्रकार का ही विरोध करते रहोगे तो मेरी गारन्टी है कि इस सदन में बीस साल तक इसी तरह उधर ही बैठना पड़ेगा। अगर आपको दुबारा हमसे सत्ता छीननी है तो उस गरीब की बात करनी पड़ेगी।

झोंपड़ी में बैठे आदमी की बात करनी पड़ेगी आज भी हम देख रहे हैं बिजली के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 52 प्रतिशत, पूरे बजट का 52 प्रतिशत दिया ताकि झोंपड़ी और गांवों में बैठे लोगों को बिजली की व्यवस्था किस प्रकार से हो।

अभी माननीय कालीचरणजी कह रहे थे, कृषि मंत्रीजी, यह एक अधिकारी की चिट्ठी आयी है, मैं पूछना चाहता हूं कि मौसम आधारित फसल

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बीमा योजना किसने लागू की? माननीय मुख्य मंत्रीजी, अशोकजी गहलोत ने की। किसानों को ऋण प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार देने का काम सबसे पहले अगर हिन्दुस्तान लेवल पर किसी ने किया तो यही माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय कृषि मंत्रीजी हैं, आपकी सरकार ने नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारियों का भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान रखा है। जो ए.एन.एम. नर्से बाड़मेर में, जैसलमेर में कहां-कहां काम करती थीं, 3500 में काम करती थीं, उनका पैसा आप देखिये, 6500 कर दिया। जो लैब टैक्निशियन था उसका बढ़ा दिया। नरेगा में जो सहायक रोजगार ग्राम सेवक काम करते थे, उनका पैसा हजार रुपये प्रति माह बढ़ा दिया।

यह सारी की सारी सोच माननीय मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत की सोच है कि कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए, व्यापारियों को भी मिलना चाहिए। अभी कह रहे थे कि व्यापारियों को यह नहीं दिया, वो नहीं दिया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पांच पृष्ठ हैं इस बजट में जिसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने केवल व्यापारियों को राहत देने वाले काम किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, हम सब को क्षेत्र के विकास की बातें सोचनी पड़ेंगी। आज सड़कों की जरूरत है, बिजली की जरूरत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा है- 1350 किलोमीटर की 19 सड़कें, 263 किलोमीटर की 6 सड़कें, 1521 किलोमीटर की 1891 करोड़ रुपये की भारत सरकार की योजना तथा 1778 किलोमीटर के 11 राष्ट्रीय राज मार्ग, 3445 करोड़ रुपये लगेंगे और नाबार्ड के सहयोग से भी 160 किलोमीटर की 96 करोड़ 75 लाख की योजनाएं। सड़कों में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इतिहास रचा है, उस बात का भी इनको धन्यवाद देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य तो कल चूरू से थे आज तारानगर से, बड़े आदमी हैं, कहीं दूसरी जगह से आ जाएंगे लेकिन हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को गरीब के लिए काम करना पड़ेगा। वो काम माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में हम सब कर रहे हैं। अच्छा गरीबों का बजट, गरीबों को रिलीफ देने वाला बजट दे रहे हैं। माननीय कृषि मंत्रीजी की उन्होंने बुराई तो कर दी लेकिन मैं नहीं जाना चाहूंगा, ज्यादा कहूंगा तो इनके तकलीफ हो जाएगी। माननीय उप नेता

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

महोदय, कृषि मंत्री तो आपके भी बने थे, कितने घोटाले लगे, कितने आई.ए.एस. अधिकारियों ने कितनी-कितनी बातें कीं? वो काम कांग्रेस सरकार में नहीं हैं। केवल आप इतनी-सी बात कर लो कि मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अभी माननीय श्रवणजी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम सब को मिल कर काम करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जल संसाधान पर भी 777 करोड़ रुपये दिये हैं। उनके मन में एक तकलीफ थी, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मौके पर कि लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के 283 गांवों के लोग जो फ्लोराइड से कूबड़े हो गये थे, जिनके दांत गिर गये थे और 40 साल की उम्र में जो बूढ़े हो गये थे, उनके लिए फ्लोराइड से मुक्ति के लिए जो योजना है, उसके सर्वे का काम चालू करवाने की घोषणा बजट में की गयी है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हुआ निवेदन करना चाहता हूं और प्रतिपक्ष से भी आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें सहयोग करें ताकि 283 गांवों में जो फ्लोराइड की समस्या से फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के लोग जूझ रहे हैं, उनको न्याय मिले, उनको स्वच्छ पानी मिले।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वृद्धावस्था और नि:शक्तजनों की पेंशन में बढ़ोतरी किस ने की? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की। अब बताइये, बी.पी.एल. के लोगों को सुविधा दे रहे हैं, एस.सी., एस.टी. के लोगों को सुविधा का बजट है, नि:शक्तजनों के लिए इसमें प्रोविजन है, व्यापारियों के लिए इसमें प्रोविजन है, किसानों के लिए इसमें प्रोविजन है इसके बावजूद माननीय सदस्य। कालीचरणजी साहब पता नहीं क्या-क्या भाषण दे गये, कहां से शुरू किया कहां अंत किया, इस बात को इनको सोचना पड़ेगा। शहरों में तो जे.डी.ए. है, नगर निगम है लेकिन गांवों से आते तब पता चलता कि एक बार को छोड़ कर 85 से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य की तरह आपको भी स्थान परिवर्तन करना पड़ता क्योंकि गरीब लोगों के प्रति आपकी सोच नहीं है। अपना निजी बजट और वो बजट बढ़ा-बढ़ा कर विपक्ष में बैठो, हम यही ईश्वर से कामना करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत जोरदार योजना 'हरित राजस्थान' शुरू की, ताकि हरे-भरे पेड़ लगें, आपको अच्छा नहीं लगता क्या? कौन ऐसा नेता है जिसके घर में पेड़-पौधे नहीं हैं,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

उनके गमले नहीं हैं? उनको अच्छा क्यों बताते हो फिर? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए, हरा-भरा बनाने के लिए एक योजना दी, आपसे एक ताली नहीं बजायी गयी। वो पेड़ खा गये, ये खा गये और वो खा गये, कुछ खा गये कि नहीं खा गये लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय की एक कल्पना देखिये कि आने वाला राजस्थान हरा-भरा होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरेक पंचायत समिति पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने क्रय-विक्रय सहकारी समिति होने की घोषणा इस बजट में की है, अब इसमें भी आपको ताली नहीं बजानी आ रही है तो इस आई.टी.आई. पर बजा दीजिए। हरेक पंचायत समिति स्तर पर चाहे निजी सहभागिता से ही हो, आई.टी.आई. खोलने का विचार है, इस पर भी आप से ताली नहीं बजायी जाए, केवल बीच में टोकाटोकी, आप तो बहुत वरिष्ठ भी हैं और बहुत पैसे वाले बता रहे थे, मैंने जो अभी सुना है ...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ध्वनि प्रदूषण।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो आपको शोभा थोड़े ही देता है मेरे जैसे गरीब आदमी के बीच में बोलना? आपको शोभा नहीं देता।

माननीय सभापति महोदय, रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी जब माननीय मुख्य मंत्रीजी सस्ते भोजन की बात कर रहे थे, तो नाड़ हिला कर उसका स्वागत कर रहे थे। जब आप में से बहुत से सदस्य स्वागत कर रहे हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की तो खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य, अभी तो शायद स्थान परिवर्तन कर लिया होगा, पता नहीं परिसीमन से किया कि कैसे किया, उन्होंने भी तालियां बजायीं, वास्तव में धीरे-धीरे मुस्करा रहे थे कि बिजली में हमने पांच साल में नहीं किया उतना माननीय मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत ने एक साल में राजस्थान की जनता को दिया है। ये सारी की सारी चीजें हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप देखिये कि टैक्स में वाटर टैंकर जो गरीब जनता को पानी पिलाता है, उसके लिए वैट माफ कर दिया। बैटरी से संचालित, प्रदूषण मुक्त हो अपना वातावरण, इसके लिए उसे भी कर मुक्त कर दिया। सौर ऊर्जा को भी कर मुक्त कर दिया। बिजली की खपत कम हो तो सी.एफ.एल. बल्ब को भी कर मुक्त कर दिया। और तीन सितारा से कम

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

वाली होटलों का भी भोजन सस्ता कर दिया इसके बावजूद भी मैं सुबह से देख रहा था कि आप आज बिना वजह, कल भी बिना वजह बोल रहे थे कि वो अमुक ऐसा कर गया, वैसा कर गया। बहुत आसान बात है किसी के ऊपर कीचड़ उछालना। खुद का दामन पवित्र रखने के लिए आपको उधर से इधर आने की चेष्टा करनी चाहिए न कि वो सीट परमानेंट करने का काम करना चाहिए। यह काम आप तभी कर सकते हैं जब गरीब की आवाज सुनेंगे। केवल दिखाने के लिए मीडिया में बाहर जाकर कि, साहब, हमने भाषण दिया और सदन को दो घंटे रोक दिया, यह नहीं। हम सोच कर आये थे कि यह सदन जोरदार चले, गरीब और अवाम के क्षेत्र के विकास की अच्छी बातें उठें। लेकिन पता नहीं चाहे जब चार घंटे बंद करा दो फिर आकर अपने आप बैठ जाते हैं। चाहे जब छह घंटे बंद करा दो, दो दिन बंद करा दो, फिर आकर बैठ जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने पिछले पांच सालों में शिक्षा जगत में जितने लोगों की पदोन्नति नहीं की, माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी ने एक साल में कर दी, इस बात का तो धन्यवाद दो। एक टीचर जो केवल अध्यापक हो कर के घर जा रहा था वो आज प्रधानाध्यापक होकर घर जाएगा, क्या यह अच्छी बात नहीं है? स्कूल का कंट्रोल बढ़िया होगा, क्लास रूम बनेगा। विज्ञान विषय में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 30 साल में सरकारी स्कूल में एक भी विज्ञान विषय नहीं खुला और माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी ने पहली बार तीन-तीन विद्यालयों में विज्ञान के संकाय खोल कर हमें पुरस्कृत किया है और आम जनता को यह दिखाया है कि हम आपके लिए हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया व्यवधान नहीं करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्योंकि आप के कारनामे यहां देख लिये हैं, आपके कारनामे अच्छे नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय डोटासराजी, आप तो यह बता दो कि मास्टर कितने लगाये?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो जनता की सेवा करेगा, जनता के विकास की बात करेगा, माननीय अमरारामजी साहब, आप तो बहुत ही ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कृपया विराजिये, जब आपका समय आए तब बोलना आप ......(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं ......(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको तो केवल इतना कहना है ......(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, माननीय सदस्य, कृपया विराजिये, आप बोलने दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कि किसान के दुःख, दर्द, तकलीफ में हम काम आएंगे। आप काम कुछ आने नहीं, डीपी दिला दो तो मेरी गारंटी, किसी का कृषि कनेक्शन फ्री करा दो तो मेरी गारंटी, आपको केवल इतना कहना है। यहां इस सदन में ....

श्री सभापति: बस, माननीय सदस्य, कृपया विराज जाएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): केवल किसान के हित की अगर कोई बात करोगे ......(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप तो यह बता दो कि मास्टर हमने लगाये, 14 महीने का बता दो ......(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यहां कहने से काम नहीं चलेगा ......(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप साइंस का खोले हो और साइंस के मास्टर कितने लगा दिये, वह बता दो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, हैडमास्टर बड़ा होता है कि मास्टर? जब हैडमास्टर लगा दिये तो मास्टर की कहां से बात आती है?

श्री सभापति: अब समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम हैडमास्टर लगाएंगे .... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापतिजी, मास्टर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि शिक्षा मंत्रीजी खुद ही मास्टर हैं, मास्टर भंवरलालजी ही नाम है उनका तो, मास्टर की जरूरत कहां है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तभी तो, माननीय उप नेता महोदय, जो पांच साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पदोन्नति नहीं कर सकी, वह मास्टर भंवरलालजी ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने केवल एक साल में करके दिखाया। आम जन जीवन के लिए केवल मात्र गरीब के हित की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार की बजट में घोषणा की है, कि सड़क ले जाकर देंगे जनता को, उन गरीब लोगों को ऊर्जा और बिजली ले जाकर देंगे तो निश्चित रूप से आम-अवाम, गरीब की आंख के आंसू पोंछे जाएंगे। चार घंटे सदन बंद कराने से, मंत्रियों पर असत्य आरोप लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपने घंटी नहीं बजा कर मेरे को घड़ी दिखाई, मैं घड़ी से ही बैठ जाता हूं। लेकिन मेरी बहुत बातें रह गई जो इनको मुझे बतानी थीं।

श्री सभापति: धन्यवाद, सहयोग के लिए धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जोधपुर और जयपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू आपसे नहीं हुई, उसके बावजूद भी आप इस तरह से कहते हो, कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो घंटे में कुछ नहीं दिया। पिछली बार की तरह आपका बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ेगा, यह हमारी गारंटी है। बाकी आम अवाम के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, उसकी हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री गजेन्द्र सिंह।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, मैं बजट का जो भाषण माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया था और जो घोषणाएं की थीं, उसमें पैरा नम्बर 288 पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज ही क्वेश्चन आवर के अन्दर माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने बोला कि टी एण्ड डी लासेज हम इतने लो ले आए हैं। गवर्नर मैडम के भाषण के अन्दर भी आपके कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इतनी बिजली पैदावार हो रही है। भाई, हमारी पुरसी हुई थाली है, बढ़िया है, आप लोग जीम लो लेकिन जब बिजली का उत्पादन इतना ज्यादा हो रहा है यानी कि 3 रुपये प्रति यूनिट से हो रहा है जबकि हम 10 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली खरीद रहे थे, और आप कह रहे हैं कि टी एण्ड डी लासेज आप 24 परसेंट पर ले आये हैं तो, यह सब होने के बावजूद यह 10 परसेंट सरचार्ज क्यों लगाया जा रहा है, यह समझ में नहीं

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

आ रहा है शहरों के अन्दर और दूसरी चीज यह जो गलत काम कर रहे हैं, यह तो कर ही रहे हैं, जनता को गुमराह और कर रहे हैं। गुमराह ऐसे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सौ यूनिट से ज्यादा जो शहरों में बिजली यूज करेगा उसके ऊपर लगेगा यह 10 सरचार्ज। 10 पैसे जो सरचार्ज लगेगा, सौ यूनिट जो बिजली यूज करेगा उससे ज्यादा, उस पर पड़ेगा। अब आप बताइए कि सौ यूनिट से ज्यादा कौन यूज करते हैं? बीपीएल के परिवार हैं उनको तो यों ही सब्सिडाइज्ड है बिजली तो यह जो गुमराह करने की जो मंशा है सरकार की, इसका मैं विरोध करता हूं और दूसरी चीज है कि इन्होंने कहा है कि हम एक स्पेसिफिक फण्ड बनाया है, यह पैसा जो हम 10 पैसे लेंगे स्पेसिफिक इसको स्पेसिफिक फण्ड में डाल देंगे, इससे हम रोड सिटी के अन्दर करेंगे, स्ट्रीट लाइट्स के अन्दर करेंगे। फर्क तो पड़ ही रहा है न जनता के ऊपर। जो आप म्यूनिसिपैलिटीज को पैसा दे रहे हैं, मतलब आप उसकी बचत कर देंगे और बिजली के भार से आप उसकी पूर्ति कर देंगे, तो ये दोनों जो बातें की हैं, इससे बिलकुल सरकार हमको गुमराह कर रही है।

इसके अलावा अभी फेमिन है। फेमिन के अन्दर क्या है कि चलो, फेमिन आप कहते हैं कि फेमिन का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टस कम होना, अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम होने का मतलब है कि जो शहरों में आ रहा है, चाहे वह ट्रैक्टर बिक रहा है, चाहे पेस्टिसाइड्स बिक रहे हैं, सब कुछ तो मंदी। जिस साल एग्रीकल्चर डाउन हो जाता है, उस टाइम शहरों में मंदी आ जाती है। तो इस मंदी के जमाने के अन्दर, इस फेमिन के अन्दर एक ऐसी चीज के ऊपर आप सरचार्ज लगा रहे हैं जो इंसान यूज करता है और गरीब से अमीर इंसान यूज करता है। इसलिए मैं यह सोचता हूं कि यह जो 10 पैसे का सरचार्ज बढ़ाया है, यह बिलकुल सही नहीं है। यह फेमिन का मौका है, इसके अन्दर बिलकुल लगाना उचित नहीं है और जो जनता को गुमराह किया है, वे मैंने आपको दो पाइंट बता ही दिये हैं।

पैरा 36- सभापति महोदय, हमारी बीजेपी की जब सरकार थी, नागौर जिले में सबसे भारी जो समस्या थी, वह थी पीने के पानी की1 खारा पानी भी नहीं मिल रहा था, इतना फ्लोराइड था, टीडीएस फैक्टर लगभग 7 हजार तक पहुंच गया कई स्थानों पर। लेकिन आज की स्थिति में गांवों के अन्दर, ढाणियों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुछ मात्रा में दूध डाल कर पानी पीते हैं क्योंकि इतना खारा पानी वे पी नहीं सकते हैं। हमारी सरकार ने इस प्राब्लम

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

को आइडेंटिफाई करके माननीय वसुंधरा जी ने 760 करोड़ रुपये स्वीकृत किये। 760 करोड़ जिस समय स्वीकृत किये, उस टाइम नागौर विधान सभा, मूंडवा विधान सभा, डेगाना विधान सभा और मेड़ता विधान सभा जो उस टाइम ये विधान सभा थीं, उनके अन्दर पहले फेज के अन्दर पानी देने की स्कीम थी 760 करोड़ रुपये की, कार्य शुरू हो गया। कार्य शुरू हो गया और इसके अन्दर 331 करोड़ रुपये, सभापति महोदय, खतम हो गये, मतलब उसका उपयोग करीब-करीब हो गया है और मेन लाइन भी नागौर शहर तक पहुंच गई है। आज क्या है जो कंटीन्यू स्कीम थी, उस पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए जिस करीबन 300 करोड़ रुपया लगेगा, उससे आपके 502 गांव और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित होते हैं। उसको इन्होंने ठण्डे बस्ते में डाल दिया, कोई चर्चा ही नहीं है। अगर काम शुरू नहीं हुआ होता तो नागौर तक भी पानी नहीं आता। लेकिन क्योंकि काम शुरू हो गया था, पाइप लाइनें लगने लग गई थीं तो उसको रोक नहीं पाये। यह स्कीम रोकने से 502 गांव जिनकी बहुत खराब हालत है, सरकार अगर इसके अन्दर कुछ नहीं करेगी तो मैं चेतावनी देता हूं कि लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। आदमी मरता क्या नहीं करता है? यह जो लिफ्ट कैनाल के बारे में सरकार ने किया नागौर के साथ, बिलकुल ही भेदभाव किया और नागौर जिले के लिए कुछ भी नहीं किया।

इसके बाद पैरा नम्बर 286 है, इसके ऊपर परिवहन डिपार्टमेंट के थ्रू इन्होंने कहा कि जो 6 स्लैब सिस्टम है, उसको हम 4 स्लैब पर ला देंगे। अब आप देखिए, आश्चर्य की बात है, समय बदल गया है, जो पहले साइकिल चला रहा था, वह आज मोटरसाइकिल चला रहा है, जो मोटरसाइकिल चला रहा था, वह मारुति कार चला रहा है, मारुति कार चलाने वाला बढ़िया कार चला रहा है। समय बदल गया है। पंखे वाला कूलर चला रहा है, कूलर वाला एसी चला रहा है Standards of living have gone up. तो यह जो सिस्टम इन्होंने लगाया है, इन्होंने कहा कि, साहब, 10 लाख से ज्यादा की गाड़ी होगी उस पर 10 परसेंट टैक्स लगेगा-रोड टैक्स। पहले, आप सब माननीय सदस्यों को ध्यान होगा, एक समय था, सब लोग हरियाणा से अपनी गाड़ियां लाते थे क्योंकि टैक्स में फर्क था। आपका पड़ोसी प्रदेश है, आधा परसेंट टैक्स का अगर फर्क हो तो कोई बात नहीं है। लेकनि अब आप देखिए कि कोई गाड़ी जो 20 लाख रुपये की है, वह अगर हरियाणा में खरीदें तो 40 हजार रुपये उसका टैक्स देंगे, राजस्थान

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

में खरीदें तो 2 लाख। 40 की गाड़ी है तो 80 हजार टैक्स भरोगे हरियाणा में और राजस्थान में भरोगे 4 लाख और अगर 50 लाख की गाड़ी है तो एक लाख टैक्स भरोगे हरियाणा में और 5 लाख टैक्स भरोगे राजस्थान के अन्दर। क्या कंजूमर इतना बेवकूफ है? आज छोटी छोटी चीजों के लिए लोग इंटरनेट के ऊपर जाकर दो पैसे बचाने के लिए अपनी चाहे होटल की बुकिंग हो, चाहे ट्रैवल का कुछ हो, तो क्या सरकार को ये पैसे मिलेंगे? क्या लोग अपनी गाड़िया राजस्थान के अन्दर खरीदेंगे? कोई नहीं खरीदेगा। सभापति महोदय, इसके अलावा, पंजाब का आप देखिए, पंजाब का आप व्यवहार देखिए, वहां पर टैक्स फ्लैट है- 6 हजार रुपये। जितने वाहन बिकेंगे उतना सरकार को पैसा मिलेगा तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इससे स्टेट को क्या प्राप्त होगा। आपको हरियाणा में गाड़ी खरीदनी है, दिल्ली में गाड़ी खरीदनी है, आपको एक एड्रेस ही तो क्रिएट कराना है और एड्रेस क्रिएट करना कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है। तो क्या यह सेम है सिस्टम? क्या यह न्याय है, इतना टैक्स। क्या हमारी सड़कों पर सोना लगाया हुआ है, जो हमारी सड़कें इतनी बढ़िया हैं कि इतना टैक्स लिया जाए? एक तरह से देखा जाए तो this is discouraging the economy. आप राजस्थान की जनता को डिस्करेज कर रहे हैं स्पैंडिंग से and this is very against the principles of economics. कोई भी देश है, लोग देखते हैं कि स्पैण्डिंग को कैसे बढ़ाया जाए। स्पैण्डिंग जैसे बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा। प्रदेश की खुशहाली चाहिए तो ऐसी ड्रास्टिक पालिसीज, ऐसी स्टुपिड पोलिसीज जो बिलकुल ही प्रैक्टिकल नहीं हैं, इनको लागू नहीं करना चाहिए।

पैरा नम्बर दस-पी डब्ल्यू डी के अन्दर बहुत तगड़ी घोषणा की मुख्य मंत्रीजी ने कि पांच हजार करोड़ रुपये हम सड़कों पर खर्च करेंगे। पांच हजार करोड़ रुपये जब आप खर्च करोगे, अभी तो पी एम जी एस वाई एक आटोमेटिक स्कीम है, ढाई सौ की आबादी तक तो आलरेडी आटोमेटिक सिस्टम हो ही रहा है। अब आपको क्या है कि सड़कों का सुधार करना है वह भी पी एम जी एस वाई दे रहा है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से अपने देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और सरफेस ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है इस प्रदेश के लिए। इसलिए जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो इनको एक ग्रिड सिस्टम बनाना चाहिए, एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए। यही सरकार नहीं, जो भी

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

सरकार आए उसको फालो करे। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम इनको ग्रिड सिस्टम बनाना चाहिए कि हर पचास किलोमीटर में एक बढ़िया रोड हो। हमारी सरकार ने जो मेगा हाई-वेज बनाए हैं, आप देखिएगा, सभापति महोदय, कि सवाई माधोपुर जो कट आफ होता था वह अलवर से लेकर दिल्ली से कनैक्ट हो गया, फलौदी से बिलकुल गुजरात की सीमा तक सड़क पहुंच गयी, कुचामन से जो सीकर साइड से आ रही है, यह जो मेगा हाई-वेज बने हैं, यह इंटर कनेक्टिविटी, हनुमानगढ़ और यह पूरा एरिया ओपन आउट हो गया है।

मैं सोचता हूं कि यह जो पैसा खर्च हो रहा है इसको जुडीशियसली खर्च करना चाहिए, एक ग्रिड सिस्टम बनाना चाहिए, मेगा हाई-वेज को प्रमोट करना चाहिए सबसे ज्यादा। बजट के अन्दर यह मैंशन नहीं हुआ है कि टूरिज्म रोड्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो हर विधायक की विधान सभा के अन्दर रोड्स का इम्प्रूवमेंट होगा। टूरिज्म के अन्दर भी सबसे बड़ा टूरिज्म अपना है रिलीजियस टूरिज्म, जहां मन्दिर और मस्जिद हैं। इन रोड्स को सुधारा जाए तो टूरिस्ट भी आएगा, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और सड़कें भी अच्छी होंगी। तो मैं सोचता हूं कि ये जो पांच हजार करोड़ रुपये हैं, इसको अच्छे तरीके से, एक दिशा के साथ, अच्छा प्रोग्राम बनाकर इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। खाली एक पेपर्स में नहीं निकालें कि पांच हजार करोड़ रुपया हम दे रहे हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): बस दो मिनट और। पैरा नम्बर 103 के अन्दर सभापति महोदय, वन्य जीव के ऊपर बोला है कि एक हजार पोस्ट वन अधिकारी हम दे रहे हैं। मैं सोचता हूं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन सेव दी टाइगर प्रोजैक्ट के ऊपर इतना हल्ला मच रहा है, इतनी अवेयरनैस है, इण्डीजीनस स्पेसीज टाइगर हैं, तो मेरा सोच है कि कम से कम जो नेशनल पार्क्स हैं, उनकी जो फीस आती है, वह पार्क के डवलपमेंट के लिए उनको दे देनी चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कुछ भी बजट टाइगर के लिए या नेशनल पार्क्स के लिए इस बजट में नहीं दिया है, मैं कनक्लूजन में यही कहना चाहूंगा

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

कि यह जो बजट पेश किया गया है It lacks vision, it lacks direction and it is a budget of without any direction.

श्री सभापति: श्री पेमाराम।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने बजट रखा, एक ऐसे समय में बजट रखा जब पूरा का पूरा राजस्थान भंयकर अकाल और भंयकर रूप से मंहगाई की चपेट में है। ऐसी सूरत में राजस्थान की सरकार ने वैट बढ़ाकर वाकई में पक्ष और विपक्ष एक जुदा बात है, लेकिन राजस्थान की जनता का कचूमर निकाल करके रख दिया। के हो सकता है कि होटलों पर हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने सब्सिडी दे दी होगी, मगर जो नरेगा में गरीब मजदूरी करके आने वाला मजदूर है, तीन सितारा होटल तो बाद की बात है, गांव से आकर किसी शहर में भी किसी होटल पर खाना खाना भी उसके लिए आसान काम नहीं है। अभी सूरजगढ़ वाले मेरे माननीय सदस्य कह रहे थे, वाकई में गांव के लिए, गरीब के लिए, झोंपड़ी वाले के लिए इस मंहगाई और अकाल में कायदा तो यह बनता था राजस्थान की सरकार का, जहां कुदरत ने अन्याय कर दिया, राजा और महाराजाओं के समय में भी यदि अकाल पड़ जाता तो दूजे राजा के वहां से अनाज भी जाता और उस इलाके के पशुओं को बचाने के लिए चारे की व्यवस्था भी करता, वैसी व्यवस्था सरकारी करती।

लेकिन हमारे राजस्थान की सरकार ने छह सात महीने लगातार होने के बाद राजस्थान के अन्नदाता को, जो इस जमीन का कलेजा चीर कर अनाज पैदा करता है, एक नया पैसा भी अकाल से मुकाबला करने के लिए, अभी बजट में घोषणाएं की हैं कि हम लघु और सीमान्त किसान को आगे जब बिल्कुल उस किसान की कमर टूट जाएगी, उसके बाद अभी घोषणा कर रहे हैं। सात महीने के बाद हमारे राजस्थान की सरकार को अहसास हो रहा है कि राजस्थान में भंयकर अकाल है और अकाल के समय उस गरीब मजदूर के बारे में राजस्थान की सरकार ने, माननीय सदस्यों, मैं आप तमाम से भी इसलिए कहना चाहूंगा कि हमारे सीकर जिले में इस अकाल में क्या दिया गरीब को? आपने एक ऐसा सर्कूलर निकाल कर रख दिया, जिसमें ऐसी पाबंदी लगा दी कि सौ दिन नरेगा में काम करने के बाद यदि कोई अकालपर काम के लिए आएगा तो महीने में उसका परिवार चाहे कितना बड़ा हो या छोटा, महीने में मात्र दस दिन काम देकर के सरकार पल्ला झाड़ लेगी। आज तक राजस्थान में

(श्री पेमाराम)

अकाल से इतने पीड़ित हैं, उसके बाद भी न गरीब को मजदूरी दी, न गरीब को काम दिया, न किसान को फायदा दिया।

कह रहे हैं, अभी उसका बढ़ा दिया, उसका पैसा बढ़ा दिया। जो बढ़ा दिया उसका तो मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि जब कर्मचारी का बढ़ गया, छठा वेतन आयोग लागू हो गया, जब राजस्थान में विधवा, वृद्धावस्था इन पेंशनों का बढ़ा दिया, स्वतंत्रता सेनानियों का बढ़ा दिया, फौजियों का बढ़ा दिया, तो निश्चित तौर पर जो नरेगा में काम करने वाला मजदूर है, राजस्थान की सरकार को विचार करना चाहिए और नरेगा में काम करने वाले मजदूर की न्यूनतम मजदूरी किसी भी कीमत पर सरकार को बढ़ानी चाहिए। वर्ना इस मंहगाई में उस गरीब के साथ इससे बड़ा अन्याय कोई हो नहीं सकता। वह गरीब आने वाले वक्त में राजस्थान की इस कांग्रेस की सरकार को कभी भी किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगा।

मेरी मांग है कि नरेगा पर काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का काम किया जाए।

जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली की नीति बनी हुई है कि यह नीति है और उस नीति के तहत यह कह रहे हैं कि आकाश में बिजली बनाएंगे, पाताल में बिजली बनाएंगे, इतनी बिजली बनाएंगे, यह कर देंगे, इतने कनेक्शन दे देंगे। यह एक आदेश है इसी सरकार का, जो राजस्थान के ढाणियों में आवास करने वाले हैं, सभापति महोदय, यदि ढाणी में कोई ट्यूबवैल बनाकर वहां रहता है, कुएं पर उसका कनेक्शन है, पुख्ता मकान बना लिया, ढाणियों में आवास करने वाला वह किसान उजाले के लिए बल्ब नहीं चास सकता और यदि कोई चास लेता है तो कनेक्शन पर पाबंदी लगा दी। इन्होंने कनेक्शन बंद कर रखे हैं शायद ढाणियों में।

कांग्रेस की सरकार वोट के लिए तो कह रही है कि हमने कड़ी से कड़ी जोड़ दी, वोट के लिए तो उन ढाणियों वालों के पास जा सकते हैं लेकिन ढाणी वाले को घरेलू कनेक्शन देने के लिए राजस्थान की सरकार ने पाबंदी लगा कर यह माना है कि राजस्थान की ढाणियों में आवास करने वाला शायद कोई पाकिस्तानी नागरिक हो। वर्ना ढाणियों में आवास करने वाले उन किसानों में

(श्री पेमाराम)

यदि कोई कनेक्शन लेना चाहता है तो सरकार को घरेलू लाइट का कनेक्शन खोलना चाहिए।

जहां तक कह रहे हैं किसानों के हम बिल नहीं बढ़ाएंगे। सभापति महोदय, यह इनका बिल है और यह इनका आर्डर है। मुझे पूरे राजस्थान का तो पता नहीं लेकिन इन्होंने एक ही आदेश निकाला है, सीधी रेट न बढ़ाकर अकाल से मुकाबला करने वाले किसान के साथ किस कदर उनके पास बिल भेजे जा रहे हैं, जिनके कुओं पर मीटर लगे हुए हैं, मीटर वाले किसानों के भी फ्लैट रेट से एवरेज के नाम पर नाजायज तौर पर वसूल कर रही है राजस्थान की सरकार। राजस्थान की सरकार यह समझती है कि आकड़े का जैसे पत्ता लगा है वैसे किसान के घर में पैसे का पेड़ लगा है और मर्जी आए वैसे बिल भेज देंगे। बिल नहीं चुकाने पर उसका कनेक्शन काटने का काम करते हैं।

इसलिए मैं यह कहूंगा कि इस बजट में दिखावा चाहे कुछ भी क्या है लेकिन राजस्थान की जनता के साथ, राजस्थान के किसान के साथ अन्याय करने का काम किया है ।

जहां तक पंचायतों का प्रश्न है, माननीय सभापति महोदय, पहले अभी तो 10 पंचायतें और नयी बन गयीं। लेकिन जहां से मैं चुनकर आया हूं पंचायत समिति धोद, अभी तक उसका खुद का भी निजी भवन नहीं है। जैसे कोई कर्मचारी का स्थानान्तरण होता है उसी तरह पंचायत समिति के कार्यालय का स्थानान्तरण होता है। अब 10 नयी और बन गयीं, क्या नयी बनने वाली पंचायत समिति भी अपना कार्यालय सिर पर लिये कर्मचारी की तरह यूं घूमेगी? हम वहां विकास की उम्मीद करें? निश्चित तौर पर बजट में प्रावधान किया जाना चाहिये कि उन पंचायत समितियों के लिये बजट अलाट हो, उनका कोई भवन बने जो निश्चित तौर पर विकास में सहयोगी होगा। तो सरकार को चाहिये कि इसके लिये कोई व्यवस्था करे।

जहां तक शहीदों का, प्रश्न है, माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर दिया होगा, लेकिन मेरी कांस्टीयुएंसी में जेरठी गांव का एक शहीद आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गया स्वर्ण मंदिर में जहां कांग्रेस की सरकार थी, दर-दर की ठोकरें खाती उसकी यह वीरांगना घूम रही है। 50

(श्री पेमाराम)

बीघा जमीन दे देंगे, उसके वारिस को नौकरी दे देंगे। मैं समझता हूं, जब मेरी कांस्टीयुएंसी में है तो शायद राजस्थान में भी शहीदों की इसी प्रकार से उपेक्षाएं हो रही होंगी। यह बजट या किताबों में लिखकर जनता के सामने ढकोसला पीटना एक जुदा बात है, बाकी प्रैक्टिकल में ये पत्रावलियां आज भी राजस्थान की सरकार के कार्यालयों में शहीद के पुत्र को, आश्रित को नौकरी और 50 बीघा जमीन के लिये हर कार्यालय में जमा हैं। वीरांगनाएं चक्कर लगाते-लगाते थककर अब घर बैठ गयीं, राजस्थान में चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए और चाहे भारतीय जनता पार्टी की आ जाए, कहने को कुछ भी हो लेकिन प्रैक्टिकल में किसी दुखियारे के दुःख-दर्द में काम आने वाली सरकारें नहीं हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि वह भी सरकार करे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करें।

श्री पेमाराम (धोद): अब पल भर का काम है। जहां तक इस बात का सवाल है कि इनका उद्धार करेंगे, उनका उद्धार करेंगे। शिड्यूल्ड कास्ट का यह कर दिया, वह कर दिया। माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान की आजादी से लेकर आज तक एक मात्र निर्णय ऐसा है जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट के साथ सरकार ने अन्याय किया है, अभी सरकार ने इस बजट में घोषणा की है कि राज्य की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में कार्य करने वाले शिक्षक ग्रामीण इलाकों के विद्यालयों, महाविद्यालयों में जाएंगे। निश्चित तौर पर भेजने चाहिये, लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट का जितना आरक्षित कोटा है अभी बैकलाग चल रहा है। हर साल बैकलाग भरने की बात करते हैं। यह सरकार भी पिछले बजट में कह रही थी कि बैकलाग के द्वारा शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की भर्ती की जाएगी। लेकिन अब तो यह करने का मतलब शिड्यूल्ड कास्ट का बच्चा कोई नौकरी के काबिल भी हो तो शायद आने वाले पांच साल में जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी, उसकी नौकरी लगना असम्भव हो जाएगा।

समय कम है, इसलिये मैं यही कहूंगा कि इस बजट में मजदूर का कोई पैसा नहीं बढ़ाया। किसी का बढ़ गया होगा, कर्मचारी का बढ़ गया होगा, अधिकारियों का बढ़ गया होगा, ठेकेदारों का बढ़ गया होगा, नरेगा में जो संविदा पर ग्राम सेवक लगता है उसका बढ़ गया होगा, लेकिन नरेगा पर काम करके मिट्टी खोदने वाले मजदूर का नहीं बढ़ाया इसलिये मेरी मांग है कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ायी जानी चाहिये।

(श्री पेमाराम)

अकाल के समय, सभापति महोदय, बैंकों में जाता है, जमीन गिरवी रखता है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें आप।

श्री पेमाराम (धोद): हर बैंक में फसल बीमा के नाम पर किसान से पैसा काटा जा रहा है राजस्थान में। पर आज तक एक नया पैसा भी राजस्थान के किसी भी किसान को नहीं दे पाये हैं। किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। रोजगार का कोई अवसर नहीं, नौजवानों का विरोधी है। राजस्थान की सरकार ने जो बजट पेश किया है वह राजस्थान की जनता का विरोधी है।

डीजल और पैट्रोल पर फिर वैट बढ़ाकर तस्करी बढ़ाने का काम किया है, हरियाणा और पंजाब से जिस तरह से शराब लाकर बेची जाती है उसी तरह से डीजल और पैट्रोल लाकर यहां पर बेचेंगे। केस, मुकदमे बनेंगे। यह बजट राजस्थान की जनता का घोर विरोधी बजट है इसलिये मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या मोहतरमा जकिया।

श्रीमती जकिया (टोंक): माननीय सभापति महोदय, आपकी इजाजत से मैं बजट 2010-2011 के पक्ष में बोलने की इजाजत चाहती हूं। इससे पहले कि मैं बजट पर बोलूं, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस में कुछ बिन्दु ऐसे थे जो मुझे बहुत नागवार गुजरे, उन पर 2-4 लाइनें बोलना चाहती हूं।

2-4 मिशन के नाम थे, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, राजीव गांधी स्वास्थ्य मिशन, राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा, राजीव गांधी पशुपालन मिशन। राजीव गांधी की शख्सियत किसी अलंकार की मोहताज नहीं है। उन्होंने जिस वक्त में अपनी राह चुनी थी, देश भयंकर आतंकवाद से गुजर रहा था। ऐसा मुमकिन ही नहीं था, छोटे-छोटे प्रिमिसेज में बम विस्फोट होता है, सुरक्षा एजेंसीज को इसका पता होता है तो देश के प्रधान मंत्री को कैसे पता नहीं होगा ? मगर उन्होंने चुना देश की अखंडता को, हमारी सुरक्षा को ऊपर रखा और अपने कर्तव्य का पालन किया। आज हम इस सदन, इस प्रान्त, इस हिन्दुस्तान को अखंड रखने में कामयाब हुए हैं। उनकी मौत कोई हादसा तो थी नहीं। यह एक ऐसी उनकी आकांक्षा थी जिसको उन्होंने पूरा करने के लिये कि मेरा देश महफूज रहे, मेरे देशवासी महफूज रहें, उस रास्ते को चुना अपनी

(श्रीमती जकिया)

मर्जी से। चालीस प्लस की उम्र में उन्होंने वीरगति प्राप्त की। देश को शहादत का तोहफा दिया। बहुत यंग ऐज थी।

'एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, बहुत तेज जिन्दगी गुजरी है शायद।' हम लोग उनका नाम कुछ मिशन में जोड़ते हैं वह इसलिये नहीं कि उनको अलंकृत करें या उनकी तारीफ करें। हमारा मकसद यह है कि आने वाली जनरेशन जब उनका इतिहास पढ़े तो उनके खून में भी देशभक्ति का बलबला पैदा हो कि उनका भी जन्म देश के लिये हो और उनकी भी मौत शहादत की हो इसलिये इनके नाम को जोड़ा जाता है। राजीव गांधी जी की शहादत अविस्मरणीय इंसीडेंट था।

उप नेता महोदय, मैं आपकी तवज्जोह चाहूंगी। जो जिस शान से मकतल तक, मकतल का मतलब कत्लगाह-

'जो जिस शान से मकतल में गया, वह शान तो बाकी रहनी है।

इस जान की क्या कीमत है, यह जान तो आनी-जानी है।'

मैं थोड़ा तल्ख बोल रही हूं इसलिये आप लोग माफ करेंगे। आप लोग एहसास-ऐ-कमतरी से थोड़ा ऊपर उठिये। अब आपकी पार्टी के किसी महापुरुष को यह स्थान नहीं मिला तो इसका कोई इलाज तो है नहीं और मुझे आने वाले समय में भी ऐसी सम्भावना नहीं दिखती।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): एक आध तो पैदा करो।

श्रीमती जकिया (टोंक): अब बजट पर बात कर लें। 2010-2011 का बजट आम आदमी और आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को समर्पित है, ऐसा मेरा दृष्टिकोण है। आज की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है पानी और बहुत बड़ा बजट कृषि के लिये 777 करोड़ 58 लाख अलाट हुआ है। इसके अलावा सी एस एस में भी हुआ है।

पीने के पानी के लिए भी 1100 करोड़ का। मैं इन सबके ऊपर मुख्य मंत्री का धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने टौंक की जनता का खयाल करके 10 करोड़ की योजना से टौंक शहर को पानी के लिए स्वीकृति दी है, डेढ़ महीने के अन्दर-अन्दर वहां पानी पहुंच जाएगा।

(श्रीमती जकिया)

सभापति महोदय, अभी लोगों ने बहुत बड़ी-बड़ी योजनाओं की बात की, मैंने इस बजट के लिए कहा था कि पंक्ति में आखिरी खड़े हुए आदमी की भी फिक्र की गयी है। बीपीएल की तरफ, गरीब आदमी की तरफ, विधवा की तरफ, मरीज की तरफ कौन देखता है? ख्याल भी नहीं आता जब हम सफर में आगे बढ़ते हैं और कामयाबी सामने देखते हैं। मगर यह कांग्रेस गवर्नमेंट है, अशोकजी की सरकार ने इसको टाप प्रायोरिटी पर लिया और बीपीएल के 26 लाख लोगों को 28 करोड़ रुपये की दवाइयां दीं और इलाज फ्री में करवाया। उप नेता महोदय, आप बहुत अच्छे से उस पीड़ा को समझ सकते हैं, जिस घर में एक मरीज हो और उस घर में पैसा भी न हो, उस घर की क्या मनोदशा होती है। अब यह बजट बढ़कर 60 करोड़ किया गया है, यह वही दर्द है जो एक इंसानियत के नाते कोई इंसान महसूस कर सकता है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती जकिया (टोंक): 108-एम्बुलेंस के लिए 37 करोड़ रुपया अलॉट हुआ है, बहुत छोटी सी बात लगती है सुनने में। मगर चार दिन पहले मैंने निवाई में नजारा देखा है, यह 108-एम्बुलेंस नहीं है, एक ट्रेक्टर से सवारी गाड़ी की टक्कर हुई, तीन तो वहीं मृत हुए और 15 घायल हुए, ले जाने की व्यवस्था करना कयामत से कम नहीं था। इन मानवीय पहलुओं की भी आप लोग कम से कम तारीफ तो करें कि एक मुख्य मंत्री ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको सोचा है, इसकी तरफ कदम बढ़ाया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, मैं तो उनकी क्या तारीफ करूं, आपकी करता हूं।

श्रीमती जकिया (टोंक): वह तो जमाना गुजर गया, साहब। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं तो पुराने जमाने की याद कर रहा हूं, जकियाजी।

श्रीमती जकिया (टोंक): वह सीकर की बात है। (व्यवधान) ग्रामीण नर्सेज का पे-स्केल बढ़ाया, ग्रामीण नर्सेज का वेतन बढ़ाया, इसके पीछे कितनी दूर की मंशा है कि वह ग्रामीण महिला या वह बच्चा जो अस्पताल तक नहीं जा सकता है, वह क्या करेगा। जब उनके पे-स्केल बढ़ जाएंगे तो वे वहीं स्टे करेंगी, यह एक सक्रिय सोच है। इसी तरह जयपुर से लेकर के कोटा तक के राज मार्ग में कहीं भी आईसीयू नहीं था, टौंक में आईसीयू खोला है।

सभापति महोदय, अकाल पर विपक्षी सदस्यों को बहुत बड़ी चिंता है। आपको इतनी चिंता क्यों है? 2001-02 देखा हुआ है आपका, बहुत भयंकर अकाल था। हर पंचायत समिति पर अकाल राहत कार्य के अलावा 5 बोरी अनाज रखा गया था और हर पंचायत पर एक बोरी अनाज था जिससे कि कोई भूखा नहीं रह सके। आप विश्वास कीजिये इस वक्त भी राजस्थान का कोई बंदा न तो भूखा रह सकेगा और न प्यासा रहेगा, ऐसी कांग्रेस गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर सम्भव कोशिश करेगी।

सभापति महोदय, पीड़ित जो कपल होता है उनके बच्चों की दुर्दशा आप अच्छे से समझ सकते हैं कि समाज में उनका क्या स्थान है, उनको भी मुख्य मंत्रीजी ने पैसा देने की घोषणा की है।

श्री सभापति: कृपया आपस में बात न करें।

श्रीमती जकिया (टोंक): अब मैं मुस्लिमों पर आऊं, आप लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं कि इस तरफ कुछ किया जाना चाहिए। यहां प्री मैट्रिक 17 हजार थीं, अब 60 हजार स्कालरशिप होंगी। 5 आईटीआई जहां मुस्लिम बहुल एरिया होगा, वहां खोली जाएंगी। दस्तकारों की भी योजना है। सरकार देखना चाहती है कि हर तबके का इंसान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आगे बढ़ सके, उसमें सरकार पूरा सहयोग करने के लिए कटिबद्ध है।

सभापति महोदय, सहकारिता विभाग टोटल ही किसानों से जुड़ा हुआ है, पिछले साल 16 लाख किसानों को ऋण दिया गया था, इस साल 21 लाख का टारगेट रखा गया है। 5 हजार करोड़ रुपया लोन दिया जाएगा। यह शोर्ट टर्म लोन होगा और किसान अपनी जरूरत पूरी कर सकेगा।

सभापति महोदय, अब महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के नाम पर सबसे पहले तो राज्य सभा में जो 33 प्रतिशत का बिल पास हुआ है,

(श्रीमती जकिया)

उस पर सदन को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी, इसमें सबका ही कोआपरेशन था। मगर महिला को अगर आगे बढ़ना है तो खुद को ही अपनी हिम्मत पर आगे बढ़ना होगा। 'अपने अंधेरों का खुद इलाज करो, कोई चिराग जलाने इधर नहीं आएगा'। वह अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, एजुकेटड होती है तो घर में, समाज में कहीं भी वह इज्जत पाने की हकदार होगी। वर्ना वह किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की बहिन, किसी की मां इन नामों से ही चिह्नित की जाएगी और जितने जुल्म आज हो रहे हैं वह किसी से छुपे नहीं है, आगे इन जुल्मों में इजाफा भी हो सकता है। औरत को चारदीवारी में बांधने के लिए बहुत लम्बी साजिश की तरह घूंघट में रखा गया। घूँघट जब तक नहीं हटेगा, औरत आगे कैसे बढ़ेगी। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, किसी चीज को जब छुपाया जाता है, या तो वह बदशक्ल हो या कोई ऐबदार हो या कोई डिफैक्ट हो। इस कायनात की सबसे खूबसूरत शै अगर खुदा ने कोई बनायी है तो वह औरत बनायी है, फिर उसको पर्दे में रखकर घूंघट निकालने का मकसद मेरे अभी तक समझ में नहीं आया है। 'तेरे रूख पर यह आंचल बहुत ही खूब है।

लेकिन तू इसे परचम बना लेती तो अच्छा था'।

एक माननीय सदस्य: एक दीवाने को दीवाना बना दो ...(व्यवधान)

(समय : 17.0 0 बजे)

श्रीमती जकिया (टोंक): इंट्रेस्टेड नहीं हूं।

अब बी जे पी की बात कर लें, आंकड़ों का मायाजाल जो मैं कल सुन रही थी, उससे सदन तो अचम्भित हो सकता है मगर सरकार नहीं चल सकती। आपने बड़ी-बड़ी स्पीचों में कहा, हमने यह किया, वह किया। मुझे अभी तक परिसम्पत्तियों का मतलब समझ में नहीं आया। परिसम्पत्तियों में मुझे शराब की दुकानें दिखती हैं...।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): परिसम्पत्तियों से मतलब परियों की सम्पत्तियां।

श्रीमती जकिया (टोंक) : या साइड पर दीवारों पर चित्रकारी दिखती है। इससे किसी गरीब का पेट नहीं भरता। आपने जयपुर में एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ी, यह आपकी उपलब्धि है। बार्डर बेच दिया यह इससे बड़ी उपलब्धि है। आपका राज 1990 से 1998 और अभी पिछले पांच सालों में देखा है, और वह कितना नाकामयाब था, यह जनता ने तस्दीक किया है चुनावों में मोहर लगाकर। अब मैं दो लाइनें पढ़ कर खतम कर रही हूं, उप नेताजी।

(श्रीमती जकिया)

न शमशीर उठेगी, न खंजर उठेगा।

ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): भावुक हो जाएंगे उप नेताजी।

श्री सभापति: श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): उप नेताजी घायल हो जाएंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांति बनाए रखें सदन में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर):

जरूरत क्या है तुम्हें तलवार, तीरों और कटारों की,

नजर भर कर जिसे तुम देख लेती हो, वह यूं ही मर जाता है।

श्री सभापति: सम्माननीय राधेश्यामजी गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर परसों यहां बजट प्रस्तुत किया विधान सभा में उस पूरे को उन्होंने सवा दो घंटे में पढ़ा। मेरे ख्याल में, मेरी दृष्टि में हो सकता है कि मैं गलत होऊं, वह एक असत्य का पुलिंदा था। पिछले साल जो घोषणाएं हुईं। वे चीजें ही पूरी नहीं हुई और आज उसको आगे पढ़ कर बता दिया। सबसे पहले पेज पर उन्होंने रोड्स को लिया है, बी ओ टी वाली हमारी तरफ कहावत है कि माल तो मालिकों का और मशहूरी कम्पनी की, तो पैसा तो आएगा भारत सरकार से और सबसे पहले आप वे चीजें दिखा रहे हो, बजट में पढ़ रहे हो, ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके, लोगों को कैसे जताया जा सके कि हम इतनी सड़कें बना रहे हैं प्रदेश में। प्रश्न इस बात का है कि जो भी उन्होंने घोषणाएं की हैं, एक भी घोषणा, एक स्कूल नहीं, बड़े गजब की बात है, एक हास्पिटल नहीं, एक पशु चिकित्सालय नहीं, और एक कृषि उपज मण्डी में एक सड़क नहीं। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): राधेश्यामजी के गंगानगर में नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं तो मेरी बात कर रहा हूं जी, गंगानगर की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): पशु चिकित्सालय बहुत सारे खोले गए हैं, पढ़ो तो सही आप बजट को।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय, मैं अभी आपको बताऊंगा, फिर आप कहना, आप तो मेरे बड़े प्यारे भाई हो, मेरे साथी लोग हो।

श्री सभापति: आप गंगानगर की बात कर रहे हो न?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय सभापतिजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बजट में हमारे पास कोई फण्ड्स की कमी थी तो कम से कम हास्पिटल्स में डाक्टर्स, कम से कम स्कूलों में टीचर, आपके एक जगह बच्चे तो हैं 80 और टीचर है एक और बच्चे हैं 14 टीचर हैं वहां 8 और समानीकरण की दुहाई दे रहे हो। साल भर हो गया, करोड़ों रुपए लोगों के बर्बाद हो गये, वह समानीकरण कहा गया, क्या हो गया उसको, कोई ले गया उसको उठा कर? आज तक समानीकरण नहीं हुआ, क्या कारण था इसका?

अभी बात की इन्दिरा गांधी कैनाल की कि वहां 35 हजार एकड़ जमीन को सिंचित करेंगे। आपके पास पानी की एक बूंद नहीं है तो 35 हजार एकड़ नए एरिये को कहां से सिंचित कर देंगे? बड़ी गजब की बात है। इतनी बड़ी असत्य बात कहना सदन में और वह भी मुख्य मंत्रीजी के मुंह से जो गांधीवादी व्यक्ति हो, मुझे तो अचम्भा है कि यह कहलवाया गया है। उनकी कही हुई बात नहीं है, कैसे सिंचित करेंगे, जब पानी आपके पास है नहीं। माननीय सभापति महोदय, आप अगर मेरे साथ चलो, आपको दिखाएं कि पंजाब के सेम का जो पानी है, पंजाब के सीवरेज का जो पानी है, फैक्ट्रीज का जो पानी है मात्र वही कैनाल में चल रहा है। उस पानी को पीने से आने वाले समय में वहां बड़ा भयंकर पीलिया रोग फैलेगा, बड़ी भयंकर हालत खराब हो जाएगी।

गंग कैनाल की लेनिंग के लिए पहले जो 465 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, वह गंग कैनाल की मेन लेनिंग कहां गई? खालों के ऊपर किसानों से 10 प्रतिशत लेकर 90 प्रतिशत गवर्नमेंट पे करती थी, वह पैसा कहां गया? पीने वाले पानी के लिए आज से 50 साल पहले जो पाइप लाइन डाली थी वह जर्जर हो गई, उसमें गंदा पानी मिक्स होकर जा रहा है, उसके लिए आपके

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

पास कोई पैसा नहीं है। मैं तो यही कहता हूं कि बड़ी अजीब बातें, ऐसी-ऐसी बातें कही गई हैं कि सुनकर आदमी हैरान होता है।

बिन्दु संख्या 141 में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने जा रहा है हमारा प्रदेश, चार घंटे बिजली नहीं आती सारे प्रदेश में। बिजली है? बोलो गंगानगर के भाइयों, गंगानगर में बिजली 4 घंटे आती है या नहीं? क्या कारण है? गंगानगर से ऐसी क्या नाराजगी है? पूरे राजस्थान में बिजली रहे और गंगानगर में बिजली नहीं रहे। माननीय मंत्री महोदय, एक दिन मैंने आपसे निवेदन किया था, आपने आदेश किया, मैं वहां धरने पर बैठा और दूसरे दिन पता नहीं बिजली कहां से आ गई। अब भी आप उसी तरह से करो, गंगानगर को इस तरह से अछूता मत समझो।

बिन्दु संख्या 24 इन्दिरा गांधी नहर वाली बात जो कि मैं प्रस्तुत कर रहा था, इसके अंदर बड़ी भारी सिल्ट है, सिल्ट छह-छह फीट जमा हो गई है, उस सिल्ट को निकालने के लिए बजट में कोई पैसा नहीं रखा गया है। पूरी दुनिया के अंदर स्वेज नहर के बाद राजस्थान की इन्दिर गांधी नहर है। इसको पर्यटन की दृष्टि से अगर आगे बढ़ाना है तो यह धोरों की धरती है, पूरी नहर के अन्दर स्टीमर चलें, चारों तरफ हरियाली हो और जगह-जगह कहीं तो गोल गप्पे वाले खड़े हैं, कहीं कुल्फी वाले खड़े हैं, कहीं डांस हो रहा है। पूरी की पूरी यह धोरों की धरती, दुनिया को यह पता लगे कि गंगानगर जिला, बीकानेर जिला, जैसलमेर जिला, बाड़मेर जिला, किस तरह से लोग वहां अपनी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं, तो ट्यूरिज्म से कमाई होगी, हमारे लोग काम में लगेंगे। दुनिया की दूसरे नम्बर की नहर सारे वर्ल्ड में। अगर मैं कह रहा हूं कोई गलत बात तो आपकी तरफ से जवाब दे दो और योजना थी कि इसके अन्दर स्टीमर चलेंगे ...(व्यवधान) भाइयों, कमाल की बात तो यह है कि इसके अन्दर छह-छह फीट सिल्ट है, वह सिल्ट नहीं निकाली जा रही है। हमारे जो बड़े-बड़े टैक्निकल लोग थे, कई दफा मन में बड़ी तकलीफ और दु:ख होता है कि उन लोगों ने इसका डिजाइन किया 18440 क्यूसेक्स का और वह लेता नहीं है 14000 क्यूसेक्स भी, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? आपने पेमेंट किया 18400 क्यूसेक्स का, चाहे सरकार किसी की रही हो।

प्रश्न इस बात का नहीं है, जो अधिकारी इस तरह करके चले जाते हैं वो तो चले जाते हैं पर दु:ख जनता को भोगना पड़ता है।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

सभापति महोदय, कि बिन्दु संख्या 44 में आपने चिकित्सा के लिए बातें लिखी हैं, 10 जिलों के अन्दर एक भी जिला ऐसा नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं खुला। मैंने पहले भी यह बात कही है। लेकिन डाक्टरों का अभाव, नर्सेज नहीं हैं, स्टाफ नहीं है। गरीब आदमी को, जो बीपीएल के लोग जाते हैं उनको कोई जेनरिक दवाई नहीं मिलती। पांच रुपये का जो पत्ता होता है वह 40 रुपये में मिलता है और गरीब आदमी लेकर जाता है। तो यह गवर्नमेंट बैठी-बैठी क्या कर रही है। आप कह रहे हो कि दो रुपये किलो अनाज कर दिया, बधाई हो, मुख्य मंत्रीजी ने एक सराहनीय काम किया। हमारे नेता महोदय ने कल भी कहा था, लेकिन इधर श्रवणजी बोले थे कि दो रुपये किलो वाला सारा ही दूसरे चाट जाएंगे। इधर से आयेगा और ट्रक सीधा दूसरी जगह पहुंच जाएगा, तो किसको मिलेगा? मिलने की व्यवस्था करो कि गरीब के लिए जो चीज आए, वह उस तक पहुंचे। वह उस तक पहुंचनी चाहिए। आपने कहा कि आटा देंगे, वह पता नहीं कौनसी कणक का आटा है। पहले कोई एक कणक आया करती थी आस्ट्रेलिया से लाल रंग की कणक, सफेद रंग की कणक और उसकी रोटी ऐसी हो जाती थी कि कोई खा ही नहीं सकता था, जैसे रबड़ चबाना पड़ता है वैसी होती थी। अब पता नहीं ये कौन से गेहूं हैं और आटा पिसवाकर देंगे। आटे की पिसाई क्या है? दो रुपये किलो, तीन रुपये किलो। गजब की बात है, सड़ा हुआ अनाज और उसका आटा। आप वाहवाही तो लूटना चाहते हो, गरीबों के लिए भला तो कर रहे हो लेकिन भला दिखना चाहिए, गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे सारे साथियों ने यह बात कही है और खासकर हमारे नेता गुलाबजी ने जो आंकड़े कल प्रस्तुत किये, सारा का सारा हाउस इस बात को देखता रहा। विद्वान आदमी जो इस हाउस की सम्पत्ति है, जो व्यक्ति ज्ञान देता है हमें 200 के 200 विधायक महोदय को और मंत्रियों को, वह चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसे पूछना चाहिए। उन्होंने एक ऐसी चीज कही कि थोड़ी देर बाद ही वो बात जो बोल ही रहे थे, टीवी बोल गया कि एक प्रतिशत कम। कमाल की बात है, सभापति महोदय। हमारे नेता महोदय ने यह बात कही, मुझे बताई कि देश के प्रधान मंत्री ने किसी चीज में एक पैसा, दो पैसा घटा दिये या बढ़ा दिये तो लोगों ने हाउस के अन्दर पूछा, प्रिविलेज उनके ऊपर दायर कर दिया। लेकिन प्रिविलेज इसलिए नहीं चल पाया कि वो राज्य सभा के मैम्बर थे। यह एक कानूनी प्रक्रिया है। हाउस की सम्पत्ति को हाउस के बाहर जाकर, हमारे अनेकों नेताओं ने कहा है और यह बात सरकार ने स्वीकार

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

भी की है। बड़ी गजब की बात है कि हमारे अधिकारी इस तरह हमारे मुख्य मंत्री से उनके मुंह से बात कहलवा लेते और एक घंटे बाद जब इधर प्रति पक्ष की तरफ से कोई बात आए तो उसको सुधारने का काम किया जाए। क्या हमारे अधिकारी बंधु यह नहीं समझते थे, फाइनेंस को कब से देख रहे हैं? इन-इन चीजों पर भारत सरकार के बिना आप कर ही नहीं सकते तो आपने कैसे कर दिया। बड़ी विडम्बना है और बड़ी अजीब बात है कि इस तरह की बात हो जाए।

अभी सवाल आता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कृषि उपज मण्डियों को बहुत डिग्गियां दे दीं, बड़ा अच्छा काम किया, सराहनीय कदम है। जितनी चाहें उतनी डिग्गी आप अपने खेत में बनाओ क्योंकि पानी की कमी है। लेकिन उसके ऊपर कनेक्शन लेने के लिए आप ट्रांसफार्मर लेंगे तो 90 हजार रुपया देना पड़ेगा। ''न नौ मण तेल और न राधा नाचे।'' दो कनेक्शन हुए, सिर्फ दो कनेक्शन हुए। हजारों डिग्गियों के ऊपर दो कनेक्शन, क्या इसके ऊपर आप विचार नहीं करोगे? पानी आपके पास है ही नहीं, कुदरत आपसे नाराज है। मैं तो मुख्य मंत्रीजी को और आप सब से एक प्रार्थना करूंगा कि एक बहुत बड़ा यज्ञ करो। जैसे महारानी किया करती थीं, महारानी के टाइम में कभी अकाल नहीं आया। आप आते हो तो अकाल साथ में लाते हो। कृपा करके अपन सब लोग बैठे हैं, भगवान को मनाएं और इस अकाल से पीछा छुड़ाएं, ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें अब आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय सभापति महोदय, अभी शुरू ही नहीं किया।

श्री सभापति: नहीं, यह व्यवस्था आपके सचेतक महोदय ने दी है उप नेता की उपस्थिति में जब कालीचरणजी बोल रहे थे कि उसके बाद में टाइम बाकी का कम हो जाएगा। मैं तो आपको सिर्फ निवेदन करता हूं, आप ही का टाइम है, मेरे लिए तो रात भर बैठे हैं, मुझे, आसन को कोई एतराज नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): बिन्दु संख्या 139 में श्रम एवं रोजगार के सम्बन्ध में निवेश करने की बात जो कही गई है, उसमें एक नौकरी नहीं किसी को। पूरे इस बजट में कहीं भी पढ़ने में नहीं आया। जो नौकरी आपने दी है, जो लोग रिटायर हो गये उनको आपने सर्विस दी है। वह तो देनी ही थी, कोई आपने मेहरबानी नहीं की। लेकिन नया क्या कुछ किया

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

आपने? आपने क्या गुल खिलाया नया जिस पर तालियां पीट रहे थे? खास कर मेरे छोटे भाई बाबूलालजी तो ऐसे ताली दोनों हाथों से बजाते हैं, मजा ले लेते हैं। ताली बजाने से सेहत ठीक होती है, यह बात तो बिलकुल ठीक है, लेकिन जनता को क्या लाभ मिल रहा है, गरीब तक क्या चीज पहुंच रही है इस पर हम सब लोगों को बैठकर विचार करना चाहिए। हम इधर से बोलें चाहे उधर से बोलें, हम एक दूसरे की मजाक उड़ाकर चले जाते हैं और उस मजाक में वह बात चली जाती है। सम्माननीय मंत्री महोदय, आपने इण्डस्ट्री के लिए क्या किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरे बजट में आपने इण्ड्स्ट्री के लिए क्या किया? आप बताओ। आज हमारा गंगानगर जिला रो रहा है, हजारों किसान चले गये। हमारी जो काटन मिल जेसीटी थी वह बंद हो गई, काटन काम्प्लैक्स बंद हो गया, शुगर फैक्ट्री के लिए आपने एक पैसा नहीं रखा। पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने 125 करोड़ रुपया बजट में रखा था, वह कहां गया? किधर चला गया, उसका आपने जिक्र नहीं किया। मुझे एक बात याद आती है, इसी सदन की बात है, ये राजेन्द्र सिंहजी बैठे हैं, मैं तो उधर होता था, मैं कांग्रेस का एमएलए था और भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे, तब मैंने अपने यहां इस हाउस में गंगानगर की समस्या रखी थी कि सीवरेज के अन्दर आज गंगानगर जिले की बहुत बुरी हालत है, सड़कों में 3-3 फीट पानी है। उस वक्त 84 आदमी पीलिया से मरे थे। मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी को कि उन्होंने दो मंत्रियों की वहां पर ड्यूटी लगाई। एक तो राजेन्द्र सिंहजी मौजूद हैं यहां और एक हमारे भंवरलालजी शर्मा स्वायत्त शासन मंत्री थे, उनकी ड्यूटी लगाई। ये गये तब मैंने इनको 25 किलोमीटर पैदल घुमाया और सारे शहर की हालत दिखाई। उस हालत को देखने के बाद मुख्य मंत्रीजी ने यह तय किया कि इसका सर्वे कराया जाए। चीफ इंजीनियर, पीएचईडी इसका सर्वे करेगा और यहां सीवरेज स्कीम लागू की जाएगी।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। आपने यह बात पहले भी कह दी है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सीवरेज स्कीम लागू की जाएगी लेकिन 1993 से लेकर 1998 और आज 2010 हो गया, वह सीवरेज स्कीम आपके पहले बीजेपी सरकार में भारत सरकार ने मंजूर कर दी और आपने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि टेंडर मंजूर हो गये। टेंडर होने के बाद जमीन एक्वायर कर ली, गंगानगर की जनता के अपने पैसे से जमीन एक्वायर

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

करने के बाद क्या हुआ कि आज उस सीवरेज प्रोजैक्ट का कहीं लेना-देना नहीं है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय सभापति महोदय, यह पीड़ा है, आप सुनिये, आपके इलाके में भी पीड़ा होती है। मैं रेलवे ओवर ब्रिज की बात करता हूं। मैं 1980 में एमएलए बना था तब से रो रहा हूं और परसों मैंने एक प्रश्न लगाया था तो यह जवाब आया है कि रेलवे ब्रिज बनने की जगह नहीं है। वाह जी वाह, यह बड़ा गवर्नमेंट का जवाब है। हनुमानगढ़ में दो बन सकते हैं, गंगानगर का फाटक तीन घंटे बंद रहता है, पंजाब, हरियाणा जाने के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। तीन घंटे तक जाम में अगर किसी महिला के बच्चा होने वाला हो, परली तरफ भी आबादी है, परली तरफ भी गांव हैं.....

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): तीन ब्रिगेड हैडक्वार्टर हैं आर्मी के और वह घंटों बंद रहता है। पर आप इसलिए वहां नहीं करना चाहते क्योंकि वहां से राधेश्याम जीत गया। वहां आपने नगर परिषद हारी, वहां आपने जिला परिषद हारी, वहां आपने पंचायत समिति हारी, वहां सरपंच हारे, वहां आप भूमि विकास बैंक में हारे, वहां आप गंगानगर सहकारी बैंक में हारे इसलिए बदला लेना चाहते हो। यह आपकी बदला लेने की बात है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): लेकिन गंगानगर की जनता चुप नहीं बैठेगी। नरेगा की बात करते हैं, बहुत अच्छा काम है नरेगा का और नरेगा में पैसा आपने बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात की। लेकिन नरेगा को किसान के साथ जोड़ो, पक्के कामों के साथ जोड़ो। नरेगा में पंगु न बनाओ गरीबों को। यह नहीं कि यहां से उठाया, यहां फेंक दिया, पैसा दे दिया। जाब कार्ड का पैसा खा रहे हैं सरपंच या कोई। जाब कार्ड बनते नहीं है। उस नरेगा को अगर किसान के साथ जोड़ दो, 50 प्रतिशत किसान से लो, 50 प्रतिशत आप दो, आपकी रेशो डबल हो जाएगी और किसान खुशहाल हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा उपज होगी, ज्यादा से ज्यादा अनाज आएगा। राजस्थान को सबसे बड़ा कोई रेवेन्यू देने वाला इलाका है तो हनुमानगढ़-गंगानगर है, आप आंकड़े

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

उठाकर देख लो। सबसे अधिक टैक्स देता है, सबसे ज्यादा पैसे देने वाला, रेवेन्यू देने वाला...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें अब आप। अभी अंकित नहीं होगा। आप सहयोग करें, माननीय सदस्य। यह पहले ही से व्यवस्था दी हुई है। पहले ही से इतने सारे लोग बाकी हैं अभी, वे बोल नहीं पाएंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं थोड़ी देर में खतम कर रहा हूं। जैसा आप आदेश देंगे, मैं आपके आदेश की पालना करूंगा।

श्री सभापति: आप, सचेतक महोदय, यहां पर अपना सहयोग दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ये थोड़ी देर में अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। ये कनक्लूड कर रहे हैं।

श्री सभापति: वह कोई बात नहीं है लेकिन वे रह जाएंगे बाद में। ठीक है। मैंने आपको बता दिया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): गजब की बात यह है कि आज तक कभी नहीं सुना। बिलोने की खल, उसका 50 रुपये रेट, क्या वह किसान ले जाता है या व्यापारी ले जाता है? व्यापारी तो जेब काटता है, किसान रोता है। 50 रुपये खल आज तक नहीं बढ़ी। गजब की बात है यह, किसने सोचा? किसने किया, क्यों किया, इसमें आप जरा तरीके से मनन करो और इस बात को वापस लो। कोई शर्म की बात नहीं है कि जो गलती से किसी ने लिख दिया, उस पर मान लो।

अब बताओ, रेडीमेड वस्त्र पर 14 प्रतिशत कर दिया, चार को 14 प्रतिशत कर दिया, इतना जुल्म। चार से 14 प्रतिशत किया, हमारा बोर्डर का इलाका है, हरियाणा में दो प्रतिशत, दिल्ली में दो प्रतिशत, पंजाब में दो प्रतिशत है। यहां पहले चार प्रतिशत था, अब 14 प्रतिशत कर दिया आपने। डीजल की यह हालत है, ये कहते हैं कि महंगाई कम हो। महंगाई कम कैसे होगी, सभापति महोदय? महंगाई कम होगी तब, जब पंजाब में चार रुपये डीजल कम है, एक लीटर पर चार रुपये कम मिलता है और पैट्रोल कम मिलता है तो मेरे मित्रों, इधर भी बैठे हो, आप भी कृपा करो। यह आपके भी मतलब की बात है। डीजल की रेट कम होने से महंगाई कम होगी, किसान खुशहाल होगा और आपको वोट मिलेंगे।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें आप, आप सहयोग करें अब। Please kindly cooperate.

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। श्रीमती अंजू खंगवाल। मैंने आपको कई बार निवेदन किया है, समाप्त करें। समाप्त करें। आप तो सहयोग ही नहीं कर रहे हैं और आसन का मान भी नहीं कर रहे हैं। आप कृपया विराजें। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कृपया विराजिये अब आप। समाप्त, समाप्त।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: बिलकुल समाप्त।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):×××

श्री सभापति: समाप्त, समाप्त। I had said it please, समाप्त करें अब आप। बहस खतम। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आदरणीय माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):×××

श्री सभापति: श्रीमती अंजू खंगवाल।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): Thanks for encouraging me. माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में पहली बार बोल रही हूं लेकिन मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलते हुए एक साल से सुन रही हूं और मैंने महसूस किया है कि सभी माननीय सदस्य बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन सब बोलते ही हैं। यहां बैठकर हम सब जो डिस्कस करते हैं समस्याओं के विषय में, पर कितनी समस्याओं का समाधान होता है, यह हम सब जानते हैं। हम प्रश्न पूछते हैं, विभाग उनका जवाब हमें देता है लेकिन उस जवाब का मतलब क्या होता है, यह खुद न हमें समझ आता है और शायद अगर एक बार मंत्री महोदय देखेंगे तो उनको भी समझ में नहीं आएगा। सत्ता पक्ष बोलता है यह दिखाने के लिए कि हमारी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। बोलकर वे खुश हो जाते हैं और सोचते हैं, अपने आप में, मन में खुश हो जाते हैं कि हम

(श्रीमती अन्जू खन्गवाल)

सुपीरियर हैं और विपक्ष भी सत्ता पक्ष की कमियां निकालकर, उनकी बुराइयां निकालकर अपने आपको सुपिरियर समझता है और बहुत खुश हो जाता है। आप दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत सुपीरियर हैं लेकिन उन सुपीरियर का क्या, जिन्होंने आपको अपनी समस्याओं का निपटारा करने के लिए यहां भेजा है? जो हमें एम.एल.ए., मिनिस्टर, सी.एम., पी.एम. सभी कुछ मानते हैं। वे तो आज आपके 60 साल से करते आ रहे वादों के पूरा होने के इंतजार में पलकें बिछाये बैठे हैं। आज गांव में बिजली के खम्भे हैं पर बिजली नहीं है। सड़क हैं पर उनमें सड़कों से ज्यादा गड्ढे हैं। हैण्ड पम्प है, पानी नहीं है। अगर दिल से पक्ष और विपक्ष दोनों जनता के हित में काम करें तो शायद उनका इंतजार किसी हद तक कम हो सकता है। (व्यवधान) आप मुझे प्लीज डिस्टर्ब नहीं करें वर्ना मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं पहली बार बोल रही हूं। आप मुझे सपोर्ट करें, प्लीज डिस्टर्ब नहीं करें। (व्यवधान) अगर विपक्ष अच्छी राय देता है या अपने समय में कुछ अच्छा काम किया है तो क्यों नहीं सत्ता पक्ष उनको एप्रिशिएट करता है? और अगर सत्ता पक्ष कोई अच्छी नीति बनाता है, अच्छा काम करता है तो क्यों नहीं विपक्ष उनको एप्रिशिएट करता है। हम आपस में ही क्यों लड़ते हैं, क्योंकि हम बैठे तो हैं जनता के लिए? गांव में बैठे लोग तो यह सोच रहे होंगे कि इतना पैसा रोज सदन में जो खर्च हो रहा है, शायद हम पर हो रहा है। सिर्फ शायद हम यहां आते हैं, गपशप करते हैं, एक-दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं और वापस चले जाते हैं, यह मेरा मानना हे।

माननीय सभापति महोदय, मैं भी अपने भाषण को राजनैतिक आलोचना से परे रखने का पूरा प्रयास करूंगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2010-2011 का बजट पेश किया है उसमें गरीब, महिलाओं, बच्चों, युवकों, बुजुर्गों, सभी के लिए कुछ न कुछ दिया है और आज के इस अकाल और मंदी के समय में भी इतना शानदार बजट पेश करने के लिए मैं उन्हें बधाई देती हूं। बी.पी.एल. परिवारों को 4.70 रुपये प्रति किलो के स्थान पर दो रुपये प्रति किलो गेहूं देने की उनकी घोषणा यह सिद्ध करती है कि गरीबों में जो सबसे गरीब है, उनके लिए उनके मन में कितना दर्द है। इससे पूर्व बी.पी.एल. के बीमारों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा पूर्व में ही आप द्वारा उपलब्ध कराई गई थी और उसके तहत 26 लाख व्यक्तियों को जनवरी, 2009 से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यही नहीं, इन सबसे आगे बढ़कर अब बजट में

(श्रीमती अन्जू खन्गवाल)

आपने यह व्यवस्था दी है कि बी.पी.एल. परिवारों को उन निजी चिकित्सालयों में जो सस्ती दर पर जमीन लेते हैं, नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

मैं मुख्य मंत्री महोदय का इसलिए भी आभार प्रकट करना चाहती हूं कि उन्होंने सभी तरह के बुजुर्गों की तथा विधवा, विकलांगों की पेंशन दरों में बढ़ोतरी की है। कितनी आदर की भावना है उनमें, यह इसका एहसास कराती है।

सभापति महोदय, यह आपको जानकारी होगी कि राजस्थान और अकाल का चोली-दामन का साथ है और किसान इन सबसे कितना पीड़ित और दु:खी है, इसके लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु उनके दर्द को कम करने के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो पिछले वर्ष पहले सात और बाद में 10 जिलों में लागू की गई थी, इस खरीफ फसल वर्ष 2010 से सम्पूर्ण राज्य में लागू करने की घोषणा राजस्थान के करोड़ों किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने का एक महती प्रयास है और इसकी जितनी सराहना की जाए, उतना कम है। अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों के नुकसान की शत-प्रतिशत भरपाई भी हो सकती है, यह बहुत बड़ा काम आपने किया है, जिसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का कस्बा बस्सी एवं अन्य कई गांव जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में पिछले 10 वर्ष से अधिक समय से हैं परन्तु इन 10 वर्षों में जयपुर विकास प्राधिकरण ने बस्सी के विकास के लिए कुछ नहीं किया है,

जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में आने के बाद यह वादा किया गया था कि जयपुर के साथ-साथ उप नगरीय कस्बे के रूप में बस्सी का विकास किया जाएगा, परंतु जेडीए के लिए जयपुर की नगरीय सीमा के बाहर पाँच सौ से अधिक गांव उसके उपनिवेश से अधिक नहीं है, इन सभी गांवों की जमीन तो जेडीए ने ले ली और उनसे कमाई करके जयपुर में खर्च कर रहे हैं जबकि वह सारे गांव और कस्बे उपेक्षित हैं। अंत में, मैं मुख्य मंत्रीजी से मांग करती हूं कि जेडीए की कुल आमदनी का एक निश्चित प्रतिशत संबंधित कस्बों और गांवों पर खर्च किया जाना चाहिए और बस्सी में रेलवे लाईन पर शीघ्र ही आरओबी की स्वीकृति जारी की जानी चाहिए, इसका लगभग 21 करोड़ का एस्टीमेट बन चुका है, मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि जेडीए के इसी बजट में

(श्रीमती अन्जू खन्गवाल)

इसको स्वीकृति दिलायें। सभापति महोदय, इस वर्ष की सबसे बड़ी चुनौती लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना है, बल्कि मैं तो यह कहूं कि इस वर्ष ही नहीं, आने वाले वर्षों में भी सबको स्वच्छ जल उपलब्ध कराना न केवल राजस्थान का बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान के लिए सबसे बड़ी समस्या और चुनौती बनने वाली है जिसके लिए आपने नई जल नीति भी तैयार की है और पेयजल प्रबंधन के लिए सुझाव भी आमंत्रित किये हैं। मैं अपने आज के भाषण को मूल रूप से इसी पर केन्द्रित करना चाह रही हूं और मैं तो आसन से यह अनुरोध भी करना चाहूंगी कि कम से कम दो दिन इस सदन में सिर्फ पेयजल प्रबंधन और उसके अधिकतम उपयोग पर ही पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विचार हो और उसके अनुरूप नियम-कानून बनाकर कठोरता से कार्यवाही की जाय। यह सम्भव नहीं हो, सभापति महोदय, सत्र समाप्ति के तुरंत पश्चात् इस पर विधान सभा में एक सेमीनार आयोजित की जावे जिसमें पेयजल प्रबंधन के एक्सपर्टस को आमंत्रित किया जाय, सरकार उस सेमीनार की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करे। माननीय सभापति महोदय, आज भी पीने योग्य पानी की उपलब्धता इतना बड़ा संकट नहीं है जितना उसके दुरूपयोग ने संकट बढ़ा दिया है। मैं इसे आंकड़ों से सिद्ध करने का प्रयास करूंगी। सम्पूर्ण राजस्थान में जलदाय विभाग द्वारा जितना पानी सप्लाई किया जाता है उसमें से साठ प्रतिशत पाईप लाइनों से लीकेज, ज्वाइंट के खराब होने, लाइनों के टूटने और अवैध चोरी से बरबाद हो जाता है अर्थात् यदि हम इसे रोक सकें तो वर्तमान पानी से ही दुगनी सप्लाई की जा सकती है। माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां राजस्थान में यह साठ प्रतिशत है वहीं इजरायल में यह सिर्फ 9.7 प्रतिशत है। अकेले जयपुर शहर में ही चालीस करोड़ रूपये का नुकसान सिर्फ लाइनों की लीकेज से होता है और साठ में 29 से 44 प्रतिशत लीकेज, सिर्फ लाइनों से लीकेज है अर्थात् यदि उच्च क्वालिटी की लीकेजप्रूफ लाइनें डाल दी जाये तो लगभग 30 प्रतिशत पानी हम तत्काल बचा सकते हैं और इन लाइनों के बदलने पर आने वाले खर्चे को हम एक साल में ही वापिस प्राप्त भी कर सकते हैं। यही नहीं, सभापति महोदय, शहरों में जितना पानी सप्लाई किया जाता है, उसमें से 90 से 95 प्रतिशत पानी सीवर लाइन में चला जाता है जिसे रिसाइकिल करके वापिस काम में लिया जा सकता है। इजरायल जो कि एक रेगिस्तानी क्षेत्र है अथवा समुद्र का खारा पानी है वह आज पानी के सर्वोत्तम उपयोग के लिए विश्व में नम्बर एक है और वहां पर 75 प्रतिशत पानी रिसाइकिल किया जाता है अर्थात्

(श्रीमती अन्जू खन्गवाल)

यदि शहरों में चालीस प्रतिशत लीकेज रोक दिया जाए और 75 प्रतिशत पानी रिसाइकिल द्वारा प्राप्त किया जाए तो वर्तमान में जो जल सप्लाई किया जा रहा है उसके बीस प्रतिशत से ही काम चलाया जा सकता है और एक साल का पानी पांच साल तक उपयोग किया जा सकता है। या सप्लाई का समय बढ़ा सकते हैं क्योंकि आज चार शहरों में 96 आवर्स, बीस शहरों में 72 आवर्स, छप्पन शहरों में 48 आवर्स और एक सौ छत्तीस शहरों में 24 आवर्स से पानी दिया जाता है। इस अवधि को बहुत आराम से काम में लिया जा सकता है अथवा उस पानी का अन्यत्र उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली में भी बहुत सारी टाउनशिप हैं जहां पर प्राइवेट लोग रिसाइकिल का काम कर रहे हैं। जयपुर जैसे बड़े शहरों में भी यदि सरकार द्वारा धन के अभाव में यह काम नहीं हो सकता तो बड़ी-बड़ी कालोनियों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पर यह कार्य हो सकता है। मानसरोवर जैसी बड़ी कालोनियों में कई प्राइवेट कम्पनियां यह कार्य करने को तैयार हो जाएंगी।

सभापति महोदय, सम्पूर्ण राजस्थान में हम कुल जितना जल उपयोग में लेते हैं उसका 83 प्रतिशत सिर्फ खेती के लिए काम में लेते हैं, अर्थात् यदि खेती में इस जल का उचित प्रबंधन किया जाए तो हम जल समस्या को समाप्त कर सकते हैं। सम्पूर्ण राजस्थान में खेती में ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम अनिवार्य कर दिया जाए क्योंकि नालियां बनाकर खेती करने पर अस्सी प्रतिशत जल व्यर्थ चला जाता है जिसे पूर्ण रूप से बचाया जा सकता है। ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम पर सहायता एवं प्रोत्साहन तो दिया जा रहा है परंतु इस हेतु लम्बी अवधि का कर्जा देकर या अनुदान देकर अनिवार्य कर दिया जाए। एक निश्चित समयावधि में जो किसान ऐसा न करें उनके कनेक्शन काट दिये जाएं और इसे सख्ती से लागू किया जाए। ऐसा करने पर हम बहुत बड़ी बचत कर सकेंगे।

एक सबसे बड़ी बचत वर्षा जल का संरक्षण है, स्टोरेज आफ वाटर, इसके लिए कई वर्षों से कानून बनाने की बात हो रही है लेकिन सिर्फ फाइलों में हो रही है, शायद बना भी हो, पर आवश्यकता सख्त कानून और उसे लागू करने की है। आज हम जनता को तो बहुत भाषण देते हैं परन्तु नब्बे प्रतिशत सरकारी भवनों, मंत्रियों के बंगलों, विधायकों के क्वार्टर्स, अफसरों-कर्मचारियों के बंगलों एवं मकानों में भी हम वर्षा जल संरक्षण सिस्टम नहीं बना पाये हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगी कि इसी वर्ष वर्षा से पूर्व सरकारी भवनों में तो यह सिस्टम तत्काल लागू किया जाए। सभापति महोदय, मेरी जयपुर में

(श्रीमती अन्जू खन्गवाल)

सैकड़ों लोगों से इस बारे में बातचीत हुई, वे सब अपने मकानों में वर्षा जल संरक्षण सिस्टम लगवाना चाहते हैं परन्तु वह सिस्टम कहां से बनवाएं, किससे बनवाएं, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। मैं समझती हूं कि यहां बैठे हुए अधिकांश मंत्रीगण और सदस्यों को भी इसकी जानकारी नहीं है और न ही इनमें से किसी ने भी अपने निजी मकान में यह व्यवस्था की है, फिर हम क्या मैसेज जनता को देंगे? सेविंग अकाउंट खोलने की बजाय वाटर की सेविंग करें तो बैटर होगा, यह मेरा मैसेज है। अत: सरकार इस हेतु फिर तय कर कुछ एजेंसियों को आथोराइज कर दे, शहरी लोगों को इस हेतु ब्याजमुक्त ऋण की व्यवस्था कराए और कारीगरों को यह सिस्टम लगाने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाए। मैं तो यह कहूंगी कि राजस्थान के सभी बड़े, मझले एवं छोटे शहरों में युद्ध स्तर पर वर्षा जल संरक्षण सिस्टम इसी वर्षा से पहले बनाने का अभियान चलाया जाए और इसमें सभी दलों, नगर निकायों, विधायकों, पार्षदों, स्वयंसेवी संस्थाओं की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगी कि 15 अप्रैल से 15 जून तक एक विशेष अभियान, जिस तरह से प्रशासन गांवों-शहरों की ओर अभियान चलाया जाता है, की तरह वर्षा जल संरक्षण अभियान चलाया जाए ताकि आगामी बरसात का अधिकतम पानी बचाया जा सके और अन्डरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ा सकें। अंत में निवेदन करना चाहूंगी कि पानी को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किया जाए और इसका दुरुपयोग अपराध माना जाए। लीकेज वाली लाइनों को बदला जाए और इसके पश्चात् पाइप लाइनों से पानी के नुकसान पर संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। सभी शहरों में सीवर वाले पानी को अनिवार्य रूप से रिसाइकिल किया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक बार तो इधर देख लें पढ़ते हुए।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): सर, फर्स्ट टाइम बोल रही हूं तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको देखने के लिए। (व्यवधान) Sir, it will take me a little time to look at you.

श्री सभापति: कृपया शांत रहिये, कृपया।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): सभी शहरों के सीवर वाले पानी को अनिवार्य रूप से....

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सर, गजब की बात है, इस उम्र में यह अंदाज, मजा आ गया।

श्री सभापति: जब उप नेता ने बात कही तब आप नहीं बोले।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): आज शायद मेरे देखने की जरूरत नहीं है। ये सारे सुझाव हैं, अगर हम इन सुझावों पर ध्यान देंगे तो शायद हमारे राजस्थान का कुछ भला हो पाएगा। जो गरीब जनता गांवों में सब के लिए बैठी है हमारे इंतजार में, उनका कुछ भला हो पाएगा। (व्यवधान) वैल, मैं उसी जगह पर आ रही हूं। सभी शहरों में सीवर वाले पानी को अनिवार्य रूप से रिसाइकिल किया जाए और इस हेतु सभी नगर निकायों में सौ प्रतिशत राशि का अनुदान दिया जाए। अगले दो वर्ष में सम्पूर्ण राजस्थान में हर काश्तकार के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम अनिवार्य किया जाए और इस हेतु पचास प्रतिशत अनुदान राशि तथा पचास प्रतिशत राशि का लम्बी अवधि का कर्जा दिया जाए और उसके पश्चात् उसकी पालना न करने पर कनेक्शन काट दिये जाएं।

श्री सभापति: कृपया छोटा करें अब आप, छोटा करें।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): जी। जिस प्रकार कम उपयोग पर बिजली की दर कम और ज्यादा उपयोग पर ज्यादा है, उसी प्रकार कम पानी के उपयोग पर दर कम और अधिक पानी के उपयोग पर दरें व्यवसायिक दर से ली जाएं। (व्यवधान) घरों में निजी ट्यूबवैल लगाने वाले व्यक्तियों से विशेष जल कर वसूल किया जाए। घरों एवं घर के बाहर घास में पानी देना अपराध घोषित किया जाए क्योंकि घास से कोई फायदा नहीं होता, न किसानों को, न हमें, वह सिर्फ सुंदरता बढ़ाती है। बंगलों की सुंदरता बढ़ती है उससे, और कुछ नहीं होता। स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रमों में जल संरक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाय। जल संरक्षण का कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाए। सभी जन-प्रतिनिधियों जिनमें विधायक भी सम्मिलित हैं, से निर्वाचन पर ली जाने वाली शपथ के साथ यह प्रतिज्ञा पत्र भी भरवाया जाए कि वह जल संरक्षण का कार्य स्वयं भी करेगा और आम लोगों को भी इस हेतु प्रोत्साहित करेगा।

अंत में, मैं इस आशा और विश्वास के साथ कि मुख्य मंत्रीजी मेरे सुझावों पर विचार करेंगे और हम सब उनके नेतृत्व में इस कार्य में सफल होंगे, सर, यह तो सब लिखा हुआ था इसलिए आपकी तरफ नहीं देखा, अब मैं कुछ बोलना चाहती हूं अपनी तरफ से। उससे पहले जो मैंने शुरू में..(व्यवधान) जो मैंने एक पेज का इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्टिंग में, वह मेरे मन की बात

(श्रीमती अन्जू खन्गवाल)

थी। मैं यहां मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगी, मैं मेरे क्षेत्र की बात कर सकती हूं कि मेरे क्षेत्र में कई जगह ऐसी हैं जहां पानी की दिक्क्तें तो खैर हैं ही, उसे हम मिटा भी नहीं सकते, लेकिन जो पानी की पुरानी पाइप लाइन हैं या टंकियां हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं क्योंकि उनको देख कर मन ऐसे रोता है कि शायद कल को मेरा बच्चा प्यासा रहेगा तो वह सिर्फ इस पाइप लाइन को देख कर खुश हो जाएगा क्योंकि वह इतनी बुरी तरह से टूट-फूट चुकी है। उनकी मरम्मत नहीं होती है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। दस-दस प्रस्ताव आपको लिख कर भेजे जाते हैं, उसका कोई रेस्पांस नहीं आता है। अगर उसका रेस्पांस आता है तो वह ऐसी गोलमोल बात होती है आपके मंत्रियों की, नेताओं वाली कि हमारे तो पल्ले पड़ती नहीं है।

श्री सभापति: धन्यवाद, अब समाप्त करें।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): वह जो आप जो हमें जवाब देते हैं न, वह कम से कम हमारी समझ में भी आए। हमें पता ही नहीं चलता कि यह काम होगा कि नहीं होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें। श्री दयाराम परमार।

डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं चूंकि सत्ताधारी दल का हूं इसलिए बजट के पक्ष में मैं निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं (व्यवधान) लेकिन आपकी भी मजबूरी है, अगर बजट में कोई अच्छी बात कहीं गई हैं तो आप हां करते हो तो आपको जनता में वोट नहीं मिलते हैं, इसलिए आपकी मजबूरी है विरोध में बोलना। और इधर के माननीय सदस्यों को अपनी बात अच्छी कहने में थोड़ी कहीं कमी है, उसको कहने में इसलिए संकोच होता है कि अगली बार टिकट नहीं मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एरिया। एरिया से आता हूं। वह ट्राइबल एरिया क्या है? माननीय सभापति महोदय, आपको जानकारी नहीं होगी। राजस्थान का संपूर्ण आदिवासी एरिया पांच भागों में बंटा हुआ है-टाडा, माडा, माडा क्लस्टर, बिखरी हुई आबादी और सहरिया। ये मिलाकर इस ट्राइबल एरिया के लिए एक डिपार्टमेंट सरकार ने बना रखा है ट्राइबल डवलपमेंट डिपार्टमेंट और इस डिपार्टमेंट के लिए मंत्री, उसके बजट की व्यवस्था और सारा कमिश्नर तक का कार्यालय चलता है। माननीय सभापति महोदय, ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास में दो तरह से रुपया बजट में आता है-

(डा. दयाराम परमार)

संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार की केन्द्रीय विशेष सहायता और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का पैसा। इसके बाद में ट्राइबल एरिया में राजस्थान सरकार ने महाराष्ट्र पैटर्न के अनुसार सालाना वार्षिक योजना का एक प्रतिशत रुपया देने का फैसला कर रखा है। माननीय सभापति महोदय, पिछले साल जब सरकार ने बजट अपना पेश किया था तो उस बजट में 100 करोड़ रुपए महाराष्ट्र पैटर्न के अन्तर्गत ट्राइबल एरिये के विकास के लिए रखे थे। लेकिन अब पूरा साल समाप्त होने जा रहा है और आज तक जो भी कुछ जानकारी है उसके अनुसार उस 100 करोड़ में से एक रुपया भी सरकार ने आदिवासी एरिये के लिए खर्च नहीं किया। अब यह किसकी गलती रही? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं इसमें नीयत किसकी खोटी थी? सरकार की खोटी थी, मंत्रीजी की खोटी थी, अधिकारियों की खोटी थी या फिर किसकी खोटी नीयत थी? जिससे कि एक रुपया पूरे साल में खर्च नहीं किया गया? माननीय मुख्य मंत्रीजी जब जिस तारीख को इसका जवाब देंगे, मैं इस बात को जानने की कोशिश करुंगा कि वह क्यों, किस कारण से नहीं हुआ? माननीय सभापति महोदय, इस डिपार्टमेंट को बदलकर लास्ट ईयर पहले इस एरिये के लिए, प्लान और सब प्लान एरिया का था वो, वह प्लान और सब प्लान क्या था? प्लान सरकारी वार्षिक योजना और सब प्लान ट्राइबल एरिये के लिए जितनी प्रतिशत ट्राइबल पापुलेशन है, 12 प्रतिशत, इतना प्रत्येक विभाग हर जगह पर अपना रुपया अतिरिक्त खर्च करेगा फार ट्राइबल डपवलमेंट। उस व्यवस्था को हटा दिया यह मानकर कि यह कारगर नहीं है। इसके बाद में महाराष्ट्र पैटर्न के अनुसार फैसला किया गया। अब कल-परसों बजट पेश किया उसके अन्दर और बदलकर कर दिया जनजाति कल्याण निधि। यह क्या खेल-तमाशा हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आता, कि जनजाति कल्याण निधि बनाकर कितना विकास कर देना चाहते हैं? ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट रहता है उसके माध्यम से विकास नहीं होता है, यह सरकार की सोच हमको समझ में नहीं आती है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, ट्राइबल एरिये से 17 एमएलए जीत कर आते हैं, और जिस पार्टी के 12 और 13 आदमी जीत कर आते हैं तो इधर वालों को वहां बिठा देते हैं। कांग्रेस के अगर जीत कर 12 या 13 आ जाते हैं, अबकी बार 14 आये हैं, तो कांग्रेस वालों को इधर बिठा दिया। लेकिन जो भी पार्टी जब भी सरकार में आती है, राज में आ जाने के बाद में हम लोगों को भूल जाती है। मैं आपके माध्यम से सभी दलों को,

(डा. दयाराम परमार)

माननीय मुख्य मंत्रीजी को और सब को खबरदार करना चाहता हूं कि अगर हमारी उपेक्षा सरकार करती रही तो लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है। अब पूरा उस ट्राइबल एरिया का आदिवासी जाग्रत हो चुका है, उस जाग्रति के बाद वह अगर मैदान में सामने आएगा तो फिर सरकारों को हिला देगा वह, किसी भी पार्टी की सरकार नहीं होगी। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, समय रहते हुए इस गरीब तबके के लोगों को जो भी सरकार के कानून के अनुसार वाजिब हो, मिलना चाहिए। हम जबरदस्ती मांगना नहीं चाहते हैं और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी आदिवासी भूख से मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। इस तरह की स्वाभिमानी कौम के साथ में सरकार क्या खिलवाड़ कर रही है? मुझे आपको यह भी निवेदन करना है कि आजादी के वक्त में 1500 आदिवासी गोलियां खाकर शहीद हो गये मानगढ़ में, 1200 आदमी पाल छितरिया में मर गये 7 मार्च, 1922 को, 23 आदमी भूला और भोलडिया, सिरोही में मर गये। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ मेवाड़ के भील गोलियां खाकर मर गये, लेकिन आजादी के बाद में जिस तरह से सरकार को हमारे विकास के लिए मदद करनी चाहिए, उस मदद में हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि शुरू से हम लोग स्वभाव से सबका अदब करते हैं और अदब करने में लोग समझ जाते हैं कि इनको समझ में नहीं आता, इसलिए अपनी मर्जी से जो भी कुछ काम करना है वह फैसला करते रहो, इनको घुमाते रहो। लेकिन अब वह वक्त नहीं रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर चाहे जनजाति कल्याण निधि बनाई हो 124 करोड़ रुपये की, जो भी पैसा बजट में रखा जाता है, वह पैसा पूर्ण रूप से अगर खर्च होता है, विकास पर लगता है तब हम जानेंगे कि सरकार की नीयत अच्छी है और वह रुपया नहीं खर्च होता है तो हमको समझ में आता है कि केवल इसको दिखाने के लिए बजट में प्रोविजन किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को छोड़ते हुए निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे हिन्दुस्तान में प्रधानमंत्री सड़क योजना चली और उस योजना में गांवों में सड़कें बननी थीं। लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन में कहीं पर विलेज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था और हम कह रहे हैं कि हमने 250 तक के गांवों को रोड से जोड़ दिया। सामान्य एरिया में हमने 500 तक को जोड़ दिया। उसमें हैमलेट और हैबिटेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उससे क्या हुआ? हमने भारत सरकार को खबर दे दी कि 250 तक के गांव जोड़ दिए हैं।

(डा. दयाराम परमार)

अब आपके यहां से योजना बनाकर भेजी है तो भारत सरकार रुपया देने वाली नहीं है और अगर वह रुपया नहीं दिया तो आने वाले 25 साल तक बड़े-बड़े जो आपके हैमलेट और हैबिटेशन हैं, वे कभी भी सड़कों से नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा, सरकार समय रहते पैरवी करे और पैरवी करके जो पैसा हमको चाहिए हैमलेट और हैबिटेशन के लिए, वह पैसा लाए, तब तो गांवों की जनता का भला हो जाएगा, नहीं तो फिर गांव की जनता सड़कों के बिना रह जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, हमने 4 रुपये 70 पैसे से घटाकर 2 रुपये किलो बी.पी.एल. वालों को देने की घोषणा की है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, अच्छी घोषणा है, स्वागत योग्य है। लेकिन हमने बी.पी.एल. को दो तरह का कहा है, बी.पी.एल. और स्टेट बी.पी.एल. । अगर हमने इसके अन्दर स्टेट बी.पी.एल. को नहीं जोड़ा है 2 रुपये किलो दाने के अनाज के लिए, तो हम इनके साथ में अन्याय कर रहे हैं। आपने जो बी.पी.एल. चयनित थे उन्हीं को किया है, बीमार हो जाए तो इलाज करने के लिए स्टेट बी.पी.एल. वालों को दे रहे हैं दवाई, लेकिन अनाज के लिए हमने स्पष्टीकरण नहीं किया है कि हमने क्या किया उसका, स्टेट बी.पी.एल. वालों को भी देंगे या नहीं देंगे। मैं इससे आगे भी निवेदन करना चाहता हूं ए.पी.एल वाले, सबसे ज्यादा संख्या ए.पी.एल. की है, उनको हम 6 रुपये 80 पैसे किलो गेहूं देते हैं लेकिन कभी हम तीन किलो देते हैं, कभी हम पांच किलो देते हैं। और कभी दस किलो देते हैं। या तो हम देना ही बंद कर दे या फिर हम ए.पी.एल वालों को उसके भाव का जो डिफरेंस है, जब बी.पी.एल. वालों को हम 35 किलो देते हैं, अब बढ़ाकर 45 किलो कर दिया है, तो उसके बराबर उसका भाव आप 6 रुपये से बढ़ाकर 7 कर दीजिए, 8 कर दीजिए लेकिन उसकी जरूरत का अनाज तो कम से कम उनको देने की हमको व्यवस्था करनी चाहिए। हम उनको नहीं देंगे तो फिर समाज में यह डिफरेंस बढ़ता जाएगा और लोग आपस में टकराते जाएंगे। और टकराते रहे तो फिर क्या होगा? वह अलग ही बात होगी।

माननीय सभापति महोदय, अनाज देने के लिए आपके जो डीलर हैं उनके माध्यम से आप देते हैं। कंट्रोल डीलर का लाइसेंस अगर एक बार देते हैं, उसके नाम से लाइसेंस रहता है और वो मर जाए तो उसके बेटे के नाम से लाइसेंस रहता है। यह लाइसेंस कौन सा दे रहे हैं हम? व्यापार करने के लिए लाइसेंस दे रहे हैं? यह सस्ता अनाज वितरण करने के लिए लाइसेंस है और

(डा. दयाराम परमार)

इसके रिन्यू का प्रोविजन होना चाहिए कि दो-तीन साल के अन्दर उसका रिन्यू हो। अगर वो अच्छा काम कर सकता है, करता है, ईमानदारी से अनाज वितरण करता है तो फिर उसका लाइसेंस रिन्यू हो जाए, नहीं तो उस लाइसेंस को रोक दिया जाए। अगर इस तरह से डीलरों के ऊपर हमने कंट्रोल नहीं किया तो दो रुपये किलो से एक रुपये किलो भी कर दो तो वो तो मिलना ही नहीं है गरीब आदमी को। कोई कंट्रोल डीलरों पर नहीं है।

और कूपन निकालने का अधिकार पंचायत के पास में है। हस्बैंड सरपंच है और पत्नी डीलर है या पत्नी सरपंच है तो हस्बैंड डीलर है, तो किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं हम कि वो अनाज सही आदमी को वितरण कर सकता है? माननीय सभापति महोदय, इस पर भी चिन्तन करने की जरूरत है कि मैं तो सरपंच हूं, मेरी घर वाली डीलर है, कूपन काट-काट कर दे रही है और अनाज वितरण कर रहे हैं तो उस गरीब आदमी को अनाज सही कैसे मिल सकता है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, इस मामले में पूर्ण रूप से सरकार चिन्तन करे कि जो अनाज दो रुपये किलो देने का हमने फैसला किया वो सही आदमी के पास पहुंचे, तब तो ठीक हो सकता है।

नरेगा की बात बराबर होती है, यह योजना वास्तव में बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला है उस भ्रष्टाचार के लिए भी हर आदमी चिन्ता करता है कि उसको कैसे रोका जाए। भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर कभी चिन्तन नहीं किया हमने। हमने सरपंच को जाब कार्ड जारी करने का अधिकार दिया, सरपंच को जाब देने का भी अधिकार दिया, जाब के लिए एप्लीकेशन लेने का भी उसको अधिकार दिया। अब एक आदमी बीस साल पहले मर गया, माननीय कटारिया साहब, उसका जाब कार्ड जारी हो गया। सड़क पर काम कर रहा है और महीना होते ही पगार उठा रहा है। हमें करना यह चाहिए था कि जाब कार्ड देने का अधिकार तहसीलदार को या एसडीएम को देते, तब तो सही जाब कार्ड निकलता और सही जाब कार्ड निकलता तो फिर भ्रष्टाचार भी कम हो जाता अपने आप। लेकिन हम ऐसा करना ही नहीं चाहते क्योंकि हमको पंचायतों को अधिकार देने हैं, मजबूत करना है। तो फिर वो अपने आप मजबूत हो रहे हैं, फिर हम चिन्ता क्यों करते हैं जब मजबूत हो रहे हैं और कमा-कमा कर हो रहे हैं? फिर उसकी ज्यादा चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ईमानदारी से काम करना हो तो फिर हमको व्यवस्था को बदलने की जरूरत है।

(डा. दयाराम परमार)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमने सभी तरह की पेंशनें भी बढ़ा दी हैं। हम विधवा पेंशन भी देते हैं लेकिन विधवा पेंशन तब तक देते हैं जब तक कि उनकी औलादें बालिग न हो जाएं। लेकिन, सभापति महोदय, अगर मां और बाप दोनों मर जाएं और वो बच्चे दस साल-आठ साल के हैं तो हम उस पर कभी चिन्ता नहीं करते हैं। होना यह चाहिए कि उन बच्चों को भी हम अनाथ पेंशन दें। पालना गृह तो मामूली बात होती है, पालना गृह में कुछ नहीं होता है। अनाथ पेंशन दें जब तक वो बालिग न हो जाए, इसके बाद वो बड़ा होकर गांव में रह कर पढ़-लिख कर अपनी जमीन-जायदाद संभालने जैसा हो जाए तो हम उसको पेंशन रोक दें। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा सरकार से कि अनाथ पेंशन के लिए सरकार चिन्तन करे।

माननीय मुख्य मंत्रीजी के भाषण में यह भी कहा गया है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सोना और मैंग्नीज पदार्थ निकल रहे हैं और उसके लिए आरएसएमएम खुदाई करेगा। बात बड़ी अच्छी है, लेकिन आदिवासी के खेत में खनिज निकल रहा है उसको आरएसएमएम वाले ले जाएंगे। उसमें यह भी कहा कि पचास प्रतिशत मजदूर वहां का, क्या हमको मजदूर ही रखना चाहते हो क्या? हमारी जमीन में से खनिज निकाल कर ले जाकर सरकार अपना खजाना भरना चाहती है। गरीब आदमी की जमीन है या तो आप उसकी पार्टनरशिप करें या फिर उसके नाम से माइनिंग करने की बात करें तब तो उस गरीब आदमी को फायदा होगा। उसको गरीब ही रखना चाहते हो। सोना निकल रहा है और सोना तो हम लेंगे, तुम तो मजदूरी करो। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सरकार इस पर चिन्तन करे।

माननीय उद्योग मंत्रीजी, मैं आपसे दरख्वास्त यह करना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया में आपकी उद्योग की कोई नीति नहीं है, बिना उद्योग के है। मेरी पूरी तहसील में एक मिल चलती है किसी जमाने की जिसमें बारह सौ आदमी काम करते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में एक-एक मिल चलती है कपड़े की, वहां लोग काम करते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए आपने कालेज खोल दिये, स्कूल खोल दिये, पढ़ा कर फौज तैयार कर दी है, लेकिन उस फौज के लिए अगर आपने रोजगार देने का काम नहीं किया तो फिर क्या होगा? अभी तो आपके आन्ध्रा और उधर ही वो नक्सली बंदूक ले-लेकर ढूंढ रहे हैं, फिर इधर भी शुरू हो जाएंगे। समय रहते उन पढ़े-लिखे नौजवानों को काम पर लगाने के लिए

(डा. दयाराम परमार)

सरकार को ट्राइबल एरिया में नीति बनानी पड़ेगी। इसलिए हम कहते थे कि महाराष्ट्र पैटर्न के अन्दर इस डिपार्टमेंट को सफीशियेंट बजट दें और बजट देने के बाद उद्योगपतियों को इंसेंटिव देकर उस एरिया में किसी तरह के कारखाने खोल कर नौजवानों को धंधे पर लगाएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे साल में पहली बार खड़ा हुआ हूं लेकिन अब आपके आदेश की पालना भी करूंगा क्योंकि आप फौजी आदमी हो और फौजी आदमी कभी भी अपनी आंखें दिखा दे तो फिर आगे काम चलता नहीं है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रभुलाल सैनी।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, 13वीं विधान सभा के दूसरे बजट सत्र में आज मैं मेरी ओर से आपकी अनुमति से अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय निश्चित रूप से बजट को प्रथम दृष्ट्या यदि देखते हैं तो 23822 करोड़ रुपये का बजट पिछले बजट 18634 करोड़ के मुकाबले 37 प्रतिशत अधिक होने का इसमें दर्शाया गया है लेकिन सभापति महोदय, यदि हम बजट को देखते हैं तो ऐसा हास्यास्पद बजट है, जिसने हर वर्ग को निराश किया है चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे बेरोजगार हों। सबसे दु:खद बात यह है कि किसानों के हित में, किसानों के कल्याण के लिए पूरे बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। सभापति महोदय, 63 वर्षों से बजट सदन में प्रस्तुत होते रहे हैं, चार दिन बजट पर चर्चाएं होती हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने विचार प्रकट करते हैं। लेकिन हमें इस बात पर चिन्ता करनी पड़ेगी कि पूरे देश का हमारा जो अन्नदाता है किसान, क्या हम 63 वर्षों में हमारे अन्नदाता को आत्मनिर्भर कर पाये। आज मात्र विचार यह बन गया कि नरेगा में जाएगा और रोटी खाकर आ जाएगा, यानी जानवर से भी बदतर स्थिति हमारे किसानों की हो रही है। सभापति महोदय, अन्नदाता के ऊपर मैं समझता हूं कि सदन में राजनीतिकरण करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यह कहता हूं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य यहां विराजमान हैं, 70 से 75 प्रतिशत तक

(श्री प्रभुलाल सैनी)

ऐसे माननीय सदस्य हैं जो संसद में और यहां की विधान सभा में किसान परिवार से चुन कर आते हैं, लेकिन जब किसानों पर चर्चा होती है, किसान पर बजट की चर्चा होती है तो और मदों के मुकाबले किसानों पर चर्चा बहुत कम होती है, यह बहुत चिन्ताजनक विषय पर मैं सदन में अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में राजनीतिक क्षेत्र में नैतिकता में गिरावट आयी है, मात्र किसानों के नैतिक चरित्र के बलबूते चलते यह लोकतंत्र बचा है, यह पूरा प्रदेश बचा है, इसलिए हम सबका यह दायित्व बन जाता है, सभापति महोदय, कि किसानों के हित में राजनीतिक पार्टीबाजी से हट कर हमको विचार करना चाहिए, हमको चिन्तन करना चाहिए और उनके उत्थान के लिए हमको योजनाओं में सकारात्मक सहयोग सबको मिल कर देना चाहिए।

(समय : 18.00 बजे)

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट के पैरा-4 में जो बातें कही हैं हमारे उदयपुर से आने वाले वरिष्ठ माननीय सदस्य कटारिया साहब ने भी उनकी प्रशंसा की है और मैं भी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने बिन्दु संख्या 4 में केन्द्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान में एक सुशासन देने का उद्धरण किया है। उन्होंने कहा है, सतर्कता व्यवस्था को अधिक प्रभावी हम लोग करेंगे। जन अभाव अभियोग निराकरण आयोग का गठन करेंगे, पत्रावलियों के विचाराधीन पत्रों के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित करेंगे। कर्मचारी/अधिकारियों के स्थानांतरण की हम नीति बनाएंगे, राजकीय भुगतान के नकद भुगतान की व्यवस्था भी हम करेंगे और सूचना के अधिकार को और प्रभावी बनाएंगे। एस.टी., एस.सी., अल्पसंख्यक और महिलाओं के जीवन उत्थान के लिये हमारी सरकार वचनबद्ध होगी। आंशिक रूप से मैं भी इस बात से सहमत हूं, अगर बजट में की गई घोषणाओं पर यह राजस्थान सरकार अमल करती है तो निश्चित रूप से आंशिक रूप से उनका यह काम प्रशंसनीय कार्य होगा। सभापति महोदय, माननीय सीएम साहब ने पैरा संख्या 3 में केन्द्रीय बजट की प्रशंसा की है और केन्द्रीय बजट में केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की दर को पुन: 9 प्रतिशत लाने और खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ कर शिक्षा के अवसर को बढ़ाने की बात कही गई है। शायद ऐसी ही कल्पना उनके मन में रही होगी, लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने चुनावी एजेंडे में सबसे बड़ी बात यह कही थी चुनाव के वक्त

(श्री प्रभुलाल सैनी)

2008 में कि हमारे घोषणा-पत्र का मुख्य आधार ठोस संकल्पों की घोषणा होगी और किसान के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हम काम करेंगे और सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी का प्रावधान भी हम लोग करेंगे। इन्होंने यह भी कहा कि जिला स्तर पर हम किसान भवनों का निर्माण करेंगे। इसके अलावा फसल बीमा की बात भी कही कि हम पंचायत स्तर तक इसको लेकर जाएंगे। सभापति महोदय, एक साल हो गया, यदि हम विचार करें, क्या फसल बीमा योजना को पंचायत स्तर पर ले जाने का इन्होंने कोई प्रयास किया है? इन्होंने अब जो प्रयास किये हैं उससे तो ऐसा लगता है कि फसल बीमा योजना को बंद कर मात्र मौसम आधारित बीमा योजना के सहारे ही ये किसानों का भला करने की सोचते हैं। इन्होंने कथनी और करनी में अन्तर किया है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि होता है और केन्द्रीय जीडीपी में इसका रेशो देखते हैं कृषि और संबंधित क्षेत्र पशु पालन सहित तो 16 प्रतिशत और राजस्थान की जीडीपी में कृषि और संबंधित क्षेत्र का रेशो देखते हैं तो मुझे कहते हुए हर्ष है कि 2008-09 में जीडीपी का 25.18 प्रतिशत हिस्सा कृषि और संबंधित क्षेत्र का था और 2009 में 23.71 प्रतिशत हिस्सा है। लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, जीडीपी में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा यदि 25 से 30 प्रतिशत है तो राजस्थान का जो 23 हजार करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें कितना हिस्सा हुआ है? कम से कम राजस्थान सरकार इतनी तो कल्पना करती, कि जीडीपी में कृषि और संबंधित क्षेत्र का रेशो जो आम जनता के लिये हमको मिलता है 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत जो बजट था, वह कृषि और संबंधित क्षेत्र में खर्च नहीं करना चाहिये, बजट में प्रावधान करने चाहिये। सभापति महोदय, इन्होंने एक प्रतिशत पैसा भी उसमें नहीं रखा, यह बहुत शर्मनाक बात है। सभापति महोदय, सरकार के ध्यान में था, अनावृष्टि हुई है। यह आज का विषय नहीं है, Indian agriculture has been a gamble in rain. सभापति महोदय, आप यह जानते हैं, हमारी कृषि व्यवस्था वर्षा आधारित है। यह आज का विषय नहीं है हमारा इतिहास गवाह है। लेकिन जब हमारी फसल उत्पादन के आंकड़े की बात हुई तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, 2007-08 में 145.32 लाख मैट्रिक टन अनाज का उत्पादन हुआ, 2008-09 में 148.53 लाख मैट्रिक टन

(श्री प्रभुलाल सैनी)

और 2009-10 में मात्र 97 प्रतिशत अनाज की पैदावार संभावित की गई। दलहन के क्षेत्र में 2007-08 में 15.52 लाख और 2008-09 में 28.26 और इस वर्ष 9.72 लाख मैट्रिक टन ही दलहन का उत्पादन होगा। खाद्यान्न की स्थिति के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, 2007-08 में खाद्यान्न 160.84 लाख मैट्रिक टन, 2008-09 में 166.79 और 2009-10 में 107.02 यानी 35.24 प्रतिशत खाद्यान्न की राजस्थान में इस वर्ष कम पैदावार होगी। सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमें ऐसे विचार करने चाहिये, बजट में ऐसे प्रावधान करने चाहिये कि कम लागत, कम पानी से अधिक उत्पादन कैसे हो। अगर पूरे देश की हम बात करें तो 61 प्रतिशत ड्राईलैंड हमारे राजस्थान में है और उसका सारा परिदृश्य सरकार के सामने था। यदि सरकार चाहती तो दलहन और तिलहन को बढ़ाने के लिये अनेक उपाय इसमें कर सकती थी। राजस्थान के किसान को कैसे ऊंचा उठाएं, यह परिकल्पना इनको करनी चाहिये थी। लेकिन सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख है कि हमारे राजस्थान के किसानों के लिये, हमारे आम नागरिक के लिये, खेतिहर मजदूर के लिये आज हमारी परिस्थितियां देखें तो मात्र 2009-10 में खरीफ में दालों का उत्पादन 1.33 लाख मैट्रिक टन होगा जबकि 2008 में 8.17 लाख मैट्रिक टन दालों का उत्पादन हुआ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया, साहब।

श्री सभापति: ठीक है, आप ही की व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): सभापति महोदय, आपके आदेश की मैं निश्चित रूप से पालना करूंगा।

श्री सभापति: आप कृपया बैठिए। मैं सदन के सचेतक महोदय से और इस तरफ बैठे माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, यह व्यवस्था आपके द्वारा दी गई है कि बाकी सदस्यों को कम टाइम दिया जाएगा। यहां से टिप्पणी की जाती है कि मैं भी 40 मिनट बोलूंगा, कोई पीछे से टिप्पणी की जाती है कि आप बोलने दीजिए। इस तरह की व्यवस्था आपकी अपनी है, परम्परा आपकी अपनी है। मेरा आपसे निवेदन है आपका अपना टाइम है, आसन को कोई एतराज नहीं है, अगर आपको सारी रात बैठना है तो मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं। लेकिन कम से कम व्यवस्था ऐसी रखें जिसमें शांति रहे, मान रहे, सम्मान रहे। इस किस्म की टिप्पणी जो कि मैं समझता हूं कि आसन के

(श्री सभापति)

लिये भी ठीक नहीं है और आपकी गरिमा के लिये भी ठीक नहीं है, उचित नहीं होगी । यह मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ कर। मैं कम से कम इससे बहुत पीड़ित हूं यह मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है और विशेष तौर से इस तरफ।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): सभापति महोदय, निश्चित रूप से आपके आदेशों की पालना होगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पूरे प्रदेश में 1,31,40,66 लघु और सीमांत कृषक हैं। इसके अलावा 50 लाख से अधिक कृषि श्रमिक हैं। ढाई करोड़ से ज्यादा लोगों के लिये अगर इस पूरे बजट में 1 प्रतिशत से भी कम हिस्सा आता है तो मैं समझता हूं, इससे ज्यादा शर्मनाक और राजस्थान के किसान की उपेक्षा करने वाला बजट कोई और हो नहीं सकता।

मैं पैरा संख्या 117 के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में डिग्गियों का निर्माण कराया जाएगा, उसमें 18 हजार डिग्गियां हमने स्वीकृत की हैं और 2000 डिग्गियां अबकी बार बनाएंगे। सभापति महोदय, इस सदन को गुमराह करने की योजना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राजस्थान सरकार के बजट का पार्ट नहीं है, यह केन्द्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार का एक भी पैसा इसके अन्तर्गत नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यदि हम ईमानदारी से राजस्थान के किसान को डिग्गियां देना चाहते हैं तो अकेले इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के किसान जहां पर पानी उपलब्ध है उनको 50 प्रतिशत जो अनुदान दिया जा रहा है, उसमें 25 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार की ओर से दें ताकि राजस्थान के किसानों का भला हो सके।

सभापति महोदय, पैरा संख्या 118 में इन्होंने कहा है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना को पहले 7 जिलों में अब इसको 10 जिलों में बढाकर 17 किया है आगामी वर्षों में पूरे राजस्थान में इसको लागू करेंगे। सभापति महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने मौसम बीमा योजना लागू की है, ऐसा नहीं है। राजस्थान पहला राज्य है जिसने देश को एक नई दिशा दी है और 2007 में केन्द्रीय

(श्री प्रभुलाल सैनी)

बजट में उन्होंने यह कहा है कि राजस्थान की तर्ज पर हम लोग पूरे देश के पांच राज्यों में मौसम आधारित बीमा योजना शुरू करेंगे। राजस्थान में 2007-08 में 10 जिलों में मौसम आधारित बीमा योजना हमारी सरकार ने शुरू की थी। इस सरकार ने इसको आगे बढ़ाया, इसके लिये तो हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन उनसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि मौसम आधारित बीमा योजना में कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां मौसम की खराबी नहीं होती है और वहां के किसानों को अनावश्यक प्रीमियम देनी होती है। मेरा सरकार से आग्रह होगा, सुझाव होगा कि इसके प्रीमियम की जो राशि है वह सारी की सारी राशि अभावग्रस्त क्षेत्रों में सरकार की ओर से दी जाए ताकि हम इस योजना को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा सकें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब कृपया आप समाप्त करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): सभापति महोदय, पैरा संख्या 121 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करुंगा इसमें कहा गया है, उदयपुर और बांसवाडा में हम लोगों ने गोल्डन रेज (सुनहरी किरणों) के नाम से एक प्रोजैक्ट शुरू किया जिसमें मक्का की हाई ब्रीड वैरायटी किसानों को उपलब्ध करा कर राजस्थान के खायान्न का उत्पादन बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें भी इनका कोई पैसा नहीं है, सारा पैसा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का है। टीडीएस क्षेत्र का जो पैसा था उस आधार पर इन्होंने पैसा खर्च किया है। जिस साढ़े तीन हजार मैट्रिक टन सीड वितरण की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा, मक्का के साथ में इनको दलहन के क्षेत्र में भी मूंग, मोठ और अरहर के मिनीकिट्स किसानों को उपलब्ध कराने चाहिये ताकि कम पानी, कम लागत से अधिक उत्पादन उनको मिल सके।

सभापति महोदय, मैं एक बात आपसे अंत में निवेदन करना चाहूंगा, सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की कि जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली हम लोग लागू करेंगे, घोषणा हो गई लेकिन आज हम यह देखें कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली है इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। एक छत के नीचे ये ही पकड़ेगे, ये ही छोडेंगे और ये ही जेल भेज देंगे। सीआरपीसी में पहले ही इतने प्रोवीजन्स दिये हुए हैं। आज हम ला एंड आर्डर की बात करते हैं, मैं गृह मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा, सीआरपीसी के जो प्रोवीजन्स हैं 107, 117, 151, 110 पिछले तीन वर्षो के आंकड़े देखते हैं तो वो ही 1 लाख 40 हजार से

(श्री प्रभुलाल सैनी)

आगे नहीं बढ़ते हैं, जब चुनाव आते हैं, और आते हैं, बेचारे उन्हीं को वापस-वापस करते रहते हैं। एक व्यवस्था राज्य पुलिस आयोग...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): राज्य पुलिस आयोग की स्थापना....

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह प्रणाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कमिश्नर प्रणाली लागू होगी और निश्चित तौर पर इसके परिणाम भी आएंगे। किस तरीके के परिणाम आते हैं...(व्यवधान) आप मत घबराओ, आप चिन्ता मत करो, कोई दिक्कत आए तो बताना आप तो।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी का सुझाव है, वैसे मुझे ज्यादा चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, यह आपको ही सोचना पड़ेगा। मैं इतना निवेदन करूंगा, राज्य सरकार को सदन की ओर से सुझाव देना चाहूंगा कि राज्य पुलिस आयोग का गठन भी किया जाना चाहिये। राजस्थान में राज्य पुलिस आयोग का गठन हो जाएगा उसमें गृह मंत्रीजी की अध्यक्षता हो, प्रतिपक्ष का जो नेता बने वह भी उसका मैम्बर हो, डीजी उसका मैम्बर हो और इसके अलावा प्रिंसिपल सैक्रेटरी हो।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): उससे एक बैलेंस होगा।

श्री सभापति: अब अंकित नहीं होगा।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली):×××

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, अब अंकित नहीं होगा।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली):×××

श्री सभापति: श्री गंगासहाय शर्मा। मैंने आपको तीन बार निवेदन किया, मैं फिर कह रहा हूं, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): ×××

श्री सभापति: आप कृपया विराजें, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): ×××

श्री सभापति: कृपया बैठें आप। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): ×××

श्री सभापति: (व्यवधान) आप हमेशा ही यह कहते हैं, क्लोजर क्लोजर....

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): ×××

श्री गंगासहाय शर्मा (आमेर): आदरणीय सभापति महोदय, सन् 2010-11 के राजस्थान के बजट के पक्ष में बोलने का मुझे समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है जिसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। यह बजट राज्य के सभी समाजों, अत्यन्त पिछड़े, उपेक्षित लोगों को समर्पित किया गया है। यह बजट ग्रामीण क्षेत्र व शहरों में स्थानीय नागरिक को समर्पित बजट है। बीपीएल परिवार के लोगों को 4.70 रुपये में गेहूं मिलता था, 2 रुपये किलो में गेहूं देने का मुख्य मंत्रीजी ने जो वादा किया है वह ऐतिहासिक निर्णय है। मुख्य मंत्रीजी ने बीपीएल परिवारों की तर्ज पर विकलांगों, वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा महिलाओं को मुफ्त इलाज की घोषणा की है वह सराहनीय है। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। वृद्धावस्था पेंशन के साथ विधवा व विकलांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये की गई है एवं 75 वर्ष की आयु में 750 रुपये किये हैं। भारत की आजादी हेतु लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन आठ हजार से दस हजार की गई है। महिलाओं के स्वयं का रोजगार स्थापित करने पर 50 प्रतिशत अनुदान सहायता की घोषणा की गयी है जिससे राज्य की महिलाएं स्वयं का उद्योग संचालित कर सकेंगी, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री बधाई के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में हजारों परिवार जो आबादी क्षेत्र में अपने मकान बनाकर रह रहे हैं, उनका सर्वे कराकर पट्टे देने का जो निर्णय लिया है, वह एक ऐतिहासिक फैसला है, इसके कारण से शहरों में नागरिकों का पलायन रुक सकेगा क्योंकि पट्टे के आधार पर सरकारी ऋणदाता संस्थाओं से ऋण लेकर अपना स्वयं का कारोबार कर सकेंगे। राज्य सरकार ने बजट में जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना का एलान किया है, यह भी एक क्रांतिकारी फैसला है जो सम्पूर्ण राजस्थान के किसानों के लिए लाभकारी होगा। मुख्य मंत्रीजी ने राज्य में नई औद्योगिक नीति के तहत जयपुर में सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर 42 एकड़ जमीन पर औद्योगिक मेला लगाने हेतु विकसित करने की जो योजना दी है, यह भी राज्य के उद्योग के लिए एक वरदान साबित

(श्री गंगासहाय शर्मा)

होगा। इसके कारण राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगपतियों को जयपुर में ही देश-विदेश के व्यापारियों से मिलकर अपने उद्योग को विकसित करने एवं व्यवसाय फैलाने में मदद मिलेगी। दस्तकारों, हस्तशिल्पकारों, शिक्षित युवाओं के लिए सरकार स्वावलंबन योजना लाई है, यह स्वागत योग्य है क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत लोन राशि में दो प्रतिशत अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है।

वर्तमान में जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए दस रुपये के स्टाम्प की छूट दी गई है, गरीबों और बेरोजगारों के लिए यह एक बहुत बड़ा तोहफा माना जा रहा है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर शहर के आस-पास ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कुटीर उद्योगों जैसे रंगरेज, दस्तकार, लकड़ी का काम करने वाले, नगीने की घिसाई करने वाले का सर्वे कराकर उन्हें सिंगल फेज की बिजली 24 घंटे उपलब्ध कराई जाए। उन्हें राजकीय संस्थाओं से समय पर ऋण दिलाया जाए ताकि बेरोजगार युवक जयपुर शहर में पलायन नहीं करें। मैं मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि मेरा आमेर विधान सभा क्षेत्र जयपुर का अत्यन्त ऐतिहासिक, हरा भरा एवं शांत क्षेत्र है, जयपुर शहर से सटा हुआ है। दिल्ली चौमूं से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में आते हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आवासन मण्डल एवं जेडीए के माध्यम से नई आवासीय योजना लाकर नई आवासीय बस्तियों का निर्माण कराया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली रोड पर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र की तर्ज पर प्रदूषण मुक्त उद्योग लगाने हेतु औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए ताकि बेरोजगार युवकों को स्थानीय क्षेत्र में रोजगार मिल सके।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिवायचक व गोचर भूमि काफी मात्रा में है और अभी निकट समय में जेडीए का विस्तार हुआ है, उस विस्तार में मेरा विधान सभा क्षेत्र जेडीए ने पूरा अधिग्रहित कर लिया है। मैं आपके माध्यम से स्वायत शासन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण पंचायतों से ली गई सिवायचक और गोचर जमीन श्मशान के लिए, शिक्षा हेतु विद्यालय के लिए, खेल मैदानों के लिए, पशुओं के लिए, गौशालाओं के लिए भूमि ग्राम पंचायतों की आवश्यकतानुसार पंचायतों को आबंटित की जाए।

(श्री गंगासहाय शर्मा)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बच्चों के अस्पताल जेकेलोन में विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधा दिलाने और राज्य में सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में कैंसर रोगियों के लिए चिकित्सा हेतु जो धनराशि का प्रावधान रखा है, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। मेरे आमेर विधान सभा क्षेत्र में चल रहे अस्पताल के अलावा चंदवाजी व खोराबीसल जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां भी अगर मुख्य मंत्रीजी कोई अस्पताल की योजना दे पाएं तो मैं समझता हूं क्षेत्र में बड़ा लाभ होगा।

मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने 5 प्रतिशत की जगह वापस 4 प्रतिशत वैट लगाने का निर्णय लिया, यह उनके संवेदनशील होने का परिचायक है। राज्य में लाखों छोटे व्यापारियों को वार्षिक रिटर्न भरने की योजना देकर भी राज्य में व्यापारियों को तोहफा दिया गया है, यह भी सराहनीय कदम है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हैण्डीक्राफ्ट में काम आने वाली सफेद आडूसा की लकड़ी पर 14 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर करके कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया है। मार्बल व कोटा स्टोन में टैक्स कम कर आदमी को मकान बनाने के लिये सहूलियत प्रदान की है। आमेर क्षेत्र का सब्जी उत्पादन में, कृषि क्षेत्र में राजस्थान में सबसे अग्रणी स्थान है, अतः मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में राधाकिशनपुरा में सब्जी मण्डी की स्थापना की जाए जिससे आमेर का किसान आमेर में ही अपनी सब्जी बेच सके और सारे जयपुर में जो सप्लाई हो सके। इसी तरह आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे लिए अच्छी-अच्छी योजनाएं दीं जिनमें पुलिस कमिश्नर प्रणाली जोधपुर और जयपुर में दी गई है, यह भी सराहना योग्य है। मैट्रो रेल योजना दी है, यह भी सराहना योग्य है। आमेर और घाट की गूणी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना पर्यटन को बढ़ावा देने वाला कदम है। राजीव आवास योजना के तहत कच्ची बस्तियों को नियमित करने का निर्णय मुख्य मंत्रीजी ने लिया है, यह भी एक बहुत बड़ा कदम है। अन्त में मैं 2010-11 का जो लोक कल्याणकारी बजट है, उसका पूरा समर्थन करता हूं व राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्रीमती कमला कस्वां।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, 8 मार्च, 2010 को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और उसी दिन हिन्दुस्तान के इतिहास में एक नई नजीर लिखी गई कि दिल्ली में उच्च सदन में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया और उसके एक दिन के बाद राजस्थान का बजट हमारे मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री की हैसियत से पेश किया। महिलाओं ने सोचा कि 8 तारीख इनके जहन में होगी और महिलाओं को कुछ न कुछ ऐसा दे जाएंगे कि जो महिलाएं राजस्थान की हैं, वे इनका धन्यवाद करेंगी। लेकिन पूरे बजट को देखने के बाद महिलाओं को क्या दिया, यह, आज यहां गृह मंत्रीजी बैठे हैं, इनको पता है। पूरे जिले के अन्दर एक महिला थाना बनाने की घोषणा कर देना, मैं समझती हूं, महिला उत्पीड़न को कम करने का कोई सार्थक प्रयास नहीं है। गृह मंत्रीजी से मेरा एक और भी निवेदन है कि राजस्थान की जनता 80 प्रतिशत गांवों में रहती है, सुदूर गांव में बैठी हुई महिला क्या जिला मुख्यालय पर जाकर अपनी पीड़ा कह पाएगी? यह सोचने की बात है कि जिस प्रदेश की एक महिला जो विधायक है, जो सरपंच है वही सुरक्षित नहीं है, उसके साथ ही मारपीट की जा रही है, उसको उत्पीड़ित किया जा रहा है तो साधारण-सी महिला जो गांव में रहती है, जो घर का काम करती है, आज जिसकी अस्मत लूटी जा रही है, दहेज के कारण से जिसको जलने के लिये मजबूर किया जा रहा है, उसको क्या न्याय मिलेगा। यह बजट नहीं बताता, इसमें कोई घोषणा नहीं है। मुझे बहुत दु:ख है कि महिलाओं का आप मान करने की बात करते हैं, बड़ी-बड़ी बात करते हैं और गृह मंत्रीजी कहते हैं कि जब आप सामने होती हैं तो मुझे कुछ-कुछ होता है, वह कुछ-कुछ होना, पीड़ा नहीं हो रही है आपको। आपको पीड़ा होनी चाहिए। आप भी ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां ग्रामीण परिवेश है, तो आप यह सोचिये कि अगर महिलाओं के साथ इसी तरह से अत्याचार होता रहे, एक साल का आपका इतिहास उठाकर देख लीजिए, महिलाओं के साथ इस एक-सवा साल के पीरियड में अपराध बढ़े हैं। रोज अपहरण, रोज बलात्कार, रोज चैन पुलिंग, यह क्या हो रहा है? इसको रोकना बहुत जरुरी है? मैंने तो सोचा था जैसी कि एक कहावत है, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, तो मैंने गहराई से अध्ययन किया। क्योंकि जब वित्त मंत्रीजी भाषण दे रहे थे तो हमारे तक तो आधी बात समझ में आ रही थी। तो हमने सोचा कि पढ़कर देखें। जब पढ़ा तो मैंने सोचा, महिलाओं के लिये तो कुछ न कुछ होगा। एक स्वयं सहायता समूह की महिला को ब्याज में रियायत दे देना, या एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बालिका जो मैरिट में

(श्रीमती कमला कस्वां)

तीन स्थान तक रखे, उसको छात्रवृत्ति देकर विदेश भेज देना, क्या यही महिलाओं का उत्थान है? जिन स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं विषय के, जिन स्कूलों का कोई धणी-धोरी नहीं और जिन स्कूलों में आज तक समानीकरण के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं, उन स्कूलों की बच्चियों से हम उम्मीद करते हैं कि वे मैरिट लिस्ट में आएंगी? क्यों असत्य वादे करते हैं? न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस बजट पर जरा गौर करें और जब आने वाला कोई बजट आप बनाएं तो उसमें महिलाओं का थोड़ा ध्यान रखें।

एक बात जिसके लिये सत्ता पक्ष ने बहुत मेजें थपथपाई हैं कि हम गरीब बी.पी.एल. परिवार को 4 रुपये 70 पैसे के स्थान के बजाय दो रुपये किलो के हिसाब से गेहूं दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहती हूं कि क्या वे बी.पी.एल. परिवार 1997 की बी.पी.एल. सूची के ही परिवार हैं या 2002 में जो बी.पी.एल. सूची बनी, उसके भी परिवार हैं? 20-21 लाख आदमी आज राशन कार्ड से वंचित हैं, उनको यह सुविधा नहीं मिल रही है, क्या उनको भी आपने इसमें लिया है? मुख्य मंत्रीजी ने जो पिछले बजट में घोषणा की थी और जैसा मेरे साथी अभी कह रहे थे, जिनको राज्य बी.पी.एल. सूची में लिया गया है, क्या उनको भी जोड़ा गया है? क्या मुख्य मंत्रीजी की नीयत है, 2009 से लम्बित बी.पी.एल. की नई सूची बनाने का काम कर रहे हैं? 2010 आ गया, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो यह गरीबों के साथ अन्याय है। राजस्थान में क्या 17 लाख ही गरीब आदमी हैं? 6 करोड़ के अन्दर 21 लाख व्यक्ति, 17 लाख से अलग, बी.पी.एल. लाभ पाने से वंचित हैं। इसलिये उस पर सोचना और उनके विषय पर कोई नीति बनाना, उनके विषय में निर्णय करने के लिये मंत्रीजी को सोचना चाहिए कि उन लोगों को भी लाभ मिले।

दूसरी बात जिसके लिये सत्ता पक्ष का हर वक्ता खड़ा होकर वाह-वाही लूटना चाहता है, वह है नरेगा, महानरेगा जिसको बना दिया है। कि बहुत बड़ी योजना है कि इसने बड़ी क्रय शक्ति बढ़ाई है कि इसने बड़े विकास किये हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? आज राजस्थान में 15 प्रतिशत लोगों को सौ दिन का रोजगार मिला है, 85 प्रतिशत लोगों को रोजगार नहीं मिला। उस 15 प्रतिशत में भी क्या किसी को सौ रुपये पूरे मिले हैं? पूरा औसत 20 और 40 के बीच

(श्रीमती कमला कस्वां)

में आता है। एक किसान जो अपने खेत में काम करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था, आज उसको इस योजना ने खोदने वाला मजदूर बना दिया है। आज मिट्टी खोद-खोदकर उसके खेतों का नाश कर दिया, उसके गोचर का नाश कर दिया, उसके चरागाहों का नाश कर दिया। उन जोहड़ों में जिनमें बरसात के समय पूरा पानी आता था, 4-4, 5-5 महीने तक पशु पानी पीते थे, आज वहां पानी नहीं आता क्योंकि उसके चारों तरफ खड्डे खुदे हुए हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप का पूरा ध्यान मंत्रीजी की तरफ है।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): आपकी तरफ भी है, आपकी तरफ भी कर रही हूं। क्योंकि अब मंत्री तो वहीं बैठे हुए हैं।

श्री सभापति: With due respects, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने कहा, 'कुछ-कुछ होता है', इसको कार्यवाही में रहने दें कि एक्सपंज कराऊं इसको? क्योंकि आपने मंत्रीजी की तरफ इशारा करके कहा है, 'कुछ-कुछ होता है'।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): उन्होंने कहा था। उन्होंने वहां बैठे हुए कहा था कि अनिता भदेलजी जब बैठी होती हैं तो मुझे कुछ होता है।

श्री सभापति: नहीं तो, मेरा कहना है, हटवा दें कार्यवाही से? तो आपका क्या है?

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): चलो, कोई बात नहीं।

श्री सभापति: Please carry on.

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): अब मैं यह कहना चाहती हूं कि यह नरेगा योजना दिखने में तो ऐसी लगती है कि बहुत लोगों को रोजगार देगी, लेकिन यह किसान के इतने नुकसान की चीज है कि आने वाले सालों में आपको कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा। किसान बैठा हुआ 20 और 40 रुपये लेकर भी मजे मारेगा, खुश रहेगा, खेतों में काम नहीं करेगा और खाद्यान्न की कमी का जो रोना हम रो रहे हैं, यह ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप समाप्त करें। प्लीज समाप्त करें।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): मैं ऐसे नहीं कर सकती, साहब, बोलने के लिए खड़ी हुई हूं, कृपया आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप सबको टाइम देते हैं। मैं पहली बार बोल रही हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस नरेगा का पुनरलोकन करिये।

श्री सभापति: चलिये, आप दो मिनट और बोलिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): भ्रष्टाचार रोकिये और जिस लोकपाल की नियुक्ति की आपने घोषणा की है, उसको तुरन्त करिये ताकि इस पर चैक लगे, इसमें से भ्रष्टाचार निकले। लोगों को पूरा काम मिले, पूरे 100 दिन की मजदूरी मिले, 100 रुपये मिलें, यह आप लोगों को इसमें काम करना चाहिए।

दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी जो आज के परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है कि पूरे राजस्थान में पानी की दिक्कत है। सब जगह जल, जल, जल। जल नीति बनायी। बजट के अन्दर लिखा कि हमने जल नीति बना दी। बनाने से क्या पानी की प्यास बुझ गयी? अगर, अशोकजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी बजट पेश करते समय 16 बार पानी नहीं पीते तो बजट पर बोला ही नहीं जाता। जब उनको बजट पढ़ने के लिए पानी चाहिए तो गरीब किसान को, मजदूर को अगर जीने के लिए पानी चाहिए तो वह पानी कब उपलब्ध करवाओगे? मैं मेरे क्षेत्र की बात करती हूं, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आती हूं वहां पूरे का पूरा क्षेत्र डार्क जोन है। भू-जल बिलकुल खारा है और जो स्रोत काम में आते थे, वे खतम हो चुके हैं। कोई भी साधन नहीं है कि वहां के लोग पीने का पानी प्राप्त कर सकें। इसी कारण से जब मैंने 295 के अन्दर यह मुद्दा उठाया तो सरकार का जवाब आया कि अगर इस समस्या का हल करना है, उन्होंने लिखा है, ''उपरोक्त सभी परिस्थितियों के मद्देनजर तहसील राजगढ़ के समस्त ग्रामों की समस्या के स्थाई निदान हेतु 'आपणी योजना' पी.एम.सी., चूरू द्वारा बूंदी राजगढ़ परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना आवश्यक है।'' इसी कारण से मुख्य मंत्रीजी, तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी द्वारा इस योजना की स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति भी हो गयी, टेंडर भी हो गये। लेकिन ज्यों ही सरकार बदल गयी यह योजना खटाई में डाल दी, न पिछले बजट में इसका कोई उल्लेख किया और न इस बजट में इसका उल्लेख किया। क्या चूरू जिले की राजगढ़ पंचायत समिति का क्षेत्र है, मेरा विधान सभा क्षेत्र है, वह इस राजस्थान के नक्शे में नहीं है? यहां लोगों को प्यास नहीं लगती है? अमर हैं क्या वे? (व्यवधान)

श्री सभापति: अब कृपया समाप्त करें।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): आप लोगों को यह सोचना चाहिए कि पानी से पतला क्या है। इस पतली-सी चीज को भी आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या सुशासन देंगे? क्या पारदर्शी सरकार है आपकी? क्या संवेदनशील सरकार है? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र की पानी की समस्या का तुरन्त निदान करें। बूंदी जल-प्रदाय योजना का शुभारम्भ करवाएं, नहीं तो मैं इस वैल में आमरण अनशन पर बैठूंगी जब तक यह काम नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री कमल बैरवा।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): अन्त में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, दो ही लाइन कहना चाहती हूं-

बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर।
पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।

ऐसा बजट देने से क्या फायदा जिसमें गरीब को, किसान को, महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिलता? मैं समझती हूं कि यह बजट व्यर्थ है। मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कमल बैरवा।

श्री कमल बैरवा (निवाई): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो अपना दूसरा व गांव और गरीब को ध्यान में रखकर लोक कल्याणकारी बजट पेश किया है, उसके समर्थन में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राज्य के लिए ऊर्जा को सबसे ज्यादा महत्व देते हुए इस बजट में 12434 करोड़ का योजनागत व्यय प्रस्ताव स्वीकृत किया है जो वार्षिक योजना का 52 परसेंट है, इससे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनेगा और राज्य के विकास में प्राण वायु के संचार की कमी को दूर किया जा सकेगा। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य क्षेत्र में थर्मल पावर स्टेशन, सूरतगढ़ की छठी इकाई, कोटा की सातवीं इकाई एवं छबड़ा की पहली इकाई में विद्युत उत्पादन चालू हो गया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं करें।

श्री कमल बैरवा (निवाई): इस प्रकार 2009-10 में पारम्परिक स्रोतों से विद्युत उत्पादन की क्षमता 945 मेगावाट हो जाएगी जिससे राज्य की विद्युत की कमी की पूर्ति हो सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जल संसाधन के अन्तर्गत चालू योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सिंचाई परियोजना की कुशलता पर विशेष ध्यान दिया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान की 33500 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जल नीति तैयार की है जिसमें राज्य को अति लाभ होगा। पेयजल हेतु 2010-11 में राज्य योजना मद में 1231 करोड़ रुपये एवं सी.एस.एस. मद में बजट के माध्यम से 284 करोड़ का जो प्रस्ताव रखा है उसमें 61 कस्बों, अनुसूचित जाति की 900 बस्तियों एवं 2627 गांवों-ढाणियों में पेयजल उपलब्ध करवा कर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देता हूं। अभी हाल ही में बीसलपुर परियोजना से टौंक कस्बे को भी जोड़ा गया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 'जल-मणी' कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 5000 पाठशालाओं में शुद्ध जल उपलब्ध कराने हेतु जल शोधन इकाइयां स्थापित करने का जो लक्ष्य रखा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी योजना रखी जिससे बच्चों को शुद्ध जल मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बी.पी.एल. रक्षा कोष योजना, 2009 को पुन: चालू किया। इसके अन्तर्गत चयनित बी.पी.एल. परिवार, स्टेट बी.पी.एल. परिवार, आस्था कार्डधारी तथा एच.आई.वी. पीड़ित मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अब इस योजना में वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशनरों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी जिससे इन लोगों को इलाज सुविधा मिलेगी और लाभ मिलेगा, इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत नर्सों का पारिश्रमिक 4300 से बढ़ाकर 7500 रुपये, ए.एन.एम. का 3500 से 6000 रुपये और लैब टैक्निशियन का 3000

(श्री कमला बैरवा)

से 5500 रुपये बढ़ाकर सराहनीय कदम उठाया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देना चाहता हूं। निश्चित तौर से इन कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा और वे गांव में ठहराव करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो नि:शक्तजन नीति अपनायी है इससे गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने में अधिक सुलभ अवसर बन सकेंगे। वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन 75 वर्ष से अधिक आयु वालों को 750 रुपये, 75 वर्ष से कम आयु वालों को 500 रुपये और 75 वर्ष से अधिक आयु वाले पति-पत्नी को 1500 रुपये करने से इस वर्ग के बुजुर्गों को मैं समझता हूं राहत मिलेगी, उनका जीवन-यापन अच्छी तरह से हो सकेगा। वृद्धावस्था पेंशन के साथ-साथ विधवा व विकलांग पेंशन की दरें भी 400 से बढ़ाकर 500 जो की हैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, वह सराहनीय कदम है। पालनहार योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग एवं एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चों को भी 675 रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने का जो निर्णय किया है, इसमें इन बच्चों का जीवन-यापन ढंग से हो सकेगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय का इसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मदरसा बोर्डों में भी अच्छी शिक्षा मिल सके, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो करोड़ का प्रस्ताव रखा है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देना चाहूंगा। मदरसों में पुस्तकालय, कम्प्यूटर, फर्नीचर व अन्य आवश्यक संसाधन की कमी पूर्ति हो सकेगी जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने में अच्छी सुविधाएं मिल सकेंगी।

जयपुर में अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए छात्रावास का जो निर्माण करवाया जाएगा, निश्चित तौर से यह सराहनीय काम है। इससे अल्पसंख्यक बच्चियों को पढ़ने में सुविधाएं मिल सकेंगी और वे अपना अच्छा अध्ययन कर सकेंगी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में गांवों का विकास भी शहरों की भांति हो, इसके लिये भू-उपयोग का मास्टर प्लान तैयार कर इसमें विद्यालय, अस्पताल, बस स्टैण्ड, राजकीय भवन, सरकारी आवास, खेल के मैदान, डेयरी आदि को सम्मिलित करने का प्रावधान रखा है जिससे गांवों का भविष्य में संतुलित विकास हो सके।

(श्री कमला बैरवा)

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करने की घोषणा की थी, अब उसका विस्तार करके आगामी खरीफ 2010 से सम्पूर्ण राज्य में लागू करने की घोषणा की है, वह सम्पूर्ण राज्य में लाभदायक होगी।

माननीय सभापति महोदय, अकाल की स्थिति को देखते हुए किसानों को 9 लाख दो हजार चार मिनीकिट्स दिये गये हैं जिससे निश्चित तौर से किसानों को लाभ होगा।

माननीय सभापति महोदय, शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के अन्तर्गत जो कार्यवाही हुई, उससे आमजनों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हुई, यह राज्य सरकार का एक सराहनीय कदम है।

डा. दिगम्बर सिंह: वह पढ़कर बोल रहे हैं।

श्री सभापति: वह बोल रहे हैं, बोलने दें।

श्री कमल बैरवा (निवाई): सम्माननीय डा. साहब, बोलने तो दें। पहली बार ही निवेदन कर रहा हूं, क्यों टोकते हो?

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये थोक विक्रेताओं, कार्यकारी संस्थाओं की कमीशन दर प्रति क्विंटल पांच रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये की गयी है व खुदरा विक्रेताओं को कमीशन 8 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये किया गया है, निश्चित रूप से व्यापारियों को इससे लाभ होगा, सुविधा होगी और जो घपलेबाजी करते हैं उसमें कमी आएगी।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बी पी एल परिवारों को 4 रुपये 70 पैसे में मिलने वाले गेहूं को 2 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराने की जो घोषणा की है, निश्चित तौर से राज्य की जनता को इससे लाभ होगा।

माननीय सभापति महोदय, बजट में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को आठवीं, दसवीं और बारहवीं में जिले में प्रथम आने पर 25 हजार, 40 हजार, 50 हजार रुपये का पुरस्कार देने का प्रावधान रखा है, यह सराहनीय कदम है। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा दसवीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम तीन छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु

(श्री कमला बैरवा)

जो प्रावधान रखा है, वह बहुत सराहनीय कदम है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस तरह का प्रावधान रखा ताकि हमारी प्रथम आने वाली बच्चियां विदेश में जाकर अध्ययन कर सकें, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, निश्चित तौर से सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उच्च शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के उप खण्ड मुख्यालय पर स्थापित सभी महाविद्यालयों में वाणिज्य, विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने हेतु ...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री सभापति: थोड़ा आप संक्षेप कर लीजिये। थोड़ा संक्षेप कर लीजिये।

श्री कमल बैरवा (निवाई): साहब, कुछ तो बोल ही रहे हैं। थोड़ा बहुत संक्षेप में ही है।

उप खण्ड मुख्यालय स्थित सभी महाविद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने की योजना के क्रम में आगामी वर्षों में 13 उप खण्डों में विज्ञान संकाय तथा 6 उप खण्डों में वाणिज्य संकाय प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। साथ ही राज्य के 8 राजकीय महाविद्यालयों हेतु भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाकर नवीन पदों का सृजन किया जाएगा, जिसमें 7 करोड़ 73 लाख खर्च किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में राजकीय महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में नये उपकरण क्रय करने हेतु 4 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, यह राज्य सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कदम है। इस क्रम में माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं यह भी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री कमल बैरवा (निवाई): बस दो मिनट, साहब।

मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में महाविद्यालय खोलने की मांग काफी समय से चल रही है, मैंने पूर्व में भी कई बार निवेदन किया है। टौंक जिले की सभी तहसीलों में महाविद्यालय संचालित हैं, निवाई में लगभग 1500 छात्र-छात्राएं कालेज में अध्ययनरत हैं वे टौंक अथवा जयपुर में उच्च शिक्षा हेतु जाने को विवश हो जाते हैं। जो सक्षम परिवार हैं वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला पाते हैं और जो अल्प आय वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, उनके बच्चे अध्ययन से वंचित रहते हैं। इसलिये मैं

(श्री कमला बैरवा)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि निवाई में भी महाविद्यालय खुलवाने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति: बीच-बीच में थोड़ा आसन की तरफ भी देख लें। संक्षेप करें।

श्री कमल बैरवा (निवाई): देख रहा हूं।

महाविद्यालय खुलवाने की व्यवस्था शीघ्र कर दें जिससे निवाई के आम जनों के बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिल सके और बच्चे वहां जाकर अपना जीवन-निर्वाह कर सकें।

अन्त में, 108-एम्बुलेंस सब जगह उपलब्ध करवाई गई है, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, निवाई शहर एन एच-12 पर स्थित है और वहां आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि अभी दो-तीन दिन पहले एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, उसमें 40 आदमी घायल हुए और 3 मौके पर ही खत्म हो गये। वहां 108-एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ी और टौंक जिले से वह एम्बुलेंस मंगानी पड़ी। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की, यह ठीक है, मगर 108-एम्बुलेंस वहां मौजूद होती तो निश्चित रूप से उन मरने वाले लोगों को बचाया जा सकता था।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पत्रकारों की आवासीय समस्या के समाधान हेतु जयपुर की भांति नगरपालिकाओं में योजना बनाकर प्राथमिकता से रियायती दरों पर भूखण्ड अथवा मकान आवंटन कराने की घोषणा की, इससे पत्रकार बंधुओं को लाभ मिलेगा, इसके लिये मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

अन्त में आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि 9 मार्च को जो बजट मुख्य मंत्री महोदय ने वित्त मंत्री की हैसियत से पेश किया है, वह सकारात्मक, आम आदमी एवं गरीब को ध्यान में रखते हुए राज्य के विकास के लिये समर्पित है, इसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, बजट प्रतिक्रिया में बोलने के लिये जो आपने मौका दिया, मेरी बात सुनी, उसके लिये मैं आपका और पूरे सदन का धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद, बहुत सुन्दर। डा. जसवन्त यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, 2010-11 जो बजट पेश हुआ है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वित्त मंत्री की हैसियत से पेश किया, सही मायने में अभी डा. रोहिताश्व जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि वसुन्धराजी ने 71 हजार करोड़ की पंचवर्षीय योजना मंजूर कराई, बहुत बढ़िया बात कह रहे थे कि सरकार ने यह बजट इस तरह पेश किया जैसे किसी मृतक कर्मचारी के बच्चों को नौकरी देनी हो, परन्तु इसमें न कोई विजन है, न कोई सोच है। बजट का मतलब तो यह होता है कि राजस्थान का भी विकास हो, किसान का भी विकास हो, कर्मचारी का भी विकास हो, मजदूर का भी विकास हो, व्यापारी का भी विकास हो, सबके लिये समान उद्देश्य हों। मैंने इस बजट की आर्थिक समीक्षा पढ़ी, राज्य की आर्थिक समीक्षा में प्रदेश में इस वर्ष कृषि उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले में 35.84 प्रतिशत कम रहने की आशंका व्यक्त की गयी है। राज्य के इस बजट में जारी की गयी आर्थिक समीक्षा में प्रदेश में उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में तो स्थिति को बहुत हद तक ठीक माना गया है, लेकिन कृषि उत्पादन की तस्वीर को चिन्ताजनक बताया गया है। कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू राज्य उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले 18.99 प्रतिशत कम रहने की आशंका व्यक्त की गयी है, जबकि उद्योग का सकल घरेलू उत्पादन पिछले की तुलना में 8.14 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का 10.76 प्रतिशत अधिक रहने की सम्भावना व्यक्त की गयी है। सकल राज्य घरेलू उत्पादन में प्रचलित कीमतों के आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में 8.97 प्रतिशत की सम्भावना व्यक्त की है। इसी तरह पानी के बारे में सरकार ने दर्शाया है कि 164 ब्लाक्स और एक्स्प्लायट हो गये, 34 ब्लाक्स क्रिटिकल पोजीशन में हैं, 8 ब्लाक्स सेमी क्रिटिकल श्रेणी में हैं और केवल 30 ब्लाक्स सुरक्षित माने गये हैं। तो यह बजट सही मायने में हमारे पक्ष के लोग बोलते हैं, गांव को, किसान को दिया, या तो वे समझ नहीं पा रहे हैं या मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सही मायनों में तो यह बजट होना चाहिए था कृषि पर आधारित। किसान के हित को बचाने के लिए एक विजन होना चाहिए था, कि कृषि की आय कैसे बढ़े, विपणन श्रृंखला उसकी कैसे सृजन हो, जल का प्रबंधन कैसे हो और वैल्यू एडिशन, ग्रेडिंग, पैकिंग कृषि की ये चीजें कैसे बनें। पर सरकार का इधर ध्यान ही नहीं गया। अब मैं बहुत लम्बी बात नहीं कहना चाहता। सारे राजस्थान में सरकार ने दर्शाया कि पानी नहीं है, अब मेरा अपना विधान सभा क्षेत्र डार्क जोन में आ गया, वहां किसान रहता है, किसानों का क्षेत्र है और सरकार...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन की सहमति है एक घंटा बढ़ाने के लिए? (व्यवधान) आपकी सहमति है दो घंटे के लिए? (व्यवधान)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र से आता हूं और मेरे अपने ही जिले के अन्दर ज्यादातर पंचायत समितियां, ज्यादातर तहसीलें डार्क जोन के अन्दर घोषित कर दी गई हैं। अब वहां प्रबंध कर दिया कि न आप कुआ गहरा कर सकते हैं, न वहां बिजली का कनेक्शन मिलेगा। तो सरकार ने एक बार भी सोचा कि जिस किसान से राम भी रूठ जाए, राज भी रूठ जाए, वह किसान बेचारा कहां जाएगा? एक किसान ही ऐसा है, हम नरेगा की बार-बार बात करते हैं, नरेगा से ज्यादा रोजगार अगर गरीब को, बीपीएल वालों को, मजदूरों को कोई दे पाता है तो वह किसान देता है। खेती अच्छी नहीं होगी, किसान बर्बाद होगा, गरीबों को मजदूरी नहीं मिलेगी, राजस्थान का विकास रुक जाएगा, और इस बात को हम सब मानते हैं कि 80 परसेंट लोग राजस्थान के अन्दर किसान हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि किसान की उन्नति हो, खेती बचे, किसान खुशहाल हो तो राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। पर सरकार ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि डार्क जोन के अन्दर जहां पानी नहीं है, किसान के बच्चे खेती पर आधारित हैं, किसान खेती पर आधारित हैं, उनके भी बच्चे हैं, वे भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको भी अपनी बेटियों की शादी करनी है, उनको भी घर के अन्दर रहना है, तो वे क्या करेंगे? सरकार को चाहिए कि जो डार्क जोन इलाके हैं उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा करे।

बिजली मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मैं कई बार मिल चुका हूं, एक ही राग है - गांव का विकास। गांव का विकास कैसे होगा? 8 घंटे की घोषणा कर दी, फिर 12 घंटे की कर दो, पर रियल में सभापति महोदय, आप भी किसान हैं, आप भी उसी एरिया से आते हैं, बिजली मंत्री भी किसान हैं, किसान को बिजली

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

नहीं मिल पाती है। किसान इतना बर्बाद हो गया, पता नहीं बिजली मंत्रीजी की नालेज में है या नहीं है यह बात, कि लोगों को 6-6 महीने हो गये डिमाण्ड नोटिस जमा कराये हुए। वे जाते हैं बिजली दफ्तर में तो बिजली के अधिकारी कह देते हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है, हमारे पास मीटर नहीं है, हमारे पास तार नहीं है। उनको कनेक्शन नहीं मिलता है, उनकी फसल चौपट हो गई है। जिस गांव की ये बात करते हैं, उस गांव के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात आज तक कभी देखी नहीं, बहुत लम्बे समय से हम भी देखते आ रहे हैं गांव की हालत, कि सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर फुंके पड़े हैं। बच्चों का भविष्य है, परीक्षाएं चल रही हैं लेकिन ए.ईएन. से बात करें तो साहब एक्स.ईएन. को धमका दो, एक्स.ईएन. से बात करें तो एस.ई. को धमका दो। एस.ई. से बात करें, वह कहता है चीफ इंजीनियर से बात कर लो। पता लगता है कि सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर हैं ही नहीं। बिजली मंत्रीजी पता नहीं क्या कर रहे हैं।

इसी तरह से, जब किसान की फसल खड़ी होती है और किसान का ट्रांसफार्मर का अगर एक भी तार जल जाता है तो, किसान के हित की आप सोच ही कहां रहे हो, उस किसान को अपना ट्रांसफार्मर ठीक कराने के लिए आफिस में लाना पड़ता है। क्या कोई टैक्निकल अधिकारी है, कोई टैक्निकल उसके बारे में है क्या? मेरे क्षेत्र में कम से कम बिजली मंत्रीजी, 15-20 नौजवान मर चुके हैं इन एक्सीडेंट्स में। उनके ट्रांसफार्मर को ठीक करने कोई जाता नहीं है। फसल खड़ी होती है, दोहरा सिस्टम है, लाने-जाने के साधन नहीं होते, वह किसान बेचारा कैसे ट्रांसफार्मर लेकर जाएगा? कई अगर करते हैं, करते भी हैं मेहनत, तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। इधर ध्यान ही नहीं है सरकार का। सरकार को होश ही नहीं है कि हो क्या रहा है। यह नहीं कि बिजली कितनी उत्पादन कर लो, बिजली उत्पादन होने से लाभ मिलेगा, आगे बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता बनेगी, पर डिस्ट्रीब्यूशन तो हो, उसकी जो रियलिटी है उस पर तो ध्यान दिया जाए कि जब मीटर नहीं, तार नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं तो बिजली कहां लेकर जाएंगे किसान? किसान को जो बिजली देते हो आप, 8 घंटे दे नहीं सकते, झूठी वाहवाही लेने से आपको कोई लाभ नहीं है। आप कम से कम इतना कर दो कि जो किसान बर्बाद होता है, जिनकी मोटरें जलती हैं, दुनिया भर का आर्थिक नुकसान होता है, उस किसान को फिक्स कर दो कि 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बिजली आएगी और फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। बीच में आई-

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

गई, आई-गई, उसकी तो मोटर जल जाती है और यहां बैठकर नेता अपनी बात कह लेते हैं। एक भी किसान ऐसा नहीं है, जो यह नहीं कहता हो, कभी इस बात का रोना रोया ही नहीं कि आप बिजली के दाम मत बढ़ाओ। वह यह कहता है कि मर्जी में आए जितने बिजली के दाम बढ़ा दो, पर कम से कम हमको बिजली दे दो, 24 घंटे दे दो। आप अगर किसान की और गांव की बात करते हो तो कौन रोक रहा है? आप सरकार में हो, कृषि को आप उद्योग का दर्जा दे देते। किसान को आप लम्बित करते हो, 6-6 महीने, साल-साल भर में आना, उनको कनेक्शन नहीं मिलते। अगर जरा-सी भी संवेदना है, राजस्थान को बचाना है तो आप जिस दिन यह फिक्स कर दें, भ्रष्टाचार भी खतम हो जाएगा और किसान को लाभ भी मिल जाएगा, कि जब वह एप्लाई करे, 6 महीने में, 2 महीने में उसको सौ परसेंट मिलेगा, वह चाहे बिजली दफ्तरों के चक्कर काटे या नहीं काटे। पर इधर कभी ध्यान ही नहीं जाता। किसान का बेटा कृषि मंत्री होगा फिर भी ध्यान नहीं तो फिर ध्यान कब जाएगा?

इसी तरह, कृषि उपज मंडी के मंत्रीजी बैठे हुए हैं, किसान की, गांव के विकास की बात आती है, तो कि, साहब, प्लानिंग बनेगी। मैं सन् 1995 में जिला प्रमुख बना, बड़े खुश हुए थे, प्लानिंग कमेटी बनी कि, साहब, ऊपर से माननीय राजीवजी का प्लान है, गांव का प्लान बनेगा। 1995 से बनते बनते तो मैं देखता आ रहा हूं, खाली कल्पना करने से क्या होगा? आज गांवों की जो दुर्दशा है शायद इससे ज्यादा और दुर्दशा का हाल और कोई हो नहीं सकता। गांव का आदमी पता नहीं किसलिए जिंदा बेचारा रह रहा है, किस तरह से अपना गुजारा कर रहा है। कृषि उपज मंडी की सड़कें, मैंने कृषि मंत्री से बात की, जो सड़कें बनी थीं, कुछ सड़कें तो आपने पीडब्ल्यूडी को दे दीं, पर जो सड़कें बनी थीं, उनका नामोनिशान रहा है, उनसे सीधे गांव जुड़ते हैं। गांव के विकास की आप बात करते हो, कृषि उपज मंडी के मंत्री के पास सीधा जवाब है कि हमारे पास इनकी मरम्मत का कोई फंड ही नहीं है। तो गांव का आदमी कहां जाए? ये सारी सड़कें शहर से तो जोड़ी नहीं गई हैं, ये तो सारी की सारी गांवों से जुड़ी हुई हैं। जब सड़कें ही नहीं हैं तो गांव का विकास कैसे होगा? सड़क और विकास तो साथ-साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। या तो उन स्थानों का पीडब्ल्यूडी में समावेश करे जिससे कि उनकी मरम्मत हो सके। या कृषि उपज मंडी का फंड, नई सड़क के बजाय इस बार सरकार इस तरह का प्रावधान करे कि उन सड़कों की मरम्मत हो सके।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

इसी तरह से, सार्वजनिक निर्माण की बात आती है। सार्वजनिक निर्माण की जब बात आती है, तो इतने किलोमीटर हम सड़कें बना देंगे, सड़कें जरूरी हैं। गांव के अन्दर पीडब्ल्यूडी की सड़कें बन रही हैं, कुछ गांवों को छोड़ कर। स्टेट हाई वेज हैं, उसके अलावा जो आम गांव के अन्दर पीडब्ल्यूडी की सड़कें जुड़ी हुई हैं, वे सड़कें खतम हो गई। सड़कें खतम हो गई तो अब यह हालत है कि न उनमें नरेगा का पैसा लग सकता है, न एमपी मद का पैसा लग सकता है, न विधायक मद का पैसा लग सकता है। वे सड़कें इस कदर क्षतिग्रस्त हो गई कि उनमें पानी भरा हुआ है, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां फैलती हैं। आप उधर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। सड़कें बनाएं या न बनाएं, गांवों की हालत आप ठीक कर दें। परिवहन मंत्रीजी भी यहां बैठे हुए हैं, पिछली बार भी बजट में था कि हम एक हजार नई बसें पुरानी बसों के स्थान पर खरीदेंगे, खुशी हुई थी। पर, परिवहन मंत्रीजी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि आपके इस सवा साल के कार्यकाल में हमारे यहां तो एक भी गांव नया परिवहन सेवा से नहीं जुड़ा। बल्कि दो गांव मेरे यहां से जहां बसें जाती थीं, उन बसों को रोक दिया। इसमें भी बहुत आराम से आप आम गांव के लोगों का विकास कर सकते हैं, गांव के लोगों को रोजगार दे सकते हैं, थोड़ा-सा बड़ा दिल करने की जरूरत है। डग्गेमारी में जो जुगाड़ चलते हैं, जीपें चलती हैं, आज गांव का नौजवान बहुत ज्यादा बेरोजगार है, अगर आप उनको जीपों का परमिट मुहैया करवा दें तो गांव के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और लोगों को राहत भी मिल जाएगी। आपका भी लाभ हो जाएगा जिससे हर गांव को परिवहन से जोड़ा जा सकता है।

(समय : 19.00 बजे)

इसी तरह गांव के विकास की बात आती है शिक्षा के मामले में। एक तरफ तो कहते हैं कि हम गांवों को कम्प्यूटर से जोड़ेंगे, पंचायतों को कम्प्यूटर देंगे जबकि सच्चाई यह है कि गांवों के कितने स्कूलों के अन्दर साइन्स के सब्जैक्ट और कितने स्कूल्स में कामर्स सब्जैक्ट हैं? क्या बिना साइन्स और कामर्स के, खाली कम्प्यूटर सीख लें? इससे गांव का विकास हो जाएगा, इससे बच्चे का भविष्य बन जाएगा? आज गांवों में टीचर नहीं हैं। मैं तो निवेदन करता हूं कि गांवों का अगर आप वाकई में भला चाहते हो, आपका मन है भला करने का, तो गांव के हर स्कूल के अन्दर कामर्स और साइन्स की शाखा खोल देनी चाहिए।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

इसी तरह इन्टरनेशनल महिला दिवस मना रहे हैं सोनियाजी भी चिन्तित हैं और हम भी चिन्तित हैं। अगर चिन्तित होते तो एकाध महिला कालेज तो खोल देते। इसके लिए किसी ने रोका है क्या? जिन विधान सभा क्षेत्रों में तहसीलों में दूर-दूर तक कोई सरकारी महिला कालेज नहीं है, वहां कम से कम एकाध महिला कालेज खोल देते तो इससे लगता कि आप महिलाओं के विकास के प्रति चिन्तित हैं।

मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं, उद्योग खूब लगाओ, उद्योगों से राजस्थान का विकास होगा, कोई नहीं रोक रहा। परन्तु गांवों के अन्दर जो आप जमीन खेती की लेते हो, यह तो देख लो कि वह फर्टाइल अधिक है तो उसे मत लो और फिर भी अगर आप लेते हो तो उनको वाजिब मुआवजा दो। दूसरा, उद्योग नीति इतनी मजबूत बनानी चाहिए कि जो बाहर से व्यापारी लोग उद्योग लगाने आते हैं, उन उद्योगों के लिए जिन गांवों के लोगों की जमीनें गयी हैं उनके अन्दर गांवों के बच्चों को नौकरी मिले, उनका हिस्सा मिले, इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी और गांवों के लोगों का उद्धार हो सकता है।

सभापति महोदय, हकीकत यह है कि आज गांव के लोगों को अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। विधवा पेंशन की बात आती है तो केन्द्र सरकार का नियम है कि 25 साल का बच्चा हो जाए, तो आप एक बात बताइये कि 25 साल का बच्चा हो गया, वह विधवा ही हो गयी, उसका बच्चा नौकरी लगा या नहीं लगा, आपने तो उसकी पेंशन बन्द कर दी। जब आप स्टेट बी पी एल को जो पिछली सूची में थे, उनको स्टेट बी पी एल मान सकते हैं, तो इसी तरह विधवाओं को भी स्टेट का विधवा मान सकते हैं जिससे उनको जिन्दगी भर के लिए पेंशन मिल जाए। तो वे आराम से गुजर कर सकती हैं, मान-सम्मान के साथ जी सकती हैं।

हम बार-बार कहते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन दें, सबसे ज्यादा अगर दयनीय स्थिति है, चाहे वह गरीब है या अमीर, तो बुजुर्गो की है। आज के इस आधुनिक युग में 80 प्रतिशत बुजुर्ग ऐसे हैं जो लाचार हैं, जिनके बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं। हरियाणा हमारे पड़ौस में है, वहां चाहे कोई गरीब हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, सबको 700 रुपये पेंशन मिलती है। आप भी कुछ बड़ा दिल करते। साठ साल मत करो, हालांकि हरियाणा में साठ साल है, आप 75 साल ही कर देते।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जो केन्द्र की योजनाएं हैं, उनमें आप अपना पूरा अनुदान देते नहीं हो और केन्द्र की योजनाओं की वाहवाही लूटना चाहते हो। केन्द्र में किसी की भी सरकार हो, वह तो राज्यों को हिस्सा देगी, लेकिन आपकी राशि नहीं मिलने से वहां से आया हुआ हिस्सा वापस तक चला गया। सारे लोग कह रहे हैं कि मुख्य मंत्रीजी का बड़ा अच्छा विजन था, सही मायने में तो यह है कि यदि सरकार का विजन ठीक नहीं होगा, सरकार जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं करेगी, सरकार जब तक इस जनसंख्या के ऊपर कोई रोक नहीं लगाएगी, तब तक इस राजस्थान का विकास नहीं हो सकता। आज राजस्थान सबसे ज्यादा त्रस्त है। खाली यह कहने से काम नहीं चलेगा कि पिछली सरकार यों, अगली सरकार यों। अगर राजस्थान का सही मायने के अन्दर सर्वेक्षण हो, सही मायने में लोगों की राय ली जाए, सही मायने में थानों का आकलन किया जाए तो राजस्थान कहीं प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है तो दो ही चीजों में कर सकता है, एक तो भ्रष्टाचार में और दूसरा जनसंख्या बढ़ाने में। हम, चिट्ठी तो जरूर लिख देंगे, मानें या नहीं मानें, कि अशोक गहलोत की सरकार को अगली जो 26 जनवरी आए, जनसंख्या बढ़ाने में और भ्रष्टाचार को बढ़ाने में और अधिकारियों की नकेल नहीं थामने में इनाम दिया जाए, हिन्दुस्तान में पहला नम्बर आएगा। राम राम सा, धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, वर्ष 2010-11 का हाल ही में जो बजट पेश हुआ है उसका सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं। जब राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के नाते बजट पेश किया उस समय महाभारत काल के कृष्ण और सुदामा की बात को उन्होंने ताजा कर दिया और वह बात याद आ गयी कि भगवान श्रीकृष्ण ने गरीबों के प्रति और दोस्ती के प्रति एक पैगाम दिया था। माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने गरीबों के प्रति सही भावना रखते हुए मात्र दो रुपये किलो गेहूं देने की घोषणा करके यह साबित कर दिया कि गरीबों के प्रति सच्ची भावना वाली और गरीबों की कोई सरकार है तो वह कांग्रेस है। गरीबों के मसीहा मुख्य मंत्री हैं तो वह लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत हैं।

(श्री मदन प्रजापत)

सभापति महोदय, आज बात करना अलग बात है लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकली खरा उतरना अलग बात है। कल दो रुपये किलो की कई माननीय सदस्य मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मैं माननीय खाद्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, दो रुपये किलो के गेहूं का यह कदम उठाना कोई मामूली बात नहीं है। साथ ही, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की बात आती है तो आज बी पी एल, स्टेट बी पी एल और उसके बाद तमाम प्रकार के पेंशनधारियों को मुफ्त में इलाज के लिए बजट में जो प्रस्ताव लाया गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि हमेशा आम आदमी के प्रति माननीय मुख्य मंत्री महोदय की भावना है। ऐसा प्रतीत होता है कि अगर आम आदमी की कोई सरकार है तो वह कांग्रेस की सरकार है। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष में बी पी एल, स्टेट बी पी एल और उनके साथ तमाम पेंशनधारियों को मुफ्त में इलाज के लिए जो किया है उससे यह एहसास करवा दिया कि अगर आम आदमी के मुख्य मंत्री और आम आदमी की सरकार है तो मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी की है और कांग्रेस की सरकार है।

सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में जाएं। आज बार-बार दो घंटे की बात कर रहे हैं, चार घंटे की बात कर रहे हैं, लेकिन सीमान्त जिले, पिछड़े जिले और रेगिस्तानी जिले में सात-आठ घंटे बिजली आती है, सर्वे करवाया जाए तो पता चल जाएगा। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य जो बात कह रहे थे, विरोध करना अलग बात है, विपक्ष का धर्म है, लेकिन बिलकुल +++ बार-बार माननीय वरिष्ठ सदस्य कहते हैं कि जनता देख रही है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आपको मालूम नहीं है। जिसको तकलीफ होती है वह बोलता है। मंत्रीजी बताएंगे। आप कौन होते हैं बोलने वाले? +++ शब्द कैसे कहा आपने?

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति महोदय, प्रोसीडिंग में से निकालो इस +++ शब्द को। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आप मंत्री हो? आप मंत्री का जबाव देंगे?

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, आज ऊर्जा के क्षेत्र में बाड़मेर जिले में हकीकत में सात-आठ घंटे बिजली आ रही है। लेकिन विपक्ष का धर्म है विरोध करना। बार-बार हम कह रहे हैं, जनता देख रही है। जनता बाहर देख रही है, राजस्थान की सौ करोड़ जनता देख रही है, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आपने सुना नहीं, मैंने कहा, सारे राजस्थान में आती है, गंगानगर में नहीं आती। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दीजिए न। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप तो सुनो, आप बोले तब कौन बोला था?

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सदस्य, पुराने हो, आप व्यवधान क्यों कर रहे हो माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो? और आप तो इधर से ही गये हो। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान की सौ करोड़ जनता देख रही है, राजस्थान की सौ करोड़ जनता ने हाल ही महीने-पन्द्रह दिन पहले पंचायत चुनाव में राजस्थान की कांग्रेस सरकार और लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय अशोकजी गहलोत के कार्यकाल से खुश होकर वापस प्रमाणित कर दिया है कि राजस्थान का अगर कोई भला कर सकता है तो वह मात्र कांग्रेस पार्टी कर सकती है, कांग्रेस सरकार कर सकती है और उसका नेतृत्व हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में गांवों में हर तीन पंचायतों में एक जी.एस.एस., मैं उसका धन्यवाद माननीय जितेन्द्र सिंजी, ऊर्जा मंत्रीजी को देना चाहता हूं। 33 के.वी. के 320 जी.एस.एस. गांवों के लिए, यह कोई क्रांतिकारी कदम नहीं तो और क्या है? किसानों के प्रति जो कनेक्शन की भावना है, 65 हजार कृषि कनेक्शन का लक्ष्य बजट में दिया है। साथ ही पेयजल के मामले ले लें तो माननीय मुख्य मंत्रीजी और पेयजल मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि दवा-उम्मेद सागर-कल्याणपुर-समदड़ी का फर्स्ट और सैकिण्ड पार्ट इसी वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य आपने रखा है। सीमांत बाड़मेर जिले में जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे पोकरण-फलसूंड-बालोतरा हो चाहे बाड़मेर लिफ्ट कैनाल हो, तमाम पेयजल की योजनाएं इसी सरकार में पूरी होंगी, हमें पूरा-पूरा विश्वास है। ऐसा नहीं कि गत सरकार की भांति झूठे उद्घाटन कर दिये कि आज भी वहां पाइप मुंह नहीं बोल रहे हैं। गवाह हैं, हजारों की संख्या

(श्री मदन प्रजापत)

में इकट्ठे किये गये और उद्‌घाटन किये गये, आज भी नहीं हैं। लेकिन मात्र छह महीने में उम्मेद सागर से बालोतरा-पचपदरा विधान सभा क्षेत्र होकर समदड़ी तक पानी पहुंचा दिया, एक मीटर की पाइप लाइन पहुंचा दी, यह कोई मामूली काम नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज सड़क क्षेत्र का ले लो, खास कर सीमांत जिले बाड़मेर और जैसलमेर में ढाणियों में बसे हुए लोग हैं, लोग खेतों में निवास करते हैं उनकी पीड़ा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने समझी। सड़क के माध्यम से 5187 ढाणियां और मजरों को जोड़ना और पेयजल के लिए 3354 करोड़ रुपये का जो लक्ष्य रखा गया है, मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का कि ढाणियों में निवास करने वाले लोग हैं, जो खेतों में आम गरीब और किसान निवास कर रहे हैं, उनका शहरों से सीधा सम्पर्क होगा, आने-जाने में उनको तकलीफ नहीं होगी। उनकी भावना गांवों में निवास करने वाले लोगों के प्रति है, ढाणियों में निवास करने वाले लोगों के प्रति है, आम जनता जानती है।

माननीय सभापति महोदय, और भी ले लें, तो माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावना युवाओं के प्रति है, माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावना छात्राओं के प्रति है, महिला-बालिका शिक्षा के प्रति है जिसका प्रमाण अपने पास में है, बजट में आप देख सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो ऊपर चाहे इलैक्ट्रिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है ...

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): एक भी लड़कियों का स्कूल कालेज नहीं है, एक भी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, देश की आजादी से लेकर आज दिन तक जो अख़बार चलाते हैं उनका जी जानता है कि अख़बार कैसे चलाया जाता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में पत्रकार कल्याण के लिए पूरे राजस्थान में तमाम नगर परिषदों में रियायती दर पर भू-खण्ड का जो लक्ष्य रखा है और पत्रकारों के लिए जो सुविधाएं की हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। पत्रकारिता है, एक संदेश देते हैं, एक-दूसरे की बात को संदेश के माध्यम से पहुंचाते हैं, उनका कल्याण अपना कर्तव्य है और आपने पूरे राजस्थान में नगर परिषद में ऐसा किया है।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, युवाओं की बात करें, तो ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ियों को नहर के अन्दर नि:शुल्क 25 बीघा देने का जो लक्ष्य रखा, कल वो सामने बैठे हैं ...

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सदस्यजी, पर पानी तो वहां है ही नहीं। पानी है ही नहीं, आप 25 मुरब्बे क्यों 50 मुरब्बे दे दो चाहे।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आ जाएगा, आ जाएगा। आप दो मिनट सुनें अगर, पानी भी आ जाएगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): पानी गंगानगर होकर आएगा बाड़मेर। माननीय सभापति महोदय, गंगानगर होकर आएगा और वहां पानी पहुंचा ही नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, मैंने बार-बार सदन में भी कहा कि आज भी लोग इंदिरा गांधीजी को याद करते हैं और जैसलमेर में हम जानते हैं, हम वाकिफ हैं कि पानी है या नहीं है। राजनीति करना अलग बात है लेकिन अंतिम छोर तक पानी गया है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अब के सरस्वती का मिलेगा आपको पानी, सरस्वती का।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): जैसलमेर से शाले मोहम्मदजी हैं, यहां बाड़मेर की जनता ने 7 में से 6 विधायक कांग्रेस पार्टी को दिये हैं, अगर पानी नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक नहीं जीतते। माननीय सदस्य, आज खिलाड़ियों के प्रति माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावना है और उन्होंने मुरब्बा और 25 बीघा जमीन देने का जो लक्ष्य रखा है इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की खिलाड़ियों के प्रति और युवाओं के प्रति क्या भावना है। यह सब दर्शाता है। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): कितनी नौकरी दे रहे हो युवाओं के लिए? (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): बोलने दो, तकलीफ हो रही है। (व्यवधान) आप लोग बोलते हो जब ...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नौकरियां कितनी दीं आपके बजट में? (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): यह बजट भाषण पर बोल रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, इधर से सरासर + + +...(व्यवधान) दो मिनट।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि राधेश्यामजी की और भी बोलने की मंशा है।

श्री करणसिंह (छबड़ा): खुलेआम +++ बोलने वाले बोलते रहे और हमारे समय सही बात बोल रहे हैं, सुनो उनको।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): तो बी.जे.पी. का समय काट कर एक घंटा और इनको दिया जाए ताकि उनको शांति हो जाए (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आपने कहा, मैं +++ बोल रहा हूं ...(व्यवधान) आपने यह बात कही।

श्री करणसिंह (छबड़ा): आप वरिष्ठ हो, कमाल कर रहे हो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह हो क्या रहा है? (व्यवधान) यह कोई तरीका है क्या इनका?

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया विराजिये, आसन पैरों पर है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह क्या तरीका है, बार-बार उठ-उठ कर इण्टरवीन कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप भी कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): अगली बार पता नहीं क्या होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कृपया विराजिये। आप जरा विराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बार-बार व्यवधान कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय राधेश्यामजी, मैं आपका नाम लेकर बोल रहा हूं, देखिये, तीन-चार बार हो चुका है, आप व्यवधान कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, अगर आपको कोई एतराज है तो बाद में आप बात कर सकते हैं। आप जब बोल रहे थे तो किसी ने बोला था क्या?

एक माननीय सदस्य: आप व्यवधान करेंगे तो हम भी नहीं बोलने देंगे आपको।

श्री सभापति: पहली बार एक ऐसी बुलंद आवाज आ रही है जो तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बोला करते थे, तो बोलने तो दीजिए इस बुलंद आवाज को। थोड़ी देर बोलिये। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, जब हम पहली बार विधान सभा में जीत कर आये, एक ही आवाज का नारा लगता था कि 108 जो नये जीत कर आये हैं, उनको अनुभव नहीं है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन आगे भी मैंने इस बात का जिक्र किया है और आज भी आपके माध्यम से मैं जिक्र करना चाहता हूं कि सामने बैठे कई वरिष्ठ सदस्य हैं, इस बात का मुझे आश्चर्य है कि शायद उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है और बहुमत भी 108 का हमारे पास है।

एक माननीय सदस्य: नये वालों को जरूरत नहीं है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की योजना चाहे एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों के लिए है कि जो जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करे उसको क्रमश: 25, 40 और 50 हजार का इनाम है, किन्तु इससे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। बालिका का हौसला बुलंद हो ताकि शिक्षा के प्रति वह जाग्रत हो। हाल ही में महिला आरक्षण बिल के परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में महिला शिक्षा की जरूरत को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कदम उठाया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैरिट में प्रथम तीन आने वालों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, शायद ऐसा बजट आज दिन तक देखने को नहीं मिला है, इस बात की भी हम तारीफ करते हैं। लेकिन कई घोर निंदा भी करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब बजट पेश कर रहे थे माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं उन साथियों को भी जो सामने बैठे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं जिनके नाम में ज्ञान है, चाहे ज्ञानदेवजी हों, चाहे ज्ञानचंदजी हों, वो मन के अन्दर मुस्कुरा रहे थे और उन्हें आखिर में तालियां बजानी पड़ीं। इससे साफ

(श्री मदन प्रजापत)

जाहिर होता है कि यह बजट सही है। यह भले ही मजबूरी है उनकी, बजट की घोर निंदा करते हैं लेकिन हमारे साथी ज्ञानदेवजी आहूजा ने, इतने आक्रोश में होते हुए भी अगर तालियां बजा दीं, इससे प्रमाणित होता है कि बजट की निंदा करना उनकी मजबूरी है लेकिन जो बजट पेश किया है वो जन हित में है, आम गरीब के हित में है, आम किसान के हित में है। प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता, वरिष्ठ सदस्यगण और उनके पास बैठे हुए आदरणीय वरिष्ठ सदस्य माननीय कटारियाजी ने भी कई बातों के लिए धन्यवाद भी दिया और मन के अन्दर इतना खुश थे, मैंने पूरा देखा नहीं है, पर शायद उदयपुर क्षेत्र के लिए जो तोहफा दिया है, उस बात का असर हो। लेकिन अपन जानते हैं कि हम समर्थन करते हैं, सामने बैठे हुए विरोध करते हैं। विरोध ही नहीं बल्कि घोर विरोध करते हैं, वह अलग बात है।

माननीय सभापति महोदय, आज अपन जानते हैं कि किसान जो गेहूं पैदा करता है, उसकी हालत क्या है। गेहूं का 1100 रुपये समर्थन मूल्य और मैं धन्यवाद देता हूं खाद्य मंत्री बाबूलालजी नागर को कि 11 रुपये 60 पैसे में खुली बिक्री में बेच रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अपन समझते हैं कि आज किसानों के प्रति उनकी भावना है, आम गरीब के प्रति उनकी भावना है। विरोध अलग चीज है लेकिन हर समय विरोध करते हैं तो वह जनता उलटी नजर से भी देखती है। कई बार सही भी होता है तो अपना दायित्व बनता है, कोई कमी है विपक्ष का धर्म बनता है, उजागर करे, लेकिन अगर सही को भी गलत कहे और गलत को भी सही कहे, आम जनता विश्वास करना बंद कर देगी।

माननीय सभापति महोदय, कई ऐसी बातें भी हमारे को देखने को मिलीं कि आज उनका कोई तुक नहीं था। और भी कई बातें हैं, समय कम है, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि सही बात कहना अपना दायित्व है। जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आया हूं इसी विधान सभा क्षेत्र से चम्पालालजी बांठिया आये थे, उस समय इस विधान सभा में मुद्दा चलता था, लेकिन उसके बाद पन्द्रह साल बाद तक इस सदन में बालोतरा का नाम तक किसी ने नहीं लिया, इस बात का भी अफसोस है। हमें पूरा विश्वास है, माननीय मुख्य मंत्रीजी मैं विनम्र निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, अपील करता हूं, करीब तीस वर्षों से मांग चल रही है और अपन सब जानते हैं कि पूरे मापदण्ड के दायरे से सही है, नियम-कायदे से सही है, किलोमीटर के दायरे में तमाम मापदण्ड देखे जाएं,

(श्री मदन प्रजापत)

वह सही है, मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार जब भी नये जिले बनाए, उसमें बालोतरा को प्रथम प्रायोरिटी पर रखते हुए बालोतरा को जिला बनाया जाए। करीब तीस सालों से मांग है। यह मेरा आग्रह और निवेदन भी है।

माननीय सभापति महोदय, आज परिवहन मंत्रीजी विराजमान हैं उनको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आपकी बाड़मेर यात्रा के दौरान बालोतरा के लिए हमने जो मांग की, बालोतरा की आम जनता की भावना की कद्र करते हुए आपने हाथों हाथ तमाम घोषणाएं कर दीं। आज जिला परिवहन कार्यालय ब्यावर, रामगंजमण्डी के साथ राजस्थान में और कई उदाहरण हैं जहां जिले के अलावा हैं, जिले सैंतीस नहीं हैं लेकिन इनका नम्बर सैंतीस है। मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि बालोतरा का आर जे- 38 बालोतरा का लगे और जिला परिवहन कार्यालय बालोतरा में खोला जाए। क्योंकि आय के हिसाब से देखा जाए तो पूरे बाड़मेर जिले में पचास परसेंट से अधिक आय बालोतरा की है। आंकड़े हैं, नियम-कायदे हैं और सौ किलोमीटर दूरी भी है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह आम-जन की भावना है, आम गरीब को दूर जाना नहीं पड़े।

साथ ही मैं और भी एक बात निवेदन करता हूं, पापलीन नगरी बालोतरा विश्वविख्यात है और शायद थोड़ा पाली और जोधपुर भी। बालोतरा में पापलीन, सूती कपड़ा जो बनता है उसका उपयोग हर घर में होता है। पेटीकोट जो बनता है वह बालोतरा की देन है। उस पेटीकोट में जो सात परसेंट का वैट है, पापलीन में भले ही लगे, उसमें कर का कोई नुकसान नहीं होगा, पर अगर सिले हुए वस्त्र जो मात्र सौ रुपये और नब्बे रुपये रेंज के हैं, उनको कर मुक्त किया जाए, जैसे साड़ी फाल को किया, जूती को किया। इसी तर्ज पर सिर्फ पेटीकोट, पापलीन नहीं या कपड़ा नहीं, सिले हुए वस्त्र पापलीन और वो भी सिर्फ महिलाओं के लिए। माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत गांवों में जो रोजगार दिया जाता है उसमें शहरों में हजारों नहीं बल्कि लाखों महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल जाएगा। वैट मुक्त होने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पेटीकोट को कर मुक्त किया जाए, यह हमारा निवेदन है। यह रोजगार का सवाल है, इनको और कोई नुकसान नहीं है। एक बार कपड़े का चार प्रतिशत लगता है, सिले हुए वस्त्र को कर मुक्त करने का मैं निवेदन कर रहा हूं, हमें

(श्री मदन प्रजापत)

विश्वास है, माननीय मुख्य मंत्रीजी हमारी भावना की कद्र करते हुए इस बात को करेंगे।

साथ ही एक जो हमारी भावना है सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जी...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आज बालोतरा औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, नेशनल हाई-वे है, मैगा हाई-वे है, लेकिन बालोतरा में अभी तक डाक बंगला नहीं है सिर्फ विश्राम गृह है। उस विश्राम गृह को डाक बंगले का दर्जा दिया जाए ताकि आप सब अतिथि आएं तो हमारे बालोतरा का मान बढ़े, सम्मान बढ़े। आज रुकने की व्यवस्था नहीं है, करीब डेढ़ लाख की आबादी है। इस पर भी हमें विश्वास है कि इस बार बालोतरा की आम जन भावना की कद्र होगी।

आपने मुझे, माननीय सभापति महोदय, पूरा समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आज जो बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है, मैं तहे दिल से इसका समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं ही नहीं, राजस्थान की सौ करोड़ जनता ने इसे देखा सौ करोड़ जनता ने इसका स्वागत किया है। कोई नया कर नहीं, किसानों, गरीबों, तमाम वर्गों के लिए आज बजट में राहत। लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी का, आप तमाम सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह बढ़िया बजट पेश कर जनता को राहत दी है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री विजय बंसल। माननीय सदस्य, मेरा आपस निवेदन है कि आप कृपया पांच मिनट में अपनी बात कहें क्योंकि दस लोग हैं।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अभी आपने पैंतीस मिनट बुलवाया है तब तो एक बार भी नहीं टोका।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तब ध्यान नहीं रखा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: +++

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरा तो आपसे इतना ही अनुरोध है कि...

श्री सभापति: विराजिये। अभी वरिष्ठ सदस्य ने एक टिप्पणी की है। आप लोग जब बोल रहे थे तो यह व्यवस्था दी गई थी कि आपको चालीस मिनट दिए जाएं, उसके बाद के लोगों को कम दिए जाएंगे। उसके बाद यह बात हुई थी कि उनका जो टाइम व्यवस्था का है उनके पास है उनके कोटे में, आपके कोटे में पांच मिनट से ज्यादा नहीं हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उनके पास बोलने वाले नहीं हैं तो हम क्या करें?

श्री सभापति: आपके उप नेता भी नहीं हैं और आपके सचेतक भी नहीं हैं, आप बुलाइये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपके पास ज्यादा हैं क्या बोलने वाले?

श्री सभापति: आप टाइम ज्यादा लेते हो, आप व्यवस्था को वो नहीं करते स्ट्रिक्ट, उसके बाद आप टिप्पणी करते हैं और फिर आप यह कहते हैं कि उधर ज्यादा दे रहे हैं। मैं तो बिलकुल इम्पार्शल हूं क्योंकि जब आप लोग टिप्पणियां करते हैं तब भी चुप रहता हूं, वो करते हैं तब भी चुप रहता हूं। लेकिन फिर भी आप टिप्पणी कर रहे हैं । अगर आप अपनी व्यवस्था करना चाहते हैं तो आप लोग, दूसरे कितने लोग सीरियस हैं I am shocked to say that most of the others are not serious when the Hon'ble Members are speaking. अपनी-अपनी सब बातें कर रहे हैं, If you are serious about it, if you really want to speak……

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हम बहुत सीरियस हैं। मैं तो यह कह रहा हूं, माननीय सभापतिजी…

श्री सभापति: देखिए, आप जोर से बोल कर तो मेरी तरफ टिप्पणी करें मत।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं जोर से नहीं बोल रहा।

श्री सभापति: मैं आपसे कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, आप दो बार जोर से बोले, मैंने कुछ नहीं कहा, आप तीसरी बार जोर से बोलेंगे तो मैं आपके नाम से आपको पुकारुंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय,.....

श्री सभापति: आप कृपया बैठिये, आपने टिप्पणी की कि मैं उधर ज्यादा टाइम दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, नहीं।

श्री सभापति: मैं बराबर टाइम दे रहा हूं। उनके कोटे में टाइम है, आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं टिप्पणी जोर-जोर से करके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे व्यक्तित्व आसन पर विराजे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या हो सकता है। आपकी निष्पक्षता के तो हम भी कायल हैं, सभापति महोदय, पर दस-दस मिनट तो बोलने का समय दे दें। आपकी कृपा हो जाएगी।

श्री सभापति: श्री विजय बंसल। पांच मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमारे पास बोलने के अलावा और है क्या? सत्तारूढ़ दल के लोग तो सत्ता के मद में चूर हैं, हम तो इस सर्वोच्च सदन में सिर्फ अपनी बात ही रख सकते हैं। फिर आप तो उदार मना हैं।

श्री सभापति: श्री विजय बंसल।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरा तो आपसे सर्वप्रथम यही अनुरोध है कि जो आपने अपनी कृपा बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य को प्रदान की है, उसका थोड़ा अंश मुझे भी प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, इस बार 9 तारीख को पेश होने वाला बजट जब भी पेश होता है, 5 करोड़ जनता की अपेक्षाएं लगी रहती हैं कि इस पेश होने वाले बजट से किसानों को लाभ मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार के कार्य मिलेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सदन के नेता और मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को कि उन्होंने राजस्थान को नाकारा बजट पेश करने के मामले में पहले नम्बर पर हिन्दुस्तान में ला दिया है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश का बजट उसकी प्रगति का प्रतिवेदन होता है। अनेक सदस्यों ने अलग-अलग तरह से अपनी बात रखी है, चूंकि आपने समय कम दिया है तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि धन्यवाद तो इस बात का कि दो स्टार होटलों से नीचे स्तर पर उन्होंने वैट 5 परसेण्ट किया है। धन्यवाद की बात है। मैं बुराई-भलाई नहीं, जो अच्छी बात है उनको जरूर कहूंगा। किसानों का जो जीवन है, जो पशु हैं उनके आहार पर खल पर टैक्स लगा दिया 5 परसेण्ट, इससे आम जनता पर असर पड़ेगा। आम जन की जो चीजें हैं दूध, घी, हर चीज और महंगी होती चली जाएगी। मैं तो यही माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी 200 सदस्यों की यह पीड़ा है, अपने जवाब में कृपया इस टैक्स को अवश्य खतम करें जिससे किसानों को राहत मिल सके।

(श्री विजय बंसल)

माननीय सभापति महोदय, भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में घना पक्षी विहार के नाम से एक नेशनल पार्क है जिससे देश और विदेशों में राजस्थान की पहचान मिलती है। दूर-दूर साइबेरिया आदि देशों से करीब 3,000 प्रवासी पक्षी वहां आकर अपनी जल क्रीड़ा करते हैं। पर्यटन की दृष्टि से देश और विदेश से अनेक पर्यटक वहां आते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है वह घना पक्षी विहार आज पानी की कमी की वजह से अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। छह महीने पहले यू एन ओ में एक मीटिंग हुई, उसमें यह तय किया गया कि 2011 तक अगर सरकार पानी की व्यवस्था नहीं करती है तो इसको वर्ल्ड हैरिटेज से हटा दिया जाए। पिछली सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए 106 करोड़ की एक योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी थी लेकिन केन्द्र सरकार की हठधर्मी के कारण आज तक वहां से उसकी स्वीकृति नहीं आ पायी। इस घने का अस्तित्व गंभीरी नदी से आने वाला पानी था लेकिन पाचना बन जाने के बाद वह पानी वहां रुक गया। मेरा आपसे अनुरोध है, एक सुझाव है, अगर चम्बल से पानी लिफ्ट करके पाचना में डाल दिया जाता है तो उसके ओवरफ्लों से ही हमारे घने का अस्तित्व बच सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान 2001 में शुरू हुई धौलपुर-भरतपुर चम्बल योजना की तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा, कि माननीय गहलोत साहब ने अपने पूर्व शासनकाल में यह योजना स्वीकृत की थी तब इसकी लागत 160 करोड़ रुपये थी, लेकिन 3 वर्ष में पूर्ण होने वाली यह योजना आज 9 वर्ष हो जाने के पश्चात् भी पूर्ण नहीं हो पायी है। इसका मुख्य कारण तो यह रहा कि 3 साल तक हाई कोर्ट के स्टे की वजह से अटकी। उस स्टे को मैंने स्वयं पार्टी बनकर तुड़वाया लेकिन दुःख की बात यह है कि चालू होने के बाद यह योजना फिर अटकने जा रही है क्योंकि राज्य सरकार इसमें पूरे बजट का प्रोविजन नहीं कर पा रही है।

माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में पेयजल की किल्लत है, पिछले शासन में इस समस्या को दूर करने के लिये अनेक ट्यूबवैल और हैण्ड पम्प खुदवाये गये थे। लेकिन सरकार बदलने के पश्चात् 45,000 हैण्ड पम्प और ट्यूबवैल जो स्वीकृत थे, जिनके वर्क आर्डर इश्यू हो चुके थे, उनको बंद कर दिया गया। आज राजस्थान की जनता पानी के लिये त्राहिमाम्-त्राहिमाम् कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, 2008-2009 के बजट में भरतपुर में मेडिकल कालेज और महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा हुई।

(श्री विजय बंसल)

घोषणा होने के पश्चात् एक ट्रस्ट ने 125 बीघे जमीन इसके लिये दान दी और सरकार ने 50 लाख रुपये और ओ एस डी देकर उस योजना को आगे बढ़ाया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आप स्वयं कोई नयी योजना तो भरतपुर को नहीं दे सकते लेकिन पिछली सरकार की दी योजना को ठण्डे बस्ते में मत डालो, नहीं तो भरतपुर में इतना बड़ा आन्दोलन होगा कि सरकार को सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान भरतपुर की सुजान गंगा ऐतिहासिक नहर है उसकी तरफ भी दिलाना चाहूंगा, सुजान गंगा नहर कभी जीवनदायिनी हुआ करती थी, आज प्रदूषित होकर उसमें एक व्यक्ति रोज आत्महत्या की संख्या आती है। यह बजट जिसको चहुं तरफ से बहुत बढ़िया बजट बता रहे हैं, सुजान गंगा नहर के बारे में बार-बार क्वेश्चन लगाने के पश्चात् भी एक पैसे का बजट इसके जीर्णोद्धार के लिये नहीं रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, भरतपुर शहर पर्यटन की दृष्टि से विश्व में पहचाना जाता है लेकिन आज वहां की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि रोज एक एक्सीडेंट। अब मैं अख़बार साथ नहीं लाया हूं, रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके क्या कारण हैं? गुणवत्ता खराब होने के कारण यू आई टी से एक वर्ष पूर्व बनी हुई सड़क टूट गयी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर साहब का इस पर ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। आज ग्रामीण सड़कों, गांव से गांव जोड़ने की व्यवस्था का इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। पिछली सरकार ने 10 किलोमीटर मिसिंग लिंक देकर गांवों से गांवों को जोड़ने का प्रयास किया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बजट का जवाब देने पर कम से कम प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 20 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़क की योजना दें जिससे गांवों का विकास हो सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें अब आप।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ओनली टू मिनट। मैं कोई वैसे नहीं, अपनी समस्या रख रहा हूं खाली।

माननीय सभापति महोदय, 1996 की बाढ़ के कारण चिकसाना बांध क्षतिग्रस्त होकर टूट गया था। रूपारेल अलवर से लेकर जितना भी पानी बारिश का आता है, उस बांध में रोका जाता था और उस बांध के पानी की वजह से

(श्री विजय बंसल)

कुओं का जल स्तर बढ़ता था एवं 40 ग्रामों में सिंचाई होती थी। आज 14 साल के पश्चात् भी उस बांध को रिपेयर नहीं किया गया है, मेरा अनुरोध है, सभापति महोदय, कि अब बजट में इसका भी ध्यान रखें क्योंकि पिछले बजट से पहले इसके लिये 3 करोड़ रुपये सैंक्शन हो चुके थे।

माननीय सभापति महोदय, भरतपुर में उद्योगों की हालत बहुत खराब है। जो उद्योग थे, किसी कारणवश वे बंद हो गये। धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन उद्योग मंत्री डाक्टर दिगम्बर सिंहजी को जिन्होंने सिमको लिमिटेड फैक्टरी तो खुलवायी। अनेक उद्योग बंद पड़े हैं। नये उद्योग लाकर बेरोजगारी दूर करने के लिये सरकार कुछ प्रयास करे, यह मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है।

माननीय सभापति महोदय, एक छोटे-से जिले दौसा में आर टी ओ कार्यालय है। भरतपुर सम्भाग है जिसके अन्तर्गत 4 जिले आते हैं। आज धौलपुर का बन्दा भी चलकर अलवर अपने रजिस्ट्रेशन का काम कराने जाता है। मेरा अनुरोध है, सम्भाग मुख्यालय पर आर टी ओ कार्यालय खुलवाने की सरकार पहल करे।

माननीय सभापति महोदय, 10 घण्टे देने का वादा करने वाली सरकार ने 4 घण्टे वह भी ट्रिपिंग-ट्रिपिंग बिजली दी है। आज एक नारा बन गया है हमारे यहां, जैसे ही बिजली जाती है, किसान कहने लग जाता है, गहलोत तो गयो। मेरा आपसे अनुरोध है, यह बिजली व्यवस्था 6 घण्टे कम से कम दिलायी जाए।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट बस। माननीय सभापति महोदय, प्रोटोकाल में विधायकों को चीफ सैक्रेटरी से ऊपर का स्तर दिया जाता है। लाल बत्ती लगाने का अधिकार एक कलक्टर को, एक ए डी एम को तो मिला हुआ है, लेकिन एक विधायक लाल बत्ती नहीं लगा सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है या तो प्रोटोकाल में एम एल एज को नीचे लाया जाए, अन्यथा उनको यह अधिकार दिलाया जाए।

साथ-साथ मैं एक अनुरोध और करना चाहता हूं, इस महंगाई के जमाने में अन्य प्रदेशों में एम एल ए लैड डेढ़ से दो करोड़ तक है लेकिन राजस्थान का एम एल ए लैड आज भी 80 लाख रुपये पर अटका हुआ है। मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसको ध्यान में

(श्री विजय बंसल)

रखें क्योंकि ग्रामीण विकास में एमपी लैड और एमएलए लैड या नरेगा के काम के अतिरिक्त कोई भी पैसा नहीं है। अगर आप गांवों की दशा सुधारना चाहते हैं तो इस एमएलए लैड को कम से कम 2 करोड़ रुपये किया जाए।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं कम बोला हूं इसका मुझे बहुत दुख है।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल खराड़ी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): सभापति महोदय, मैं इस सदन में माननीय सदन के नेता द्वारा प्रस्तुत बजट 2010-11 के विरोध में बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यह राजस्थान का जो खजाना है वह राजस्थान की 6 करोड़ जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा है। आज सत्ता पक्ष के लोग इस बजट के लिए अशोक गहलोतजी की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे। लेकिन खैरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जो पीड़ा व्यक्त की है, वह बिलकुल कटु सत्य है, बिलकुल सही बात है।

सभापति महोदय, मेवाड़ ने बहुत आशीर्वाद दिया है कांग्रेस को, 22 एमएलए जिताकर दिये हैं, इसी कारण से वह आज मुख्य मंत्री हैं। लेकिन मेवाड़ को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, इस कांग्रेस की सरकार ने क्या दिया है, वह मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, दो बजट पेश हुए हैं, बजट 2009-10 जिसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जोधपुर को क्या दिया इसकी तुलना करूंगा, ज्यादा तुलना नहीं कर रहा हूं। जोधपुर में इंदिरा गांधी नहर एवं अन्य परियोजनाओं में खालों के निर्माण हेतु 97 करोड़ और राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में चिकित्सालय, कालेज व भवन निर्माण हेतु 22 करोड़, मेडिकल कालेज जोधपुर में फिजियोथिरैपी महाविद्यालय 4 करोड़ रुपये और बांसवाड़ा में एक इंजीनियरिंग कालेज 6 करोड़ रुपये, मथुरादास माथुर चिकित्सालय में जनाना एवं शिशु विभाग 29 करोड़ रुपये, महिला चिकित्सालय-50 शैयाओं की वृद्धि व नर्सरी में 30 शैयाओं की वृद्धि 4 करोड़ रुपये और आदिवासी कन्या छात्रावास 2 करोड़ रुपये। मेवाड़ में सागवाड़ा, तलवाड़ा, घाटोल बालिका छात्रावास में 3 करोड़ और नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड 7 करोड़ रुपये जोधपुर में। आगे चलकर जोधपुर में सुमेरपुर में कालेज 14 करोड़, बाड़मेर में समग्र सहकारी विकास योजना 78 करोड़, उम्मेद सागर बैराज समदड़ी पेयजल परियोजना में

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

1127 करोड़, भीखा भाई सागवाड़ा नहर में 32 करोड़। आगे चलकर जोधपुर शहर के भू-जल स्तर के समाधान हेतु परियोजना 12 करोड़, जैसलमेर में पोलीटैक्निक महाविद्यालय 6 करोड़, जोधपुर में एंटी टैररिस्ट यूनिट की स्थापना के लिए 3 करोड़। इसकी अब गणना करें, अगर जोड़ करें तो जोड़ आता है 2919 करोड़ और मेवाड़ में 45 करोड़ और उसमें से भी 32 करोड़ हैं, इसमें से केवल मात्र 14 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

सभापति महोदय, दूसरा मैं तुलना करना चाहता हूं कि अभी का बजट है 2010-11, इसमें इंदिरा गांधी नहर जोधपुर में फीडर टूट-फूट के कारण केन्द्र द्वारा परियोजना में 90 प्रतिशत अनुदान-952 करोड़, आबू रोड में पेयजल स्कीम 18 करोड़ और बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के सार्थक उपयोग हेतु 0.1 करोड़ रुपये। आगे जोधपुर शहर एवं उसके उप नगरीय पेयजल भविष्य की आवश्यकता हेतु 540 करोड़, देवास योजना 50 करोड़, जोधपर में उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र लागत 2.60 करोड़, जोधपुर में माननीय उच्च न्यायालय एवं जुडीशियल अकादमी भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये, उदयपुर में आयुक्त कार्यालय के नये भवन के निर्माण हेतु 1.50 करोड़। अब इसकी गणना करते हैं तो जोधपुर में आता है 1532.60 करोड़ और मेवाड़ में आता है 52.50 करोड़। हां, मैं वही कह रहा हूं, क्या मुख्य मंत्रीजी केवल जोधपुर के मुख्य मंत्री हैं या पूरे राजस्थान के हैं?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सरदारपुरा के हैं, खाली सरदारपुरा के हैं। विधान सभा भी जोधपुर ले जाएंगे।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): बिलकुल सत्य कहा है खैरवाड़ा से आने वाले सदस्य। ने उदयपुर में जनजाति उप योजना क्षेत्र, उस संभाग ने 22 एमएलए जिताकर दिये हैं, क्या दिया, अभी मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं इस बजट में? मुख्य मंत्रीजी ने कहा था, हम प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर जो भी विद्यालय हैं उनमें वाणिज्य और विज्ञान संकाय खोलेंगे। कितने खोल दिये बताएं? एक भी नहीं खोला। अगर खोले होंगे तो हमारे क्षेत्र में नहीं खुले हैं। अगर नहीं खुले हैं तो या तो राजनीतिक भेदभाव किया गया है, यह भी स्पष्ट करें।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पेयजल स्कीम झाड़ोल में 22 गांवों में मानसी वाकल माननीय वसुन्धरा जी पूर्व मुख्य मंत्री थीं, उनके शासनकाल में स्वीकृत हुई थी। पूरा प्लांट बन

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

गया, वहां पर लाइन पूरी बिछ गयी, उसके बाद सत्ता बदलने के बाद में आज भी वह वैसी की वैसी पड़ी है, इसके क्या कारण हैं?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि झाड़ोल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, कोटड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, एक फलासिया मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। कोटड़ा में स्थिति यह है कि मरीज आते हैं, आजकल जापे अस्पताल में होने लग गये हैं, तो जापे वाली इतनी महिलाएं आती हैं उन्हें जमीन पर लिटाया जाता है। उनके लिए बैड नहीं हैं, शैयाएं नहीं हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी ने बजट में कहा है कि हम अस्पतालों में शैयाओं में बढ़ोत्तरी करेंगे, जब बजट का उत्तर देवें तब यह कहें कि हम कोटड़ा में 50 बैड की बढ़ोतरी कर रहे हैं, झाड़ोल में 50 बैड की बढ़ोतरी कर रहे हैं। फलासिया में भवन निर्माण के लिये स्वीकृति निकली हुई है वह स्वीकृति आज भी ऐसी की ऐसी पड़ी है, काम शुरू नहीं हुआ है, उस कार्य को शुरू कराया जाए।

सभापति महोदय, आज बीपीएल की बात कही थी, बिलकुल सत्य बात है कि 2 रुपये किलो आप गेहूं दोगे तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन आज उस ट्राइब्ल सब प्लान का प्रत्येक व्यक्ति बीपीएल लायक है। आज उसको बीपीएल से अलग किया है, मैं तो कहूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि उस क्षेत्र में जो कर्मचारी लोग हैं उन्हें अलग मानते हुए सारे लोगों को बीपीएल मानना चाहिए क्योंकि वास्तव में उनका जीवन स्तर बहुत खराब है और उनको दो टाइम के खाने के लिए रोटी भी नहीं उपलब्ध होती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब कृपया समाप्त करें।

एक माननीय सदस्य: बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): ठीक है, मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: आप किसलिए कह रहे हैं, किस अधिकार से कर रहे हैं आप?

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): मैं एक बात कहकर समाप्त कर रहा हूं कि 108-एम्बुलेंस सारी जगह दी हैं, कोटड़ा और झाड़ोल में भी एम्बुलेंस दी जाए। यही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य जनाब शाले मोहम्मद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: आप सबकी सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 9 मार्च को जो बजट सदन में पेश किया, उसके लिए पुरजोर शब्दों में उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने राजस्थान में सूखे की स्थिति और मंदी के दौर के बावजूद जो यह बजट पेश किया, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर क्षेत्र को साथ लेकर उन्होंने इस बजट को विशेष रूप से अच्छा स्वरूप दिया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं पिछले दो दिनों से जब माननीय सदस्य अपनी बात इस सम्बन्ध में सदन में रख रहे थे तो उनको अच्छी तरह से सुन रहा था। इस बजट में जो काफी अच्छी बातें थीं, आम आदमी, किसान, गरीब का जो खयाल रखा गया उसके लिए भी मेरे सामने जो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बैठे हैं, उन्होंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद नहीं दिया, मुझे इस बात का दु:ख है। जो अच्छी बात हो, जो गरीब का भला करने वाली बात हो, कम से कम उस बात के लिए तो आपको माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहिए। मैं तो तीन-चार बातों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे से पूर्व के जो वरिष्ठ सदस्य गंगानगर से आने वाले हैं, वह बार-बार इस बात को कह रहे थे कि सिंचित क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कुछ भी नहीं दिया गया। आदरणीय सैनी साहब भी इस बात को कह रहे थे। जब हम बार-बार इस चीज को कहते थे कि यह जो डिग्गियों का पैसा आ रहा है, जो कृषि क्षेत्र में पैसा आ रहा है वह सेंट्रल गवर्नमेंट का आ रहा है, उस समय हमारी बात को नहीं मानते थे, उस समय यह कहते थे कि यह पैसा हमारा है। और आज वह

(श्री शाले मोहम्मद)

अपने शब्दों में कह रहे थे कि यह पैसा सेंटर का है। तो यह बात उन्होंने उस समय क्यों नहीं मानी जब इतना पैसा यू पी ए सरकार ने दिया था? आपने सोनियाजी को धन्यवाद नहीं दिया। मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद नहीं दिया कि सर्व शिक्षा अभियान में इतना पैसा दिया, नरेगा के अन्दर इतना पैसा दिया, कृषि के क्षेत्र में इतना पैसा दिया, आपने एक बार भी एक शब्द भी उसके बारे में नहीं कहा। आप आज उस तरफ हमारे सामने बैठे हैं तो आप अपने शब्दों में कह रहे हैं कि जो इतना पैसा आ रहा है वह पूरा का पूरा सेंटर दे रहा है। यह बात यदि पहले कहते तो हम आपको धन्यवाद देते, आप धन्यवाद के पात्र होते। पर मैं आपको यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पांच साल के पूरे कार्यकाल में जितने किसानों के लिए डिग्गियां नहीं बनीं, हमारे माननीय मंत्रीजी ने एक साल में उनकी घोषणा की है, यह रिकार्डेड है, यह आप देखें। माननीय सदस्य राधेश्यामजी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि गरीबों और किसानों का भला करने वाला कौन है? आपकी सरकार है या कांग्रेस की सरकार है? कांग्रेस ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए हमेशा अच्छी सोच रखी है। आज 35 हजार हैक्टेयर असिंचित क्षेत्र को आगे सिंचित करने की बात रखी है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी सूखा है लेकिन आने वाले समय में अच्छी बारिश होगी, नहरों में अच्छा पानी आएगा। यदि यह सिंचित क्षेत्र विकसित होता है तो वहां किसानों को लाभ मिलेगा। 65 हजार फाइलें जो पिछली सरकार ने लोगों से भरवाईं, वहां आपने क्षेत्र को सिंचित नहीं किया, उस क्षेत्र में खालें नहीं बनवाईं, नहरें नहीं बनवाईं। पर आपने वहां की जो गरीब जनता थीं उस गरीब जनता को लूटने का काम किया कि 65 हजार फाइलें भरवा दीं। आज हालात ये हैं कि उनको अलाट करने के लिए जमीन नहीं है। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह सोच तो रखी कम से कम कि नहरों को बढ़ाया, उस सिंचित क्षेत्र का विकास किया ताकि जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने आवेदन किया है, उन आवेदनों में जब सिंचित क्षेत्र विकसित होगा, उसमें नहरें बनेंगी, उसमें खालें बनेंगी तो उन लोगों को, उन आवेदकों को लाभ होगा, उन लोगों को रहने के लिए जमीन तो मिलेगी, खेती के लिए जमीन मिलेगी। यह अच्छा काम है। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य अभी यहां नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो अच्छी चीजें हों, कम से कम उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। आज गंगानगर, हनुमानगढ़ में थ्री - फेस कनेक्शन देने की बात कही जो किसानों के लिए अपने आप में बहुत बड़ी

(श्री शाले मोहम्मद)

बात है। किसान आगे जाना चाहता है, मैं भी उस क्षेत्र में गया हूं, उनके साथ ट्यूबवैल एरिया बन गया है, पानी का स्तर थोड़ा बढ़ा है, तो यदि उन लोगों को थ्री-फेस के कनेक्शन मिलते हैं तो उन लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। मैं भी चाहता हूं कि मेरे जैसलमेर जिले को भी साथ जोड़ा जाए क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी कई जगहें हैं जहां पर पानी का एकदम स्तर ऊपर आ गया है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मेरे यहां पर एक जालूवाला ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के अन्दर हालांकि पहले खारा पानी था, पानी निकलने की सम्भावना ही नहीं थी, आपके जी डब्ल्यू डी द्वारा अभी ट्यूबवैल खुदवाया गया तो ईश्वर की देन से वह पानी आज आटोमेटिक ऊपर से चल रहा है तो पानी का एकदम बढ़ाव हो गया। उस क्षेत्र में वहां के किसानों को यदि थ्री-फेस का कनेक्शन मिलता है तो मैं समझता हूं कि उनके हालात में और सुधार होगा। पीने का पानी अच्छा उपलब्ध होगा और लोगों को खेती के लिए भी अच्छा पानी मिलेगा। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि पेयजल की जो स्थिति है, आज पूरा सदन उससे चिंतित है, पेयजल की हालत बड़ी गम्भीर है। पानी की चिंता सबको है और सबको चिंता करनी भी चाहिए क्योंकि हालात इस प्रकार के बन गए हैं कि हमारे क्षेत्र में, मैं अपने क्षेत्र की बात कहूं तो पोकरण विधान सभा क्षेत्र में जो पोकरण लिफ्ट योजना थी, जो पिछले पांच साल से रुकी हुई थी, मैंने बार-बार निवेदन किया, माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोकजी गहलोत पूर्व में थे तब वह लिफ्ट स्वीकृत हुई थी, उसके बाद पांच साल तक आपका शासन चेंज हो गया, बी जे पी का आ गया तो एक पैसा नहीं दिया। जब वापस माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत आए तो हमारी सारी वहां की जनता ने उनसे निवेदन किया तथा अपनी बात रखी तो उन्होंने उसे माना और आज बहुत खुशी की बात है कि पोकरण लिफ्ट का काम चालू हो गया। इसका फायदा वहां के लोगों को मिल रहा है। जो रुकी हुई पेयजल योजनाएं थीं, परियोजनाएं थीं, आज वापस इस बजट में हैं। बाकी जो परियोजनाएं थीं उनको और परियोजनाओं के साथ जोड़कर पेयजल की स्थिति को सुधारने की कोशिश की है। इससे मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा। इस बजट में जो पेयजल के लिए विशेष रूप से हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान दिया है, उसकी मैं सराहना करता हूं और उनको मैं सदन में धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में उन्होंने पिछले सवा-डेढ़ साल के कार्यकाल में अच्छे काम किए हैं चाहे हमारी रामगढ़ गैस आधारित परियोजना हो, पिछली

(श्री शाले मोहम्मद)

बार भी 150 मेगावाट से चालू किया, इस बार भी इस बजट में उसको आगे बढ़ाने की बात रखी है। इसके अलावा प्रथम बार दो 765 केवी के जी एस एस लगाने की बात कही है, वह अपने आप में बहुत अच्छी बात है।

इसके अलावा पूरे राजस्थान में 33 के वी के 320 जी एस एस बनाने की जो बात कही है, मैं समझता हूं कि किसान के लिए वोल्टेज की जो समस्या थी, वह इससे हल होगी, किसानों को इसमें ऊर्जा अच्छी मिलेगी, विद्युत सही रूप से मिलेगी और अच्छा फायदा उसको होगा।

शिक्षा की बात के लिए मैं दो दिन से सुन रहा था, काफी सदस्य अपनी-अपनी बात कह रहे थे। पर आज शिक्षा के हालात मैं समझता हूं कि इतने गम्भीर क्यों हुए? मैंने पिछले शासन में देखा, अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं किया, विद्यालय नहीं खोले, अभी हालत आपने देखी है, राजस्थान में कितने शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं? आप लोगों ने विद्यालय क्रमोन्नत किये, नये खोले पर जो पहले वाले विद्यालय थे उनको बंद करने की स्थिति में ला दिया क्योंकि आपने एक अध्यापक की भर्ती नहीं की। (व्यवधान) नहीं, पहले सुनें मेरी बात को। मेरे जैसलमेर जिले में देखें, आज 1200 पद हैं, इनमें से 600 पद रिक्त हैं। आपने विद्यालय खोल दिये, आपने क्रमोन्नत कर दिये पर वहां पर एक भी अध्यापक नहीं लगाया। यदि आप उसकी जगह अध्यापक लगाते। यदि आप शिक्षा में सुधार करना चाहते थे, आप लोग चाहते थे कि वास्तव में शिक्षा में सुधार हो तो आप क्रमोन्नत न करके उसकी जगह नये अध्यापक भर्ती करते और उसके बाद आप क्रमोन्नत करते, नये विद्यालय खोलते तो आज यह शिक्षा के हालात नहीं होते। यह शिक्षा के जो हालात खराब हुए हैं ये पिछले शासन के कारण से हुए हैं। इसलिए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो बात कही है कि शिक्षा में सुधार लाने की जरूरत है, सुधार करने के बाद में क्रमोन्नत किये जाएंगे।

(समय : 20.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में बीपीएल और स्टेट बीपीएल पहले किये और उसके बाद में अभी वृद्धावस्था, विकलांग, विधवाओं को, सबको नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था की बात की है, यह अपने आप में एक सराहनीय कदम है, इसके

(श्री शाले मोहम्मद)

लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बीपीएल के लोगों के लिए, गरीबों के लिए जो गेहूं 4.70 रुपये प्रति किलो मिलता था, उसके सम्बन्ध में बहुत बड़ी घोषणा की कि 2 रुपये प्रति किलो बीपीएल परिवारों को गेहूं मिलेगा, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसके अलावा हमारे जैसलमेर जिले में रोडवेज डिपो की जो काफी वर्षों से मांग थी, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने हमारे छोटे-से निवेदन पर आज रोडवेज डिपो लाने के लिए, सुधार लाने के लिए बात की है, नये डिपो स्थापित करने की बात की है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए कई स्थानों पर जहां अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हैं, 5 आईटीआई खोलने की बात की है, अल्पसंख्यक गरीब की शिक्षा के हालात बहुत गम्भीर हैं, उनके आईटीआई यदि खुलती है, यदि उनको साधन मिलता है तो मैं समझता हूं कि उनका भी अच्छा विकास होगा। इसके अलावा दो करोड़ रुपये का जो प्रावधान रखा है, यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है।

अंत में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा पोकरण विधान सभा क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया है, चिकित्सा के क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से दूसरी जगहों पर सामुदायिक केन्द्रों में शैयाओं की संख्या बढ़ाने की बात की है उसी प्रकार यदि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो बाबा रामदेव का स्थल है......

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। बाबा रामदेव का स्थल है, लाखों श्रद्धालु आते हैं, यदि उसमें भी शैयाओं की संख्या बढ़ाई जाती है या ट्रोमा सेंटर खोला जाता है तो मैं समझता हूं कि उप खण्ड के लोगों को लाभ मिलेगा। मुझे विश्वास है कि इस बजट में इसका भी प्रावधान रखा जाएगा, इसलिए मैं एक बार पुन: मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो बजट बनाया है वह आम आदमी, गरीबों, किसानों सबका ख्याल रखकर बनाया है, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री शिवजीराम मीणा।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2010-2011 के बजट पर जो उन्होंने

(श्री शिवजीराम मीणा)

हाल ही में 9 मार्च को सदन में पेश किया है, वाद-विवाद में भाग लेने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राज्य का बजट उस वर्ष के लेखे-जोखे का विवरण होता है जिसमें यह दर्शाया जाता है कि किस प्रकार से राज्य को आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से विकास की बात उसमें कही गई है। लेकिन इस बजट को देखने से लगता है कि इसमें विकास की कोई बात नहीं की गई है, आम आदमी की कोई बात नहीं की गई है और न किसान-मजदूर की इसमें बात है। जिस लोक-लुभावने अंदाज में भाषण देकर लोक सभा में, विधान सभा में आप सभी फर्मा रहे थे कि हमको पंचायती राज में, स्थानीय निकायों में बहुमत दिया है, जनता को आप लोगों से उम्मीद थी, जनता आप लोगों से उम्मीद किये बैठी थी कि बहुत अच्छा बजट पेश करेंगे, लोगों के रोजगार की उसमें व्यवस्था की जाएगी, रोजगारोन्मुख बजट होगा, लोगों को नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं देंगे, लेकिन इस बजट में, माननीय सभापति महोदय, कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। न तो इसमें महंगाई को कम करने की बात की गई है बल्कि इसमें गरीब लोगों का गला काटने के लिए जो वैट की दर न्यूनतम चार प्रतिशत थी, उसको बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। आप लोगों ने यह भी कहा था कि बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इस बजट में आपने शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं से जो 100 यूनिट से ज्यादा का उपभोग करेंगे, 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से उप कर के रूप में वसूल करने की व्यवस्था की है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात इस बजट में की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में हम गुणात्मक सुधार करेंगे, नये स्कूल नहीं खोलेंगे और जो व्यवस्थाएं हैं उनमें हम और अच्छी व्यवस्था करने की बात करेंगे। अब यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। अत: हमने निर्णय लिया है कि आगामी वर्ष में विद्यालयों को सिर्फ क्रमोन्नत करने के बजाय, प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे हमारे विद्यालयों में शिक्षा का अच्छा वातावरण सृजित हो सके। इसके लिए शिक्षा प्रशासन-तंत्र को मजबूत करते हुए प्रभावी पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। सभापति महोदय, इस बजट में कहीं पर

(श्री शिवजीराम मीणा)

भी नई भर्ती की बात नहीं की गई है। गत वर्ष बजट में 17229 थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती करने की बात कही गई थी, 1000 पीटीआई की भर्ती करने की बात कही गई थी और 10 हजार टीचर्स के सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों पर भर्ती की बात कही गई थी लेकिन इस बजट में कहीं भी व्यवस्था नहीं है और न उन्होंने आज तक कोई भर्ती की है। इसी प्रकार, माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार में 5000 से अधिक पदों के लिए सम्माननीय वसुंधराजी ने सैकिण्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन निकलवाया था लेकिन 18 महीने गुजरने के बाद भी आज तक उसकी एग्जाम तक आप नहीं करवा सके। संस्कृत के 2900 अध्यापकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा करवाई गयी थी, उसका रिजल्ट आये हुए 6 महीने हो गये, लेकिन आपने उनकी आज तक भर्ती नहीं की है। अब आप किस प्रकार से शिक्षा में गुणात्मक सुधार की व्यवस्था करेंगे, यह मेरे समझ से परे की बात है। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में यह भी व्यवस्था की गई थी कि मदरसों में करीब ढाई हजार विद्यार्थी मित्र भर्ती करेंगे, वो भी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। जिस पंचायत मुख्यालय में सैकण्डरी स्कूल नहीं है वहां की किसी भी स्कूल को क्रमोन्नत कर सैकण्डरी स्कूल का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक कहीं भी स्कूल नहीं खुली है। कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में कोई स्कूल खुली हो तो मेरी जानकारी में नहीं है, बाकी हमारे यहां तो कोई स्कूल खुली नहीं है। तो किस प्रकार से शिक्षा में गुणात्मक सुधार करेंगे, इसकी व्यवस्था का कहीं भी अंकन, माननीय सभापति महोदय, नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में सुदृढ़ व्यवस्था के लिए चालू योजनाओं को इसी वर्ष में पूरा करने के लिए 777 करोड़ 58 लाख की व्यवस्था की गई है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कई योजनाएं 2007 और 2008 में स्वीकृत की गई थीं, उनका काम इस सरकार के आने के बाद में रोक दिया गया है। रासेड़ में सम्माननीय पूर्व मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर की मिसेज के नाम से सरला सागर रासेड़ के रेजिंग के लिए 57 लाख रुपये की स्वीकृति की गई थी, उसमें करीब 60 प्रतिशत काम पूरा हो गया था, लेकिन यह सरकार आने के बाद ठेकेदार को पेमेंट सिर्फ 3 लाख का किया और उस काम को रोक दिया गया है। इसी प्रकार से कोटड़ी में विश्रान्ति गृह की व्यवस्था नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार में 18

(श्री शिवजीराम मीणा)

लाख से निरीक्षण गृह की व्यवस्था की गई थी, उसका 70 प्रतिशत काम पूरा हो गया है लेकिन उसका काम रोक दिया गया है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे एरिया की बात कर रहा हूं और पहली बार बोल रहा हूं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। क्योंकि आपने जो समय सीमा तय की है उसमें सहयोग करें।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से टैंक की स्वीकृति की गई थी, उसको रोक दिया गया है। मंदिर की नाड़ी एनीकट, डगर एनीकट, शोभा जी का खेड़ा एनीकट, इनकी स्वीकृति की गई थी, इनके काम पूरे हो गये लेकिन इनका कार्य अब रोक दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, पेयजल के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार ने इस बजट में 1515 करोड़ की व्यवस्था की है लेकिन पिछली सरकार के समय मेरे क्षेत्र में जो काम स्वीकृत हुए थे, उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य विराजे हुए हैं, भीलवाड़ा जिले को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यह व्यवस्था की गयी थी कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से पूरे जिले के 7 कस्बों और 1600 गांवों की पेयजल व्यवस्था करने के लिए शीघ्र ही 1020 करोड़ रुपये की योजना की क्रियान्विति की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, साल भर तो अभी कुछ नहीं किया है। इस बजट में, जो नया बजट पेश किया है इस साल का, उसमें इन्होंने यह व्यवस्था की है कि हमने लोन के लिए वर्ल्ड बैंक को एप्लाई कर दिया है। अब आप बताइये, सभापति महोदय, साल भर से इन्होंने वर्ल्ड बैंक को केवल लोन के लिए एप्लाई किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है, तो किस प्रकार से उनके लिए पेयजल की व्यवस्था करेंगे, यह हमारी समझ से बाहर है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। सहयोग करें, मेरा निवेदन है आपसे कृपया।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं। (व्यवधान) मेरे यहां कांटी-सांकड़ी पेयजल योजना के लिए 92 लाख रुपये की स्वीकृति की गई थी, अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसका आधा काम हो गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको

(श्री शिवजीराम मीणा)

निवेदन करूं कि पूरे जिले में उसमें जो सोर्स में पानी है, सर्वाधिक पानी होते हुए आज तीन साल से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से पाइप स्कीम के लिए जो स्वीकृति की गई थी, उसमें आधा काम हुआ है, न बजट दिया गया है...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि देवली कस्बे...

श्री सभापति: अब अंकित नहीं हो रहा है। मैं तीन बार आपसे निवेदन कर चुका हूं। अब अंकित नहीं हो रहा है कृपया आप विराजिये। श्री रवीन्द्र बोहरा।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर):×××

श्री सभापति: कृपया विराजिये, कृपया विराजिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर):×××

श्री सभापति: श्री शिवजीराम मीणाजी, कृपया आप समाप्त करें। श्री शिवजीराम मीणाजी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब आप समाप्त करें। श्री शिवजीराम मीणाजी, दो बार आपका नाम ले दिया मैंने।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर):×××

श्री सभापति: श्री हेमसिंह भडाना।

सूचना

जयपुर की नेमीसागर कालोनी में महिला के बोरवैल में गिरने की घटना

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। आदरणीय सभापति महोदय, I am on a point of information. वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक कालोनी है नेमीसागर which falls off queens Road. वहां एक 14 इंच का खुला बोर है, एक महिला उस बोर में गिर गई है। वह आत्महत्या का प्रयास है या हादसा है, मैं आपके माध्यम से सदन के और सरकार के ध्यान में यह चीज लाना चाहता हूं? थैंक यू।

श्री सभापति: श्री हेमसिंह भडाना।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय सभापति महोदय, इस बजट अभिभाषण में पिछले दो दिनों से सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बजट की तारीफें कीं और माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार जताया। स्वच्छ लोकतंत्र में एक व्यवस्था होती है पर स्वच्छ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। सारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने, एक-दूसरे से कहीं से कोई नम्बर कम नहीं रह जाए, तो माननीय मुख्य मंत्री ने, लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने ये बजट घोषणाएं कीं, ये बजट घोषणाएं कीं, सबने पढ़कर सुनाया। मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में जो बढ़िया बात रखी है, किसान के लिए रखी है, रोजगार के लिए रखी है, उनकी मैं भी तारीफ करूंगा, लेकिन इस बजट में किसान का कहीं भी नाम नहीं लिया गया। मैं मानता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री काश्तकार हैं...(व्यवधान) काश्तकार के बावजूद विरोध करेगा वह। (व्यवधान) काश्तकार के घर में जन्म हुआ है, किसान वर्ग से हैं लेकिन इस बजट में जिस तरह से किसानों की उपेक्षा की गई, आज इस सदन में 200 सदस्य बैठे हैं नेता सदन के समेत, पर हम सब लोगों को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान के किसान वर्ग से हम चुनकर आये हैं। राजस्थान में 80 प्रतिशत किसान रहते हैं, राजस्थान के संसाधन सारे खेती पर आधारित हैं, चाहे कोई भी जिला हो राजस्थान का, लेकिन कहीं भी किसान की कोई बात इस बजट में नहीं रखी गई है। सबसे बड़ा खुलासा किया बेरोजगारों के लिए कि बेरोजगारों को कहीं भी रोजगार देने का इस पूरे बजट में, एक साल 2010-2011 का जो बजट पेश किया है, यह दूसरा बजट मैं देख रहा हूं, पिछला बजट मैंने पढ़ा है और यह भी मैंने पूर्ण रूप से पढ़ा है, जैसे यूं का यूं योजनाओं को घटा-बढ़ाकर इन्होंने पेश किया है। किस बेरोजगार को रोजगार देने का काम किया है, मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से? बेरोजगारी को बढ़ावा देने के अलावा इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाया, आपने बी.पी.एल. परिवारों को लाभ देने का काम किया। यह सतत् प्रक्रिया है, यह पूर्ववर्ती सरकार से चली आ रही है। इसमें इस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि बहुत बड़ी योजना इसमें जोड़ी जाए।

शिक्षा के क्षेत्र में दम भरती थी यह सरकार कि समानीकरण करेंगे। आज गांव में जो शहर से 20 किलोमीटर कस्बे से दूर विद्यालय खुले हुए हैं, वहां पर 200 की संख्या विद्यार्थियों की और मात्र एक-दो अध्यापक हैं। और

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

शहर के अन्दर? यहां पर शिक्षा मंत्रीजी नहीं बैठे हैं, इन्होंने एक उत्साह किया था इस सरकार के खिलाफ होकर बात करने का, मैंने भी उसका स्वागत किया था, कि ये पहले शिक्षा मंत्री हैं जो समानीकरण शिक्षा का करेंगे। लेकिन वह फाइल भी जाने कौन से बस्ते में पटक गई, कहीं भी शिक्षा में समानीकरण नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि हम स्थानान्तरण नीति तय करेंगे, कौनसी नीति तय करेंगे? लाइन लिखने से नीति थोड़े ही तय हो जाएगी? कहीं भी इन्होंने स्थानान्तरण नीति तय नहीं की।

देवनारायण योजना के नाम से अभी ये कह रहे हैं कि दो साल से चला रहे हैं। एस.सी. एस.टी. ओ.बी.सी. के लिए हम देवनारायण योजना दो साल से चला रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, देवनारायण योजना हमारी सरकार के समय में चलाई गई थी, आप लोगों के आने के बाद में तो इसको बंद करने का काम किया है। सवा साल के अन्दर जिन 13 जिलों को आप पूरे राजस्थान में देवनारायण योजना में जोड़ना चाहते हैं, ये 13 वही तहसीलें हैं जहां हमने बोर्ड का गठन किया था। इन्होंने कहा है कि 11 सी.एच.सी. खोल रहे हैं, सारी 11 सी.एच.सी. को भारतीय जनता पार्टी के समय में गया हुआ पैसा है, कांग्रेस सरकार ने एक पैसा लगाया हो तो मुझे बताएं। उस राशि का बड़े तरीके से मैंने मंत्री महोदय को निवेदन किया था। हमारे जिले के एक मात्र काबीना मंत्री माननीय दुरु मियांजी थे, देवनारायण योजना है इसकी कार्यकारी एजेंसी पहले तो सी.एच.सी. की, बाद में पी.डब्ल्यू.डी. की, फिर ग्राम पंचायत की और आज तक वहां पैसा वैसा का वैसा पड़ा है। आप बच्चों को लाभान्वित करने की बात कर रहे हैं, आपने कौनसा क्राइटेरिया तय कर दिया है कि हम इस क्राइटेरिया से विद्यार्थियों को स्कालरशिप देंगे? कहीं कोई खुलासा नहीं किया। सवा साल तो ये निकाल दिये और एक साल जो हमारी सरकार ने पैसा दिया हुआ है, उसको निकालोगे। कितनी बार वाहवाही लूटोगे झूठी बातों को कहकर? इस सदन को गुमराह करते हो जो योजना पहले से संचालित है।

तीसरी बात कह रहा हूं पंचायती राज के संबंध में। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार यहां पर उन्होंने नगर निगम और नगर पालिकाओं के सीधे चुनाव कराये, लेकिन वह भी हमारे मध्य प्रदेश के भाजपा के मुख्य मंत्री से अनुसरण करके। लेकिन क्या भाजपा के मुख्य मंत्री का अनुसरण किया? फिर भी मैं माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत को धन्यवाद देना चाहूंगा कि नगर निगम और नगर पालिकाओं के सीधे चुनाव कराकर आपने दूषित व्यवस्था को दूर करने का काम किया।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

सत्ता पक्ष के हमारे नेता बैठे हैं, विपक्ष के नेता बैठे हैं, मैं सदन के माध्यम से सभापति महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूं, निश्चित रूप से बजट में बहस का अर्थ तभी होता है जब उसमें पक्ष और विपक्ष की, सभी की राय उभरकर सामने आए और फिर मुख्य मंत्रीजी, विभाग के मंत्री विभाग की समीक्षा करके उस बात को प्रदेश के लिए लागू करें।

अभी पंचायतों के चुनाव हुए। पंचायत चुनावों में पहली बार जन प्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त करके चाहे बी.जे.पी. ने बनाया हो चाहे कांग्रेस ने बनाया हो, प्रधान और जिला प्रमुख बने हैं, सारों ने राजनैतिक पार्टी को छोड़कर धन के लालच में आकर दूसरी जगह वोट डाले हैं। कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत का एक वक्तव्य आया था कि हम सीधे चुनाव कराना चाहते हैं, मैं भी इस बात में आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका सीधा अगर चुनाव हो जाए तो यह निश्चित रूप से प्रजातंत्र की स्वच्छ परम्परा रहेगी। नहीं तो आने वाले समय में, इस तरह की जो व्यवस्था अब पंचायत चुनावों में देखने को मिली, इसके बहुत घातक परिणाम होंगे। आप बात करते हैं, अकाल पड़ गया, बहुत अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं। भगवान ऐसा न करे कि आपको अकाल का प्रबंधन करने की जरूरत पड़े। ऐसे काम ही क्यों करो कि अकाल का प्रबंधन करने का खतरा हो? ऐसा करो न कि वर्षा हो, पानी बढ़े, अच्छा हो। आपने जल नीति की बात की है, इससे ज्यादा इस सरकार की मंशा में खोट नहीं हो सकती कि आपने जल नीति की बात की है। आज राजस्थान में आवश्यकता न बेरोजगारी की है, न किसानों की है, सबसे बड़ी आवश्यकता जल की है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही और माननीय मुख्य मंत्रीजी इस तरह ही प्रबंध करते रहे तो आने वाले समय में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। आज आवश्यकता है पानी पर चिंतन करने की। पिछली सरकार के द्वारा मेरे जिले के अन्दर 1200 हैण्ड पम्प और 104 ट्यूबवैल स्वीकृत थे, आपने उनको कहा कि आगामी आदेश तक इनको रोका जाए और फिर उनको निरस्त कर दिया गया। इससे बड़ा धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। पानी तो हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। आपने जल नीति बनाई, कहीं भी इसमें उल्लेख नहीं किया, आप कह रहे हैं आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, तो मिसेज ने कही, बाद में बांधना आकाश-पाताल, पहले अपने घर की छान ही बांध लो। आप जल नीति कह रहे

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

हैं यमुना नदी को जोड़ने की, नर्मदा नदी को जोड़ने की, नदियों के पानी लाने की। कागजों की बात कर रहे हैं कि कितने ट्यूबवैल सैंक्शन कराओगे, कितने आप हैण्ड पम्प दोगे, कहां-कहां, आपने सब जगह का नाम रख दिया। अलवर जिले के अन्दर हमारे यमुना नदी भरतपुर-अलवर को, अगर उसमें बजट को जोड़ा जाए और निश्चित रूप से यमुना नदी का जल लाने का प्रयास करें तो राजस्थान के लिए खुशहाली का काम होगा।

श्री सभापति: कृपया आप थोड़ा छोटा करें, निवेदन है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय सभापति महोदय, आपकी बात रख रहा हूं।

पंचायत राज के बारे में, मैंने पैरा पढ़ा। मैंने पूरे बजट को बहुत शालीनता से सुना, माननीय मुख्य मंत्रीजी दो घंटा दस मिनट बोले, सारा सुना। एक मिनट मैंने कोई अपनी बात रखी थी, उसके अलावा सारा सुना था। इन्होंने कहा था, हम ग्राम पंचायत को पट्टे देने का अधिकार दे रहे हैं। यह कहां से आ गया अधिकार? हमेशा से ग्राम पंचायत ही आबादी के पट्टे देती है, इसमें नया क्या कर दिया? और जो ग्राम पंचायत के पास भूमि नहीं होती है उस सिवाय चक भूमि को सिफारिश करके माननीय जिलाधीश महोदय के पास भेजा जाता है, जिलाधीश महोदय उसको आबादी में कन्वर्ट करके पट्टे देते हैं। इसमें सरकार का क्या एहसान हो गया? मतलब इस तरह की बातों से गुमराह करने की बात कर रहे हैं कि, साहब, हमने किया। माननीय गृह मंत्रीजी नहीं हैं यहां पर, इन्होंने...(व्यवधान)...सुन लो बात। सारी सुन रहा था मैं तो। इन्होंने होड़ लगाई, मेजें थपथपा रहे थे, हमने तो कुछ कहा ही नहीं । आपका दायित्व बनता है कि आपके नेता की जय बोलो, लेकिन राजस्थान की जनता को गुमराह मत करो। राजस्थान की जनता में झूठी बात मत रखो। मैं दावे से कह सकता हूं कि ग्राम पंचायतों को पट्टे देने का अधिकार हमेशा है, रहा है और आज भी है, चाहे सरकार किसी की भी हो। पहले से है, हमेशा से है, कोई नया काम नहीं किया। हम पट्टा देने का काम करेंगे, आप कहां से देंगे पट्टा, साहब? पंचायती राज एक्ट के अन्दर, आपने कहा, दूसरी बात, आपकी नेता...(व्यवधान)... सुन लो, एक मिनट आप सुनो। (व्यवधान) हां, दे रहे हैं, हमेशा दिये हैं। मैं प्रधान रहा हूं, आपको पता नहीं है, बैठिये आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): ..इसीलिए तो हम बोल रहे थे कि सरकार देगी यह पट्टा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये, बोलने दीजिये इनको। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): इन्होंने कहा कि पंचायतों का हम सुदृढ़ीकरण करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि राजस्थान का, ग्राम पंचायतों का विकास होगा। पहले अलवर शहर को सम्भाल लो, जयपुर को कर लो, जोधपुर को कर लो, किसान का तो भला नहीं होने वाला। किसान का भला तब होगा जब ग्राम पंचायत मजबूत होगी। हमें भी अब इस बात की मोहर लगेगी कि राष्ट्रीय कांग्रेस की माननीय अध्यक्ष और कांग्रेस की नेता सोनियाजी यहां पर आईं नागौर के अन्दर। राजीव गांधी ने एक सपना लिया था, आप भी कहते हो, हालांकि पंचायती राज माननीय भैरोंसिंहजी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया। लेकिन राजीवजी एक्ट लाये, इस एक्ट के अन्दर उन्होंने कहा, पंचायतों का सुदृढ़ीकरण करेंगे, दो अक्टूबर से। आज सवा साल हो गया, एक भी ग्राम सेवक को, एक भी अध्यापक को, एक भी जेईएन को, सोलह विभागों की बात करते हैं, माननीय पंचायती राज मंत्री हों तो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस बात को उजागर करना चाहूंगा कि कौन से अधिकार दे दिये आपने? कोई अधिकार नहीं दिये पंचायतों को। सब पंचायतों को अधिकार देंगे। हर मामले के अन्दर नरेगा की बात कर रहे हैं, नरेगा राष्ट्रीय रोजगार योजना है। प्रधान मंत्री सड़क योजना है, राष्ट्रीय योजना है, केन्द्र में हमारा भी हिस्सा है, हमारे राजस्थान के हर व्यक्ति का टैक्स जाता है, उसमें किसी के एहसान और कर्मों की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया नरेगा के अन्दर? आपने मानिटरिंग करने की बात की, कल माननीय मंत्रीजी यहां वक्तव्य दे रहे थे कि इस बार दो सौ कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसका मतलब करप्शन बढ़ा है और बढ़ा है तो उसका दायित्व आपका है। आज भी सवा साल पहले का रोजना रोओ। सवा साल आपकी सरकार थी, पांच साल की क्वार्टरली तो गई, आपने आज तक क्या किया? जब पीछे कुछ खामियां रहीं उसकी वजह से हम यहां हैं, लेकिन आप भी जल्दी तैयारी कर लो इधर आने की। अब गृह मंत्रीजी नहीं हैं, मैं कहना चाहता हूं, अलवर जिले के अन्दर हमारे चार थाने-बानूसर, थानागाजी, खेड़ली और लक्ष्मणगढ़ हैं, चारों थानों को कस्बे से चार किलोमीटर बाहर निकाल दिया। ठीक है, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग हैं उनमें आज पशु बंध रहे हैं। उनमें चौकियां

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

स्थापित हों, कस्बे पर नियंत्रण हो, आपने कहीं भी उल्लेख नहीं किया। भिवाड़ी के अन्दर तो कह दिया कि यहां पर तो इण्डस्ट्रियल एरिया है, यहां पर चौकियों को थानों में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन जो चार थाने पहले थे यहां पर मौजूद, उनके अन्दर भी आप चौकियों को स्थापित करने की बात करें। इतना क्राइम बढ़ रहा है, कहीं भी उल्लेख नहीं किया कि हम इतने पुलिस वालों की भर्ती करेंगे। जब भर्ती ही नहीं करोगे तो क्राइम रोकेंगे कहां से? दूसरी बात, मेवात विकास बोर्ड की बात करता हूं, अल्पसंख्यक समुदाय को अपना वोट बैंक मानती है कांग्रेस-आई। माननीय सभापति महोदय, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस सरकार को, ये दम भरते हैं अल्पसंख्यकों का, मेवात विकास बोर्ड का गठन तो भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार में भैरोंसिंहजी ने किया और मेवात विकास बोर्ड के अन्दर चेयरमैन बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मेवात विकास के लिए पिछली हमारी सरकार ने ग्यारह आवासीय विद्यालय महिलाओं के लिए मेवात क्षेत्र में पांच तो भरतपुर के अन्दर और छह अलवर जिले के अन्दर खोले जिनकी एक-एक की लागत आठ-आठ लाख रुपये थी। लेकिन इस सरकार के आने के बाद उस पर लगा ताला खोलने का काम भी नहीं किया। कहां दे रहे हैं आप मेवात विकास बोर्ड के अंदर पैसा? (व्यवधान) देवनारायण बोर्ड में कह रहे हैं गुर्जर समाज को, रैबारी समाज को, चारों समाजों को, मैं भी स्वागत करता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह योजना चालू की, इसका तो धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद तभी दूं जब हमारे वाला पैसा देकर आगे चलाओगे तब। भई, हमारा जो दिया हुआ पैसा है देवनारायण बोर्ड के अन्दर, हमने इतने ट्यूबवैल, हैण्ड पम्प स्वीकृत कराये, हमने पीएचसी खोली, हमने आईटीआई खोली, उसका लम्बित पैसा आज तक पड़ा है। आपने नहीं कहा इसमें आगे। हमने गठन कर दिया बोर्ड, बोर्ड का गठन कर दिया राजस्थान में। (व्यवधान) मैं सब के लिए, मैं तो मेवात के लिए बोल रहा हूं। एस.सी.एस.टी. के लिए बोल रहा हूं। अब इन्होंने बात कर दी...(व्यवधान)...मैं तो यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस सरकार को, कि भगवान इनको सद्-बुद्धि दे, एक तो ये अकाल से निबटने की तैयारी की बजाय सोचें कि भगवान बरसे और प्रजा सुखी हो। निबटने की बात तो अकाल से तब करोगे जब अकाल पड़ेगा। वैसा काम करो कि अकाल पड़े ही नहीं। आप आओगे नहीं तो अकाल पड़ेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड आज कहीं योजना

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

नहीं, मानता हूं कि सहकारिता मंत्रीजी ने कहा कि पंचायत मुख्यालयों पर जीएसएस खोली जाएंगी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब कृपया समाप्त करें। आपसे तो सहयोग की ज्यादा अपेक्षा की जाती है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय सभापति महोदय, अलवर की बात बताता हूं आपको। माननीय सभापति महोदय, आप आसन से हटकर हमारे सदस्य हैं, अलवर से हैं, आपने कहा, साहब, अलवर को दिया। अलवर को क्या दिया, साहब? कलेक्ट्रेट खाली करवा दी, क्यों करवा दी? राजनीतिक कारणों से खाली कराने की बात कर रहे हो आप। और कहीं नहीं कराई कलेक्ट्रेट खाली आपने, सिर्फ अलवर में कराई। वह आपने सिर्फ कांग्रेसी नेताओं की वजह से, व्यक्तिगत आकांक्षा की वजह से। दूसरे ऐसे ही करने वाले थे अलवर की तो विश्वविद्यालय हमारा खोलेंगे...

श्री सभापति: कृपया, माननीय सदस्य, समाप्त करें। आपका ही समय तय किया हुआ है एक घंटा। बस, अब तो बाकी कुछ नहीं रहेगा, बाकी बोल नहीं पाएंगे। आपके साथी कई।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): भर्तृहरि विश्वविद्यालय, भरतपुर में विश्वविद्यालय, शेखावाटी विश्वविद्यालय, तीनों विश्वविद्यालयों को खोलने का काम करो, बंद करने का काम मत करो। किसी चीज को बढ़ाने का काम करो। मैं तो आपके माध्यम से, सभापतिजी, इस सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत को यही कहना चाहूंगा कि हमारे अलवर जिले में जो विश्वविद्यालय खोला उसको तनस्तुर जारी किया जाए। देवनारायण बोर्ड योजना में जो इन्होंने छलावा किया है, उसका खुलासा किया जाए। मेवात का जो पैसा अटका पड़ा है, उसको लागू किया जाए। और तीसरी बात यह कह रहा हूं कि झूठी वाहवाही लूटने की बजाय स्वच्छता से काम करें, बेरोज़गारों को रोजगार देने का काम करें, जनता को गुमराह नहीं करें। जनता देख रही है, यहां पर मेजें थपथपाने की होड़ हो रही है, उससे ज्यादा होड़ होगी जनता के बीच जाकर....

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें अब।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): अपनी बात रखें। किसान विरोधी, बेरोजगार विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी और ओबीसी

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

विरोधी इस बजट की मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य जनाब अलाउद्दीन आजाद।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोतजी ने वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया है, उसके समर्थन में आपके समक्ष अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। मेरे सामने विपक्ष के जो सीनियर सदस्य बैठे हुए हैं, वहां आधे दर्जन के करीब जो लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूं। दो वरिष्ठ सदस्यों से तो मैंने सीखा है अपनी ही सीट पर पूरे टाइम बैठकर पूरी बात सुनना। मैं पिछली बार जब बोल रहा था तो इन्हीं सदस्यों में से एक ने, चूंकि मैं सवाईमाधोपुर से आता हूं और आप सब ने देखा होगा, वहां टाइगर प्रोजैक्ट है, और टाइगर को जब भी आप देख लेते हो किसी की तरफ जाते हुए तो सबसे पहले वह घेटू पकड़ता है यहां से यूं-यूं, हमारे बोलते ही, हमने टाइगर का नाम लिया और एक सदस्य ने फट से कह दिया। मैंने कहा था पोइन्ट आफ आर्डर, कि शून्यकाल में नहीं होता है। हमने कहा, सारी, पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन। अपने विचार प्रकट नहीं कर सका अपने उस क्षेत्र के बारे में। मैं आज इस सदन में जो कुछ भी चर्चा हो रही है, उसके बारे में बड़े खुले रूप से कहना चाहता हूं। यह सही है कि जो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं वे अपनी ढपली बजाएंगे, अपनी बात कहेंगे। मगर यह याद रखिए, मनुष्य को जो जन्म मिलता है, जो धर्म पर विश्वास रखता है, जो नैतिकता, सदाचार और शिष्टाचार के नियमों में बंधा रहता है उसको इस हद तक झूठ नहीं बोलना चाहिए कि उसकी आत्मा भी उसको धिक्कारे। यह सही है कि आप अपने विचार कहेंगे। अभी वरिष्ठ सदस्य दूसरे भी यहां पर मौजूद नहीं हैं, उन्होंने आंकड़ों के मायाजाल से साबित करने की कोशिश की, और एक माननीय सदस्य जो यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने जो कहा, उनकी तो पूजा करनी चाहिए। याद रखिए, आंकड़ों के मायाजाल से भ्रमित करने से गरीब का पेट नहीं भर सकता। मैं यह कहना चाहता हूं आप हमारी बात सुनिए, हम आपकी बात सुनते हैं तो बिलकुल बोलते नहीं हैं। तभी बोलते हैं जब कुछ होता है। आप अपनी बात सुनिए। हमको मौका मिला है बात करने का, बड़ी मुश्किल से यहां पर आये हैं, वहां से कूदकर आये हैं। मगर यूं ही नहीं आये, जनता के बीच में जाकर डंके की चोट पर यहां पर आये हैं। तो आप कृपा करिए, थोड़ी हमारी

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

बात सुनिये। याद रखिए कहा गया सब कुछ पूरा खाका। पूरे खाके को खींच कर कहा गया कि मुख्य मंत्री ने बड़ा ही लोक-लुभावन बजट पेश किया है, मगर इसकी आत्मा बिलकुल नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस बजट की आत्मा उनको क्यों नजर आएगी जिन लोगों ने कभी गरीब का घर नहीं देखा, गरीबी नहीं देखी? शुरू से लगाकर आखिर तक, जन्म से लेकर जन आंदोलन का, आजादी का, गरीबों का और सामंतवाद से टक्कर लेने, पूंजीवाद से टक्कर लेने का काम इस पार्टी ने किया है, वह जानती है, गरीबों का क्या हाल है और गरीबों का विकास किस तरह से होगा। कैसे आत्मा नहीं है इस बजट की, जो पेश किया गया है? देखिए, यह गरीबों के लिए है, आम आदमी के लिए है। यह उन लोगों के लिए है जो अंधता, कमदृष्टि, कुष्ठ रोग के शिकार हैं, जिनकी श्रवण शक्ति कम है। जिनमें निःशक्तता है, मानसिक रुग्णता है, जो कुष्ठ रोगी हैं, एड्स रोगी हैं। ऐसे लोगों के लिए भी इसमें जगह दी गई है और आपको उसमें आत्मा नजर नहीं आ रही है? आत्मा उसको नजर आएगी जिस आदमी ने गरीब की झोंपड़ी में जन्म लिया हो, जो उसके दुःख को देखता हो। उस झोंपड़ी में जिनके छह बच्चे-बच्ची, बहिन-भाई पैदा होते हैं और बकरी के बच्चे, गाय के बच्चे भी जिसमें बांध देते हैं। तो उस गरीब परिवार में जन्म लेकर मुसीबतें देखी हैं। हमने वह भी देखा है आजादी का टाइम जब धर्म के नाम पर इस देश में आग लगाई जा रही थी। आज वे लोग एकता की बात करें, गरीबों की बात करें, राष्ट्रीय एकता की बात करें और ऐसी बात करें कि हम इस देश को बनाएंगे, यह बात नहीं चल सकती किसी भी स्तर से। आपको यह तो तय करना होगा, अगर आपको राष्ट्रीय बनना है, अगर आपको राष्ट्रीयता की बात करनी है, आपको भाईचारे की बात करनी है, आपको सद्‌भावना की बात करनी है तो हर वर्ग की बात आपको करनी पड़ेगी तब जाकर यह बात होगी। मुख्य मंत्रीजी ने हर वर्ग की बात की है। अगर यह पूछ लिया जाए तो हिन्दुस्तान में कौनसा ऐसा बजट है कि उस राज्य में बिलकुल चुनाव नहीं हो रहे हों और बिना चुनाव हुए ऐसा बजट पेश कर दिया जो चुनाव वाले राज्य पेश करते हैं? हिन्दुस्तान के इतिहास में उठा कर आप देख सकते हैं। यह बजट ऐसे टाइम पर पेश किया और दिल से पेश किया, उन्होंने दिल उंडेल कर रख दिया, क्यों रख दिया? माननीय उप नेता महोदय, आपको सादर नमस्कार, क्यों किया उन्होंने? उन्होंने इसलिए किया कि चुनाव हुए। जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं और जो पचास तरह की उलटी-सीधी बातें यहां कुलापे कर करके करते हैं, उनको याद

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

रखना चाहिए कि पिछली बार चुनाव हुआ है। जनता क्या कहती है वह निर्णय है। आप और हम यहां भाषण दे दें, आप और हम यहां आंकड़े स्पष्ट कर दें, वह कुछ साबित नहीं कर सकता। जनता क्या कहती है? जितने भाषण आप यहां दे रहे हो, अपने इलाके में भाषण दिये हैं, जनता के सामने सारी बातें की हैं, आपने इससे भी अधिक बातें कहीं हैं। कठोरता की, लड़ाने और विरोध करने की, उस सब के बाद में जनता ने आपको अपना आईना दिखा दिया है, आपको हराया है। आप वहां बैठे। आप एमपी चुनाव में हारे, आप पंचायतों के चुनाव में हारे। नगर पालिका में जो आप कहते थे कि हमारा शहरों में राज है, आपका राज उलट गया। उस राज को उलटने के बाद में आप जितनी बातें अभी यहां कह रहे हो, वे मूल्यहीन यूं हैं कि उसका निर्णय जनता ने दे दिया है। यहां बात चली महंगाई की। मैं आपसे कहता हूं, पूरी दुनिया में महंगाई है। आप सुनिये-

दोस्ती को दायरे इस तरह फैलाइए,

कि दुश्मनी को सूई रखने की जगह हासिल न हो।

मैं आपसे यह कह रहा था, महंगाई पूरे विश्व में बढ़ रही हैं। भारतवर्ष एक ऐसा मुल्क है जिसका असर तो इस पर हुआ है, हम पर भी हुआ है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर उस पर काबू पाने में दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसने पहली कोशिश की है। मुल्क ने कोशिश की और उसके बाद में इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने कोशिश की। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को साथ लेकर, लोगों के पैसे बढ़ाकर और सुविधाएं देकर इस तरह की स्थिति पैदा की कि जनता पर उसका ज्यादा असर नहीं पड़े। कुछ साथियों ने, माननीय सदस्यों ने मायनोरिटी के बारे में यह कहा है कि किसने क्या किया और किस सरकार ने क्या किया। मैं पिछली सरकार की बात बताना चाहता हूं। माननीय अशोक गहलोतजी के उस कार्यकाल और अभी इस कार्यकाल का अगर यह रखा जाए कि राजस्थान की जनता के लिए सबसे पहले किसने काम किया तो जितने नम्बर अशोक गहलोतजी को आएंगे, दूसरा आदमी बिलकुल सामने खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने सबसे पहले आम लोगों के लिए, हर लोगों के लिए छांट-छांट करके काम किया। जिन लोगों ने हमको विश्वास दिया, जिस जनता ने हमारा विश्वास किया, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका कर्ज चुकाएं और हमने इस बजट के द्वारा जनता का कर्ज चुकाने की कोशिश की है। मायनोरिटी की बात बता दूं मैं पिछली बार की आपकी, आपने मदरसा बोर्ड बनाया। याद रखिए, मदरसा बोर्ड में 17 सदस्य और बनते हैं। उर्दू के विद्वान

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

लिए जाते हैं, अरबी के विद्वान लिए जाते हैं, प्रसिद्ध महसूर जो मदरसे हैं उनके आदमी लिए जाते हैं, समाजसेवी लिए जाते हैं। आपने एक आदमी नहीं लिया। ऐसे आदमी को बना दिया जिसका उर्दू से कोई लेना-देना नहीं था। माननीय अशोकजी गहलोत पहले आदमी थे जिन्होंने पूरे राजस्थान में सबसे पहले मदरसा बोर्ड बनाया और मैं यह कहते हुए अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता हूं कि उस मदरसा बोर्ड का सबसे पहला चेयरमैन बनने का मुझे सौभाग्य मिला। पूरा बोर्ड बनाया, सात दिन में सदस्य बनाये पूरे। सात दिन में मीटिंग बुलायी। मीटिंग बुलाने के बाद जितने लोगों को रोजगार मिला है उस मदरसे में आज तक, उनमें से तीन चौथाई को अशोकजी गहलोत के टाइम पर दिया हुआ है, आपके टाइम पर कुछ नहीं दिया। उर्दू अकादमी को आपने निष्क्रिय कर दिया। हज कमेटी का आपने क्या हाल किया, यह सब जानते हैं कि आपने किस तरह का तमाशा किया। अल्पसंख्यक वित्त निगम का आपने क्या किया? उसको पांच करोड़ रुपये मिलते हैं, आपने उसको बनाया ही नहीं। पांच करोड़ रुपये केन्द्र से मिलते ओर पांच यहां से मिला कर दस करोड़ रुपये उन गरीबों को मिलते, वो आपने उनको नहीं लेने दिये। आज क्या हुआ है? आज यह हुआ है कि उन्होंने मदरसा बोर्ड के लिए ढाई हजार टीचर्स की नियुक्ति करने की बात की है। एक हजार के लिए प्रोविजन रखा, दो करोड़ रुपये देने की बात की। उसी तरह से मदरसों के लिए, वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति के लिए बीडीओ को अलाउ करने की बात की। माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वक्फ की सम्पत्तियों पर करोड़ों रुपये सरकारी महकमे का किराये का बाकी है, आप उसको दिलाने की कोशिश करें तो उनकी आर्थिक कमजोरी दूर होने की बात होगी। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि माइनोरिटी की जितनी संस्थाएं थी, पिछली सरकार ने उनको बिलकुल निष्क्रिय करके रख दिया। मगर हम वो सहते रहे।

'हजारों गम सहे फिर भी नहीं आये आंसूं।

हम अहले जर्फ हैं, पीते हैं चिल्लाया नहीं करते।

और जहां जुल्मों सितम का दौर दौरा रुक नहीं सकता।

जिगर के जख्म हम जालिमों को दिखलाया नहीं करते।'

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ...(व्यवधान)... चाहे जितना पूजिये, पत्थर खुदा होता नहीं।

और कौन कहता है कि पत्थर में खुदा होता नहीं।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): न जाने किस कदर का हम मुकद्दर लेकर आये हैं।

आह, हमारे आस्तीनों में हमारे ही सांप पलते हैं।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): 'पहले तो नजर डालो तुम अपनी जफाओं पर।

इल्जाम कोई रखना फिर हमारी वफाओं पर।'

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): न जाने कितनी तंगी में ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप अपना वाद-विवाद जारी रखिये, शेरोशायरी समाप्त।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): भाजपा के खारजी टुकड़ों पर पलते हैं, इसलिए, दोस्तों, 'जहं तहं कछु भय नहीं, अपनी जाति न पास। काठ बिना कुठार कहुं तरपे कल्प निरज निशान।'

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): 'ये वक्त की गर्दिश भी क्या शै है चमन वालों।

कल वक्त हमारा था अब वक्त तुम्हारा है।'

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): 'हमने तलवारों को पाला पेट पर देकर जगह।

उम्र भर जीते रहे हैं म्यानों की तरह।

जानते हैं बोलने से बंद होगी ये जबां।

बंद रह नहीं सकते फिर भी बेजुबां लोगों की तरह।'

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): 'वो बेरक्त की नब्जे हैं फिर भी नहीं काबू में। क्या तुमने सदा दी है, क्या तुमने पुकारा है।'

श्री सभापति: अभी इसके बाद में शेरोशायरी अंकित नहीं होगी। अब चलिये।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): माननीय सभापतिजी, मैं यहां यह निवेदन कर रहा था कि माननीय अशोकजी गहलोत के पिछले साल के टाइम पर अकाल पड़ा था और बार-बार हमारे साथी यह कह रहे थे कि जब भी अशोक गहलोत आते हैं तो अकाल पड़ जाता है। जितने भी लोग यहां बैठै

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

हुए हैं, मेरी न तो उनसे उम्र कम है, कुछ लोग मेरे बुजुर्ग हैं जिनको मैं नमस्कार करता हूं, दो-तीन हैं, मगर मैंने चुनावों के टाइम पर पूरे हालात देखे हैं, 57 साल के इतिहास में 53 बार राजस्थान में अकाल पड़ा है। जितने भी राज्यपाल के अभिभाषण हुए हैं, आप पढ़ लीजिये 1952 से लगाकर आज तक, उनमें सबमें अकाल की बात की गयी है। एक बार कहा गया है कि राज्य में अकाल पड़ा है और अतिवृष्टि भी हुई है। तो यह कहना, मुझे तो वो दिन भी याद है जब न अशोकजी गहलोत कुछ थे न मुख्य मंत्री थे। सुखाड़ियाजी मुख्य मंत्री थे तो उनके लिए आपके बड़े नेता यह कहा करते थे कि सूखा इसलिए पड़ रहा है कि सुखाड़ियाजी मुख्य मंत्री हैं। तो आपकी यह सीरत है शुरू से लेकर आखिर तक, नेताओं को बदनाम करने की। असत्य बात कहने की आदत आपकी शुरू से रहती रही है। याद रखिये, ईश्वर की आस्था को स्वीकार नहीं करना है यह। एक आदमी को मुसीबत पड़ती है, मगर याद रखिये, हमारा नेता इस तरह का नेता है कि मुसीबत पड़ने के बाद में हिम्मत के साथ में खड़ा होता है। हमारी पार्टी वो है जो मुसीबत आने के बाद ही लोगों के दिल में जाती है। पिछली बार कोई घर गरीब का ऐसा नहीं था जिसमें गेहूं की बोरी नहीं रखी हो। पिछली बार कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसका हाथ हमने नहीं थामा हो। जब आप लोग आलोचना कर रहे थे, जब आप लोग उनका हंसी-मजाक उड़ा रहे थे, पूरे लोगों के घर में खाने के लिए अनाज पड़ा हुआ था। अब भी आपको यकीन दिला देना चाहते हैं कि हमने गरीब का हाथ थामा है, हमने आम लोगों की बात सोची है और याद रखिये...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। आपका ज्यादातर टाइम शेरोशायरी में चला गया आसन की कोई गलती नहीं है।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): माननीय सभापतिजी, आप और मेरे में तो समानता है। माननीय सभापतिजी, मैं यह सारी बात छोड़ कर आपको यह बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सवाईमाधोपुर गेम्स सैंक्चुरी विश्व प्रसिद्ध स्थान है, वहां पर आजकल ऐसी स्थिति चल रही है कि बड़े-बड़े पैसे वाले लोग-बाग़ राजनीति कर करके स्थानीय लोगों को बेदखल करने की बात कर रहे हैं। मैं इस मौके पर यह बात कह देना चाहता हूं कि वहां पर टाइगर्स अपना क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, वहां पर दर्रा है, करौली है, मानसरोवर गेम्स सैंक्चुरी है, रामगढ़ सैंक्चुरी है, उस पूरे इलाके को कारीडोर बनाया जा सकता है और कारीडोर बनाकर उनकी सुरक्षा की जा सकती है।

श्री सभापति: कृपया अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात आपको और याद दिलाना चाहता हूं कि...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, केवल दस मिनट हैं, और लोगों को बोलना है उसके बाद में हाउस एडजर्न होगा। कृपया समाप्त करें, मेरा निवेदन है आपसे।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): आखिरी बात कहना चाहता हूं, एक मिनट। आपने सब पर तो बड़ी कृपा की है, आपके और मेरे सफेद बाल हैं, दो मिनट मेरे ऊपर भी कृपा कीजिये।

माननीय सभापतिजी, सवाईमाधोपुर में बड़ी प्रसिद्ध सीमेंट फैक्ट्री थी जो बंद हुई, क्यों हुई? 1947 में सीमेंट फैक्ट्री बनी थी, 1953 में उत्पादन चालू हुआ और 1987 में उसको बंद कर दिया गया। पांच हजार मजदूर मर रहे हैं, दो हजार करोड़ की कंपनी बनी हुई है...

श्री सभापति: Please finish it now. I request you to kindly finish it now.

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): हरिशंकरजी भाभड़ा उद्योग मंत्री थे और शेखावतजी मुख्य मंत्री थे तब से वो पड़ी हुई है, हम चाह रहे हैं कि उन मजदूरों के साथ इंसाफ हो।

श्री सभापति: प्लीज, मेरा निवेदन है, माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करें। श्री केसाराम चौधरी। कृपया अपनी बात दो मिनट में कहें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: कृपया विराजिये।

शासकीय वक्तव्य

जयपुर की नेमीसागर कालोनी में महिला के बोरवैल में गिरने की घटना

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी पाइंट आफ इंफार्मेशन के माध्यम से एक जानकारी दी, उस जानकारी को मैं सदन को बता देता हूं।

(श्री परसादीलाल)

श्रीमती उषा जैन वाइफ आफ श्री सुभाष जैन, उम्र 55 वर्ष, जैन मंदिर कैंपस, नेमीसागर कालोनी, वैशाली नगर में जमीन से तीन फीट बोरवैल का प्लेटफार्म है। रोज वहां श्रद्धालु उस बोरवैल से पानी निकाल कर, जो भी आते हैं वहां, उससे पानी निकाल कर काम में लेते हैं। उनके परिवारजनों से जैसी जानकारी मिली है, ये बीस साल से मेंटली डिस्टर्ड हैं। जो बोरवैल है वो 220 फीट गहरा है, उसका एक कपड़ा जो सफेद है, वो दिखाई दे रहा है 170 फीट के आस-पास। प्रशासन के पूरे अधिकारी-कलक्टर, एस.पी., डिफेंस के जो भी हैं, सारे अधिकारी मौजूद हैं और उसको निकालने की कार्ययोजना पर विचार कर रहे हैं। यह जानकारी हमारी सरकार को मिली है, जो आपको बता दी।

श्री सभापति: I hope, you got it. श्री केसाराम चौधरी।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, 9 मार्च, 2010 और 8 जुलाई, 2009 को मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने इस सदन में दो बजट रखे, सबसे पहले तो मैं 8 जुलाई, 2009 के बजट में जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणाएं की थीं, उनकी तरफ ध्यानाकर्षण करना चाह रहा हूं आपकी मार्फत। इन्होंने पहली घोषणा की थी कि हर तहसील स्तर पर एसडीएम हैडक्वार्टर खोल दिया जाएगा। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या एसडीएम हैडक्वार्टर खुल गया? एसडीओ लग गया क्या? स्टाफ लग गया? कोई पता नहीं है। राज्य में किसान आयोग का गठन किया जा चुका है। 8 जुलाई, 2009 के अनुच्छेद 122 में लिखा है, राज्य में किसान आयोग का गठन किया जा चुका है। यह आयोग शीघ्र ही अपना कार्य शुरू कर देगा। हो गया क्या? इसके सदस्य कौन-कौन हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी यह भी बता दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह वाद-विवाद है, आप प्रश्न नहीं पूछ सकते यहां।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं वाद-विवाद नहीं कर रहा हूं। गत बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनकी क्रियान्विति के बारे में बता रहा हूं। कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मिले, इस दृष्टि से कृषि व्यवसाय एवं उद्योग नीति बनाई जाएगी, कैसी नीति बन गई? और किसानों की हालत क्या है? हर पंचायत हैडक्वार्टर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे, क्या खोल दिये गये?

(श्री केसाराम चौधरी)

कितने खुले? अगर खोल दिये तो आप लिस्ट रख दें। अनुच्छेद 46 में 30 परियोजनाओं के कार्य आगे बढाये जाएंगे जिसमें जवाई-पाली पाइप लाइन भी शामिल थी। जंवाई-पाली पाइप लाइन माननीय वसुंधराजी ने पाली तक लाकर छोड़ी, उसके आगे एक इंच भी नहीं बढ़ी और वाहवाही लूट रहे हैं। सभापति महोदय, मैं पूछना चाह रहा हूं कि इस बजट में उस योजना को जैतारण तक पहुंचाने को 400 करोड रुपये और सैंक्शन कर दिये थे, वह वहीं की वहीं पड़ी है। इसी के अनुच्छेद 43 में पेयजल उपलब्ध कराने की सबसे बड़ी चुनौती है। मारवाड़ जंक्शन की कई पंचायतें ऐसी हैं जिनमें आज भी पीने का पानी नहीं है। उन्होंने जो घोषणा की थी उन योजनाओं में बांता, बोरीमांदा, सिरायरी और घूंधला में विगत सरकार ने योजनाएं सैंक्शन कर दी थीं मगर अभी कुएं खुदे नहीं, आधी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, कहीं पाइप लाइन नहीं डाली है, जबकि उसका बजट सैंक्शंड है। दो बजट और निकल गये, मगर वे योजनाएं अभी तक अधूरी पड़ी हैं।

सभापति महोदय, जोधपुर शहर के भू-जल स्तर में वृद्धि चिंता का विषय है जिसके लिये ज्यादा पानी के लिये 12 करोड 27 लाख रुपये की योजना बन रही है। क्या उस पानी को पाली के लिये नहीं लाया जा सकता? पाली ने कई वर्षों तक जवाई बांध से जोधपुर को पानी पिलाया है, अब पूरा पाली जिला पीने के पानी के लिये तरस रहा है और उसमें हालात भयंकर खराब हो रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से पाली ने जोधपुर को पानी पिलाया, अब जोधपुर के पास सरप्लस पानी है, उस पानी को अकाल की विषम परिस्थिति में पशु और मनुष्यों के पीने के लिये अगर मारवाड़ जंक्शन और पाली जिले में पहुंचाया जाए तो जनता के हित में होगा।

हरित योजना का सपना साकार करना है तो सीख लीजिए। गत बजट के 102 पैरा में आपने हरित राजस्थान की कल्पना की थी और इन्होंने इस अकाल में कैसा हरित राजस्थान किया? अगर कोई सीख लेना चाहे तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में रानी एक गांव है, उस गांव में किशोर भाई खिमावत नाम का एक व्यक्ति है जिसने लाखों पेड़ लगा कर रानी के अन्दर आने वाले सभी रास्तों पर लाखों पेड़ लगाये हैं। एक भी वृक्ष का गैप फीलिंग नहीं है इतने सुन्दर रो में वृक्ष लगाये हैं। वे वृक्ष देखने लायक हैं । ऐसे व्यक्ति को राजस्थान सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाना चाहिये। ऐसे व्यक्ति को राज्य स्तर पर धरती पुत्र की उपाधि देकर सम्मानित किया जाना चाहिये जिसने हरित

(श्री केसाराम चौधरी)

राजस्थान का सपना साकार कर दिखाया है। जब एक व्यक्ति यह कर सकता है तो सरकार जो कर रही है वे पेड़ क्यों सूख रहे हैं? ये मैंने पुराने बजट की बातें कहीं हैं।

सभापति महोदय, 2010-11 का जो बजट रखा है उसके बारे में आपसे निवेदन कर रहा हूं। सभापति महोदय, जब-जब धरती पर किसान दुःखी रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक किसान सुखी नहीं रह सकता, तब तक धरती पर महंगाई कम नहीं हो सकती। आर्थिक समीक्षा में पहले 92.86 हैक्टेयर क्षेत्रफल में खेती हो रही थी, उसके पहले जो खेती हो रही थी उससे तुलना की जाए तो आपका उत्पादन घट रहा है। खाद्यान्न उत्पादन का जो नक्शा दिया है उसमें खाद्यान्न का उत्पादन भी 2009-10 में बिलकुल घट रहा है और अनाज का उत्पादन भी .....

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। आपसे निवेदन है, सहयोग करें, समाप्त करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): साहब, थोडा तो बोला हूं अभी, 5 मिनट भी नहीं हुए। आप घड़ी देख लीजिए, 5 मिनट भी नहीं हुए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के सचेतक महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे 3-4 माननीय सदस्य और बाकी हैं, कृपया एक घंटा सदन का समय और बढा दें। (व्यवधान) सभापति महोदय, सदन तो कई बार 12-12 बजे तक चला है, क्या फर्क पड़ता है?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति: क्या आपकी सहमति है ?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आधे घंटे की ।

श्री सभापति: आधे घंटे के लिये सदन का समय बढाया जाता है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, 15 वर्ष अकाल की मार झेलते हुए किसान की माली हालत खराब हो चुकी है, ऐसी

(श्री केसाराम चौधरी)

हालत में फसली ऋणों की सीमा को बढाया जाए और ब्याज दर को घटाया जाए। सहकारिता मंत्रीजी बैठे हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, आपने वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सहकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन करना बताया। वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट पूर्णत: कब तक लागू कर देंगे, इसको मंत्रीजी स्पष्ट करें ताकि इससे किसानों का भला हो सके। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के सहयोग से राज्य के शेष 11 जिलों में पाली जिले को विकास की गति देने हेतु आईसीडीएफ समग्र सहकारी विकास योजना में शामिल करने पर आपको मैं धन्यवाद देता हूं। माइक्रो फाइनेंस ऋण उपलब्ध कराने के क्रम में प्रस्तावित योजना में 100 करोड़ का ऋण स्वयं सहायता समूह को देने के लिये सर्वदलीय बैठक बुलाकर योजना क्रियान्वयन हेतु ....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। आप सहयोग करें, आधा घंटा और भी लोग बोलने वाले हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ... गठन करें ताकि जरूरतमंदों को ऋण मिल सके। जिस तरह से जयपुर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक द्वारा बगरू औद्योगिक क्षेत्र की नाटाणी ग्रेनाइट मार्बल एण्ड स्टोन प्राइवेट लिमिटेड को अवधि पार 5327346 रुपये होते हुए भी 10 लाख का ऋण दे दिया ....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया समाप्त करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अगर कोई किसान जिसका अवधिपार ऋण कुछ होता है...

श्री सभापति: अब अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, अब अंकित नहीं हो रहा है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: आप मुझे कह रहे हैं ?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):×××

श्री सभापति: श्री पदमाराम । अंकित नहीं हो रहा है, कृपया विराजिए आप।

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, आपने मेरे को 2010-11 के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको और माननीय

(श्री पदमाराम)
मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में राजस्थान की जनता के विकास और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिये बजट पेश किया है। जो बजट पेश किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं।

(समय : 21.00 बजे)

श्री सभापति: श्री बंशीधर खण्डेला।

श्री पदमाराम (चौहटन): यह क्या, मैंने चालू अभी तो किया है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आसन से व्यवस्था आ गई है अब तो। माननीय सभापति महोदय, बंदूक से कारतूस निकल चुका है।

श्री पदमाराम (चौहटन): मैंने तो बोलना ही स्टार्ट ही किया है।

श्री सभापति: मैंने नाम बोल दिया, मैं नाम बोल चुका हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक बार आसन से व्यवस्था आ गई, आपने आसन से व्यवस्था दे दी, अब कुछ हो ही नहीं सकता? बोलिए, बंशीधर जी। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलना चाहते हैं? (व्यवधान) आप विराजिये। इनके बाद बोल लेना।

श्री पदमाराम (चौहटन): राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी ने...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अब तो आसन से व्यवस्था आ गई ... (व्यवधान).....

श्री पदमाराम (चौहटन): बोलना स्टार्ट ही किया है।

श्री सभापति: मैं दुबारा बुला दूंगा, बैठ जाइये। अभी आप बैठ जाइये, मैं मौका दे सकता हूं बाद में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बैठिये, बैठिये। (व्यवधान) आसन की व्यवस्था है।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 2010-11 का बजट रखा है, वह मुंगेरीलाल के सपने के बराबर बजट है। सपने संजोने का काम किया है इन्होंने। पिछले बजट के बारे में अपन देखते हैं तो पिछले बजट के 50 प्रतिशत काम अभी भी अधूरे

(श्री बंशीधर खण्डेला)

हैं। सपने सजाना इनका फितरत का काम है, सपने सजाते रहेंगे। मैं एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूं, पीडब्ल्यूडी के द्वारा इन्होंने सड़कें बनाई हैं और अभी बनाने की जो घोषणा की है ज्यादातर सड़कें सेन्टर से अनुदानित सड़कें हैं, अपना यहां क्या योगदान है इसमें कहीं स्पष्ट नहीं है। सड़कें नई बनती हैं लेकिन यह मालूम नहीं कि आज से 7-8 वर्ष पहले जो सड़कों की हालत थी, वही सड़कों की हालत अब हो गई है। सड़कों को सुधारने के नाम पर एक पैसा भी नहीं है बजट के अन्दर। हालत ऐसी नाजुक हो रही है, सड़कों के मामले पर कोई सोच भी नहीं सकता है।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, बजट का 52 प्रतिशत ऊर्जा के बारे में खर्च करने की बात कही है उसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों ही शामिल हैं। पर अपने पास सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों में मुफ्त ईंधन मिल रहा है उसका उपयोग कम किया जा रहा है। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, उसका ज्यादा उपयोग करना चाहिये।

यदि काश्तकार की सच्ची हितैषी है कांग्रेस सरकार, तो बूंद-बूंद सिंचाई योजना के अन्दर काश्तकार को, दूसरे प्रान्तों में चालू है यह बात, दो या तीन एचपी की मोटर के लिए सौर ऊर्जा के लिए अनुदान देना चाहिए ताकि किसान खुद की बिजली पैदा करे और उससे बूंद-बूंद पद्धति के हिसाब से दो या तीन एचपी की मोटर चला सके तो किसान की हिम्मत बढ़ेगी, किसान का प्रोडक्शन बढ़ेगा। सरकार को बिजली के लिए जो हाय-हाय कर रहे हैं, उससे बचना पड़ेगा। मैं यह चाहूंगा, दूसरे प्रान्तों में जो चल रहा है उसके हिसाब से राजस्थान में भी किसानों के लिए सब्सिडाइज करके सौर ऊर्जा पर ध्यान देना चाहिए।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): सभापति महोदय, बोलना चालू नहीं किया। मैं बैठ जाऊंगा, एक शब्द बोला है मैंने तो अभी। माननीय, दो मिनट में क्यों खानापूर्ति कर रहे हो? मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, मुझे 5-10 मिनट तो दीजिए।

पेयजल के मामले में राजस्थान बहुत बड़ा है पर पेयजल के अन्दर बहुत कम बजट दिया गया है, ऐसा काम कर रहे हैं मुख्य मंत्री महोदय। सीकर जिले के फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के अन्दर फ्लोराइड के लिए सर्वे कराया

(श्री बंशीधर खण्डेला)

जाए। फ्लोराइड का सर्वे दो बार हो चुका है, अब तो क्रमित कीजिए 50 हजार रुपये को, उसके ऊपर क्यों पानी फेर रहे हैं? खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के अंदर 60 प्रतिशत एरिया फ्लोराइड युक्त है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, वहां भी सर्वे कराकर फ्लोराइड का इन्तजाम किया जाए।

चिकित्सा के हिसाब से मुख्य मंत्रीजी सपने दिखा रहे हैं कि सीकर जिले के अन्दर आईसीयू चालू कर दिया जाएगा। दो साल से पांच बैड का आईसीयू चल रहा है, उसका उद्‌घाटन कर रहे हैं। दुबारा थोड़े ही जाएंगे आप लोग यहां से? सीकर जिले में ट्रोमा इकाई चालू कर दी जाएगी वह भी दो साल से चालू है। ऐसे काम नहीं करने चाहिये। जो आलरेडी चल रहे हैं, उनकी क्या घोषणा कर रहे हैं आप? मैं चैलेंज करता हूं, वहां जाकर देखिये। थोड़ा शर्म की बात है, और तो आप जानें, इसमें क्या हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक न्याय के हिसाब से जिन बच्चों को, जिन महिलाओं को, बूढों को 58 से 65 साल के लिए 300 रुपये बताये, वह बढ़ाकर कम से कम 500 रुपये करने चाहिये। 75 से नीचे वालों को कम से 800 रुपये करने चाहिये और 75 से ऊपर वालों को कम से कम 1500 रुपये करना चाहिये जिससे कि वे अपना बुढापा सुधार सकें, यह बहुत कम पैसा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, कृषि के ऊपर मौसम बीमा योजना चालू किया है, जो बीमा योजनाएं करते हैं, जो नीति निर्धारण करते हैं, उसमें किसानों को साथ लेना चाहिये। आपने मौसम बीमा के अन्दर टैम्परेचर का एक उदाहरण दे दिया, टैम्परेचर चाहे 15-20 हो, यदि हवा पुरवाई चल गई या धोला चल गया तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, वह फसल के अन्दर काम आता है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): पांच मिनट और दीजिए। आप तो बिलकुल बोलने ही नहीं दे रहो हो, बिलकुल गड़बड़ करने लगे। फसल बीमा के अन्दर 40 प्रतिशत तक काश्तकारों का नुकसान हो जाएगा, उसमें एक पैसा नहीं देते हैं जबकि बीमा का पूरा पैसा लेते हैं। काश्तकारों के साथ यह अन्याय होगा। उनको जो मुआवजा मिले, वह पूरा मिलना चाहिये।

सभापति महोदय, पशुपालन अच्छा होता है राजस्थान में। काटन शीट पर टैक्स लगाया है, वैट लगाया है उसको खतम करना चाहिये। मैं एक और

(श्री बंशीधर खण्डेला)

कहना चाहूंगा, अच्छा उदाहरण है आपके सामने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छा काम किया, पिछले समय में हवाई जहाज के बारे में कहा कि जितने भी सम्भाग हैं उनको हवाई जहाज से जोड़ा जाएगा, पर्यटक बढ़ जाएगा। किसी न किसी बहाने से जो हवाई जहाज का ईंधन था पिछले समय, नौ महीने पहले सरकार ने बजट पेश किया था उसमें 28 प्रतिशत एटीएफ बोलते हैं उसको पैट्रोलियम भाषा के अन्दर, 28 प्रतिशत एटीएफ को घटाकर 4 प्रतिशत किया, पर पर्यटक को एक प्रतिशत भी फायदा नहीं हुआ, वह फायदा कहां गया ? करोड़ों रुपये का गबन हुआ है। प्राइवेट संस्था हैं, हवाई जहाज चलाने वाले हैं, सारा का सारा फायदा करोड़ों रुपयों का, सारा उनकी जेब में गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दूसरों को मौका देना है, आप समाप्त करिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): इसमें मेरे को बदबू नहीं दुर्गन्ध आती है, केवल पर्यटन का तो नाम लिया गया है।

इसी तरीके से एक चीज और बताऊंगा। बजट में जो आल इण्डिया टयूरिस्ट परमिट की बसें हैं, 15 हजार से बढ़ाकर उनका टैक्स 25 हजार कर दिया गया। यहां से पर्यटन की एक हत्या करने वाली बात है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, सदन के या इधर के नेता हैं उनके आल इण्डिया ट्यूरिस्ट की बसें चलती हैं, आल इण्डिया परमिट के हिसाब से उन पर कैरिज अलाउ नहीं है, लेकिन मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा, उनकी आंख के नीचे उनकी सहमति से आज ट्यूरिस्ट बसें ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही हैं, ट्रकों का काम कर रही हैं इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है? 2-4 कम्पनियां हैं, दो-चार विधायक होंगे, दो-चार मंत्रियों की बसें चलती हैं, उनको हाथ नहीं दिया जाता, जो गरीब आदमी की बसें चलती हैं वे वहीं सीज कर दी जाती हैं। यह दोहरी नीति क्यों है? (व्यवधान) नाम पूछ लो आप, मैं बताऊंगा क्या? सरकार से पूछें। (व्यवधान) मेरा काम नहीं है नाम बताने का।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, एक चीज और रह गई।

श्री सभापति: कृपया आप समाप्त करें। आपके दूसरे साथी नहीं बोल पाएंगे ऐसे तो। मैं तो आपके लिए ही बोल रहा हूं।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): घास मत काटो, दो मिनट बोलने दीजिए।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। श्री मेवारामजी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, 2010-11 का बजट हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने प्रस्तुत किया। यह आम गरीब, झोपड़ी वाले, किसान, मजदूर, महिलाओं, छात्र और सभी वर्गों के लिए एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिसकी मैं सराहना करता हूं। अभी चर्चा चल रही थी, हमारे प्रपितक्ष के नेता भी इस बजट की जोरदार आलोचना कर रहे थे, मैं कहना चाहूंगा कि कौनसा क्षेत्र इसमें छोड़ा गया है? चाहे आप बिजली ले, सड़क लें, चिकित्सा लें, आम गरीब आदमी को लें, इसमें जितने भी आप मुद्दे देखेंगे, सभी के लिए बहुत अच्छा प्रबंधन इसमें किया है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्रीजी के दिल में गरीब के प्रति कितनी दया का भाव है कि उन्होंने गरीब, झोंपड़ी में रहने वाले बीपीएल परिवार के लिए दो रुपये किलो गेंहू करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। कोई मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा भी कर सकते हैं, इतना बड़ा कार्य हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने किया। इसके साथ-साथ विधवाओं, विकलांग, असहाय, एड्स पीड़ित एवं जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, बी.पी.एल. में जो चयनित परिवार हैं, स्टेट बी.पी.एल. में जो चयनित हैं, उनके लिये पेंशन और मुफ्त दवाई-इलाज के लिये करोड़ों रुपये का प्रबन्धन किया गया है, यह एक बहुत ही बढ़िया मुख्य मंत्रीजी ने गरीब के लिये, असहाय के लिये बजट प्रस्तुत किया है। मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप देखेंगे, आम आदमी के लिये क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा।

बिजली की बात करें, बिजली के अन्दर हमारे इस सवा साल के कार्यकाल में आप देखेंगे कि कितनी बिजली की व्यवस्था ठीक की गई है। जो पहले बजट था उससे 52 प्रतिशत अधिक बजट इस वर्ष करके बिजली में किस प्रकार हम आत्मनिर्भर बनें, इसका प्रयास किया गया है। आज बिजली की बात कर रहे थे, 4-5 घण्टे की भी बात कर रहे थे, मैं कहना चाहूंगा कि बाड़मेर बार्डर एरिया है उसमें आप लाइट की व्यवस्था कहीं से चैक करा लीजिये, 8 घण्टे से कम वहां लाइट नहीं मिलती है, बराबर 8 घण्टे लाइट किसानों को मिलती है, यह मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ आज सड़कों की बात करें, सड़कों के लिये करोड़ों रुपये की व्यवस्था इस बजट के अन्दर की गई है। हमारे भाई कह रहे थे कि

(श्री मेवाराम जैन)

यह तो केन्द्र का है, यह उधर का है। मैं कहना चाहूंगा, इससे पहले प्रधान मंत्री सड़क योजना चालू थी जिसमें ढाई सौ तक की ढाणियां, हैबिटेशन जो थी उन तक को जोड़ना था, परन्तु पिछली सरकार ने सिर्फ ढाई सौ आबादी के गांवों को ही जोड़ा, ढाणियों को और जो ढाई सौ के समूह थे, उनको छोड़ा गया। हमारी सरकार के आते ही मंत्रीजी ने यह देखा कि पहले जानबूझकर इसको सरकार ने छोड़ा है, तो उन ढाणियों को जोड़ने के लिये यहां से प्रपोजल भेजा और वो सब ढाणियां जोड़ने का इस बजट के अन्दर प्रावधान किया गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं कहना चाहूंगा, आज सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की, हमको और आप सबको देखना पड़ेगा कि इस पेयजल की समस्या से किस तरह से निपटा जाए। यह एक चुनौती है। बाड़मेर में पानी की भंयकर समस्या है, अभी यहां कोई फ्लोराइड की बात कर रहे थे, कोई कह रहे थे कि हमारे मीठा पानी नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में इतनी पानी की भयंकर समस्या है कि वहां शहर एक लाख की आबादी का है उसमें भी सात दिन के अन्दर सिर्फ दो घण्टा है। और गांवों के अन्दर तो कई ऐसे गांव हैं जहां एक-एक साल पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सौ-सौ होदियां वहां खाली पड़ी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भवनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट कैनाल स्कीम बनायी 539 गांव, बाड़मेर शहर, जिसमें जैसलमेर के गांव, शिव के गांव, बायतू के गांव, रासमर के गांव और बाड़मेर तहसील के गांव और इसके साथ-साथ डिफेंस, मिलिट्री, बी.एस.एफ. के नौजवानों को पानी पहुंचाने के लिये। आज से सात साल पहले उसका शिलान्यास किया गया था परन्तु 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब उस स्कीम को ठण्डे बस्ते में डाला गया। हमारी सरकार आई, आते ही उस स्कीम को चालू किया। काम शुरू करवाया गया और आज 500 करोड़ रुपये का काम हो चुका है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया आप समाप्त करें। कृपया सहयोग करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, हमारे वहां की समस्या है पानी की, उसके लिये मैं निवेदन करुंगा, मुझे आप समय दें। पानी की इतनी समस्या है, उसका समाधान हम कैसे करें, इसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्कीम को आप ज्यादा से ज्यादा

(श्री मेवाराम जैन)

बजट देकर जल्दी इसको पूरा करावें। इसके साथ-साथ आप चिकित्सा क्षेत्र में देखिये, किस तरह से ए.एन.एम. के पैसे बढ़ाये, किस तरह सब सेण्टर खोले, किस तरह सब सेण्टर के भवन बनाने के लिये बजट में प्रावधान रखा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं अब कहना चाहूंगा, बाड़मेर में रिफाइनरी के लिये हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कोशिश की और बाड़मेर में रिफाइनरी खोलने के प्रयास जारी हैं। मुख्य मंत्रीजी ने भाषण में भी कहा, इस बजट में भी बताया है कि रिफाइनरी बाड़मेर में खुलेगी। आज भी स्टेटमेंट आया था, मुरली देवड़ाजी, पैट्रोलियम मंत्री आ रहे हैं और हमारे मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, बाड़मेर में रिफाइनरी खोलेंगे। इस बजट के अन्दर इतनी सारी बातें हैं, मुझे बार-बार टोक रहे हैं, मैं सारी बातें कहना चाहता था, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बजट..

श्री सभापति: आप सहयोग करें, कृपया समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सभी वर्गों के लिये, सभी के लिये इस तरह का बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया है। मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आम गरीब किसान और सभी वर्गों के लिये इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया है, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: डा. विश्वनाथ।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण 2010-11 पर चर्चा की जा रही है, सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्य दो दिन से मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दे रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं सत्ता पक्ष के बहुत सारे सदस्य भी निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों में जो जीत हासिल की है, उस उपलब्धि को गिना रहे हैं। पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनावों में जो जीत हासिल की है उसके उपरान्त जो जनता को तोहफा दिया है माननीय सदस्यों ने, वह महंगाई और बेरोजगारों को बेरोजगारी है। माननीय सभापति महोदय, इस संवेदनशील सरकार ने महंगाई पर कल जो वक्तव्य दिया है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न करें।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): इससे जाहिर होता है, यह प्रतीत होता है कि यह सरकार संवेदनशील सरकार नहीं, संवेदनहीन सरकार है। कल जो वक्तव्य दिया उसमें सिर्फ गेहूं की बात कही गई है कि गेहूं में हमने दो रुपये किलो कर दिया है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि यह महंगाई क्या गेहूं के आसपास ही घूम रही है? माननीय सभापति महोदय, जैसे चीनी के भाव बढ़े हैं, जैसे दाल के भाव बढ़े हैं, आम चीजों के भाव बढ़े हैं, पैट्रोल-डीजल के भाव बढ़े हैं, इसमें सरकार ने कोई अपनी तरफ से वक्तव्य नहीं दिया जो एक संवेदनहीनता का परिचय है। माननीय सभापति महोदय, नरेगा की बात करते हैं, नरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है, एक गरीब को और गरीब बनाने की नीति इन्होंने की है। कांग्रेस की 50 साल की जो यह नीति बनी हुई है कि गरीब को और गरीब बनाया जाए, उसके लिए नरेगा जैसी योजना चालू कर दी। जिस आदमी की कैपेसिटी दिन के 500 रुपये कमाने की है, उसको सौ दिन के रोजगार के नाम पर सिर्फ 20-30 रुपये दिहाड़ी देकर एक पैरासाइट और परजीवी की तरह तैयार कर दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, यह कांग्रेस सरकार एक गरीब को और गरीब बनाना चाहती है। मैं इन पर आरोप लगाता हूं कि इसमें ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें, पिछले बजट में इन्होंने घोषणा की, 90 हजार कनेक्शन देने का इन्होंने जो वादा किया इसके एवज में इन्होंने 64 हजार कनेक्शन दिये। मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं, एक साल से कृषि कनेक्शन और घरेलू कनेक्शन के जो डिमाण्ड नोटिस भरे जा चुके हैं, आज तक इस सरकार ने कोई कनेक्शन नहीं दिया है? सभापति महोदय, जो ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धति को इन्होंने प्राथमिकता दी है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज तक आपके पास कितने आवेदन आये और कितनों को आपने कनेक्शन दिया? इस ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम में इन्होंने 80 हजार रुपये एक ट्रांसफार्मर पर चार्ज किया और 10 हजार रुपये प्रति पोल के हिसाब से। इस प्रकार एक किसान को करीब डेढ़-दो लाख रुपये का नुकसान हुआ। दो रुपये 10 पैसे जो प्रति यूनिट चार्ज किया, एक किसान को कनेक्शन देना नहीं है इनको, ये किसान के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां पर डिग्गियां, डग वैल के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि 5 और 10 एच.पी. का कनेक्शन किसान को मांगते ही तुरन्त दिया जाए। ऐसे क्षेत्र के लिए जहां

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

आज सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है, किसान को प्राथमिकता के आधार पर यह कनेक्शन दिया जाए, यह मैं सरकार से मांग करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप कृपया समाप्त करें।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, सरकार ने बात कही है कि पांच साल तक बिजली के भाव नहीं बढ़ाये जाएंगे, दूसरी तरफ सरकार 100 से अधिक यूनिट आने पर 10 पैसे प्रति यूनिट जो चार्ज कर रही है, यह सरकार सबके साथ खिलवाड़ कर रही है। किसानों को आठ घंटे हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने, माननीय वसुन्धराजी ने बिजली दी, आज यह सरकार चार से छह घंटे पर आ गयी है। वह भी ट्रिप सिस्टम से किसानों को बिजली दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र में बिजली की बात करता हूं, आज देश को आजाद हुए 63 साल हो गये हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में पंचायत हैडक्वार्टर पर भी बिजली के बिना लोग बैठे हैं। आज पंचायत हैडक्वार्टर पर भी बिजली नहीं है, यह एक शर्म की बात है। माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन, सिंचाई की बात करता हूं, पिछले बजट में इन्होंने कहा कि एक लाख हैक्टेयर को सिंचाई योग्य बनाया जाएगा और इस बजट में भी इन्होंने कहा कि 35500 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र विकसित किया जाएगा। मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूं कि पहले से जो आबाद सिंचित क्षेत्र है वह उजड़ रहा है, सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है? वहां पर बिलकुल ही पानी नहीं मिल रहा है। पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि और ज्यादा हैक्टेयर सिंचित ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ...(व्यवधान) करने का क्या औचित्य है? सरकार ने बजट में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पंजाब क्षेत्र की मरम्मत के लिए 952 करोड़ रुपये दिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि अनूपगढ़ और पूगल ब्रांच भी बहुत क्षतिग्रस्त हैं, उनके लिए भी अलग से बजट में प्रावधान किया जाए।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): जल वितरण प्रणाली को सही किया जाए, पानी की चोरी को रोका जाए और अन्तिम छोर पर बैठे किसानों को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब अंकित नहीं हो रहा है। कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें। मैंने काफी वक्त दे दिया है आपको। ....(व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री सभापति: श्री पदमाराम, जो आपका शेष बचा है, आप दो मिनट में पूरा करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में रहने वाले किसान, गरीब, मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उद्योगपति, व्यापारी सभी के चहुंमुखी विकास के लिए प्रावधान किया है। उनके विकास के लिए जो योजनाएं बनायी हैं, जो नीतियां बनायी हैं, वे सराहनीय हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ऊर्जा के विकास के लिए जो योजना बनायी है, उसके लिए जो प्रावधान किया है, वह सराहनीय है। उन्होंने इस योजना का 52 प्रतिशत विद्युत के अन्दर खर्च किया है और यह सिद्ध किया है कि एक किसान जो गरीब झोंपड़ी में रहने वाला है वह अपना कृषि कनेक्शन लेकर अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकेगा। राजस्थान के जो अमीर लोग विराजे हैं, वे अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति उसी से कर सकते हैं। उन्होंने राजस्थान के रहने वाले किसानों को 64 हजार कनेक्शन दस साल में दिये और 65 हजार कनेक्शन देने का जो प्रावधान किया है वह बहुत सराहनीय है। गांव के अन्दर, गली के अन्दर, ढाणी के अन्दर जो रहने वाले किसान हैं, गरीब हैं, जो दूर-दूर ढाणियों में बसते हैं, उनके उजाले के लिए 20 हजार सोलर ऊर्जा की व्यवस्था की है, वह धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने किसानों की सिंचाई योजना को मजबूत बनाने के लिए 7700 से अधिक करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, उसके अन्दर बाड़मेर लिफ्ट कैनाल, मोहनगढ़, कवास, समदड़ी और मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर नर्मदा नहर परियोजना के लिए जो प्रावधान किया है, वह धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री सभापति: अब कृपया समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): नर्मदा नहर के अन्दर हमारे क्षेत्र के पचास गांव छूट गये हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से और सिंचाई मंत्री महोदय से मैंने कई बार निवेदन किया है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन पचास गांवों को जोड़ा जाए। शिक्षा के विषय में हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने जो व्यवस्था की है, विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा हमेशा यह आवाज उठायी जाती है कि शिक्षा का स्तर गिर गया, स्कूलें खाली हो गयी हैं। स्कूलें वे खाली कहां से हुई? स्कूलों के अन्दर हमने तो एक मास्टर का ट्रांसफर नहीं किया। आपने पांच साल के अन्दर एक लाख लोगों को नियुक्तियां दीं, जवानों को जो नियुक्तियां दीं, वे लोग कहां गये? वे घर जाकर बैठ गये क्या?

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने कहा कि गांव के अन्दर 200 बच्चों के अन्दर एक मास्टर है और सिटी के अन्दर 8 बच्चों के अन्दर, 10 बच्चों के अन्दर 8 मास्टर हैं, यह व्यवस्था आपने ही बिगाड़ी है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने समानीकरण योजना लागू की परन्तु उन पर परीक्षा का बोझ आ गया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। मैंने आपको मौका दिया है।

श्री पदमाराम (चौहटन): पांच-छह महीने के अन्दर यह हम आपको सिद्ध करके बताएंगे, समानीकरण योजना लागू करेंगे और ट्रांसफर करेंगे।

श्री सभापति: मेरा निवेदन है आपसे, कृपया समाप्त करें। श्रीमती चन्द्रकान्ता।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। आप बैठिये। अंकित नहीं हो।

श्री पदमाराम (चौहटन): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। कृपया विराजिये आप।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): 2010-2011 के बजट भाषण पर माननीय सभापति महोदय ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरा निवेदन है कि मुझे बैठने के लिए नहीं कहा जाए क्योंकि सबसे लास्ट में मेरा नम्बर आया है।

श्री सभापति: और अगर एक और हो तो?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): भारत एक कृषि प्रधान देश है और महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। इस बजट भाषण को मैंने सुना और पढ़ा भी सही, लेकिन इसको पढ़कर मुझे नहीं लगता कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। जो कुछ मैंने इसमें पढ़ा, उसके आधार पर मैं इस बजट भाषण का निचोड़ कुछ पंक्तियों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी।

हाल डेढ़ साल का, कांग्रेस के शासनकाल का।

रामभरोसे से कानून-व्यवस्था।

बढ़ते रहे बेकार हाथ, सरकार ने नहीं दिया साथ।

बर्बाद हुआ अन्नदाता, सरकार ने तोड़ा नाता।

राज्य में अंधकार का बोलबाला।

जनता की बत्ती गुल, पानी बिना सब सून।

पीड़ित रही नारी, कौन सुध ले हमारी।

कमजोर हुए और कमजोर, उस पर अत्याचार का जोर।

बंद हुए कारखाने, मजदूरों की राम जाने।

केन्द्रीय सहायता के दुरुपयोग में अव्वल।

इस कांग्रेस सरकार से न्यायालय चिन्तित।

बीमार हुई स्वास्थ्य व्यवस्था। कौन सुने बीमारों की व्यथा।

भ्रष्टाचार ने किया कमाल, मंत्री हुए मालामाल।

चाहे जनता रहे बेहाल।

वास्तव में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कुछ अच्छा किया, उसके लिये तो तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूंगी, लेकिन जो कुछ उनको करना चाहिये था, वह नहीं कर पाये, उसके लिये जो मेरे मन में पीड़ा है, उसे भी मैं व्यक्त करना चाहूंगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पृष्ठ नम्बर 6 पर पैरा संख्या 14 में एक बात लिखी कि थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ की छठी इकाई, कोटा की सातवीं इकाई एवं छबड़ा की पहली इकाई से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। लेकिन मेरा निवेदन है और मैं यह कहूंगी कि यह देन वसुन्धरा राजेजी की है। यह वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर इसके लिये आप यह बोल दें कि यह हमारी देन है तो यह बिलकुल गलत है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति: माननीय सदस्या, विराजिये। क्योंकि दोनों ही दलों के सचेतक महोदय यहां नहीं हैं तो मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करता हूं कि जो वर्तमान वक्ता बोल रही हैं, उनके लिये पांच मिनट सदन का समय बढ़ाया जाता है। मेरे खयाल से आप सब लोगों की सहमति है।

(स्वीकृत)

सदन का समय पांच मिनट के लिये बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगी। सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि बिजली की हालत में सुधार हुआ है, ऊर्जा उत्पादकता बढ़ी है। लेकिन मैं कहती हूं कि नगर निगम के क्षेत्र में आज भी यह हालत है कि लगातार 13 महीने से वहां पर पांच घण्टे की, छह घण्टे की बिजली कटौती डेली हो रही है। मेरे भाइयों, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो कल ही मेरे साथ कोटा में चलें और आवली रोजड़ी, नगर निगम की जो कालोनी है, उसको आप देख सकते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप अपनी बात कहें। सदन का टाइम पांच मिनट बढ़ा है, उसके बाद तो कुछ अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): और तो और, दो वर्ष पूर्व जो ट्रांसफार्मर चोरी हुआ था सूपड़ा पंचायत में, वह दो वर्ष बाद भी आज तक चेंज नहीं हुआ, यह हमारा दुर्भाग्य है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगी कि जल संसाधन के अन्तर्गत चालू योजनाओं को समय पर पूरा किया जाएगा, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा। लेकिन तापली बांध जो 175 करोड़ रुपये की योजना थी और 19-7-2006 को जिसका काम चालू हुआ और जिसको 2010 में पूरा होना था, मुझे बताते हुए दु:ख हो रहा है कि 17.1.2009 से उसका कार्य बंद पड़ा है। मैंने तीन बार लगातार उसका कार्य शुरू करवाया। अभी कुछ दिन से उसका कार्य शुरू हुआ है, लेकिन आज भी वहां के किसानों के मन में पीड़ा है कि न तो उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गयी है और न ही उनको कोई मुआवजा दिया गया। हर चीज की रेट बढ़ चुकी है, जो 175 करोड़ रुपये

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

इस योजना के लिये पास हुए थे, मेरा मानना है कि 175 करोड़ में आज के समय में यह योजना पूरी नहीं हो सकती। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहती हूं कि वह कुछ पैसा इस योजना के लिये बढ़ाएं ताकि किसानों को फायदा हो। हमने सुना कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम राज्य में कई वर्षों से जल नीति लम्बित है, उसको तैयार कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत काटी गयी 508 करोड़ रुपये की राशि राज्य को पुन: जारी करने का निर्णय लिया गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें अगले तीस सैकण्ड में।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे बोरा बास पदमपुरा योजना है, अखेलगढ़ योजना है, उस योजना को क्यों नहीं पैसा दिया गया? आज भी उस क्षेत्र में यह स्थिति है कि फरवरी के महीने से वहां टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। भविष्य की आवश्यकताओं को लेकर 150 करोड़ रुपये की पेयजल की जो योजना तैयार की गयी, उन योजनाओं से हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा, लेकिन मेरा एक निवेदन है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें। अब समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैंने कहा था, इससे अच्छा तो मुझे बोलने का मौका नहीं देते। नहीं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते आप तो ठीक रहता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दो मिनट और।

श्री सभापति: सदन की सहमति पांच मिनट की ली गयी थी। नहीं, सचेतक महोदय।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 12.3.2010 प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.36 बजे शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2010 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

सिरोही जिले के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

91. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्व ग्राम कितनी आबादी पर घोषित किया जाता है?

(2) जिला सिरोही में जनगणना 2001 के अनुसार 250 की जनसंख्या से अधिक कितने गांव, ढाणियां व गोलुआ हैं, को कब तक राजस्व गांव घोषित कर दिया जावेगा?

(3) सरकार द्वारा जिला सिरोही में उपरोक्त क्षेत्रों को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए कब व क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा अब तक इन्हें राजस्व ग्राम घोषित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में सामान्य क्षेत्र में 250 की आबादी पर एवं रेगिस्तानी व अनु. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 200 की आबादी पर ग्राम/ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि संबंधित मजरा या ढाणी मूल राजस्व ग्राम से 1 किमी की दूरी पर स्थित हो तथा नया राजस्व ग्राम बनाने के बाद मूल राजस्व ग्राम की आबादी सामान्य क्षेत्र में 250 तथा रेगिस्तानी व अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 200 से कम नहीं रह जावे।

(2) जिला सिरोही में जनगणना 2001 के अनुसार 250 की जनसंख्या से अधिक के किसी भी गांव, ढाणी व गोलुआ को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना शेष नहीं है।

(3) जनगणना 2001 के आधार पर सिरोही जिले में अब तक 21 नये राजस्व ग्राम घोषित किये जा चुके हैं। अब ऐसी कोई ढाणी, मजरा या गोलुआ शेष नहीं है जो कि भाग-1 में यथा वर्णित शर्तों को पूरा करता हो। अतः वर्तमान में सिरोही जिले के किसी भी ढाणी, मजरा व गोलुआ को राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव नहीं है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके

तारांकित प्रश्नोत्तर

नदबई विधान सभा क्षेत्र के भवनराहित पशु चिकित्सा उप केन्द्र

93. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' (नदबई) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत चार वर्षों में जिला भरतपुर में कुल कितने पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नदबई में कितने पशु चिकित्सा उप केन्द्र बिना भवन के संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त भवनरहित पशु उप केंन्दों के लिए भवन निर्माण हेतु राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में जिला भरतपुर में कोई नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र नहीं खोला गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नदबई में 9 पशु चिकित्सा उप केन्द्र क्रमशः सुखवली, शाहपुर, डहरा, खेरिया ब्राह्मण, रोनीजा, झारोली, मई गूजर, सिनपिनी व जहांगीरपुर के लिए राजकीय भवन उपलब्ध नहीं हैं।

(3) जी नहीं। नवसृजित उप केन्द्रों के उपयोग हेतु राजकीय भवन की अनुपलब्धता की स्थिति में भवन की नि:शुल्क सुविधा स्थानीय निकाय संस्थाओं/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा/स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाना होता है।

स्थगित प्रश्न

(शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2010)

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में हरित राजस्थान योजनांतर्गत वृक्षारोपण

58. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में हरित राजस्थान के तहत किस-किस जिले में कहां-कहां वृक्षारोपण कार्य चलाया गया और कितने पौधारोपण किये गये व उक्त पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कौन-कौन से ग्रामों में वृक्षारोपण किया गया और उनमें कितने पौधे लगाये गये तथा उक्त पर कुल कितना व्यय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2010 तक वृक्षारोपण किये गये पेड़ों में से कितने पेड़ सुरक्षित पाये गये एवं कितने नष्ट हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा हरित राजस्थान के तहत किये गये वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु किसी को जिम्मेदारी दी गई? यदि हां, तो किसको नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में हरित राजस्थान के तहत जिलेवार करवाये गये वृक्षारोपण की सूचना परिशिष्ट ''अ'' पर है। राज्य में दो करोड़ उनसठ लाख सत्रह हजार एक सौ पच्चीस पौधारोपण मय बीजारोपण किया गया था, इस पर एक सौ चार करोड़ सत्ताईस लाख तेरह हजार रुपये व्यय किये गये ।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सात ग्रामों में वृक्षोरोपण कर कुल छब्बीस हजार दो सौ सत्तर पौधे लगाये गये जिस पर तियालीस लाख बासठ हजार रुपये व्यय किया गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जनवरी 2010 तक छब्बीस हजार दो सौ सत्तर पौधे लगाये गये, इनमें से कुल सतरह हजार दो सौ बीस पेड़ सुरक्षित पाये गये एवं नौ हजार पचास पेड़ वर्षा के अभाव में पनप नहीं पाये ।

(4) राज्य में हरित राजस्थान के तहत किये गये वृक्षारोपण की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित कार्यकारी संस्थाओं को प्रदान की गई है।

परिशिष्ट-अ

कितने पौधारोपण किये गये? कितना व्यय हुआ? कितने पौधे जीवित हैं और कितने नष्ट हो गए।

क्र.सं.	जिले का नाम	लगाये गये पौधे	व्यय की गयी राशि	कितने पौधे जीवित हैं	कितने पौधे नष्ट हो गए	योग (5+6)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अजमेर	1353885	381.38	940606	413279	1353885	30 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव के कारण नष्ट हुए
2	अलवर	981929	20.13	751010	230919	981929	24 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव के कारण नष्ट हुए
3	बांसवाड़ा	2905450	116.53	1931252	974198	2905450	33 प्रतिशत पौधे प्रतिकूल जलवायु के कारण नष्ट हुए
4	बारां	1023901	111.84				जीवितता का मूल्यांकन करवाया जाना है।
5	बाड़मेर	97313	239.31	73901	23412	97313	24 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव के कारण नष्ट हुए
6	भरतपुर	890932	241.07	637785	253147	890932	24 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव एवं दीमक के कारण नष्ट हुए
7	भीलवाड़ा	812471	403.05	546730	265741	812471	33 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव के कारण नष्ट हुए
8	बीकानेर	158230	89.81	105253	52977	158230	24 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव एवं नहरी पानी के अभाव के कारण नष्ट हुए
9	बून्दी	375293	208.14				मूल्यांकन किया जाना है।

1	2	3	4	5	6	7	8
10	चित्तौड़गढ़	1076885	1280.12	833076	243759	1076835	23 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव के कारण नष्ट हुए
11	चूरू	349411	210.82	284893	64518	349411	19 प्रतिशत पौधे प्रतिकूल जलवायु के कारण नष्ट हुए
12	दौसा	416087	173.71				मूल्यांकन किया जाना है
13	धौलपुर	526616	308.63	374846	151770	526616	29 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव एवं दीमक के कारण नष्ट हुए
14	डूंगरपुर	1806534	298.03	1319519	487015	1806534	27 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव के कारण नष्ट हुए
15	गंगानगर	1332000	104.28				मूल्यांकन नहीं किया
16	हनुमानगढ़	506809	123.83	368997	62406	431403	वन विभाग द्वारा मूल्यांकन नहीं
17	जयपुर	318260	211.91	270228	48032	318260	15 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव एवं दीमक के कारण नष्ट हुए
18	जैसलमेर	448309	163.85	386398	61911	448309	14 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव के कारण नष्ट हुए
19	जालौर	313959	284.33	214117	99842	313959	32 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव के कारण नष्ट हुए
20	झालावाड़	115080	162.91				उप वन संरक्षक, आयोजना द्वारा मूल्यांकन प्रगतिरत है
21	झुन्झुनूं	872555	442.95				मूल्यांकन नहीं किया
22	जोधपुर	735000	408.9				पौधों का सर्वे किया जा रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8
23	करौली	530000	99.58	249106	280894	530000	53 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव के कारण नष्ट हुए
24	कोटा	76567	112.2	49329	27238	76567	36 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव के कारण नष्ट हुए
25	नागौर	821749	751.5	754889	66860	821749	8 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव एवं दीमक के कारण नष्ट हुए
26	पाली	1598182	720.68	1160196	437986	1598182	28 प्रतिशत पौधे नष्ट
27	प्रतापगढ़	149404	187.38	106360	43044	149404	29 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव के कारण नष्ट हुए
28	राजसमन्द	1032086	241.51	671991	360095	1032086	35 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव के कारण नष्ट हुए
29	सवाईमाधोपुर	78932	90.74	55798	23134	78932	29 प्रतिशत पौधे नष्ट
30	सीकर	795089	530.53	650466	144623	795089	18.50 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव एवं दीमक के कारण नष्ट हुए
31	सिरोही	370197	160.68	327732	42465	370197	11.50 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव के कारण नष्ट हुए
32	टोंक	243070	495.19	113270	129800	243070	54 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव के कारण नष्ट हुए
33	उदयपुर	2805000	1051.61	1746000	1059000	2805000	38 प्रतिशत पौधे वर्षा के अभाव के कारण नष्ट हुए
		25917185	10427.13	14923748	6048065	20971813	

परिशिष्ट-ब

क्र.सं.	कार्यकारी एजेन्सी का नाम	वृक्षारोपण की जगह	लगाये गये पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	नष्ट पौधों की संख्या	व्यय राशि लाखों में
1	ग्राम पंचायत ढाणी बोराज	ढाणी बोराज	12000	6500	5500	12.72
2	ग्राम पंचायत श्री रामपुरा	श्री रामपुरा	8000	5000	3000	19.95
3	जल संसाधन विभाग	नरेना रेस्ट चौकी	70	70	0	0.15
4	उपवन संरक्षक, जयपुर दक्षिण	भोजपुरा रोड साइड	200	200	0	
5	उपवन संरक्षक, जयपुर दक्षिण	भादवा भैंसलाना	2000	1780	220	10.80
6	उपवन संरक्षक, जयपुर दक्षिण	कांचरोदा	2000	1915	85	
7	उपवन संरक्षक, जयपुर दक्षिण	डूंगरीकलां	2000	1755	245	
			26270	**17220**	**9050**	**43.62**

अनुपुरक सूचना

हरित राजस्थान कार्यक्रम के तहत विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कुल सात ग्रामों में 26270 पौधे लगाये गये । तथा सभी गांवों में पौधारोपण हेतु पिट्स खुदाई का कार्य पूर्ण करवा लिया था तथा कुछ स्थानों पर वर्षा ऋतु निकल जाने से पौधारोपण नहीं हो पाया था। इसी वजह से पौधोरोपण का कार्य करवा लिया जावेगा। जिले में कुल रोपित पौधे 3,18,260 में से 2,70,228 पौधे ही पनप पायें। शेष पौधों में दीमक लगना, प्राकृतिक स्थिति एवं जिले में बहुत कम वर्षो होने के कारण पौधे पनप नहीं पाये। अत: नष्ट होने वाले पौधों के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है तथा किसी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई है।

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं

मुख्य कारी अधिकारी, जयपुर

राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत रहे अपूर्ण कार्य

94. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारण्टी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कितने कार्य कहां-कहां पर नियोजित रूप से चल रहे है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में गत दो वर्षों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत कराये गये कार्यों में कई कार्य अपूर्ण हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कौन-कौन से कार्य ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपूर्ण कार्यों को अब पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में 161 कार्य प्रगति पर चल रहे हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। योजना अन्तर्गत दो वर्षों में 29 कार्य अपूर्ण हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है ।

(3) जी हां। अपूर्ण कार्य इसी वित्तीय वर्ष पूर्ण करा लिये जायेंगे।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर जिले में घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु लम्बित आवेदन

95. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2005 में घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन दे दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या जिन उपभोक्ताओं द्वारा डिमाण्ड राशि जमा करवा दी गई है, को मौके पर कनेक्शन दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) जिला बाड़मेर में कितने उपभोक्ताओं को डिमाण्ड राशि जमा करवाने के उपरान्त भी कनेक्शन नहीं दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्काम के अन्तर्गत सभी जिलों में वर्ष 2005 में घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं में से जिन आवेदकों ने मांगपत्र राशि जमा करा दी थी एवं एल-फार्म दे दिये थे (विवादास्पद के अतिरिक्त) उन्हें कनेक्शन दे दिये गये हैं। जयपुर डिस्काम के अन्तर्गत 57 आवेदक ऐसे हैं, जिन्हें कनेक्शन नहीं दिये जा सके जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. दौसा जिले के उपखण्ड ए-द्वितीय, हिण्डौन के अन्तर्गत 5 घरेलू कनेक्शन साइट पर विवाद होने के कारण लम्बित हैं।
2. अलवर जिले के नीमराना पंचायत समिति में 11 आवेदकों के कनेक्शन लाइन खींचने के विवाद के कारण लम्बित हैं तथा मुण्डावर पंचायत समिति में 41 आवेदकों के कनेक्शन लम्बित हैं, जिनमें से 3 आवेदकों पर पूर्व की राशि बकाया है तथा 38 आवेदक गैर आबाद क्षेत्र में 500 मीटर से अधिक की दूरी पर हैं जिन्हें नोटिस दे दिये गये हैं। क्योंकि निगम के प्रचलित नियम के अनुसार उन्हें वर्तमान में कनेक्शन नहीं दिये जा सकते।

(2) बाड़मेर जिले में माह जनवरी 2010 तक घरेलू श्रेणी में 7414 आवेदकों के मांगपत्र की राशि जमा है। जिन्हें विद्युत सम्बन्ध प्रदान किये जा रहे हैं उनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

मार्च-2007	22
मार्च-2008	317

(ऊर्जा मंत्री)

मार्च-2009	2075
जनवरी-2010	5000
कुल	**7414**

(3) उपरोक्त लम्बित आवेदकों को साइट पर/लाइन खीचने का विवाद व पूर्व राशि जमा नहीं कराने का विवाद समाप्त होने पर प्राथमिकता से कनेक्शन दिये जायेंगे। गैर आबादी क्षेत्र में 500 मीटर से अधिक दूर लम्बित कनेक्शन देना नीतिगत होने के कारण वर्तमान में कनेक्शन जारी नहीं किये जा सकेंगे।

जिला बाड़मेर में उपरोक्त सभी लम्बित आवेदकों को माह मार्च 2011 तक विद्युत सम्बन्ध प्रदान करना प्रस्तावित है।

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. के रिक्त पद

96. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में किस-किस ग्राम पंचायत में कितने उप-स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं तथा उनमें ए.एन.एम. के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु नई नियुक्तियां करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2009-10 में ए.एन.एम. को नई नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो कितने पदों पर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायत एवं उनके अधीन आने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम तथा उनमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। दिनांक 05.05.2010 को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के निर्धारित साक्षात्कार उपरान्त इन रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) जी हां। वित्तीय वर्ष 2009-10 में एनआरएचएम/आयोजना मद के अन्तर्गत 2853 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (संविदा) को नियुक्ति प्रदान की गई हैं।

परिशिष्ट-अ

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों एवं उनके अधीन आने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम तथा उनमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है

ग्राम पंचायत का नाम	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	
		स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
चैनपुरा	चैनपुरा	1	-
	पिथ्यावास	1	-
श्रीरामपुरा	श्रीरामपुरा	1	-
बारदोती	श्याम की ढाणी	1	-
कौरसीना	कौरसीना	1	-
आकोदा	आकोदा	1	-
शार्दुलपुरा	शार्दुलपुरा	1	-
काचरोदा	काचरोदा	1	-
रोजडी	रोजडी	1	-
सुरसिंहपुरा	माल्यावास	1	-
हिरनोदा	हिरनोदा (उच्चीकृत)	1	-
हवसपुरा	हवसपुरा	1	1
	हचूकडा	1	-
अणतपुरा	अणतपुरा	1	-
बासड़ीखुर्द	बासड़ीखुर्द	1	-
	नाथी का बास	1	-
भादवा	भादवा (उच्चीकृत)	1	-
डूंगरी खुर्द	डूंगरी खुर्द	1	-
डयोडी	डयोड़ी	1	-

ग्राम पंचायत का नाम	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	
		स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
हरसोली	हरसोली	1	-
इटावा	इटावा	1	-
जयसिंहपुरा	जैतपुरा	1	-
काजीपुरा	काजीपुरा	1	-
खण्डेल	खण्डेल	1	-
खेडीमलिक	खेडीमलिक	1	-
लालासर	लालासर	1	-
	जुनसिया	1	-
लूनियावास	लूनियावास	1	-
मिलकपुर	मिलकपुर	1	-
मूण्डियागढ़	मूण्डियागढ़	1	-
मूण्डवाडा	मूण्डवाडा	1	-
नान्दरी	नान्दरी (उच्चीकृत)	1	1
नवरंगपुरा	नवरंगपुरा	1	-
पचकोडिया	पचकोडिया	1	-
रलावता	रलावता	1	-
रामजीपुरा	रामजीपुरा	1	-
सिनोदिया	सिनोदिया	1	-
तैज्याकाबास	तैज्याकाबास	1	-
त्योदा	त्योदा	1	-
आइदान का	आइदान का बास	1	-
डूंगरसी का	डूंगरसी का बास	1	-

स्थगित प्रश्न

(शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2010)

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में हरित राजस्थान योजनान्तर्गत वृक्षारोपण

61. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष के दौरान विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में हरित राजस्थान कार्यक्रम के दौरान पेड़-पौधे लगाने का कार्य किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां और कितने पेड़-पौधे लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पेड़-पौधे सिवायचक भूमि पर भी लगाये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ लोगों ने सिवायचक भूमि पर कब्जा कर अपनी फसल बो दी जिससे सारे पेड़-पौधे नष्ट हो गये? यदि हां, तो नष्ट पेड़-पौधों की संख्या एवं नुकसान की राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा धौलपुर जिले में पेड़-पौधों को जिन्दा रखने के लिए कोई विशिष्ट योजना बनाई गई? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में गत एक वर्ष के दौरान महानरेगा योजनान्तर्गत सरकारी भूमि सड़क, चरागाह विकास, तालाब पौखर एवं नहर के किनारे कुल 79893 पौधे लगाये गये इनमें से सरकारी भूमि पर 1650, सड़कों के सहारे 3660, चरागाह विकास में 22455, तालाब एवं पौखर के किनारे 13138, नहर के किनारे 4190 पौधे एवं वन विभाग द्वारा 34800 पौधे लगाये गये तथा 3480 बीजारोपण द्वारा तैयार पौधे वन भूमि पर वन विभाग द्वारा लगाये गये ।

(2) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में महानरेगा योजनान्तर्गत सिवायचक भूमि पर पौधे नहीं लगाये गये हैं। यद्यपि महानरेगा योजनान्तर्गत सरकारी भूमि सड़क, चरागाह विकास, जालाब पौखर एवं नहर के किनारे पौधे लगाये गये हैं। विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कराये गये कार्यों की सूची मय लगाये गये पौधों की संख्या परिशिष्ट-''अ'' पर अकिंत है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में महानरेगा योजनान्तर्गत सिवायचक भूमि पर कब्जा कर पेड़-पौधे नष्ट नहीं किये गये हैं। मगर यह सही है कि पंचायत समिति बसेड़ी की ग्राम पंचायत अतरसूमा के ग्राम नौनेरा में सिवायचक एवं चरागाह भूमि पर 4000 पौधे लगाये गये थे, जिनमें से 400 पौधे व्यक्ति विशेष श्री रूसी पुत्र श्री भूली, जाति कुशवाह, निवासी सलेमपुर द्वारा नष्ट कर दिये गये एवं उस स्थान पर चने की फसल बो दी गई, जिसकी विरुद्ध पुलिस में तत्काल ही एफआईआर दर्ज करा दी गई थी ।

(4) जी हां। पेड़-पौधों को जिन्दा रखने के लिये महानरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत तकमीने में रख-रखाव एवं देखरेख का प्रावधान लिया गया है।

परिशिष्ट -अ

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर धौलपुर

हरित राजस्थान महानरेगा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में लगाये गये पौधों की सूची का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	नाम ग्राम पंचायत	लगाये गये पौधों की संख्या
1	चरागाह विकास कार्य खसरा नं. 31 उमरारा	करीमपुर	1016
2	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	करीमपुर	800
3	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	करीमपुर	600
4	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	कोटरा	300
5	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	कोटरा	200
6	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	विश्नौदा	2000
7	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	विश्नौदा	1150
8	चरागाह विकास कार्य खसरा नं. 201 मोहल्लीकापुरा	पंचगाव	2500
9	चरागाह विकास कार्य खसरा नं. 387 मोहल्लीकापुरा	पंचगाव	2500

क्र. सं.	कार्य का नाम	नाम ग्राम पंचायत	लगाये गये पौधों की संख्या
10	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	पंचगाव	1125
11	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कर्यालाय	पंचगाव	1125
12	चरागाह विकास कार्य खसरा नं. 604/33 पथैना	पुरैनी	700
13	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	पुरैनी	200
14	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	पुरैनी	250
15	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	बसईसामन्ता	1000
16	पोखर/तालाब एवं चरागाह वृक्षारोपण कार्य सैयदवाला चांदपुर	बसईसामन्ता	15600
17	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	बसईसामन्ता	50
18	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	बसईनीम	30
19	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	बसईनीम	20
20	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	कोलारी	120
21	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	कोलारी	200
22	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	कोलुआ	200
23	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	कोलुआ	120
24	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	मालौनीखुर्द	200
25	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	मालौनीखुर्द	50
26	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	मूसलपुर	310
27	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	मूसलपुर	50
28	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	चितौरा	300
29	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	चितौरा	50
30	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	निधेराकलां	280

क्र. सं.	कार्य का नाम	नाम ग्राम पंचायत	लगाये गये पौधों की संख्या
31	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	निधेराकलां	50
32	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	पुरानी छावनी	1125
33	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	पुरानी छावनी	100
34	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	सरानीखेड़ा	175
35	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	सरानीखेड़ा	400
36	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	सरानीखेड़ा	300
37	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	सरानीखेड़ा	385
38	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	ओदी	200
39	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	ओदी	50
40	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	टहरी	300
41	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	टहरी	50
42	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	गढीचटोला	150
43	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	गढचटोला	50
44	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	तसीमों	480
45	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	तसीमों	250
46	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	तसीमों	250
47	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	मौरोली	300
48	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	मौरोली	50
49	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	दूवरा	300
50	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	दूवरा	50
51	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	सखवारा	400
52	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	सखवारा	72

क्र. सं.	कार्य का नाम	नाम ग्राम पंचायत	लगाये गये पौधों की संख्या
53	पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य	मानपुर	50
54	वृक्षारोपण कार्य सरकारी कार्यालय	मानपुर	0
55	वृक्षारोपण कार्य तालाब एवं नहरों के किनारे	सिंचाई विभाग	4190
56	1. पौधा रोपड़ कार्य रा.मा.वि. कासिमपुर-30, रा.प्रा.वि. कासिमपुर-10	कासिमपुर	20
57	2. तालाबों व पोखरों के सहारे वृक्षारोपण कार्य कासिमपुर		20
58	1. पौधा रोपड़ कार्य रा.मा.वि. भैंसेना-20, प्रा.वि. हथियारवार-20, चौरपुरा-20, घेर 20	भैंसेना	40
59	2. पोखर व तालाब के सहारे वृक्षारोपण कार्य भैंसेना		40
60	1. पौधा रोपड़ कार्य रा.उ.मा.वि. बरेहमोरी-50, उ.प्रा.वि. पथरोला खुर्द-30, सादिकपुर-30, प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र बरेहमासी-15	सादिकपुर	45
61	2. वृक्षारोपण कार्य सम्पर्क सड़क सादिकपुर से मिर्जापुर 0-2 किमी दोनों तरफ		560
62	3. पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य सादिकपुर		100
63	1. पौधा रोपड़ कार्य मा.वि. तगावती-50, रा.प्रा.वि. मसूदपुर-20, भैसांख-20, समौला-50	तगावली	40
64	2. पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य तगावली		100
65	3. वृक्षारोपण कार्य सम्पर्क सड़क धौलपुर राजाखेड़ा रोड से खरगपुर		900

क्र. सं.	कार्य का नाम	नाम ग्राम पंचायत	लगाये गये पौधों की संख्या
66	1. पौधारोपड़ कार्य रा.मा.वि. जाटौली-20, उ.प्रा.वि. बादरपुर-50	जाटौली	30
67	2. पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य जाटौली		40
68	1. पौधारोपड़ कार्य रा.मा.वि. महाराजपुर प्रा.वि. बहबलपुर-20, उ.प्रा.वि. लुहारी-10	लुहारी	20
69	2. पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य जाटौली		30
70	1. पौधारोपड़ कार्य रा.उ.मा.वि. सिंघावली बरेह-50, उ.प्रा.वि. फरागपुर-200, मलिकपुर	सिंघावली बरेह	200
71	2. पोखर व तालाबों के सहारे वृक्षारोपण कार्य सिंघावली बरेह		135
वन विभाग द्वारा रोपित पौधे			**45093**
1.	शाहबाजपुरा सागर 25 है., नरेगा	शाहबाजपुरा	7800
2..	गुन्नापुरा 50 है., नरेगा	गुन्नापुरा	4000
3..	काला पहाड 25 है., नरेगा	काला पहाड़	2800
4.	भिलगवां 40 है., नरेगा	भिलगवां	3000
5.	हथियाखार 50 है., नरेगा	हथियाखार	8800
6.	चम्बल ब्रिज 50 है., नरेगा	हथियाखार	8400
			34800
		महायोग	**79893**

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद धौलपुर

भीम तहसील के ग्राम नन्दावत की चरनोट एवं बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण

97. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) तहसील भीम के ग्राम नन्दावत में कुल कितनी बिलानाम सरकारी व चरनोट जमीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) बिलानाम सरकारी जमीन में से सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में किन-किन विभागों एवं संस्थाओं को भूमि आबंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में पशुओं के अनुपात में गोचर भूमि आबंटित है ? यदि हां, तो कितनी ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत की चरनोट एवं बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन द्वारा व कब?

(5) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर वस्तुस्थिति की जानकारी करके अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हेतु विधायक द्वारा मांग की गई थी? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार झूठे तथ्य पेश करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले के तहसील भीम के ग्राम नन्दावत में कुल बिलानाम सरकारी भूमि 1169.05 बीघा एवं चरनोट भूमि 554 बीघा है।

(2) विगत पांच वर्षो में ग्राम नन्दावत में कुल 12 विभागों/संस्थाओं को बिलानाम सरकारी भूमि आबंटित की गयी है। सूची परिशिष्ट-01 संलग्न है।

(3) ग्राम नन्दावत में कुल पशु संख्या 437 के मुकाबले 554 बीघा चरागाह भूमि उपलब्ध रिकार्ड है जो निर्धारित प्रति पशु आधा बीघा के नोर्म्स से अधिक है।

(4) जी हां। ग्राम नन्दावत की चरनोट एवं बिलानाम भूमियों पर वर्ष 2008-09 में कुल 38 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। सूची परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(5) जी हां।

(राजस्व मंत्री)

श्री हरिसिंह रावत विधायक ने विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 432/राजस्व दिनांक 10.8.09 द्वारा अतिक्रमण हटाने की मांग की थी । उक्त अतिक्रमियों के विरूद्ध उक्त विधानसभा प्रश्न के प्राप्त होने से पूर्व ही एल.आर.एक्ट. 1956 की धारा 91 के तहत अनाधिकृत कब्जों की पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर दिनांक 17.2.2009 एवं दिनांक 16.7.2009 को बेदखली के आदेश पारित किये गये थे । उक्त अतिक्रमियों के अनाधिकृत कब्जों को भौतिक रूप से दिनांक 03.03.2010 एवं दिनांक 04.03.2010 को हटाया गया है। इस प्रकरण में झूठे तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अत: अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट-1

ग्राम नन्दावत में विगत पांच वर्षों (2005-2009) में विभिन्न विभागों/संस्थाओं को आबंटित सरकारी बिलानाम भूमि का विवरण

क्र.सं.	नाम विभाग/संस्था	आ.नं.	आवंटित रकबा (बीघा -बिश्वा में)	भूमि किस्म	आबंटन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	राजकीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	1419 मि.	12.10	बिलानाम	प.12/3(क)(23)राजस्व/05/2011-16 दिनांक 23.05.2005
2	ग्राम पंचायत टोगी को आबादी हेतु	1816	05.00	बिलानाम	उपखण्ड अधिकारी भीम के आदेश क्रमांक:-एफ.(2)आबादी भूमि/राजस्व/05/1383-86 दिनांक 24.11.2005
3	राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय टोगी	1478	05.00	बिलानाम	उपखण्ड अधिकारी भीम के आदेश क्रमांक:- एफ.() राजस्व/आबंटन/06/288-90 दिनांक 08.05.2006
4	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नन्दावट	1816, 1826, 1835	09.00	बिलानाम	प.12/3(क)(43)राजस्व/06/3014-17 दिनांक 17.06.2006
5	जन आनन्द जन परमार्थ संस्थान	1817	02.00	बिलानाम	प.12/3(ख)(17)राजस्व/04/3153-58 दिनांक 30.06.2006

1	2	3	4	5	6
6	श्री प्रेरणा संस्थान कार्यालय आर्शीवाद स्टेशन रोड सुजानगढ़ जिला चुरू को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु	1419	05.00	बिलानाम	प.12/3(ख)(02)राजस्व/07/984-94 दिनांक 05.03.2007 नोट:- निदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर के पत्रांक:-32213 दिनांक 06.10.2009 के क्रम में आबंटी संस्था द्वारा आबंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:प.12/3(ख)()राजस्व/09/3792-3808 दिनांक 03.12.09 से आबंटन निरस्त किया गया है।
7	राजकीय महाविद्यालय भीम	1419 मि.	30.00	बिलानाम	प.12/3(क)(39)राजस्व/07/3238-44 दिनांक 02.0620.07
8	भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा भीम	1419	01.04	बिलानाम	प.12/3(ख)(302)राजस्व/07/1509-14 दिनांक 20.03.2008
9	उपखण्ड कार्यालय भीम	1817 मि.	10.00	बिलानाम	प.12/3(क)(92)राजस्व/08/235-38 दिनांक 14.01.2009
10	तहसील कार्यालय भीम	1817 मि.	10.00	बिलानाम	प.12/3(क)(93)राजस्व/08/239-42 दिनांक 14.01.2009
11	राजकीय आवासगृहों के निर्माण हेतु	1817 मि.	15.00	बिलानाम	प.12/3(क)(94)राजस्व/08/243-46 दिनांक 14.01.2009
12	न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीम	1817 मि.	05.00	बिलानाम	प.12/3(क)(108)राजस्व/08/1883-87 दिनांक 15.07.2009

जिला कलक्टर
राजसमन्द

परिशिष्ट-2

ग्राम नन्दावत की सरकारी बिलानाम एवं चरागाह भूमि पर वर्ष 2008-09 में अनाधिकृत अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों की सूची

क्र. सं.	नाम अतिक्रमी	आ.नं.	किस्म	अतिक्रमित रकबा
1	भगवानसिंह/रामसिंह रावत	1768	बिलानाम	01 बीघा
2	प्रेमसिंह/किशनसिंह	446	बिलानाम	08 बिश्वा
3	दिपेन्द्रसिंह/गोविन्द सिंह रावत	1514	चरागाह	01 बीघा 10 बिश्वा
4	मुन्नीबाई/किशनसिंह रावत	1775	चरागाह	15 बिश्वा
5	श्रवणसिंह/किशनसिंह रावत	1775	चरागाह	01 बीघा
6	बालूसिंह/विजयसिंह	1775	चरागाह	01 बीघा
7	चौथूराम/हीरालाल बलाई	1775	चरागाह	01 बीघा
8	गोपाललाल/बुद्धाराम बलाई	1775	चरागाह	01 बीघा
9	मीरादेवी/लक्ष्मणसिंह रावत	1775	चरागाह	01 बीघा
10	जय आनन्द जन परामर्श संस्थान भीम	1817	बिलानाम	01 बीघा 02 बिश्वा
11	मदनलाल/भूरा रेगर	1843	बिलानाम	02 बिश्वा
12	गोविन्दसिंह/जालमसिंह	1816, 1419	बिलानाम	01 बीघा 06 बिश्वा
13	फतहसिंह/पन्नासिंह रावत	1774	चरागाह	11 बिश्वा
14	हिम्मतसिंह/हालसिंह	1775	चरागाह	02 बिश्वा
15	नोजसिंह/केशरसिंह	1872	चरागाह	36 वर्गफीट
16	केशरसिंह/पन्नासिंह	1872	चरागाह	36 वर्गफीट
17	डाउसिंह/दूदसिंह रावत	1872	चरागाह	36 वर्गफीट

क्र. सं.	नाम अतिक्रमी	आ.नं.	किस्म	अतिक्रमित रकबा
18	हजारीसिंह/हिम्मतसिंह रावत	1872	चरागाह	36 वर्गफीट
19	दौलतसिंह/भीमसिंह रावत	1872	चरागाह	198 वर्गफीट
20	दूदसिंह/हीरासिंह रावत	1872	चरागाह	198 वर्गफीट
21	तेजसिंह/पूरणसिंह रावत	1872	चरागाह	36 वर्गफीट
22	नारायणसिंह/उदयसिंह रावत	1872	चरागाह	36 वर्गफीट
23	नोलसिंह/पन्नासिंह	1872	चरागाह	36 वर्गफीट
24	टेकसिंह/चिमनसिंह रावत	1872	चरागाह	36 वर्गफीट
25	जसवंतसिंह/लक्ष्मणसिंह रावत	1816	चरागाह	36 वर्गफीट
26	भेरूसिंह/भूरसिंह रावत	1816	चरागाह	36 वर्गफीट
27	हेमसिंह/अर्जुनसिंह	1816	बिलानाम	176 वर्गफीट
28	डाउसिंह/राजूसिंह रावत	1816	बिलानाम	90 वर्गफीट
29	पेमी/तुलसीसिंह रावत	1816	बिलानाम	140 वर्गफीट
30	जमकू/विजयसिंह रावत	1816	बिलानाम	154 वर्गफीट
31	मीरा/मकनसिंह रावत	1816	बिलानाम	154 वर्गफीट
32	हीरासिंह/मानसिंह रावत	1872	बिलानाम	176 वर्गफीट
33	कमला/कैलाशसिंह रावत	1872	चरागाह	143 वर्गफीट
34	कमला/अमरसिंह	1872	चरागाह	143 वर्गफीट
35	प्यारी/प्रेमसिंह	2535/1817	बिलानाम	132 वर्गफीट
36	जमनी/केशरसिंह रावत	2535/1817	बिलानाम	121 वर्गफीट
37	मीठूसिंह, जोरावसिंह/खंगारसिंह	1827	बिलानाम	07 बिश्वा
38	प्रभुसिंह, नारायणसिंह/मोतीसिंह एवं लाछी बेवा मोतीसिंह	1827	बिलानाम	07 बिश्वा

जिला कलक्टर
राजसमन्द

जोधपुर जिले की उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

98. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) वर्तमान में जिला जोधपुर में राशन की कितनी दुकानें संचालित हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशन की दुकानों पर बी.पी.एल. परिवार तथा आमजन को कौन-कौनसी वस्तुओं का कितनी-कितनी मात्रा में वितरण किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में उक्त जिले में इन वस्तुओं, गुणवत्ता माप एवं वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब ?

(4) क्या उक्त शिकायतों के आधार पर जांच कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो इनमें कितनी शिकायतें सही पाई गईं व कौन-कौन दोषी पाये गये तथा दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्तमान में जोधपुर जिले में 1204 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं इनमें से जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में 345, फलोदी नगरपालिका में 28, पीपाड़ नगरपालिका में 13 एवं बिलाड़ा नगरपालिका में 5 दुकानें कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 813 दुकानें हैं जिनकी पंचायत समितिवार दुकानों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) उक्त राशन की दुकानों पर बीपीएल परिवारों तथा आम जन को वितरित की जाने वाली वस्तुओं एवं मात्रा का विवरण निम्नानुसार है :-

योजना का नाम	वितरित की जाने वाली सामग्री	निर्धारित मात्रा प्रतिमाह
ए.पी.एल.	गेहूं, चावल (खाद्यान्न)	पूर्व में जिला जोधपुर में 5 किलो प्रति परिवार गेहूं वितरित किया जा रहा था। माह सितम्बर 2009 से जोधपुर शहर में 10 किलो आटा प्रति परिवार एवं ग्रामीण क्षेत्र में भी माह जनवरी 2010 से 10 किलो आटा प्रति परिवार वितरित किया जा रहा है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

योजना का नाम	**वितरित की जाने वाली सामग्री**	**निर्धारित मात्रा प्रतिमाह**
बी.पी.एल.	गेहूं (खाद्यान्न)	31 से 32 किलो प्रति परिवार आबंटन उपलब्धता के आधार पर समानुपातिक मात्रा में किया जा रहा है।
	चीनी	500 ग्राम प्रति व्यक्ति आबंटन उपलब्धता के आधार पर समानुपातिक मात्रा में किया जा रहा है।
सिंगल बैरल गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए केरोसीन	केरोसीन	2 लीटर प्रति राशन कार्ड
सामान्य राशन कार्ड धारक के लिए केरोसीन	केरोसीन	3 से 5 लीटर तक प्रति राशन कार्ड उपलब्धता के आधार पर समानुपातिक मात्रा में किया जा रहा है ।
डबल बैरल गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए केरोसीन	केरोसीन	शून्य

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर निम्नानुसार सामग्री भी वितरित की जा रही है।

1. जिला जोधपुर मुख्यालय की नगरीय सीमा में ए.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह 10 किलोग्राम आटा 9 रुपये प्रति किलो की दर से ।
2. खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिना राशन कार्ड 20 किलोग्राम गेहूं का आटा 14 रुपये प्रति किलो की दर से आवश्यकतानुसार।
3. सभी श्रेणी के राशन कार्ड धारी उपभोक्ताओं को 20 किलोग्राम आटा

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

13 रुपये 30 पैसे प्रति किलो की दर से 2 माह के लिए विशेष आवंटन श्रेणी में किया गया।

4. जिला जोधपुर मुख्यालय की नगरीय सीमा में प्रति राशन कार्ड अधिकतम 4 किलो चना दाल 29 रुपये प्रति किलो सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को।

5. जिला जोधपुर मुख्यालय पर प्रति राशन कार्ड 1 किलोग्राम मूंग की दाल 47 रुपये प्रति किलो की दर से एक बार माह नवम्बर 2009 में प्राप्त कर माह नवम्बर से जनवरी 2010 की अवधि में एक बार सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए वितरित की गई थी।

(3) जिला जोधपुर में गत दो वर्ष में वस्तुओं की गुणवत्ता व माप सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है परन्तु इस अवधि में वितरण/अनियिमितता के सम्बन्ध में 18 शिकायतें प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(4) जी हां। गत दो वर्षों में प्रप्त 18 शिकायतों में 9 शिकायतें जांच में सही पाई गई एवं 9 में कार्यवाही लम्बित है तथा दोषी पाये गये उचित मूल्य दुकान डीलरों के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-'ख' के कालम 5 में संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर जिले के ऋणी कृषकों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ

99. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रबी की फसल वर्ष 2009-10 के लिए राजस्थान के सत्रह जिलों में ऋणी कृषकों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना अनिवार्य रूप से लागू की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि क्लेम के लिये पैरामीटर्स जिलेवार अलग अलग रखे गये हैं? यदि हां, तो इसके मानदण्ड क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष सरसों की फसल के क्लेम हेतु भरतपुर जिले के लिए दो डिग्री तापमान निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो इस वर्ष भरतपुर जिले के कितने ऋणी कृषकों को इस योजना का लाभ मिलने की सम्भावना है, और नहीं, तो मात्र दो डिग्री ही तापमान निर्धारित किया

(डा. दिगम्बर सिंह)

जाना क्या न्यायसंगत है? नियमानुसार निर्धारित समय में मापे गये तापमानों की सूची तिथिवार सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार अधिक से अधिक ऋणी कृषकों को लाभ के दृष्टिकोण से निर्धारित दो डिग्री तापमान को बढ़ाकर चार डिग्री करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस वर्ष सरसों के फसल के नुकसान के लिए भरतपुर जिले के कितने ऋणी कृषकों को इस योजना का लाभ मिलने की सम्भावना है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार सरसों की फसल के नुकसान पर भरतपुर जिले के ऋणी कृषकों को क्लेम की बीमित राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रबी 2009-10 में राज्य के सत्रह जिलों यथा अलवर, भरतपुर, बारां, बून्दी, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जयपुर, जोधपुर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनूं, करौली, कोटा, नागौर एवं सवाईमाधोपुर जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य रूप से लागू की गई है।

(2) क्लेम के लिए जिले के मौसम पैरामीटर्स का निर्धारण निम्न घटकों के कारण अलग–अलग रखे गए हैं:-

1- जिले का सामान्य मौसम

2- जिले में पिछले 20-30 वर्षों के मौसम के आंकड़े

3- भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रति फसल की प्रिमियम की अधिकतम सीमा

4- कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा जिलेवार प्रत्येक फसल में फसल नुकसान हेतु निर्धारित तकनीकी पैरामीटर्स

उपरोक्त घटकों को दृष्टिगत रखते हुए बीमा कम्पनियों द्वारा फसलवार मौसम मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं।

(3) भरतपुर जिले में सरसों फसल में 7754 कृषक बीमित हैं। वहां सरसों फसल के दो प्रकार के जोखिम मापदण्ड यथा दिनांक 10-02-10 से 31-03-10 तक अधिक वर्षा एवं दिनांक 16-12-09 से 20-02-10 तक तापमान में कभी निर्धारित किए गए थे।

(कृषि मंत्री)

प्रत्येक तहसील में मौसम के आंकड़ों को मापने के लिए एन.सी.एम.एस.एल. द्वारा स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित किए गए हैं। तहसीलवार तिथिवार आंकड़े परिशिष्ट-1 पर सलंग्न हैं।

न्यूनतम तापमान के जोखिम में 2 दिन लगातार 2^0 से कम तापमान होने पर मुआवजा देय होगा। अभी तक प्राप्त मौसम आंकड़ों के अनुसार उक्त पैरामीटर्स प्राप्त नहीं पाए जाने के कारण मुआवजा देय नहीं है।

(4) भारत सरकार द्वारा फसलों हेतु अधिकतम प्रिमियम दरें निर्धारित की गई हैं। न्यूनतम तापमान में वृद्धि में बढ़ोतरी से फसल की वास्तविक प्रिमियम में बढ़ोतरी होगी। इसके मद्देनजर न्यूनतम तापमान को वर्तमान में बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है।

(5) सरसों फसल के लिए बीमित राशि 8100/- रुपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित है। सरसों फसल हेतु निर्धारित फसल बीमा राशि का निर्धारण पूर्व के वर्षों के औसत उत्पादन को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। बीमित राशि बढ़ाने पर कृषक की प्रिमियम राशि भी बढ़ जाएगी।

परिशिष्ट-1

भरतपुर जिले में तहसीलवार, तिथिवार न्यूनतम तापमान

तहसील	भरतपुर	बयाना	डीग	कामां	कुम्हेर	नदबई	नगर	पहाड़ी	रूपवास	बैर
दिनांक	न्यूनतम तापमान									
16-12-2009	12.2	14	12.2		11.4	11.6	14.2	103	12.3	13.1
17-12-2009	12.9	11.3	12.2		9.8	11.1	12.9	9.4	12.9	12.1
18-12-2009	11.1	14.1	11.1		9.6	10.3	10.9	6.2	11.8	13.3
19-12-2009	9.7	7.2	9.9		6.4	7.8	10.3	5.8	9.9	8.5
20-12-2009	9.4	5.9	6.5		6.4	7.1	11	6.9	8.7	7.7
21-12-2009	8.6	6.4	7.9		6.1	7.3	11.3	7.6	9.1	7.7
22-12-2009	8.8	6.7	7.9		6.9	6.4	10.4	7.3	9.7	7.8
23-12-2009	9.1	7.8	7.7		7.1	7.9	11	7.2	9.7	8.9
24-12-2009	10.3	8.8	7.8		7.7	8.1	11.1	6.3	9.3	9.6
25-12-2009	8.9	6.8	9.7		5.8	7.5	10	5.9	9.9	8.1
26-12-2009	7.8	7.8	7.2		5.8	6.7	8.1	6.1	7.2	8.6
27-12-2009	8.2	7.2	7.4		5.7	6.7	8.9	5.7	7.8	8
28-12-2009	8.6	8.3	8.8		6.3	6.8	10.1	6.6	7.7	8.6
29-12-2009	8.6	7.1	6.7		5.2	6.3	8.5	5.4	8.9	8.3
30-12-2009	10.4	9.3	8.5	7.1	8.2	8.3	9.4	6.8	10.2	7.9
31-12-2009	7.9	3.8	6.8	8.4	5.4	5.2	7.4	4.7	7.8	6.6
01-01-2010	7.7	5.6	6.1	9.4	5.1	6.6	7.9	5.4	7.8	6.3
02-01-2010	9.1	6.3	8.5	9.5	8.3	7.2	7.8	8.1	9.6	7.3
03-01-2010	9	9.2	9	8.3	6.3	9.7	9.8	9.7	8.3	9.5
04-01-2010	7.7	9.3	7.9	5.1	9.4	6	9.3		7.4	8.9
05-01-2010	6.6	7.8	8.8	6.1	7.8	6	8		5.1	7.7
06-01-2010	5.4	5.5	6.8	4.7	6.3	4.6	6.6		6.7	5.2
07-01-2010	6.5	7.4	7.9	8.9	3.4	6.3	7.1		6.9	7.6
08-01-2010	6.4	7.3	8.8	8.9	6.7	7.3	6.6		7.5	7.4
09-01-2010	5.8	6.5	7.5	4.8	6.5	6.3	8.7		7.6	6.8
10-01-2010	6.7	5.1	7.3	2.8	7.5	4.2	6.6		5.1	6.3
11-01-2010	4.9	7.4	7	8.6	6.4	3.6	5.2		4.6	5.9
12-01-2010	4.8	4.2	7.4	6.2	3.2	3.6	3.8		9.7	4.1
13-01-2010	10	9.8	9.5	8.6	8.6	7.2	7.9		7.9	8.8
14-01-2010	7.7	7.7	9.2	6.4	7	7.5	7.4		7.4	8
15-01-2010	8.4	6.2	8.8	5.6	7.1	5.6	8.1		6.6	6
16-01-2010	7.8	5	8.4	8.1	6.2	5.4	6.6		6	5.3
17-01-2010	6.4	5.2	6.9	5.8	4.4	4.1	4.8		6.2	5.1
18-01-2010	6.8	5.2	6.8	5.3	7.1	5	7.8		5.6	5.3
19-01-2010	5.7	5	7.3	8.3	6	4.7	6.4		5.9	5

तहसील	भरतपुर	बयाना	डीग	कामां	कुम्हेर	नदबई	नगर	पहाड़ी	रूपवास	बैर
दिनांक	न्यूनतम तापमान									
20-01-2010	5.2	5.9	7.8	8.4	4.8	4.7	4.8		5.9	5.4
21-01-2010	7.4	7.2	8.8	8.9	9.2	8.4	7.8		7.3	7.5
22-01-2010	7.9	5.8	9.2	7.3	8.9	7.2	8.3		7	6.5
23-01-2010	8.8	9.2	10.4	9.1	9.2	7.8	9.9		9.3	9.8
24-01-2010	8.8	9.6	11.7	8.1	9.8	8.4	9.2		9.4	9.5
25-01-2010	9.5	10.7	11.7	7.5	9.4	9.1	10		10.3	9.7
26-01-2010	9.8	8.2	12.9	8.2	10.8	11.7	8.8		9.1	7.8
27-01-2010	10.2	8.9	13.9	9.8	11.9	7.9	10.6		9.7	8.6
28-01-2010	11.2	10.1	14.9	11.8	12.8	7.5	11.6		11.3	9.5
29-01-2010	12.3	10.7	14.7	11.5	10.3	6.2	12.3		12	10.5
30-01-2010	13.7	12.2	14.6	8.5	10.1	8.8	9.8		13.3	12.2
31-01-2010	11.1	9.7	10.6	10.5	10.1	6.2	9.5		10.9	9.2
01-02-2010	10.7	9.8	10.1	10.1	11	8.8	9.2		11.1	8.9
02-02-2010	10.9	8.3	10.1	10.1	10.6		10.2		9.8	7.5
03-02-2010	11.7	10.5	11	10	11.5		10.1		11.7	10.2
04-02-2010	11.1	7.8	10.6	10.6	12.8		10.6		9.6	7.7
05-02-200	12.4	9	11.5	11.5	14.3		12.2		11.1	9.3
06-02-2010	13.3	10.2		12.8	16.6		13.4		12.1	10.4
07-02-2010	15.1				14.3		16.8		13.1	10.7
08-02-2010	16.4				12.4		13.2		14.8	14.5
09-02-2010	15.3				10.1		9.7		14.4	13.7
10-02-2010	14.4				14.7		8.4		13.7	9.7
11-02-2010	11.8				12.3		13.8		10.6	8.7
12-02-2010	15.5				13.5		11.5		15.1	14.2
13-02-2010	12.9				12.7		12.9		12.1	11.6
14-02-2010	14.1				13.3		11.9		13.8	13.9
15-02-2010	13.5				12.5		13		12.1	12.6
16-02-2010	13.6				9.4		12.2		12	12.4
17-02-2010	12.7				11		9.3		12.2	12.6
18-02-2010	9.4				11.5		10.1		8.8	10.1
19-02-2010	11.9						10.2		10.6	10.9
20-2-2010	12.6				11.5		10.2		11.6	11.2

पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि

100. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायती राज को अधिकार देने हेतु वर्ष 2004-2008 एवं 2008-2010 में मंत्रिमण्डलीय समिति बनाई गई? क्या समिति द्वारा अपनी सिफारिशें कर दी गई हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायती राज स्वर्ण जयन्ती के नागौर सम्मेलन में पंचायतों को अतिशीघ्र अधिकार देने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो अब तक पंचायतों को क्या-क्या अधिकार दिये गये और नहीं, तो क्यों और अब तक अधिकार नहीं देने के क्या कारण रहे?

(3) अब सरकार कब तक पंचायतों को फंड, फंक्शन एवं फंक्शनरी सहित अधिकार देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) दिनांक 10 अगस्त, 2004 को गृह मंत्री श्री गुलाब चन्द कटारिया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। वर्ष 2008-10 में कोई समिति नहीं बनाई गई है।

कटारिया कमेटी द्वारा अपनी सिफारिश दिनांक 26-12-2005 को प्रस्तुत कर दी हैं। सिफारिशों की प्रति परिशिष्ट-''क'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। पंचायतों को अधिकार दिये जाने के लिए राज्य सरकार गम्भीरता से प्रयास कर रही है। संसद, नगरपालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के चलते इस कार्य में प्रगति धीमी रही है।

(3) पंचायतों को अधिकार देने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है जिस पर शीघ्र ही कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में बिजली छीजत रोकने हेतु फीडर सुधार योजना

101. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में बिजली छीजत 40 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है? यदि हां, तो क्यों? क्या राज्य के 1000 गांवों को ही 24 घण्टे बिजली मिल रही है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

(2) क्या सरकार बिजली छीजत रोकने हेतु फीडर सुधार कार्यक्रम लागू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। दिसम्बर 2009 के अंत में डिस्कॉमवार प्रतिशत छीजत निम्न प्रकार है:-

अजमेर डिस्काम	28.54
जोधपुर डिस्काम	24.72
जयपुर डिस्काम	20.36
राज्य का औसत	**24.20**

राज्य में पांच हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जबकि 20 प्रतिशत से कम छीजत वाले फीडर पर जुड़े गांवों को 14 घण्टे एवं 20 प्रतिशत से अधिक छीजत वाले फीडरों पर जुड़े गांवों को 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) राज्य में फीडर सुधार कार्यक्रम जारी है, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुचारू विद्युत आपूर्ति, ट्रान्सफार्मर जलने की दर व विद्युत छीजत कम करना एवं ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को निकटतम शहरी क्षेत्रों के समान विद्युत आपूर्ति करना है। फीडर सुधार कार्यक्रम पर लगातार कार्य चल रहा है व शेष कार्य वर्ष 2010-11 में पूर्ण हो सकेगा।

जयपुर स्थित सरकारी अस्पतालों में खराब पड़े जीवनरक्षक उपकरण

102. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर के एस.एम.एस., जे.के. लोन, जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय व टी.बी. अस्पताल में वेंटीलेटर्स व अन्य जीवनरक्षक उपकरण, गहन चिकित्सा इकाई एवं स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की हुई है? यदि हां, तो इन अस्पतालों में सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये चिकित्सा उपकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों में से कुछ खराब भी हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से चिकित्सा उपकरण कब-कब से खराब हैं?

(श्री कालीचरण सराफ)

(3) उक्त चिकित्सा उपकरणों के खराब होने के क्या कारण रहे तथा इन्हें अब तक ठीक नहीं कराये जाने के क्या कारण रहे?

(4) क्या सरकार इन अस्पतालों के गहन चिकित्सा इकाई में बैड्स की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इन अस्पतालों में सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये चिकित्सा उपकरणों की सूची परिशिष्ठ ''अ'' पर है।

(2) जी हां। सवाईमानसिंह अस्पताल, जयपुर में खराब उपकरणों की सूची परिशिष्ट ''ब'' पर है।

वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय में एक ब्रोकेस्कोप मशीन 8.12.2004 से खराब है एवं एक एक्सरे मशीन दिनांक 8.11.09 से खराब है।

जनाना अस्पताल में एक वेंटीलेटर अगस्त 2009 से खराब है।

महिला चिकित्सालय में एक सेमी आटो एनेलायजर दिनांक 9.2.2010 से खराब है जो कि वर्तमान में मरम्मत प्रक्रिया के अन्तर्गत है उक्त उपकरण अत्यधिक उपयोग आने के कारण खराब हुआ है। जिसे दिनांक 9.03.2010 को ठीक करा लिया गया है।

(3) सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में खराब उपकरणों एवं कारणों की सूची परिशिष्ट ''ब'' पर है।

(4) जी हां, बैड्स की संख्या में वृद्धि किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर तहसील में राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत लम्बित प्रकरण

103. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया एवं प्रावधान क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील अलवर में वर्ष 2006 से जनवरी, 2010 तक कितने कृषकों के विरूद्ध राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कब एवं क्या कार्यवाही की गई व कितने कृषकों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना लम्बित है?

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

कार्यवाही लम्बित रहने के कारणों व कृषकों के नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर संबंधित पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर और सुनवाई का अवसर देकर संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय किया जाता है। निर्णयानुसार बेदखली, नीलामी एवं शास्ती आरोपित करने की कार्यवाही की जाती है। लगातार अतिक्रमण सिद्व होने पर धारा 91 में तीन वर्ष तक की सजा व 20 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

(2) तहसील अलवर में वर्ष 2006 से जनवरी 2010 तक राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कुल 4558 प्रकरण दर्ज हुए, 4391 प्रकरणों का निर्णय किया गया। शेष 167 प्रकरणों में से 47 प्रकरणों का फरवरी माह में निस्तारण किया गया। 120 प्रकरणों में विभिन्न न्यायालयों का स्थगन आदेश होने के कारण कार्यवाही लम्बित रहने के कारणों सहित सूची संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अजमेर शहर के डेयरी बूथों पर सस्ती दाल का वितरण

104. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार द्वारा सस्ती दाल वितरण योजना के तहत अजमेर शहर को गत दो माह में कब-कब कितनी दाल आबंटित की गई?

(2) उक्त शहर में कुल कितनी राशन की दुकानें हैं व उन पर दुकान अनुसार कितने राशनकार्डधारी उपभोक्ता हैं?

(3) उक्त शहर के प्रत्येक परिवार को एक किलो दाल कितने अन्तराल पर उपलब्ध कराई गई?

(4) उक्त शहर में सरकार ने डेयरी बूथों पर चने की दाल कब-कब उपलब्ध कराई? क्या सरकार अब भी यह दाल उपलब्ध करवा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा सस्ती दाल वितरण योजना के तहत अजमेर शहर को गत दो माह में दाल का आबंटन नहीं किया गया है। माह अक्टूबर, 2009 में 304.40 क्विंटल चने की दाल एवं माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2009 में 905 क्विंटल मूंग की दाल आवंटित की गई, जिसे 92 डेयरी बूथों एवं 274 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से वितरण करवाया गया।

(2) उक्त शहर में 92 डेयरी बूथ एवं 274 उचित मूल्य दुकानें हैं। उचित मूल्य दुकानों के अनुसार बीपीएल के 11275, अन्त्योदय के 851, अन्नपूर्णा के 139 एवं एपीएल के 119795 राशन कार्यधारी उपभोक्ता हैं। दुकानवार राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं की संख्या परिशिष्ठ-1 पर संलग्न है।

(3) उक्त शहर में 131921 परिवार हैं, जिसमें से 90500 परिवारों को चने की दाल प्रति राशन कार्ड प्रति माह अधिकतम 4 किलोग्राम माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2009 में तथा मूंग की दाल प्रति राशन कार्ड केवल एक बार अधिकतम 1 किलोग्राम माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2009 में उपलब्ध कराई गई।

(4) सरकार द्वारा 92 डेयरी बूथों पर चने की दाल माह अक्टूबर 2009 एवं शेष नवम्बर 2009 में तथा मूंग की दाल माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2009 में उपलब्ध कराई गई।

वर्तमान में चने एवं मूंग की दाल उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। गत दो माह जनवरी, 2010 व फरवरी, 2010 में किसी प्रकार की दाल उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

(संख्या विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में कृषकों को खरीफ फसल बीमा का मुआवजा

105. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राज्य में खरीफ की फसल में 100 प्रतिशत तक खराबा होने के सात माह बाद भी किसानों को फसल बीमा का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों? अब सरकार कब तक मुआवजा देने का विचार रखती है?

उत्तर

खरीफ फसल मौसम, 2009 के अन्तर्गत कृषि बीमा योजना में

(कृषि मंत्री)

राजस्व मण्डल द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के परिणाम एग्रीकल्चर इश्योरेंस कम्पनी को जनवरी, 2010 में (समय पर) उपलब्ध करा दिये हैं। एग्रीकल्चर इश्योरेंस कम्पनी द्वारा खराबे के आधार पर देय मुआवजे की गणना करने की कार्यवाही की जा रही है।

एग्रीकल्चर इश्योरेंस कम्पनी द्वारा राज्य सरकार द्वारा देय हिस्सा राशि की जानकारी उपलब्ध कराने पर राज्य की हिस्सा राशि इश्योरेंस कम्पनी को हस्तांतरित करवायी जायेगी। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि एग्रीकल्चर इश्योरेंस कम्पनी को प्राप्त होने पर कृषकों को मुआवजा दिया जायेगा।

सोजत विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का भुगतान

106. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सोजत के खाखरा नाडी से सबलपुरा में दिनांक 18-5-09 से 31-5-09 तक के मस्टररोल संख्या 250-710 से 716 (7) की राशि रुपये 58,900 का भुगतान बकाया है? यदि हां, तो किस-किस का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सोजत के वर्ष 2009 से जनवरी, 2010 तक ऐसे कितने कार्य हैं जिसमें बकाया मजदूरी का भुगतान किया जाना है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नरेगा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सोजत के खाखरा नाड़ी से सबलपुरा में दिनांक 18-05-09 से 31-05-09 के मस्टररोल संख्या 250710 से 250716 (7) की राशि रुपये 58,900 का भुगतान बकाया नहीं है। अनुपूरक सूचना के बिन्दु संख्या संलग्न है।

(2) उक्त योजना के अंतर्गत सोजत विधानसभा क्षेत्र के वर्ष 2009-10 तक ऐसे 25 कार्य है जिसमें बकाया मजदूरी का भुगतान किया जाना है। इन कार्यों में से 7 कार्यों पर अक्टूबर द्वितीय पखवाड़े तक भुगतान कर दिया गया है। ये सभी कार्य ग्राम पंचायत देवली कलां के है। ग्राम पंचायत देवली के

(ग्रामीण विकास मंत्री)

निरीक्षण के दौरान संबंधित ग्राम सेवक व रोजगार सहायक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गयी थी। जिस कारण दिसम्बर द्वितीय पखवाड़े तक के मस्टररोल व श्रमिक सूचियां पंचायत समिति में प्राप्त नहीं हो पाई हैं। अत: इन कार्यो की श्रमिक भुगतान की सूचियां प्राप्त कर भुगतान एक सप्ताह में कर दिया जायेगा। शेष 18 कार्यों का दिसम्बर द्वितीय पखवाड़े तक का भुगतान कर दिया गया है तथा बकाया भुगतान एक सप्ताह में कर दिया जायेगा।

अनुपूरक सूचना

उत्तर (1) नरेगा योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोजत के खाखरा नाडी से राबलपुरा तक ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य के मस्टररोल संख्या 250710-716 (7न.) का श्रमिक भुगतान राशि रुपये 58900/- का चैक संख्या 227414 दिनांक 15.06.09 को मारवाड़ ग्रामीण बैंक रायपुर में दिनांक 18.06.09 को सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड बर प्रथम द्वारा जमा करवा दिया गया था ।

सहायक अभियन्ता सार्व. निर्माण विभाग उपखण्ड बर प्रथम को उक्त कार्य पर कार्यरत मेट द्वारा उक्त अवधि का भुगतान श्रमिकों को नहीं होना बताया गया। तत्पश्चात सहायक अभियन्ता द्वारा अपने पत्र क्रमांक 318 दिनांक 06.01.2010 द्वारा ग्रांच मैनेजर मारवाड ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर को श्रमिक भुगतान की वस्तुस्थिति की जानकारी चाही गयी थी। ब्रांच मैनेजर ने अपने पत्र क्रमांक 2302 दिनांक 11.01.10 द्वारा उक्त चैक बैंक शाखा में उपलब्ध नहीं होना बताया । तत्पश्चात् सहायक अभियन्ता सार्व. निर्माण विभाग खण्ड बर प्रथम ने अपने पत्र क्रमांक 337 दिनांक 9.12.2010 द्वारा अधिशासी अभियन्ता सार्व. निर्माण विभाग खण्ड सोजत को उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत कराया तथा अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सोजत द्वारा चैक संख्या 056919 दिनांक 25.02.10 राशि रुपये 58900/- का पुन चैक जारी किया गया तथा यह चैक दिनांक 27.02.10 को पुन: मारवाड़ ग्रामीण बैंक रायपुर में श्रमिक भुगतान हेतु जमा करवा दिया गया है।

अत: नरेगा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सोजत के खाखरा नाडी से सबलपुरा तक ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य के मस्टररोल संख्या 250710-716 (7 न.) का श्रमिक भुगतान राशि रुपये 58900/- का भुगतान वर्तमान में बकाया नहीं है।

अनुपूरक सूचना

उत्तर (2) महानरेगा योजनान्तर्गत सोजत विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 2009 से 2010 तक के निम्न 25 कार्यों के बकाया मजदूरी का भुगतान किया जाना है:-

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	भुगतान की स्थिति
1	देवली कलां	बेकडी नाडी, खुदाई कार्य	इन कार्यों का अक्टूबर 2009 के द्वितीय पखवाड़े तक का भुगतान हो चुका है। शेष भुगतान शीघ्र करवा दिया जायेगा।
2	देवली कलां	खाण्डी नाडी खुदाई कार्य	
3	देवली कलां	पुनरिया नाडा खुदाई कार्य	
4	देवली कलां	हुकावा नाडा खुदाई कार्य	
5	देवली कलां	हरकटिया नाड़ा खुदाई कार्य	
6	देवली कलां	काली नाडी खुदाई कार्य	
7	देवली कलां	सांखला नाडी खुदाई कार्य	
8	झूंठा	बिचडी से खेजडा बेरा तक ग्रेवल सड़क	इन कार्यों का दिसम्बर, 2009 के द्वितीय पखवाड़े तक का भुगतान हो चुका है। शेष भुगतान शीघ्र करवा दिया जायेगा।
9	झूंठा	बिचडी से करमावास प्याउ तक ग्रेवल सड़क	
10	झूंठा	धोला नाडी खुदाई कार्य	
11	झूंठा	मोहरा रोड से इकरिया बेरा ग्रेवल सम्पर्क सड़क	
12	लिलाम्बा	हनुमान सागर खुदाई कार्य	
13	लिलाम्बा	खेज़डिया नाडी खुदाई कार्य	
14	लिलाम्बा	गौचर नाड़ी खुदाई कार्य	
15	लिलाम्बा	गांवाई तालाब फीडर खुदाई कार्य	
16	लिलाम्बा	मामाव तालाब फीडर खुदाई	इन कार्यों का अक्टूबर 2009 के द्वितीय पखवाड़े तक का भुगतान हो चुका है। शेष भुगतान शीघ्र करवा दिया जायेगा।
17	लिलाम्बा	नवोडा नाडी खुदाई कार्य	
18	रामपुरा कलां	गौचर से खींच नाड़ी खुदाई कार्य	
19	रामपुरा कलां	नौख नाडी खुदाई कार्य नौख	
20	रामपुरा कलां	रीमजानिया नाडी खुदाई कार्य	

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	भुगतान की स्थिति
21	सबलपुरा	पूर्व निर्मित रपट के डाउन स्ट्रीम पर खरंजा निर्माण	
22	सबलपुरा	बेरा रिया से धडा की तरफ रास्ते पर रपट बनाना	
23	सबलपुरा	राइकों की ढाणी से कांकरिया तक ग्रेवल सड़क	
24	सबलपुरा	नवे चावण्डिया से रायरा सीमा तक ग्रेवल सड़क	
25	सबलपुरा	चावण्डिया खुर्द से रायरा सीमा तक ग्रेवल सड़क	

निजी क्षेत्र में संचालित विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण

107. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए विधेयक में प्रावधान किया गया है ? यदि हां, तो प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य में अब तक कितने विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं एवं कितने निजी विश्वविद्यालय खोलने की स्वीकृति सरकार के विचाराधीन है और उन्हें स्वीकृति नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं?

(3) राज्य में निजी क्षेत्र में कार्यरत विश्वविद्यालयों पर सरकार किस किस तरह अपना नियंत्रण एवं निरीक्षण करती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा दिनांक 26.7.2007 को The Guidelines for the Establishment of private Universities by Separate Act जारी कर प्रदेश में निनी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रावधान किया गया है। उक्त दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) राज्य में अब तक 16 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जा चुके हैं एवं 23 संस्थाओं को आशय पत्र जारी किये हुये हैं। इनके अतिरिक्त 17 अन्य प्रस्ताव विचाराधीन हैं। ये प्रस्ताव आशय पत्र की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने/समिति से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण लम्बित हैं।

(3) निजी क्षेत्र में कार्यरत विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु जारी अध्यादेशों/अधिनियमों में प्रावधान किये हुये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट–ब पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर में स्वाइन फ्लू की जांच एवं निदान हेतु कार्य-योजना

108. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में फैले स्वाइन फ्लू रोग से सबसे अधिक मौतें किस जिले में हुई व इसके क्या कारण रहे ? प्रदेश में हुई मौतों की जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वाइन फ्लू से अधिक मौतें होने का प्रमुख कारण जांच की व्यवस्था व उचित दवाओं की उपलब्धता न होना है? क्या सरकार इसके लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि जोधपुर में लैबोरेट्री व अन्य जांच सुविधाएं नहीं होने के कारण स्वाइन फ्लू से मौतें हुई हैं ?

(4) क्या सरकार उम्मेद चिकित्सालय एवं मथुरादास माथुर चिकित्सालय जोधपुर में वांछित जांच सुविधा/उपकरण उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में स्वाइन फ्लू से सबसे अधिक 48 मौतें जोधपुर जिले में दिनांक 09 मार्च 2010 तक दर्ज की गई हैं। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :-

इस रोग के लक्षण सामान्य पाये जाने वाले फ्लू के समान ही होने के कारण रोगी द्वारा देरी से चिकित्सक से सम्पर्क करना।

स्वाइन फ्लू रोग से ग्रसित रोगी द्वारा समय पर उपचार नहीं लिये

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जाने पर उक्त रोग शीघ्र ही गम्भीर अवस्था धारण कर लेता है जो मृत्यु का कारक बनता है।

इसके अतिरिक्त बच्चे, गर्भवती महिलाऐं, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों एवं उच्च रक्तचाप, डायबटीज, कैंसर व अस्थमा से पीड़ित मरीजों में यह रोग तीव्र गति से फैलते हुए गम्भीर रूप धारण कर लेता है जो उनकी मृत्यु का कारण बनता हैं।

प्रदेश में स्वाइन फ्लू रोग से हुई मृत्युओं का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

प्रारम्भ से ही जोधपुर में स्वाइन फ्लू के संभावित मरीजों की सैम्पल की जांच एन.सी.डी.सी. लैब दिल्ली से करवाई जा रही थी, तत्पश्चात राज्य में ही 14 अक्टूबर 2009 से एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर के माइक्रोबायलोजी लैब में तथा दिनांक 19 नवम्बर, 2009 से डी.एम.आर.सी लैब जोधपुर में भी जांच सुविधा आरम्भ कर दी गई जो निरन्तर क्रियाशील हैं।

इसके साथ-साथ शीघ्र निदान हेतु 2 निजी लैबोरेट्रियों के 4 नमूना संग्रहण केन्द्र भी जोधपुर में कार्यरत है:-

डा. लाल पैथ लैब

1. जोधपुर सीसी 1-10 चन्द्रकला बिल्डिंग जालोरी वाडी, एम.जी. हास्पिटल के पास

2 जधपुर सीसी 1-बी 17 शास्त्री नगर, शास्त्री सर्किल के पास

मैसर्स सुपर रेलिगेयर लैबोरेट्रीज

1. जोधपुर-एडवास पैथ लैब ए-255 शास्त्री नगर

2. जोधपुर-मैसर्स सुपर रेलिगेयर लैबोरेट्रीज, 22 जालोर वाडी

(4) एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के माइक्रोबायोलाजी विभाग में स्वाइन फलू जांच हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाये जा चुके हैं। एवं निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। लैब शीघ्र ही प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है। यह दोनों चिकित्सालय इस मेडिकल कालेज से सम्बन्धित हैं।

परिशिष्ट-अ

प्रदेश में स्वाइन फ्लू रोग से हुई मृत्युओं का दिनांक 09 मार्च, 2010 तक का जिलेवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	जिले का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या
1	अजमेर	10
2	भीलवाड़ा	3
3	नागौर	15
4	भरतपुर	2
5	करौली	5
6	बीकानेर	9
7	चूरू	6
8	श्रीगंगानगर	4
9	जयपुर	30
10	अलवर	5
11	सीकर	4
12	झुंझुनूं	2
13	जोधपुर	48
14	पाली	4
15	जालौर	3
16	जैसलमेर	8
17	बाड़मेर	9
18	कोटा	11
19	बारां	1
20	झालावाड़	1

क्र.सं.	जिले का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या
21	बूंदी	3
22	उदयपुर	5
23	चित्तौड़गढ़	5
24	राजसमंद	3
	कुल योग	**196**

शेष 9 जिलों में स्वाइन फ्लू रोग से कोई मृत्यु नहीं हुई है।

1. टोंक
2. सवाईमाधोपुर
3. धौलपुर
4. हनुमानगढ़
5. दौसा
6. सिरोही
7. बांसवाड़ा
8. डूंगरपुर
9. प्रतापगढ़

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खटवाड़ा ग्राम (जयपुर) में पुनर्गृहीत भूमि के बदले खुद काश्त हेतु भू-आबंटन

120. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के अन्तर्गत ग्राम खटवाड़ा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में किन-किन की भूमि पुनर्गृहित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पुनर्गृहित भूमि के बदले किन-किन को कितना-कितना मुआवजा दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिनकी भूमि पुनर्ग्रहित की गई उनके द्वारा खुदकाश्त की भूमि आबंटन हेतु प्रस्तुत आवेदनों पर निर्णय लिया जाकर खुदकाश्त की भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो आवंटी का नाम, भूमि का रकबा जिस स्थान पर आबंटन किया गया है उसका नाम, कब्जा देने की तिथि सहित सूची सदन की मेज मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत ग्राम खटवाड़ा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में जिन व्यक्तियों की भूमि पुनर्ग्रहित की गई है उसका विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) पुनर्ग्रहित भूमि के बदले में दिये गये मुआवजे का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। खुदकाश्त आयुक्त राज. जयपुर द्वारा निम्नाकित व्यक्तियों को जयपुर जिले की सांगानेर तहसील के ग्राम खटवाड़ा में खुदकाश्त भूमि आबंटित की गयी है:-

क्र.सं.	नाम आबंटी	भूमि का रकबा
1	युधिष्ठर राज पुत्र सीताराम पुरोहित	15 बीघा 15 बिस्वा
2	श्याम सुन्दर पुरोहित	19 बीघा 17 बिस्वा
3	सुन्दरलाल, सीताराम पुत्र नानगराम	7, 3/4 एकड़

श्री श्याम सुन्दर पुरोहित को सम्वत 2015 में कब्जा दे दिया गया है शेष 2 को कब्जा नहीं दिया गया है।

परिशिष्ट-अ

क्र.सं.	नाम जागीरदार जिनकी भूमि पुनर्ग्रहित की गई	मुआवजा राशि
1.	श्री हरसहाय पुत्र मथुरा लाल	1,000
2	श्री गोपाल सहाय	1,000
3.	श्री विमल कुमार	800
4.	श्रीमती भोरी देवी	800
5.	श्री सीताराम	1,700
6.	श्रीनारायण	400
7.	श्री बंशीधर	1,800
8.	श्रीमती केसर देवी	150
9.	श्री रामसहाय	5,650
10.	श्री दुर्गासहाय	2,400
11.	श्री हरिनारायण	2,400
12.	श्री हरिनारायण पुत्र सुन्दरलाल	1,500
13.	श्री घनश्याम पुत्र सुन्दरलाल	1,500

कलक्टर (जागीर)
जयपुर

उनियारा (टोंक) की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

121. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उनियारा (टोंक) की राजस्व सीमा (नगरपालिका क्षेत्र सहित) में स्थित निजी खातेदारी एवं सरकारी भूमि का अंकन विभाग के रिकार्ड में किया हुआ है? यदि हां, तो प्रति सहित किस्म भूमि आदि का पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो रिकार्ड को कब तक संधारित कर पूर्ण कर लिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि में अनेक स्थानों पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है? यदि हां, तो किस-किस खसरा नम्बर की

(श्री रामनारायण मीणा)

कितनी भूमि पर किस व्यक्ति के द्वारा तथा इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा अब की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र में अधिकतम जोत सीमा निर्धारण अधिनियम के तहत अवाप्त भूमि भी स्थित है? यदि हां, तो अवाप्ति के आदेश सहित वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उनियारा (टोंक) की राजस्व सीमा (नगरपालिका क्षेत्र सहित) में स्थित निजी खातेदारी एवं सरकारी भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में संधारित है, जिसकी किस्म का विवरण निम्नानुसार है:-

1. सिवायचक 465 किता रकबा 289.36 है.
2. खातेदारी 2777 किता रकबा 2229.85 है.
3. गैर खातेदारी 6 किता रकबा 3.30
4. चरागाह 133 किता रकबा 110.42 है.
5. नगरपालिका 149 किता रकबा 102.14 है.
6. विभागीय 54 किता रकबा 83.77 है.

कुल योग 3584 किता रकबा 2818.84 है.

(2) जी हां। सिवायचक एवं चरागाह भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। खसरा परिवर्तनशील संवत् 2066 के अनुसार अतिक्रमण निम्न प्रकार है:-

1. सिवायचक पर 257 अतिक्रमियों द्वारा 166.03 हैक्टेयर पर
2. चरागाह भूमि पर 52 अतिक्रमियों द्वारा 23.96 हैक्टेयर पर

अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही जैरकार है। अतिक्रमियों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त क्षेत्र में अधिकतम जोत सीमा निर्धारण अधिनियम के तहत अवाप्त 603 बीघा 15 बिस्वा भूमि भी स्थित है। उक्त अवाप्त शुदा भूमि की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:-

(अ) 123 बीघा 15 बिस्वा भूमि कोर्ट डिग्री से खातेदारी देने से रेफरेंस कार्यवाही मा. राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है।

(राजस्व मंत्री)

(ब) 285 बीघा भूमि नगरपालिका उनियारा सीमा में होने से नगर पालिका को हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव विचाराधीन है।

(स) 195 बीघा भूमि आबंटन हो चुकी है। नामाकरण की प्रतियां एवं अवाप्त भूमि के आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(सूची व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर जिला कलक्टर कार्यालय में कार्मिकों के रिक्त पद

122. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर में दिन प्रतिदिन के कार्य का बोझ अत्यधिक है तथा कार्मिकों की नवीन भर्ती नहीं हो रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर कार्यालय में कार्य की अधिकता के कारण जिले के अन्य विभागों में नियुक्त कार्मिकों को जिला कलक्टर कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है?

(3) क्या सरकार नवीन भर्ती कर अन्य विभागों के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति स्थायी नहीं होकर कार्य विशेष के लिये की जाती है और कार्य पूरा होने पर कर्मचारी को मूल विभाग के लिये कार्यमुक्त कर दिया जाता है।

नवीन भर्ती/नवीन पद सृजन के प्रस्ताव राजस्व मण्डल से आने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

सिलीसेढ़ बांध अलवर की वन विकास हेतु आबंटित भूमि पर अतिक्रमण

123. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(1) क्या यह सही है कि सिलीसेढ़ बांध अलवर के डूब क्षेत्र में वर्ष 2009 में अतिक्रमण कर सड़क व दीवार का निर्माण किया गया था? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी पाये गये व दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कब व क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सिलीसेढ़ बांध के किनारे पर लोगों को 25 वर्ष की लीज पर वन विकास के उद्देश्य से भूमि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को व कब एवं लीज अवधि कब समाप्त हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर वनों के विकास संबंधी निरीक्षण का दायित्व किसी अधिकारी को सौंपा गया था? यदि हां, तो किसे व निरीक्षण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तहसील अलवर के सिलीसेढ़ बांध के भराव क्षेत्र में श्री एस.सी. जैन पुत्र श्री सुमेर चन्द जैन निवासी 13 पालम मार्ग बसन्त बिहार, दिल्ली द्वारा अतिक्रमण कर सड़क व दीवार का निर्माण किया गया था। श्री एस.सी. जैन के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत बेदखली का निर्णय दिनांक 31.12.2009 को किया जा चुका है, पालना शेष है। इस प्रकरण में तत्कालीन पटवारी श्री मोहन लाल यादव को लापरवाही का दोषी पाये जाने पर निलम्बित किया गया था तथा 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय जांच की कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) जी हां। सिलीसेढ़ बांध के किनारे 04 व्यक्तियों को निजी वन विकास हेतु लीज पर भूमि 25 वर्ष के लिये दी गई थी जिसकी अवधि 07.09.2013 को समाप्त हो रही है। विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। निजी वन विकास हेतु भूमि आबंटन के बाद आबंटित भूमि पर वन विकास हुआ या नहीं, यह देखरेख करना आवंटन के प्रथम तीन वर्ष के दौरान क्षेत्र में नियुक्त तत्कालीन सहायक वन संरक्षक एवं पटवारी हल्का का दायित्व था।

एक प्रकरण में पूर्व में अपील होने पर न्यायालय जिला कलक्टर,

(राजस्व मंत्री)

अलवर के निर्णय दिनांक 06.01.2009 के द्वारा आबंटन खारिज किया गया तथा आबंटित भूमि को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किया जा चुका है।

शेष तीन प्रकरणों में मौका जांच की जाकर तहसीलदार अलवर द्वारा आबंटन शर्तों की पालना में वृक्षारोपण नहीं करने तथा मौके पर कृषि कार्य करके आबंटन शर्तों का उल्लंघन की रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रेषित की गई है। आबंटन निरस्त करने हेतु प्रकरण दर्ज कर आबंटी को सुनवाई का नोटिस दिनांक 12.03.2010 हेतु जारी किया हुआ है। बाद सुनवाई आबंटन निरस्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	ग्राम का नाम	नाम आबंटी	खसरा नम्बर/रकबा	अवधि	उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी आबंटन क्रमांक व दिनांक	विशेष विवरण
1.	पैतपुर	किरण कुमार पुत्र श्री युवराज शर्मा निवासी अलवर	3/2.54, 4/0.27, 5/0.05, 6/0.11, 7/0.15, 8/0.12, कुल किता 3 रकबा 3.24	07.09.2013 तक	क्रमांक 27 दिनांक 09.05.89	इन्तकाल सं. 212 दिनांक 06.03.09 के द्वारा आबंटन खारिज कर सिवायचक दर्ज किया गया।
2.	पैतपुर	धर्मेन्द्र सिंह पुत्र जय महेश सिंह राजपूत सा. अलवर	52/0.07, 55/0.11, 355/3.01 कुल किता 3 रकबा 3.19	07.09.2013 तक	क्रमांक 88 दिनांक 20.09.89	-
3.	पैतपुर	रामनिवास पुत्र बुद्धाराम महाजन सा. अलवर	01/1.28, 10/0.04, 11/0.04, 66/0.22 कुल किता 4 रकबा 1.68	07.09.2013 तक	क्रमांक 28 दिनांक 09.05.89	-
4.	पैतपुर	श्रीमती कलावती देवी पत्नि श्रीराम सैनी सा. खोहरा अलवर	357/0.38, 360/0.68 किता 2 रकबा 1.06	08.09.2013	क्रमांक 76 दिनांक 10.08.89	-

भीम विधान सभा क्षेत्र में पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों के रिक्त पद

124. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं तथा ग्राम पंचायतवार पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं?

(2) क्या प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी स्वीकृत पदों के अनुसार कार्यरत हैं?

(3) विधान सभा क्षेत्र भीम की दोनों तहसीलों में पटवारियों एवं निरीक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 9166 ग्राम पंचायतें है। राज्य में पटवारियों के 10298 एवं भू-अभिलेख निरीक्षकों के 1580 पद स्वीकृत हैं।

(2) जी नहीं। स्वीकृत पदों के विरूद्ध कुछ पद रिक्त हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र भीम की दोनों तहसीलों में पटवारियों के 17 पद रिक्त है एवं भू-अभिलेख निरीक्षकों के 6 पद रिक्त हैं।

राजस्थान लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के अन्तर्गत आये पटवार प्रशिक्षणार्थियों को पटवारी का प्रशिक्षण दिलवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। पटवार प्रशिक्षण के उपरान्त उर्त्तीण आशार्थियों को पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दी जायेगी।

भू-अभिलेख निरीक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र पदोन्नति से भरा जायेगा।

अजमेर के थोक तेलियान व थोक मालियान के राजस्व रिकार्ड की वैधता

125. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर के राजस्व रिकार्ड थोक तेलियान व थोक मालियान की जमाबंदी वर्तमान में अप्रमाणित है? यदि हां, तो राजस्व रिकार्ड को प्रमाणित करने के सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(श्रीमती अनिता भदेल)

(2) वर्तमान में अजमेर के थोक तेलियान व थोक मालियान का राजस्व रिकार्ड अप्रमाणित होने के कारण कौन से संवत का रिकार्ड वैध माना जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। थोक तेलियान व थोक मालियान के राजस्व रिकार्ड को प्रमाणित करने में आ रही कठिनाइयों का अध्ययन करके उनके निराकरण हेतु राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 26.5.2009 द्वारा संभागीय आयुक्त, अजमेर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है।

(2) अजमेर थोक तेलियान में संवत 2014-2017 की जमाबन्दी प्रमाणित है तथा अजमेर थोक मालियान के फसली सन 1365 की फसली खेवट प्रमाणित है।

वर्ष 2009-10 में राज्य को आबंटित राशन कोटा

126. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2009-10 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को कुल कितना गेहूं, चावल, चीनी आबंटित किया गया?

(2) उक्त आबंटित गेहूं, चीनी एवं चावल में से कितनी मात्रा राज्य सरकार द्वारा उठा ली गई है?

(3) उक्त में से अब तक आम जन को कितनी सामग्री वितरित की जा चुकी है ? अवधि, मात्रा तथा सामग्री का वितरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) आगामी वर्ष हेतु केन्द्र से आबंटन हेतु राज्य सरकार की मांग क्या है ? सामग्रीवार मांग का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार चीनी पर वैट कम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) प्रदेश में खुदरा और थोक विक्रेताओं के लिये प्रभावी अधिकतम स्टाक सीमा क्या है? क्या सरकार बढ़ती मंहगाई के मद्देनजर इसमें बदलाव करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य को पूरे वर्ष 2009-10 हेतु केन्द्र द्वारा कुल आबंटित सामग्री/मात्रा निम्नानुसार है :-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

मात्रा टनों में

सामग्री	एपीएल	बीपीएल	एएवाई	सूखाग्रस्त	खुली बिक्री	ऐडहोक ऐडिशनल	योग
गेहूं	772320	629532	391488	152124	173864	177340	2296668
चावल	-	-	-	-	78	-	78
चीनी	-	79669	-	-	-	-	79669

(2) आवंटित सामग्री के विरूत्र किये गये उठाव की मात्रा (जनवरी, 2010 तक) निम्नानुसार है-

मात्रा टनों में

सामग्री	एपीएल	बीपीएल	एएवाई	सूखा ग्रस्त	खुली बिक्री	ऐडहोक ऐडिशनल	योग
गेहूं	631366	521925	320014	76062	96646	उठाव जारी है।	1638109
चावल					78		78
चीनी		27743					27743

खुली बिक्री एवं सूखाग्रस्त का आबंटन माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2009 तक का शत-प्रतिशत उठाव हो गया है। माह जनवरी, 2010 से मार्च, 2010 तक खुली बिक्री के आबंटन की वैधता अवधि दिनांक 15.3.2010 तक, माह जनवरी, 2010 से मार्च, 2010 तक सूखाग्रस्त आबंटन एवं माह जनवरी-फरवरी, 2010 तक के अतिरिक्त विशेष आवंटन की वैधता अवधि दिनांक 31 मार्च, 2010 तक है। शेष उठाव जारी है।

(3) बिन्दु संख्या 2 में उठाई गई सामग्री का आमजन में वितरण किया जा चुका है।

(4) राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से माहवार निम्नानुसार मांग की गई है :-

एपीएल, बीपीएल योजाना में वर्तमान में आबंटित गेहूं की मात्रा 64,360 मै0टन प्रतिमाह को बढाकर 1.6 लाख मै.टन करने एवं चावल का आवंटन 20,000 मै. टन प्रतिमाह की मांग की गई है। बीपीएल योजना के अन्तर्गत वर्तमान में आबंटित गेहूं की मात्रा में 5250 मै.टन प्रतिमाह अतिरिक्त गेहूं आबंटन तथा 42648 के.एल. को बढ़ाकर 60000 के.एल. कैरोसीन की मांग की गई है।

ए.पी.एल		बी.पी.एल	कैरोसीन
गेहूं	चावल	गेहूं	
1.6 लाख मै. टन	20000 मै. टन	5250 मै. टन	60000 के.एल.

(5) वर्तमान में राज्य में चीनी पर वैट लागू नहीं है।

(6) वर्तमान में चीनी एवं दालों के लिये राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.09.2010 तक लाईसेंसिंग प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत स्टाक सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है, जिसमें अभी कोई बदलाव करने का विचार नहीं है।

चीनी-

डीलर	स्टाक सीमा	टर्न ओवर अवधि
खुदरा डीलर	25 क्विंटल	30 दिवस
थोक डीलर	2000 क्विंटल	30 दिवस

दालें–

डीलर	स्टाक सीमा	टर्न ओवर अवधि
खुदरा डीलर	30 क्विंटल	30 दिवस
थोक डीलर	1000 क्विंटल	30 दिवस
दाल मिलें 1. साबुत दाल	30 दिन की उत्पादन क्षमता के बराबर	30 दिवस
2. दली हुई दाल	15 दिन की उत्पादन क्षमता के बराबर	30 दिवस

राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का गठन

127. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए राज्य में नागरिक आपूति निगम के गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए राज्य में नागरिक आपूर्ति निगम बनाने की घोषणा बजट भाषण 2010-11 में कर दी गई है।

राज्य के चिकित्सालयों से संक्रामक कचरे का निस्तारण

128. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राज्य बड़े एवं छोटे शहरों में स्थापित चिकित्सालयों से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में संक्रामक कचरा निकलता है और उसके निस्तारण की कोई संतोषप्रद व्यवस्था नहीं है, जिससे रोग फैलते हैं? यदि हां, तो किन-किन चिकित्सालयों में संक्रामक कचरे के निस्तारण की व्यवस्था है और शेष में कब तक उक्त व्यवस्था को लागू कर दिया जायेगा?

उत्तर

राज्य के बड़े-छोटे सभी शहरों में स्थापित राजकीय चिकित्सालयों से प्रतिदिन संक्रामक कचरा निकलता है।

उक्त राजकीय चिकित्सालयों में संक्रमित कचरे के निस्तारण हेतु संतोषप्रद व्यवस्था है। राजकीय मेडिकल कालेजों तथा उनसे सम्बन्धित चिकित्सालयों का संक्रमित कचरा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदण्डों के अनुसार निस्तारित किया जाता है।

आरएचएसडीपी के माध्यम से 343 द्वितीय स्तर के संस्थानों पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट के तहत डीप ब्यूरियल पिट्स व स्टोरेज सेन्टर की व्यवस्था उपलब्ध है। उपरोक्त सभी संस्थानों पर बैग्स व बीनस् उपलब्ध करवाये जा चुके हैं। इनमें से 317 संस्थानों पर डीप ब्यूरियल पिट्स है व 26 संस्थानों पर स्टोरेज सेन्टर है। अब तक 244 संस्थान सीटीएफ से जोड़े जा चुके हैं। द्वितीय स्तर के शेष 63 संस्थानों पर डीप ब्यूरियल पिट्स बनवाये जा रहे हैं व अन्य आवश्यक सप्लाई उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही द्वितीय स्तर के संस्थानों के 12621 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर के 2515 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

बाड़मेर जिले के राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पद

129. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी है?

(श्री मेवाराम जैन)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले के सबसे बड़े राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में स्वीकृत पदों में से चिकित्सकों के दो तिहाई पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में चिकित्सकों के कुल 250 पद स्वीकृत है। जिनमें से 102 पद रिक्त हैं।

(2) राजकीय जिला चिकित्सालय, बाड़मेर में चिकित्सकों के कुल 54 पद स्वीकृत हैं। जिनमें से वरिष्ठ विशेषज्ञ का 1, कनिष्ठ विशेषज्ञ के 9, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 2 तथा चिकित्सा अधिकारी के 19 कुल 31 पद रिक्त हैं।

वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर तथा चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से भरने के प्रयास किये जायेंगे।

स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु अरजेन्ट टेमप्रेरी बेसिस पर चिकित्सा अधिकारियों के 600 रिक्त पदों को अधिकतम 6 माह के लिए अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने (दोनों मे से जो भी पहले हो) तक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें से बाड़मेर जिले में चिकित्सकों के 30 रिक्त पदों के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को वाक-इन-इन्टरव्यू से भरने हेतु अनुमति प्रदान की गई। जिसके विरूद्ध 30 चिकित्सकों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारियों के 20 और रिक्त पदों को अरजेन्ट टेमप्रेरी बेसिस पर भरने हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है। जिनमें से 15 चिकित्सक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन एवं 5 चिकित्सक राजकीय जिला चिकित्सालय बाड़मेर में नियुक्त किये जाने हैं। इनको नियुक्ति देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बांगड़ चिकित्सालय पाली में जांच हेतु उपलब्ध उपकरणों का उपयोग

130. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(1) बांगड चिकित्सालय पाली में खून, पेशाब एवं अन्य जांचों के कौन कौन से उपकरण कितने समय से उपलब्ध हैं एवं इन उपकरणों से कौन कौनसी जांचें की जा सकती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालय में उपकरण होने के बावजूद भी कौन-कौनसी जांचें कितने समय से किन-किन कारणों से नहीं की जा रही हैं?

(3) अब मौजूद उपकरणों से की जाने वाली जांचें कब तक प्रारम्भ करा दी जायेंगी?

उत्तर

(1) चिकित्सालय में उपलब्ध खून, पेशाब एवं अन्य जांचों के उपकरण कितने समय से हैं एवं उनसे कौन-कौनसी जांचें की जा सकती हैं का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) चिकित्सालय में उपलब्ध निम्नांकित उपकरणों से सम्बन्धित जांचे वर्तमान में समुचित संख्या में मांग नहीं होने से सम्पन्न नहीं होती है।

1. ऐलिजा रीडर से टी3, टी4, टीएचएस
2. कोगुलोमीटर
3. ब्लड गैस ऐनालाईजर
4. फ्लेम फोटोमीटर

(3) चिकित्सालय के उपकरण ऐलिजा रीडर, कोगुलोमीटर आदि से सम्बन्धित जांचें प्रत्येक माह की दिनांक 10 को किया जाना निश्चित किया गया है।

परिशिष्ट-अ

चिकित्सालय में उपलब्ध खून, पेशाब एवं अन्य जांचों के उपकरण कितने समय से हैं एवं उनसे कौन-कौनसी जांचें की जा सकती है का विवरण निम्न प्रकार है

उपकरणों के नाम	स्थापना दिनांक	कार्यरत/ खराब	जांच जो की जाती है का विवरण
सेमी ऑटोएनालाईजर	22.0.09	कार्यरत	शुगर, यूरिया, कॉलेस्ट्राल, क्रियेटिनीन, बिलीरूबीन, सिरम ओ.टी.पी.टी. सी.पी.के. एम.बी. एल्केलाईन फोस्फेटस की जांच की जाती है।

उपकरणों के नाम	स्थापना दिनांक	कार्यरत/ खराब	जांच जो की जाती है का विवरण
ऐराबेक्सी-300 (फुल्ली ऑटोएनालाइजर)	04.12.04	कार्यरत	उपरोक्तानुसार
कलरी मीटर	12.09.05	कार्यरत	बिलीरूबीन, सिरम ओ.टी.पी.टी. सी.पी.के. एम.बी. एल्केलाइन फोस्फेटस की जांच की जाती है।
एबीएक्स पेन्टरा 60	26.03.04	कार्यरत	सी.बी.सी. की जांच
ऐलिजा रीडर (3)	(1) 04.06.01	दिनांक 12.01.10 से खराब	टी3, टी4, टीएसएच, एचआईवी, एचबीएस, एजी, एचसीवी इत्यादि
	(2) 15.04.04	कार्यरत	उपरोक्तानुसार
	(3) 05.12.08	कार्यरत	उपरोक्तानुसार
कोगुलोमीटर	17.06.04	कार्यरत	पी.टी. टेस्ट (प्रोथमबिन टाइम टेस्ट)
ब्लड गैस ऐनालाइजर	17.06.04	कार्यरत	गैस एनालाइसिस पीसीओ 2 एवं ओ2
फ्लेम फोटोमीटर	10.10.06	कार्यरत	एस-इलेक्ट्रोलाइट
ब्लड बैंक चेम्बर	17.07.95	कार्यरत	ब्लक स्टोरेज
माइक्रोस्कोप	08.08.07	कार्यरत	यूरिन कम्पलीट टीएलसी, एलसी,सीमेन, स्टूल की जांच
डिजीटल एच बी मीटर	04.09.08	कार्यरत	एचबी ऐस्टीमेशन
यूरिस्केन ऑप्टिमा	19.01.04	दिनांक 10.02.06 से खराब	यूरिन कम्पलिट जांच
सीटी स्केन मशीन	2005	कार्यरत	मस्तिष्क में क्लोट, रक्त स्त्राव, अनियमितता की जांच एवं शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों की जांच।
एक्सरे मशीन 500 एम.ए.	11/2003	कार्यरत	शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों एवं अस्थियों की जांच।
डिजीटल एक्सरे मशीन	16.02.09	कार्यरत	शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों एवं अस्थियों की जांच।

उपकरणों के नाम	स्थापना दिनांक	कार्यरत/ खराब	जांच जो की जाती है का विवरण
सोनोग्राफी (यू.एस.जी.) मशीन	01.04.1997	कार्यरत	शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों की जांच।
ईकोकार्डियोग्राफी मशीन	2005	कार्यरत	ह्रदय की विभिन्न प्रकार की जांच।
सी.आर्म मशीन	2007	कार्यरत	अस्थिरोगियों के आपरेशन के समय विभिन्न फैक्चर देखने के लिए काम में ली जाती है।
ई.ई.जी. मशीन	2004	कार्यरत	धनुषबाय (टीटनेस) एवं मिर्गी संबंधी रोगियों की जांच की जाती है।
टी.एम.टी. मशीन (2)	2005	कार्यरत	
	1998	2005 से खराब	ह्रदय रोगी मरीज की दौड़ करते हुए कार्डियोग्राम लिया जाता है।
ई.सी.जी. मशीन			
मल्टी चैनल 6	2004	कार्यरत	ह्रदय रोगियों की ह्रदय संबंधी बीमारी की जांच।
डिजीटल मल्टी चैनल 3	2010	कार्यरत	
डिजीटल मशीन 2	2008	कार्यरत	
एम.के.4 108 पोरटेबल टी.	1995	2005 से खराब	
एम.के.6 108 पोरटेबल टी.	1998	कार्यरत	

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालाडेरा का क्रमोन्नयन

131. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं की ग्राम पंचायत कालाडेरा के महाविद्यालय व विद्यालयों में 10,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत होने के बावजूद चिकित्सा सुविधा के नाम पर केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध है?

(2) क्या यह भी सही है कि कालाडेरा के आस-पास की 6-7 ग्राम

(श्री भगवान सहाय सैनी)

पंचायतों के निवासी भी उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से ही चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हैं?

(3) क्या सरकार कालाडेरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) ग्राम पंचायत कालाडेरा में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का जनवरी, 2009 से जनवरी, 2010 का आऊटडोर व इनडोर मरीजों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालाडेरा, पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के अन्तर्गत आती है। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वर्ष 2001 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की कमी है। आगामी वित्तीय वर्षों में पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमौन्नत करने के प्रयास किये जायेंगे।

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालाडेरा में 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2010 तक 41482 मरीज आऊटडोर में एवं 1542 मरीज इनडोर में तथा मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, कालाडेरा में 1297 मरीज आऊटडोर में एवं 1223 मरीज इनडोर में पंजीकृत हुये।

नवचौकिया स्वास्थ्य केन्द्र जोधपुर में प्रसूति हेतु व्यवस्था

132. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर स्थित नवचौकिया स्वास्थ्य केन्द्र के प्रसूतिगृह में कितनी शय्या हैं तथा प्रतिवर्ष कितनी प्रसूति होती हैं? विगत पांच वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसूति हेतु पृथक से चिकित्सक तथा अन्य स्टाफ कार्यरत है तथा प्रसूति कक्ष की व्यवस्था है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिटी डिस्पेन्सरी नवचौकिया जोधपुर में शैयाऐं स्वीकृत नहीं है। प्रसूति की संख्या शून्य है।

(2) सिटी डिस्पेन्सरी नवचौकिया जोधपुर में नगर सहभागी योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार एवं दानदाता द्वारा प्रसूति गृह का निर्माण करवाया गया हैं।

सिटी डिस्पेन्सरी नवचौकिया जोधपुर में स्टाफ के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पदनाम	**स्वीकृत पदों की संख्या**	**कार्यरत पदों की संख्या**
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी, स्त्रीरोग, बालरोग)	3	3
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	2
चिकित्सा अधिकारी	2	2
चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	1
नर्स श्रेणी द्वितीय	5	5
प्रसाविका	1	1
वार्डबाय	3	3

डिस्पेन्सरी में मातृ शिशु सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए 1 चिकित्सा अधिकारी (महिला) एवं 1 नर्स श्रेणी द्वितीय का पद स्वीकृत है। जो उक्त स्वीकृत पदों में सम्मिलित है।

नवचौकिया डिस्पेन्सरी से लगभग डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर डा. एस.एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर के अन्तर्गत तृतीयक स्तर (ट्रसरी लेवल) की प्रसव, स्त्रीरोग व शिशुरोग की विशेषज्ञ सेवाऐं उपलब्ध कराया जाने वाला संस्थान उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर स्थित है।

इसलिए नवचौकिया क्षेत्र के आमजन प्रसूति को सेवा उम्मेद चिकित्सालय से प्राप्त कर रहे हैं।

जिससे नवचौकिया चिकित्सालय क्षेत्रवासी प्रसूति सुविधा से वंचित नहीं है। सिटी डिस्पेन्सरी नवचौकिया में प्रसूति सुविधा प्रारम्भ किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बयाना में स्त्री रोग एवं बालरोग चिकित्सक स्थापन का पद

133. श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बयाना में स्त्री रोग एवं बालरोग के चिकित्सक नहीं हैं? क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर दोनों चिकित्सकों का पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना में स्वीकृत कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग) के पद पर डा. कृष्ण गोपाल मित्तल, कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग) पदस्थापित है। कनिष्ठ विशेषज्ञ (बालरोग) का पद रिक्त ह।

कनिष्ठ विशेषज्ञ (बालरोग) के पद को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

स्वास्थ्य केन्द्र रूपावास (सोजत) का नामकरण

134. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम रूपावास में स्वास्थ्य केन्द्र बना हुआ है?

(2) क्या उसके नामकरण हेतु कोई प्रकरण सरकार के समक्ष विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का अब नामकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) दानदाता से प्रस्ताव एवं दानपत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार नामाकरण करने की कार्यवाही की जायेगी।

पिनान ग्राम (अलवर) के 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन से विद्युत आपूर्ति

135. श्री सूरजभान (राजगढ़ लक्ष्मणगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के गांव पिनान में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत है? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करवा दी जायेगी?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के गांव पिनान में दिनांक 11.9.2008 को 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत किया गया था। इस ग्रिड सब-स्टेशन को वर्ष 2010-11 में पूर्ण कर बिजली आपूर्ति प्रारम्भ करवाना प्रस्तावित है।

खेडली (अलवर) की विद्युत व्यवस्था

136. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सहायक अभियन्ता कार्यालय खेडली, जिला अलवर में अक्टूबर 2009 से फरवरी 2010 तक कृषि व घरेलू विद्युत संबंध हेतु कितने ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार खेडली में ट्रांसफार्मर की कमी की पूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विद्युत कनेक्शन कब तक दे दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता कार्यालय खेडली जिला अलवर में माह अक्टूबर 2009 से फरवरी 2010 तक कृषि कनेक्शन हेतु 391 व आवासीय कनेक्शन हेतु 10 ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता थी। इनमें से कृषि कनेक्शन हेतु 362 ट्रांसफार्मर प्राप्त हुए हैं।

(2) जी हां। माह मार्च 2010 तक उपरोक्त सभी ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

(3) राजस्थान सरकार की अधिसूचना वर्ष 2002 के अनुसार विधान

(ऊर्जा मंत्री)

सभा क्षेत्र कठूमर में बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं। कुछ बी.पी.एल. कनेक्शन गैर आबादी क्षेत्र में होने के कारण लम्बित हैं जिन्हें नियमानुसार कार्यवाही कर कनेक्शन जारी करने के प्रयास किये जायेंगे।

कोटा वृत्त के जले हुए ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति

137. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा वृत्त के जले हुए ट्रांसफार्मरों को विद्युत निगम के जयपुर मुख्यालय तक नहीं पहुंचाने के कारण निगम ने कोटा वृत्त को नये ट्रांसफार्मर देने से मना कर दिया है और इसके कारण कोटा वृत्त के किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहा हैं? क्या इसके लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जले हुए ट्रांसफार्मर गारंटी अवधि में होने के बावजूद समय पर नहीं बदलवाने के कारण विद्युत निगम को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। कोटा वृत्त के अन्तर्गत समय-समय पर जले हुए ट्रांसफार्मर कोटा वृत्त भण्डार में जमा कराये जाते हैं। कुछ ट्रांसफार्मर खेतों में फसल खड़ी होने के कारण उपखण्ड कार्यालय तक नहीं पहुंच पाने से देरी हो जाती है, परन्तु इसके कारण अधिनस्थ क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बदलने हेतु निगम द्वारा हमेशा उपलब्ध कराये जाते हैं। अत: इसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

(2) गारन्टी अवधि में जले हुये ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कराना एक सतत प्रक्रिया है एवं समय-समय पर ट्रांसफार्मर की मरम्मत संबंधित फर्म द्वारा की जाती रही है और निर्धारित अवधि में ट्रांसफार्मर मरम्मत नहीं किये जाने पर संबंधित फर्म से शास्ति राशि वसूल किये जाने का भी प्रावधान है। इसके बावजूद संबंधित फर्म द्वारा गारन्टी अवधि में जले हुये ट्रांसफार्मर नहीं उठाने पर उचित कार्यवाही की जाती है। जिसके तहत समय-समय पर संबंधित फर्म

(ऊर्जा मंत्री)

का आपूर्ति का भुगतान रोक लिया जाता है तथा संबंधित फर्म की बैंक गारन्टी की राशि को जब्त करने की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में जयपुर निगम द्वारा 6 करोड़ से ज्यादा का भुगतान रोका गया है तथा 2.73 करोड़ की बैंक गारन्टी राशि व भुगतान रोकने की कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार अजमेर निगम में 9.28 करोड़ रुपये का भुगतान रोक दिया गया है।

गारन्टी अवधि में जले हुये ट्रांसफार्मरों को तीव्र गति से ठीक कराने हेतु जयपुर निगम द्वारा जयपुर में एक केन्द्रीय भण्डार स्थापित किया गया है ताकि विभिन्न भण्डारों में पडे हुये ऐसे ट्रांसफार्मरों को एक ही स्थान पर मंगवाकर इस कार्य पर पूरा ध्यान देकर संबंधित फर्मों से शीघ्र उक्त ट्रांसफार्मर ठीक करवाये जा सकें।

धौलपुर के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

138. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से पशु चिकित्सालय किस-किस ग्राम में हैं तथा वर्तमान में उनमें अधिकारियों व कर्मचारियों के कितने पद सृजित हैं और उक्त पदों पर किस दिनांक से कौन कौन अधिकारी नियुक्त है एवं कौन-कौन से पद रिक्त हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में संचालित श्रेणीवार पशु चिकित्सालयों में सृजित पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पशु चिकित्सा का नाम एवं श्रेणी	वरि. पशु चिकि. अधि.		पशु चिकि. अधि.		पशु चिकि. सहा.		पशुधन सहायक		पशुधन परिचर		सफाई कर्ता जलधारी		नियुक्त अधिकारी का नाम	पद पर नियुक्ति की दिनांक
		स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त		
1	प्रथम श्रेणी पशु चिकि. धौलपुर	1	1	1	-	-	-	3	-	2	-	1	-	डा. महेश चन्द शर्मा	08/2001
2	पशु चिकि. पंचगांव	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	1	डा. आलोक सक्सैना	01/2003
3	पशु चिकि. तसीमो	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	-	डा. अजय कुमार पाठक	07/2001
4	पशु चिकि. खेडा सरानी	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	1	-	डा. पूरण सिंह	12/2009
5	पशु चिकि. बरेहमोरी	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	डा. पी.के. सिंह	02/2001

(पशुपालन मंत्री)

(2) जी हां। रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त होने पर, रिक्त पदों को भरा जाता है।

श्रीगंगानगर के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

139. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला श्रीगंगानगर में कहां-कहां पशु चिकित्सालय हैं तथा इसमें कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं और रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला गंगानगर में संचालित पशु चिकित्सालयों का विवरण संलग्न है।

रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त होने पर, रिक्त पदों को आवश्यकतानुसार भरा जाता है।

जिला गंगानगर में संचालित पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम		सहायक निदेशक		व.प.चि.अ.		प.चि.अ.		वी.ए.		प.ध.स.		एक्सरे तक.		व. लिपिक		क. लिपिक		सईस		डाकरूम सहा.		गडरिया		पटटी बंधक		जलधारी		स्वीपर	स्वीपर
			स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त
1	ब.उ.प.वि.	श्रीगंगानगर	1	-	2	-	1	-	-	-	5	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2	प.चि.	जवाहरनगर	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	प्र.श्रे.प.चि.	पदमपुर	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	प्र.श्रे.प.चि.	श्रीकरणसर	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	प्र.श्रे.प.चि.	रायसिंहनगर	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
6	प्र.श्रे.प.चि.	सादुलशहर	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
7	प्र.श्रे.प.चि.	श्री विजयनगर	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
8	प्र.श्रे.प.चि.	सूरतगढ़	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
9	प्र.श्रे.प.चि.	अनूपगढ़	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
10	प्र.श्रे.प.चि.	घड़साना	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11	प.चि.	ख्यालीवाला	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12	प.चि.	गणेशगढ़	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
12	प.चि.	गणेशगढ़	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
13	प.चि.	केसरीसिंहपुर	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
14	प.चि.	मिर्जेवाला	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15	प.चि.	दौलतपुरा	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
16	प.चि.	रोहिडावाली	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र.सं.	संस्था का नाम		सहायक निदेशक		व.प.चि.अ.		प.चि.अ.		वी.ए.		प.ध.स.		एक्सरे तक.		व. लिपिक		क. लिपिक		सईस		डाकरूम सहा.		गडरिया		पटटी बंधक		जलधारी		स्वीपर	स्वीपर
			स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त
17	प.चि.	फतुही	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	प.चि.	चूनागढ़	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
19	प.चि.	अरायण	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20	प.चि.	गुलाबेवाला	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
21	प.चि.	जोरावरसिंहपुरा	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
22	प.चि.	गजसिंहपुर	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	प.चि.	लालगढ़	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
24	प.चि.	दलियावाली	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
25	प.चि.	59एनपी	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
26	प.चि.	5एनपी	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
27	प.चि.	घमूडवाली	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
28	प.चि.	बीझबायला	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
29	प.चि.	रिडमलसर	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
30	प.चि.	सरदारपुराबीका	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
31	प.चि.	जैतसर	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
32	प.चि.	बीरमाना	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1

क्र.सं.	संस्था का नाम		सहायक निदेशक		व.प.चि.अ.		प.चि.अ.		वी.ए.		प.ध.स.		एक्सरे तक.		व. लिपिक		क. लिपिक		सईस		डाकरूम सहा.		गडरिया		पटटी बंधक		जलधारी		स्वीपर	स्वीपर
			स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त
33	प.चि.	सरदारगढ़	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
34	प.चि.	रामसिंहपुर	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
35	प.चि.	18 पी	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	प.चि.	रावला	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	प.चि.	बाजूवाला	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
38	प.चि.	समेजा कोठी	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
39	प.चि.	2 एफएफ ए	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
40	प.चि.	लाधवाला	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
41	प.चि.	मनियावाली	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
42	प.चि.	मलंकाना कलां	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
43	प.चि.	17 जैड	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

केकड़ी में नवीन पशु चिकित्सालयों की स्थापना

140. डॉ. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सा केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं तथा इन केन्द्रों पर कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में स्थित पशु चिकित्सा केन्द्रों में आवश्यकतानुसार नवीन पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में 21 पशु चिकित्सा केन्द्र संचालित हैं। इनका विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त होने पर, रिक्त पदों को आवश्यकतानुसार भरा जाता है।

(3) दिनांक 1 अगस्त, 2009 से प्रदेश में पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योंजना प्रारम्भ की गई हैं। जिसके अन्तर्गत जहां विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाएं कार्यरत नहीं है वहां प्रत्येक माह एक पशु चिकित्सा शिविर एवं पशुपालक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी की पशु चिकित्सा संस्थाओं में आवश्यकतानुसार पद सृजित हैं।

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कार्यरत पशु चिकित्सा केन्द्रों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	संस्था का प्रकार	स्थान जहां संस्था कार्यरत है	स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति															
			वरिष्ठ पशु चिकि. अधिकारी		पशु चिकि. अधिकारी		पशु चिकि. सहायक		पशुधन सहायक		पशुधन परिचर		जलधारी		गडरिया		सफाईकर्ता	
			स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	प्रथम श्रेणी पशु चिकि.	केकड़ी	1	-	-	-	1	-	3	-	3	-	-	-	1	-	1	-
2	पशु चिकि.	सरवाड़	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	1	1	-
3	पशु चिकि.	सराना	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
4	पशु चिकि.	बघेरा	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	1
5	पशु चिकि.	बाजटा	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-
6	पशु चिकि.	कादेडा	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
7	पशु चिकि.	सावर	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
8	पशु चिकि.	देवगांव	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
9	पशु चिकि.	सांपला	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	1

क्र. सं.	संस्था का प्रकार	स्थान जहां संस्था कार्यरत है	स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति															
			वरिष्ठ पशु चिकि. अधिकारी		पशु चिकि. अधिकारी		पशु चिकि. सहायक		पशुधन सहायक		पशुधन परिचर		जलधारी		गडरिया		सफाईकर्ता	
			स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
10	पशु चिकि.	बोगला	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
11	पशु चिकि.	प्रान्हेडा	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
12	पशु चिकि.	बिसून्दनी	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
13	पशु चिकि.	घटियाली	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
14	उपकेन्द्र	अलोली	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
15	उपकेन्द्र	खवास	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16	उपकेन्द्र	पीपलाज	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	उपकेन्द्र	जोताया	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
18	उपकेन्द्र	मेहरू कलां	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
19	उपकेन्द्र	ताजपुरा	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	उपकेन्द्र	जूनिया	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	उपकेन्द्र	पारा	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन

141. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार पंचायती राज संस्थाओं को भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक बनाने के लिये पुनर्सीमांकन एवं पुनर्गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। भोगौलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक बनाने के लिए अधिसूचनाएं दिनांक 28-11-2009 द्वारा राज्य में 2.50 लाख की जनसंख्या एवं 60 से अधिक पंचायतों वाली 8 पंचायत समिति, बीकानेर, सांचोर, तालेडा, खैरवाडा, औसिया, अनूपगढ़, नोहर व हनुमानगढ़ का पुनर्गठन कर 10 नई पंचायत समिति, खाजूवाला, चितलवाना, बून्दी, ऋषभदेव, बावड़ी, घड़साना, रावतसर, संगरिया, पीलीबंगा एवं टिब्बी का गठन किया गया है। पंचायती राज अधिनियम, 1994 में यह व्यवस्था है कि किसी पंचायत का पुनर्गठन करने पर पंचायत भंग हो जाती है और 6 माह में नये चुनाव करवाया जाना आवश्यक हो जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी-फरवरी, 2010 में सम्पन्न हुए हैं। अत: फिलहाल पुनर्गठन का कोई विचार नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालय हेतु योजना

142. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में शौचालय स्थापित करने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में स्वीकृत शौचालय 6984333 में से अब तक 2550141 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। शेष रहे शौचालयों का निर्माण वर्ष 2012 तक किया जाना प्रस्तावित है।

बाड़मेर जिले की पंचायती राज संस्थाओं में अनुकम्पा नियुक्ति के लम्बित प्रकरण

143. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायतीराज संस्थानों में कर्मिकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने का प्रावधान है? यदि हा, तो तत्संबंधी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक पंचायती राज विभाग के कार्मिक हैं एवं इन कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में मृत पंचायतीराज कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्रकरण विचाराधीन है? यदि हां, तो कितने बाड़मेर जिले के बकाया प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार मृत पंचायतीराज कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 277 एवं राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 1-2)

(2) जी हां। प्रदेश में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक पंचायती राज विभाग के कार्मिक हैं।

इन कार्मिकों की नियुक्ति पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 79, 80, 83, 89 एवं पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 257 से 259 के अनुरूप की जाती है। उक्त कार्मिक राजस्थान पंचायती राज पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवाओं के अन्तर्गत नियोजित है। पंचायत राज संस्थायें स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं अत: इनमें नियुक्त कार्मिकों राज्य कर्मचारी नहीं हैं।

(3) जी हां। पंचायत राज कर्मचारियों के 53 प्रकरण पद रिक्त नहीं होने के कारण विचाराधीन है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-3)

(पंचायतीराज मंत्री)

(4) जी हां। नियमानुसार रिक्त पदों की उपलब्धता एवं आयु/देरी से प्रस्तुत प्रकरणों में शिथिलन की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण होने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भरतपुर जिले में मिड-डे मील योजना की निगरानी हेतु समिति का गठन

144. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा फरवरी, 2009 में एक आदेश जारी कर मिड-डे मील योजना की पर्यवेक्षण के लिए राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर समितियों का गठन कर उनमें विधायकों का मनोनयन किया गया है? यदि हां, तो इन समितियों की बैठकें अब तक किस-किस जिले में हो चुकी हैं? समिति का कार्य क्षेत्र दायित्व एवं उठाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही का दायित्व किसको दिया गया हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भरतपुर जिले में गत एक वर्ष में इस समिति की कितनी बैठकें हो चुकी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार द्वारा फरवरी 09 में समिति का गठन नहीं किया गया था, फरवरी 09 में समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। समितियों का गठन दिनांक 01.09.09 को किया गया था। समिति की बैठकों व कार्यवाही का दायित्व का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

समिति का दायित्व तथा विभिन्न बैठकों में उठाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही का दायित्व जिला कलक्टर को दिया गया है जो कि समिति का अध्यक्ष होता है।

(2) भारतपुर जिले में गत एक वर्ष में मिड-डे मील योजनान्तर्गत समिति की बैठकें दिनांक 04.03.09, 12.06.09, 30.07.09 एवं 25.09.09 को आयोजित की गई हैं। बैठक कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत अनियमितताएं

145. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती अंजु खन्गवाल)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी की ग्राम पंचायत बस्सी के इंदिरा आवास योजना में हुई अनियमितता के भौतिक सत्यापन का प्रकरण सरकार के समक्ष विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत के इंदिरा आवासों में हुई अनियमितता का भौतिक सत्यापन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

बसेड़ी में लाभान्वित बी.पी.एल. परिवार

146. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे कुल कितने परिवार हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अब तक ऐसे कितने परिवारों को सरकार द्वारा लाभान्वित किया गया है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष रहे परिवारों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) वर्तमान में राज्य में गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में कुल 9067 चयनित बी.पी.एल. परिवार हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में विभिन्न योजनाओं में कुल 4270 बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया गया है। सूची संख्या परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। बी.पी.एल. परिवारों को निरन्तर लाभान्वित किया जा रहा है।

(4) राज्य में ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों को ग्रामीण विकास एवं

(ग्रामीण विकास मंत्री)

पंचायती राज विभाग द्वारा निम्नांकित योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है-

1. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण व अनुदान उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार प्रदान किया जाता है।
2. इंदिरा आवास योजनान्तर्गत नवीन/कमोन्नत भवनों का लाभ प्रदान किया जाता है।
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 के अनुसूची-1 में अनुमत केटेगिरी संख्या-4 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समस्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालके परिवारों की स्वामित्वाधीन भूमि के लिए सिंचाई प्रसुविधा, बागवानी, बागवान एवं भूमि विकास सुविधा का प्रावधान है।
4. आवासीय भूखण्ड योजनान्तर्गत ग्रामीण बीपीएल परिवारों के लिए नि:शुल्क/ रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड ग्राम पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाते हैं।
5. पन्नाधाय योजनान्तर्गत बी.पी.एल. के मुखिया के विकलांग/मृत्यु होने पर एक मुश्त सहायता भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है जिसका नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है।

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र	पंचायत समिति का नाम	चयनित बीपीएल परिवारों की संख्या	लाभान्वित करने का वर्ष एवं संख्या		किस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है
			वर्ष	संख्या	
बसेड़ी	बसेड़ी	9067	2006-07	28 25 356 98	एसजीएसवाई मृत्यु दावे, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना छात्रवृत्ति योजना पेंशन
			2007-08	96 458 67 315 196	एसजीएसवाई आइ.ए.वाई मृत्यु दावे, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना छात्रवृत्ति योजना पेंशन
			2008-09	143 574	एस जीएसवाई आई.ए.वाई.

विधान सभा क्षेत्र	पंचायत समिति का नाम	चयनित बीपीएल परिवारों की संख्या	लाभान्वित करने का वर्ष एवं संख्या		किस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है
			वर्ष	संख्या	
			2008-09	44 400 190	मृत्यु दावे, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना छात्रवृत्ति योजना पेंशन
			2009-10	12 26 12 707 253	एसजीएसवाई आई.ए.वाई. मृत्यु दावे, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना छात्रवृत्ति योजना पेंशन
			योग	**4270**	

प्रदेश के विश्वविद्यालयों हेतु नियामक आयोग का गठन

147. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार राज्य में निजी शिक्षण संस्थानों व विश्वविद्यालयों की मनमानी रोकने व शिक्षण स्तर पर निगरानी के लिए विनियामक आयोग गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य में निजी शिक्षण संस्थाओं व विश्वविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता बनाने हेतु रेग्यूलेटरी मेकेनिज्म पर विचार कर राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया हुआ है। समिति की अनुशंषाएं प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

सेवानिवृत्त प्राचार्यों/उपाचार्यों के लम्बित पेंशन प्रकरण

148. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उच्च शिक्षा में कार्यरत कितने प्राध्यापक, उपाचार्य एवं प्राचार्य वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में सेवानिवृत्त हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किन-किन को सेवानिवृत्त पर पेंशन व अन्य भुगतान कर दिया गया एवं शेष कितने तथा किन-किन के प्रकरण बकाया हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत 23 प्राध्यापक 19 उपाचार्य तथा 35 प्राचार्य एवं वर्ष 2009-10 में (माह फरवरी 2010 तक) 22 प्राध्यापक, 16 उपाचार्य तथा 31 प्राचार्य सेवानिवृत्त हुए थे। जिनकी सूची परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) जिन अधिकारियों के सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्रकरणों का निस्तारण हो गया है। उनकी सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

जिन अधिकारियों का पेंशन प्रकरणों का निस्तारण नहीं हुआ है के कारणों सहित सूची परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

नदबई (भरतपुर) में महाविद्यालय की स्थापना

149. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' (नदबई) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार कस्बा नदबई (भरतपुर) में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विभाग की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण एवं राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

मकराना में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

150. श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना में 14 राजकीय व 16 निजी उच्च माध्यमिक तथा 2000 से अधिक विद्यार्थी होने के उपरांत भी महाविद्यालय नहीं है? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मकराना में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विभाग की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण एवं राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

ईण्टाली ग्राम (उदयपुर) के राजकीय आयुर्वेद औषधालय भवन की मरम्मत

151. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ईण्टाली, तहसील मावली जिला उदयपुर में वर्तमान में राजकीय आयुर्वेद औषधालय का भवन बना हुआ है? यदि हां, तो कब से व किस स्थान पर और इसे किसने बनाया?

(2) उक्त औषधालय के निमित्त कितनी जमीन है तथा इसका माप क्या है?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(3) क्या यह सही है कि आम रास्ते पर सड़क निर्माण के दौरान इस औषधालय की चारदीवारी को तोड़ा गया है? यदि हां, तो क्यों तथा किसकी अनुमति से? अब इसको कब तक दुरुस्त करवा दिया जाएगा एवं इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं तथा सरकार दोषी के विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त औषधालय का भवन जीर्ण-शीर्ण एवं जर्जर स्थिति में है? क्या सरकार इसकी मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि निदेशालय, आयुर्वेद विभाग द्वारा वर्ष 2008 में उक्त औषधालय सहित अन्य दो औषधालयों के भवनों की मरम्मत हेतु राशि रुपये 1.74 लाख स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो इस राशि का कहां कहां, कितना-कितना उपयोग किया गया तथा उक्त औषधालय भवन की मरम्मत अब तक क्यों नहीं की गई? इस हेतु स्वीकृत राशि का क्या उपयोग हुआ व किस अधिकारी की लापरवाही के कारण उक्त भवन की मरम्मत नहीं हो पाई है?

(6) क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? अब कब तक उक्त भवन की मरम्मत करा दी जाएगी?

उत्तर

(1) ग्राम ईण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर के आयुर्वेद औषधालय का भवन, ग्राम के बस स्टैण्ड चौराहे पर स्थित है तथा वर्ष 1992 में विभाग को श्री झमकूलाल बोहरा पुत्र श्री रामनाथ ने भेंट किया है।

(2) उक्त औषधालय निमित्त लगभग 900 वर्गफीट जमीन है तथा इसकी माप 48 फीट गुना 21 फीट है।

(3) फतेहनगर से रूडेडा सड़क निर्माण के दौरान औषधालय भवन की चारदीवारी प्रभावित हुई है, सड़क निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को चारदीवारी दुरुस्त कराने हेतु लिखा गया है।

(4) जी हां। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उक्त औषधालय के भवन की मरम्मत हेतु कार्यवाही के संबंध में विचार किया जावेगा।

(आयुर्वेद मंत्री)

(5) जी हां। इस औषधालय सहित जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय उदयपुर एवं एक अन्य औषधालय की मरम्मत हेतु रुपये 1.74 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी। इस राशि से जिला आयुर्वेद अधिकारी उदयपुर के कार्यालय भवन की मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। राशि शेष नहीं रहने से अन्य दो औषधालय भवनों की मरम्मत नहीं हो सकी है।

(6) विभागीय राय में कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उक्त औषधालय के भवन की मरम्मत हेतु कार्यवाही के संबंध में विचार किया जावेगा।

सिरोही में नवीन आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय

152. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय कहां-कहां, किस-किस गांव में कब-कब से संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में कौन-कौनसी श्रेणी/संवर्ग के पद स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में वर्तमान में 26 आयुर्वेद एवं 2 होम्योपैथिक औषधालय व चिकित्सालय संचालित हैं जिनकी सूची (परिशिष्ट-क) संलग्न है।

(2) इन चिकित्सालयों में चिकित्सक, नर्स-कम्पाउन्डर व परिचारक के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण (परिशिष्ट-ख) संलग्न है।

(3) नवीन औषधालय खोले जाने का बजट प्रावधान होने पर मांग व गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

परिशिष्ट-क

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में संचालित विभागीय चिकित्सालयों व औषधालयों की सूची

क्र. सं.	स्थान	औषधालय आरम्भ वर्ष	चिकित्सा पद्धति	चिकित्सालय/औषधालय	विशेष विवरण
1.	सिरोही	1960	आयुर्वेद	चिकित्सालय	
2.	सिरोही	2005	आयुर्वेद	औषधालय	सामान्य चिकित्सालय में
3.	उड	1976	आयुर्वेद	औषधालय	पी.एच.सी. जावाल में 2005 से
4.	देलदर	1966	आयुर्वेद	औषधालय	
5.	मनादर	1965	आयुर्वेद	औषधालय	
6.	गोल	1961	आयुर्वेद	औषधालय	
7.	ल्हास उर्फ कैलाशनगर	1948	आयुर्वेद	औषधालय	पी.एच.सी में 2005 से
8	मनोरा	1985	आयुर्वेद	औषधालय	
9.	बरलूट	1992	आयुर्वेद	औषधालय	पी.एच.सी में 2005 से
10.	चड़वाल	1984	आयुर्वेद	औषधालय	
11.	फूगंणी	1980	आयुर्वेद	औषधालय	
12.	मोहब्बतनगर	1960	आयुर्वेद	औषधालय	
13.	माकरोडा	1985	आयुर्वेद	औषधालय	
14.	रामपुरा (सिलदर)	1992	आयुर्वेद	औषधालय	पी.एच.सी में 2005 से
15.	मडिया	1985	आयुर्वेद	औषधालय	
16.	मेरमाण्डवाडा	1985	आयुर्वेद	औषधालय	
17.	बेलागरी	1972	आयुर्वेद	औषधालय	पी.एच.सी में 2005 से
18.	कृष्णगंज	1966	आयुर्वेद	औषधालय	
19.	शिवगंज	1965	आयुर्वेद	औषधालय	
20.	जोयला	1956	आयुर्वेद	औषधालय	
21.	रोवाड़ा	1989	आयुर्वेद	औषधालय	
22.	जुनाजोगापुरा	1996	आयुर्वेद	औषधालय	
23.	पोसालिया	1960	आयुर्वेद	औषधालय	
24.	आलपा	1976	आयुर्वेद	औषधालय	
25.	कानाकोलर	1990	आयुर्वेद	औषधालय	
26.	मोबाईल	2008	आयुर्वेद	औषधालय	
27.	सिरोही	1981	होम्योपैथिक	औषधालय	सामान्य चिकित्सालय में 2004 से
28.	मन्डावरिया	1977	होम्योपैथिक	औषधालय	

परिशिष्ट-ख

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में संचालित विभागीय चिकित्सालयों व औषधालयों में स्वीकृत पदों, पदस्थापित एवं रिक्त पदों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	स्थान	चिकित्सा पद्धति	स्वीकृत पदों की संख्या			पदस्थापितों की संख्या			रिक्त पदों की संख्या		
			चिकित्सक	नर्स/कम्पा.	परिचारक	चिकित्सक	नर्स/कम्पा	परिचारक	चिकित्सक	नर्स/कम्पा	परिचारक
1.	सिरोही	आयुर्वेद	**2**	**5**	**4**	**2**	**3**	**4**	-	**2**	-
2.	सिरोही	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	-	-	-	-
3.	उड	आयुर्वेद	1	1	1	-	1	-	1	-	-
4.	देलदर	आयुर्वेद	1	1	1	1	-	-	-	1	-
5.	मनादर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	-	-	-	-
6.	गोल	आयुर्वेद	1	1	पद सृजित नहीं	1	1	-	-	-	-
7.	ल्हास उर्फ कैलाशनगर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	-	-	-	-
8	मनोरा	आयुर्वेद	1	1	1	-	1	-	1	-	-
9.	बरलूट	आयुर्वेद	1	1	1	-	1	-	1	-	-
10.	चड़वाल	आयुर्वेद	1	1	1	-	1	-	1	-	-
11.	फूगंणी	आयुर्वेद	1	1	1	-	-	-	1	1	-
12.	मोहब्बतनगर	आयुर्वेद	1	1	1	-	-	-	1	1	-
13.	माकरोडा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	-	-	-	-
14.	रामपुरा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	-	1	-	-
15.	मडिया	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	-	-	-	-

क्र. सं.	स्थान औषधालय	चिकित्सा पद्धति	स्वीकृत पदों की संख्या			पदस्थापितों की संख्या			रिक्त पदों की संख्या		
			चिकित्सक	नर्स/कम्पा	परिचारक	चिकित्सक	नर्स/कम्पा	परिचारक	चिकित्सक	नर्स/कम्पा.	परिचारक
16.	मेरमाण्डवाडा	आयुर्वेद	1	1	1	1	-	-	-	1	-
17.	बेलागरी	आयुर्वेद	1	1	1	-	-	-	1	1	-
18.	कृष्णगंज	आयुर्वेद	1	1	1	-	-	-	1	1	-
19.	शिवगंज	आयुर्वेद	1	1	1	1	-	-	1	1	-
20.	जोयला	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	-	1	-	-
21.	रोवाड़ा	आयुर्वेद	1	1	1	-	-	1	1	1	-
22.	जुनाजोगापुरा	आयुर्वेद	1	1	1	1	-	1	-	1	-
23.	पोसालिया	आयुर्वेद	1	1	1	-	1	-	1	-	1
24.	आलपा	आयुर्वेद	1	1	पद सृजित नहीं	-	1	1	1	-	-
25.	कानाकोलर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	-	-	-
26.	मोबाईल	आयुर्वेद	1	1	पद सृजित नहीं	-	-	1	1	1	-
27.	सिरोही	होम्योपैथिक	1	1	1	1	-	1	-	1	-
28.	मन्डावरिया	होम्योपैथिक	1	1	पद सृजित नहीं	-	1	-	1	-	-

नोट- आयुर्वेद चिकित्सालय, सिरोही में कनिष्ठ लिपिक का एक पद स्वीकृत है जो कि वर्तमान में रिक्त है।

आर.एन.टी. मेडिकल कालेज उदयपुर व महाराणा भूपाल चिकित्सालय के रिक्त पद

153. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या चिकित्सा (शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) आर.एन.टी. मेडिकल कालेज उदयपुर एवं महाराणा भूपाल चिकित्सालय में विभिन्न श्रेणियों के कितने पद स्वीकृत एवं कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की सूची श्रेणी एवं तिथि अनुसार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उदयपुर में ट्रोमा वार्ड तैयार है, जिस पर राज्य सरकार एवं नगर विकास न्यास उदयपुर द्वारा करोड़ों रुपये व्यय किये गये हैं? यदि हां, तो क्या ट्रोमा वार्ड पर्याप्त स्टाफ के अभाव में प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है?

(3) क्या उदयपुर मेडिकल कालेज एवं कई विभागों में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से केन्द्रीय टीम ने मान्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाये हैं? यदि हां, तो इसका स्थाई हल कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) आर.एन.टी. मेडिकल कालेज उदयपुर एवं महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर में विभिन्न श्रेणियों के कुल पद एवं रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। ट्रोमा वार्ड का निर्माण उपलब्ध ससांधनों से निर्मित कराया जाकर सुचारू रूप से चल रहा है। इसके सुदृढ़ीकरण के लिए अस्थि रोग विभाग को इस नव निर्मित ट्रोमा भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है। नगर विकास प्रन्यास के अनुदान राशि रुपये 1.30 करोड़ से इसी भवन में आपरेशन थियेटर काम्पलेक्स बन कर तैयार हो गया है। आर.एस.एम.एम. द्वारा दी गयी सहायता राशि (1.5 करोड़ रुपये) से इस सुविधा के लिये उपकरणों की खरीद प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2010-11 में अस्थिरोग विभाग के लिये नर्स ग्रेड-द्वितीय के चार पदों की स्वीकृति विचाराधीन है।

(3) भारतीय आर्युविज्ञान परिषद, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षण के पश्चात् उनके पत्र क्रमांक : MCI No.- 34 (41) यू.जी./2008/Raj./3/67173 दिनांक 21.1.10 द्वारा उदयपुर मेडिकल कॉलेज की एम.बी.बी.एस. की डिग्री की मान्यता यथावत रखी गयी है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

फुलेरा में नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

154. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत वर्ष 2008 व 2009 में किस-किस ग्राम पंचायत में कितनी कितनी राशि के क्या कार्य करवाये गये तथा कितने श्रमिकों को रोजगार दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की कितनी ग्राम पंचायतों में उक्त योजनान्तर्गत कार्य करवाये गये तथा उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन किस संस्था द्वारा किस-किस ग्राम पंचायत का करवाया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों में स्वीकृत राशि का उपयोग सही प्रकार से नहीं किया गया? यदि हां, तो ऐसी पंचायतों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार दोषी ग्राम पंचायतों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में महानेरगा के तहत वर्ष 2008 से दिसम्बर 2009 तक करवाये गये कार्यों में पंचायत समिति दूदू की 12 ग्राम पंचायतों में 19,82,60,857 रुपये व्यय किये गये तथा 39,126 श्रमिकों को रोजगार दिया गया तथा पंचायत समिति सांभरलेक में 26,54,83,733 रुपये व्यय किये गये तथा 21,535 श्रमिकों को रोजगार दिया गया। दोनो पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में हुए कार्यों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की पंचायत समिति दूदू में 12 ग्राम पंचायतों में नरेगा के तहत कार्य करवाये गये तथा ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा, नरायना, रोजडी, कोरसीना, शर्दुलपुरा, आकोदा, हबसपुरा का मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग से तथा शेष का विभाग से मूल्यांकन कराया गया। इसी प्रकार पंचायत समिति सांभरलेक की 30 ग्राम पंचायतों में महानरेगा के तहत कार्य करवाये गये तथा उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया गया।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) महानरेगा के तहत इस विधान सभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में स्वीकृत राशि का सही एवं नियमानुसार उपयोग किया गया है।

(4) विधान सभा क्षेत्र की किसी भी ग्राम पंचायत के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में कार्यरत स्टाफ को यूजीसी वेतनमान

155. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ हेतु अभी तक यूजीसी वेतनमान लागू नहीं किया गया है? यदि हां, तो अब कब तक लागू कर दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि कृषि विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी स्कीम लागू नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों व अब कब से लागू की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

पढ़े हुए माने गये नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

कोटा की आवासन मण्डल की बस्तियों की क्षतिग्रस्त सीवर लाइनें

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर की राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा बसाई गई आवासीय कालोनियां, विज्ञान नगर, महावीर नगर प्रथम, द्वितीय व तृतीय, एम.पी.बी. कालोनी, महावीर नगर विस्तार, तलवंडी हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बसंत विहार, गणेश तालाब, दादाबाड़ी आदि में डाली गई सीवरेज लाइनें और पेयजल की पाइप लाइन साथ-साथ होने से इन कालोनियों के निवासियों को सीवरेज लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण पेयजल प्रदूषित होने की सम्भावना रहती है तथा पीलिया जैसी विभिन्न संक्रामक बीमारियों से ग्रसित होने की सम्भावना बलवती होती जा रही हैं। सीवरेज की लाइनें क्षतिग्रस्त और जगह-जगह से टूट चुकी हैं जिसके कारण आम दिनों के साथ-साथ बरसात के दिनों में सीवरेज का गंदा पानी घरों में घुस जाता है। जिसके कारण आमजन का सामान्य रूप से जीवन जीना दूभर हो जाता है। उक्त सीवरेज की पाइप लाइन बहुत छोटी और डिफेक्टिव है जिसके कारण बरसात के दिनों में स्थिति बहुत खराब हो जाती है। जिससे कई प्रकार की संक्रमण बीमारियां फैलने की सम्भावना रहती है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि उक्त सीवरेज लाइनों को तुरन्त परिवर्तन किया जाए, टूटी लाइनों को बदला जाए तथा नई सीवरेज लाइन डाली जाए। अन्यथा हजारों लोग पीलिया आदि गम्भीर बीमारियों से बीमार पड़ जाएंगे। उक्त गंदे पानी से बरसात में तो उनकी स्थिति नारकीय जीवन से भी बदतर हो जाती है।

मेरी सरकार से प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से पुरजोर शब्दों में मांग है कि कोटा शहर की उक्त आवासीय कालोनियों में क्षतिग्रस्त लाइनों के स्थान पर नई सीवरेज की लाइन डाली जाए तथा पेयजल लाइन व सीवरेज को अलग-अलग किया जाए।

ओम बिरला

(कोटा दक्षिण)

जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायतों में सिवाय चक/चरागाह भूमियों पर अतिक्रमण

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में चरागाह भूमि व सिवाय चक भूमि पर अवैध अतिक्रमण होने से महानरेगा का कार्य बंद होने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की अधिकांश ग्राम पंचायतों में सिवाय चक चरागाह भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कई वर्षों से अतिक्रमण किया हुआ है। सिवाय चक/चरागाह भूमि पर अतिक्रमण होने की वजह से सरकार द्वारा चलाये जा रहे महानरेगा के अन्तर्गत चरागाह भूमि की मेड़बंदी का कार्य बंद पड़ा है। उक्त अतिक्रमणों के कारण से ग्रामीण जनता को महानरेगा के अन्तर्गत 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण ग्रामीण जनता में भारी रोष व्याप्त है। अत: सिवाय चक/चरागाह भूमियों से अविलम्ब अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन द्वारा क्रमबद्ध प्रत्येक पंचायतवार एक अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए ताकि महानरेगा का कार्य सुचारू रूप से शुरू हो सके और ग्रामीण जनता को रोजगार मिल सके।

अत: मेरी राज्य सरकार एवं राजस्व मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग है कि मेरे क्षेत्र में सिवाय चक/चरागाह भूमियों पर हुए अवैध अतिक्रमण को तुरन्त प्रभाव से हटाने की कार्यवाही की जाए जिससे महानरेगा का कार्य शीघ्र चालू करवाया जा सके।

गोपाल मीणा

(जमवारामगढ़)

जोधपुर शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता

महोदय,

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर में बिगड़ी सफाई व्यवस्था का आलम यह है कि जगह-जगह कचरे के ढेर के साथ पुरानी सीवर लाइनें या तो क्षतिग्रस्त हो गयी हैं या पुरानी होने के कारण भराव क्षमता से अधिक पानी बहने के कारण होने वाले ओवरफ्लो से, सड़कों पर प्रात:काल बहने वाले गन्दे पानी से जनता त्रस्त होने के साथ धरने, प्रदर्शन एवं रास्ता रोकने जैसी प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए मजबूर हो जाती है।

जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्रों में सीवर लाइन करीबन 50 वर्ष पुरानी है जो उस वक्त की जनाधार को मध्यनजर रखते हुए बनायी गयी थी। परन्तु वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या में बढ़ते हुए मकानों को दृष्टिगत रखने के साथ बहते हुए गन्दे पानी के बहाव की क्षमता को मध्यनजर रखते हुए जोधपुर शहर के सम्पूर्ण भीतरी क्षेत्र में एक मास्टर प्लान बनाकर नयी सीवर लाइन डालने की आवश्यकता है। (वर्तमान में पन्ना निवास हाथीराम का ओडा, गांधी चौक, चेतानियो की गली व्यापारियों का मौहल्ला, न्याति नोहरा के साथ अन्य काफी ऐसे एरिया हैं जहां पर नियमित रूप से सीवर लाइन ओवर फ्लो होती है) सीवर लाइन डालने के साथ ही विद्युत एवं टेलिफोन लाइनों को भी भूमिगत केबल बिछाने के तदुपरान्त सड़क निर्माण की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होने से मात्र 6 माह के भीतर ही नई सड़कें बहते हुए गन्दे पानी की भेंट चढ़ जाती हैं स्थिति पुन: जस की तस हो जाती है। इसी के साथ ही नगर निगम द्वारा शहर के भीतरी क्षेत्रों में जगह-जगह नये डम्पिंग स्टेशन बनाने से स्थिति और विकट हो गयी है। उन डम्पिंग स्टेशनों से कचरा एवं गन्दगी समय पर नहीं उठने से सड़ान्त के मारे वहां के आस-पास के निवासियों का जीना दुर्भर हो जाता है। जहां तक मेरी जानकारी में है कि नगर निगम में सफाई कर्मियों का जोधपुर के बढ़ते शहर को देखते हुए काफी टोटा है। सफाई कर्मियों की कमी की वजह से कई स्थानों पर नियमित एवं निर्धारित समय पर सफाई नहीं होना भी एक कारण है।

अत: मेरी राज्य सरकार से मांग है कि राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर जो कि पर्यटकों का भी काफी मनभावक है उसे साफ सुन्दर एवं पोललैस सिटी बनाने के लिए मास्टर प्लान बनाकर, वर्तमान एवं आगामी 20 वर्षों की क्षमता को देखते हुए शहर के भीतरी क्षेत्रों में नई सीवर लाइन डालने के साथ भूमिगत विद्युत एवं टेलिफोन लाइन डाली जावे। इसी के साथ शहर साफ एवं सुन्दर रहे इस हेतु मेरा सुझाव है कि रात्रिकालीन अवस्था में ही सम्पूर्ण मुख्य सड़कों, सीवर लाइनों एवं नालियों की सफाई व्यवस्था करने के साथ डम्पिंग स्टेशन पर पड़ी गन्दगी को रात्रिकालीन 12.00 बजे से सवेरे 5.00 बजे तक शहर से बाहर ले जाया जावे। इसी के साथ सफाई कर्मियों की तत्काल तादाद बढ़ाकर वार्ड वाइज उनको सफाई की जिम्मेदारी तय की जावे। साथ ही जोधपुर की तीनों विधान सभा (सरदारपुरा, शहर एवं सूरसागर) के लिए एक अलग से टॉस्क फोर्स गठित किया जावे ताकि सफाई व्यवस्था की विधान सभा वार मोनिटरिंग हो सके एवं शिकायत दर्ज होने पर 2 घण्टे में सफाई हो सके।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को देखते हुए इस विषय पर चर्चा कराने का श्रम करें।

कैलाश चन्द भंसाली
(जोधपुर)

बीकानेर (पूर्व) में दो सैटेलाइट अस्पतालों की स्थापना

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बीकानेर चिकित्सा सुविधा के नाम पर प्रीन्स बिजय सिंह मेमोरीयल (पी.बी.एम.) अस्पताल ही नजर आता है। इक्का दुक्का स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधा नहीं होने से लोगों को पी बी एम अस्पताल जाना पड़ता है। बड़े शहरों में सेटेलाइट अस्पताल खोलने की नीति के तहत मेरा आग्रह है कि बीकानेर पूर्व विधान सभा क्षेत्र में अमरसिंहपुरा-रामपुरा (तीनों में से एक) तथा गंगाशहर में सेटेलाइट अस्पताल की स्थापना की जाए। वर्तमान में गर्भवती महिलाओं और दुर्घटना में घायलों को पीबीएम अस्पताल तक ले जाना कई बार जान लेवा साबित होता है। अत: मेरा आग्रह है कि बीकानेर (पूर्व) विधान सभा क्षेत्र में दो नए सेटेलाइट अस्पताल स्थापित किए जाएं। इसमें गंगाशहर में सरकार को भवन सहित सुविधाएं पहले से ही तैयार मिल सकती हैं। उम्मीद है सरकार गरीब, बीमार और असहाय लोगों के लिए संवेदनशील होकर सेटेलाइट अस्पताल खोलेगी।

सिद्धि कुमारी
(बीकानेर)

जोधपुर शहर में वन भूमि पर बसी बस्तियों का नियमन

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि देश की आजादी के पूर्व सात वन खण्ड जो जोधपुर शहर के समीप हैं कि दिनांक 05.11.92 को रक्षित वन भूमि होने बाबत प्रारम्भिक विज्ञाप्ति राजपत्र में प्रकाशित हुई है। वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में अस्तित्व में आने पर इस अधिनियम में दिनांक 25.10.1980 के बाद किसी भी वन भूमि पर आबादी बसावट या अन्य प्रकार के गैर वानिकी कार्यो के लिये राज्य सरकारों को भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया। वर्तमान में जोधपुर शहर में पूर्ण, आंशिक एवं अप्रत्यक्ष रूप से कुल 34 कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं। इस बात के साक्ष्य नगर सुधार न्यास, जोधपुर के रिकार्ड एवं इन बस्तियों में बिजली, पानी व सड़क

सुविधाओं का कार्य भी नगर सुधार न्यास द्वारा वर्ष 1980 से पूर्व प्रारम्भ कर दिये गये थे। जोधपुर शहर में लगभग 500 हैक्टयर वन भूमि पर रिहायशी अतिक्रमी काबिज है, 24 कच्ची बस्तियां पूर्णतया तथा 10 कच्ची बस्तियां आंशिक रूप से वन भूमि पर बसी हुई हैं। इन बस्तियों के बसावट के कंकरीट के जंगल को नष्ट कर पुन: वन भूमि में बदलना भी अमानवीय होगा, जिसमें लगभग 50 हजार की जनसंख्या निवास करती है।

इन बस्तियों के नियम के लिये अनारक्षण प्रस्ताव के मार्फत भारत सरकार से कार्योत्तर अनुमति प्राप्त करना ही इस समस्या का एकमात्र विकल्प है। अनारक्षण की आवश्यक शर्तें दो होती हैं प्रथम तो उक्त भूमि के बराबर भूमि अन्यत्र वन विभाग को राज्य सरकार उपलब्ध करावें, जो कि सम्भव है, ग्राम चौखा, ग्राम बडली एवं ग्राम मोकलावास में वन विभाग द्वारा वन विकास के कार्य करवाये गये हैं, जो कि आज दिनांक तक प्रबन्धन एवं पर्यवेक्षण की दृष्टि से भी उक्त भूमि वन विभाग के पास है। अत: जोधपुर विकास प्राधिकरण यह भूमि वन विभाग को उपलब्ध करवाता है तो स्थानीय जन समुदाय को भी आपत्ति नहीं होगी।

द्वितीय शर्त एन.पी.वी. (नेट प्रजेन्ट वेल्यू) की है, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के अन्तर्गत 5.80 लाख से 9.20 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर भूमि की दर से राशि वन विभाग के कोष में जमा करवाने के आदेश हैं। इस आदेश की पालना में 444 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लगभग 42 करोड़ रुपये एन.पी.वी. राशि के बारे में नगर सुधार न्यास, जोधपुर के पुराने पत्रों में वर्णित है, परन्तु वर्तमान में दिनांक 24.03.08 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश में वर्ष 1980 से पूर्व बसी कच्ची बस्तियों को एन.पी.वी. राशि की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया। इस प्रकार कुल 458.77 हैक्टेयर अतिक्रमी रकबे से 345.83 हैक्टेयर रकबे की एन.पी.वी. राशि अनिवार्यता समाप्त हो जाती है, शेष बची 112.94 हैक्टेयर वन भूमि पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम आदेश की पालना में राशि 6.26 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से एन.पी.वी. 7.07 करोड़ रुपये की देयता अनिवार्य प्रतीत होती है। इस प्रकार राज्य सरकार इन बस्तियों हेतु अनारक्षण प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार के पास भेजे एवं 1980 के बाद बसी बस्तियों के एन.पी.वी. 7.07 करोड़ रुपये वन विभाग के कोष में जमा करवाकर उक्त भूमि का वन भूमि के दर्जे से मुक्त कर वन भूमि पर बस्तियों के नियमन का स्थायी समाधान हो सके।

इसके पश्चात् राज्य सरकार वन भूमि या अतिक्रमण सम्भावित वन

भूमि को विशेष संसाधन उपलब्ध करवाने तथा वन भूमि पर पक्की दीवारें आदि का निर्माण करावें, जिससे भविष्य में ऐसी पुनरावृति न हो।

बाबूसिंह राठौड़

(शेरगढ़)

मारवाड़ जंक्शन के गांवों में फ्लोराइड पानी की समस्या का समाधान

महोदय,

मैं प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री महोदय का पाली जिले के विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी होने की वजह से वहां की जनता को दूषित पानी पीने के कारण फैल रहे रोगों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के अधिकतम गांवों में फ्लोराइड व खारे पानी की समस्या है। कण्टालिया बांध सूख जाने से इससे सम्बन्धित चलने वाली पेयजल की सारी योजना बन्द पड़ी है। इसलिए हर गांव में 10 हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था करावें नहीं तो आने वाली गर्मी में पेयजल समस्या विकराल रूप ले लेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा जो पानी पेयजल योजनाओं एवं हैण्डपम्पों के माध्यम से पिलाया जा रहा है, उनमें फ्लोराइड अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है। राज्य में लगातार अकाल के कारण जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है व प्रतिवर्ष फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है।

कई किलोमीटर तक शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है यही समस्या पूरे पाली जिले में विद्यमान है। मैं श्रीमान की जानकारी में लाना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के 120 गांवों में फ्लोराइड एवं खारे पानी की समस्या को देखते हुये पूर्ववर्ती सरकार ने एक महत्वाकांक्षी जवाई बांध केनाल पेयजल योजना स्वीकृत की थी। जिसमें विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के 120 गांवो को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाना था लेकिन आज तक सरकार ने कार्य प्रारम्भ करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया। इससे क्षेत्र के लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता तथा रोष व्याप्त है।

फ्लोराइड का पानी पीने से जिले में कुबड़े एवं विकलांगों की संख्या बढ़ती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय ये 6 विधान सभा क्षेत्रों का मामला है, अत: जन

स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री महोदय से आग्रह है कि इतने वर्षों तक पाली ने जोधपुर को अपने जवाई बांध से पानी पिलाया है वो भी अब सूख रहा है इसलिये राजस्थान केनाल तथा जवाई केनाल को जोड़कर हमारे पूरे जिले को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करावें तथा सदन में उपस्थित मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि इस योजना के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करें।

केसाराम चौधरी

(मारवाड़ जंक्शन)

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में संस्कृत ऐच्छिक विषय से उत्तीर्ण को नियुक्ति नहीं

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान इस ओर आकृर्षित करवाना चाहता हूं कि वर्ष 2008 में संस्कृत शिक्षा विभाग की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (संस्कृत) की नियुक्ति प्रक्रिया में ऐच्छिक विषय संस्कृत सहित सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित करने के बाद भी संस्कृत निदेशालय द्वारा नियुक्ति से वंचित करने का कार्य किया जा रहा है, जो कि अन्याय पूर्ण है।

प्रारम्भ में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति में सीनियर सैकण्डरी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया था, मगर जब विज्ञापन के विरोध में प्रदर्शन किया गया, तो राजस्थान सरकार ने विज्ञापन का शुद्धि पत्र जारी कर इन अभ्यथियों को शामिल किया।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होने के बावजूद अब राज्य सरकार नए सेवा नियम, 2008 का हवाला देते हुए संस्कृत शिक्षक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दे रही है, परन्तु जिन छात्रों ने वर्ष 2008 से पूर्व डिग्रीयां प्राप्त कर रखी हैं, उन अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है। जब राज्य सरकार NTT डिग्रीधारी को ब्रिज कोर्स करवा एसटीसी के समकक्ष लाभ दे रही है, तो निवेदन है कि ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया अपनाकर इन चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी जाये ताकि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 700 अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके।

पवन दुग्गल

(अनूपगढ़)

जोधपुर डिस्काम के विजयनगर कार्यालय में फर्जी विद्युत कनेक्शनों की जांच

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में जोधपुर डिस्काम के श्रीगंगानगर वृत्त के श्रीविजयनगर में सैकड़ों फर्जी विद्युत कनेक्शनों का मामला सामने आया है। डिस्काम प्रबन्धन ने आरम्भिक तौर पर एक बाबू को निलम्बित किया है। और कनिष्ठ अभियन्ता को एपीओ कर अन्दरखाने जांच कर रही है। चालू वित्त वर्ष में श्रीविजयनगर के कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय को 1700 मीटरों की आपूर्ति की गई। कार्यालय के रजिस्टर में 1000 मीटरों का ही इन्द्राज है शेष 700 मीटरों का कोई अता पता नहीं है। कर्मचारी द्वारा वास्तविक प्राप्त मीटरों से कम मीटरों का राजकीय रिकार्ड में अंकन गबन की श्रेणी में आता है। सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा इन मीटरों को फर्जी कनेक्शनों में उपयोग लिये जाने की आशंका है यह कृत्य निजी स्वार्थ हेतु राजकीय सम्पत्ति के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है।

जोधपुर डिस्काम के श्रीविजनगर कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों/ठेकेदारो की मिलीभगत से फर्जी कनेक्शन देने के साथ-साथ लगभग 3 महीने से उपभोग की जा रही विद्युत की बिल राशि स्वयं द्वारा वसूल कर राजकीय कोष को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मामले में अभी तक ऐसे 3 फर्जी कनेक्शन पकड़कर तीन जनों को गिरफ्तार किया गया है। हैरत की बात ये है कि तीन महीने से डिमांड नोट के बिना चल रहे इन कनेक्शनों की डिस्काम प्रबन्धन को कानोकान खबर तक नहीं। इन्होंने मिलकर क्षेत्र में 3 माह पहले बीपीएल, घरेलू और अघरेलू श्रेणी के कनेक्शन जारी कर ये मीटर लगाये जबकि डिस्काम में इनकी फाइलों में अभी तक डिमांड नोटिस भी जारी नहीं हुये, इस प्रकार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना में जोधपुर डिस्काम के अधिकारियों/कर्मचारियों और ठेकेदारों द्वारा फर्जीवाड़ा कर वास्तविक पात्र लोगों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में जोधपुर डिस्काम के इस समान्तर डिस्काम एवं फर्जी कनेक्शनों की निष्पक्ष जांच तुरन्त प्रभाव से उच्च स्तरीय एजेन्सी से करवाई जावे।

धन्यवाद।

दौलतराज
(रायसिंहनगर)

बायतू की पेयजल समस्या

प्रदेश की सरकार द्वारा बाड़मेर जिले हेतु मुख्य रूप से मोहनगढ़-बाड़मेर लिफट परियोजना नाचना-पोकरण-फलसूण्ड-हीरे की ढाणी, सिणधारी पेयजल योजना, उम्मेदसागर-कल्याणपुर-समदडी-खण्डप पेयजल योजना एवं नर्मदा केनाल पेयजल योजना से पानी पहुंचाने की योजना स्वीकृत की गई है। जो काफी लम्बी योजनाऐं हैं। गत वित्तीय वर्ष में उम्मेदसागर परियोजना में आंशिक बजट स्वीकृत किया गया था।

लेकिन मेरा आग्रह यह है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन होने तक प्रदेश के रेगिस्तानी जिले बाड़मेर सबसे विकट भौगोलिक परिस्थिति के बायतू विधानसभा क्षेत्र में लगभग 60 ग्राम पंचायत के सभी राजस्व ग्रामों एवं ढाणियों में उण्डू के जलस्त्रोतों से विभागीय जल प्रदाय योजनाओं को जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। चूंकि इस क्षेत्र के अलावा बायतू समूचे क्षेत्र में जमीन में पानी उपलब्ध नहीं है इसलिए मजबूरी है कि इस क्षेत्र की जनता को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु जो योजनाऐं बनाई जाती है। वे बहुत ही लम्बी एवं कीमती होती हैं। लागत राशि अधिक होने के कारण मंजूर नहीं हो पा रही है। परन्तु प्रकृति को चुनौती देना सम्भव नहीं है।

वर्तमान में विभाग द्वारा जो जल प्रदाय योजना संचालित है वो बहुत पुरानी होने के कारण जगह-जगह पर क्षतिग्रस्त और कहीं-कहीं तो समाप्त प्राय: है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, पाइप लाइन के लम्बे एवं पुराने होने, मरम्मत एवं रख-रखाव के अभाव एवं पानी की कमी होने के कारण इस योजना के अन्तिम छोर पर स्थित ग्रामों एवं बस्तियों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसी समस्या के तत्काल समाधान हेतु उक्त योजना उण्डू-हीरे की ढाणी योजना के मेन्टेनेन्श एवं रिपेयरिंग हेतु प्रस्तावित योजना जिसकी अनुमानित लागत 02.25 करोड़ जोगासरिया-सोमेसरा जलप्रदाय योजना लागत राशि 10.72 करोड़ एवं उण्डू-पनावडा-सांईयों की ढाणी जलप्रदाय योजना लागत राशि 06.50 करोड़ स्वीकृति हेतु लम्बे समय से राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। यदि उक्त तीनों योजनाओं का बजट प्रावधान कर स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में हो जाती है तो क्षेत्र की जनता को बड़ी योजनाओं के लागू होने तक राहत मिलेगी और गौरतलब है कि यह योजनाऐं इन बड़ी योजनाओं की सहायक होने के कारण दुबारा पैसा खर्च नहीं होगा। वर्तमान में पेयजल समस्या के समाधान हेतु यदि कन्टीजेन्सी मद के तहत बायतू क्षेत्र में जहां सफल है वहां हैण्डपम्प एवं परम्परागत जलस्त्रोतों के नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विद्युतीकरण करने

हेतु जो विभाग में प्रस्तावित है, के लिये राशि का आबंटन किया जाये तो जनता को राहत मिल सकती है। इस विषय पर राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार कर शीघ्रतिशीघ्र स्वीकृति जारी करने का निर्णय लेना चाहिए।

कर्नल सोनाराम चौधरी

(बायतू)

बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन की स्थापना

अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके माध्यम से मा. मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर जिले का सबसे बड़ा चिकित्सालय है जहॉ पर रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज कराने आते हैं। लेकिन जिले के इस सबसे बड़े चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं चिकित्सकीय उपकरणों की कमी के चलते मरीजों का सही एवं सुलभ इलाज सम्भव नहीं हो पाता है। विशेषकर राजकीय चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन नहीं होने के कारण सैकड़ों मरीजों को जिले से 250-300 किमी दूर जोधपुर अथवा अहमदाबाद इलाज के लिए मजबूरन जाना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिला जहां पर खनिज एवं पैटोलियम पदार्थों के अथाह भण्डार मिलने के बाद कई बाहरी कम्पनियां यहा कार्य करती हैं जिसमें हजारों की संख्या में अधिकारी, कर्मचारी एवं श्रमिक कार्य करते हैं साथ ही पावर प्लांट में भी हजारों लोग कार्य करते हैं। जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इलाज के लिए जिले का सबसे बड़ा राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में लाया जाता है। ठीक इसी तरह पिछले दो वर्षो में सड़क दुर्घटनाओं का दौर यकायक बढ़ा है जिले में दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते है जिस पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और मरीज को सीटी स्कैन जांच हेतु बाहर रैफर करना पड़ता है। और कई मर्तबा मरीज की बीच रास्ते में मृत्यु तक हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में जिला मुख्यालय पर स्थित इस चिकित्सालय में एक सीटी स्कैन मशीन का होना अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी एवं चिकित्सा मंत्रीजी से आग्रह है कि अत्यन्त जनहित की इस मांग पर विचार कर इस बजट में राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराने

की लगाकर आम गरीब को राहत पहुंचाएं। मुझे विश्वास है कि जनहित की इस महत्वपूर्ण मांग पर अवश्य विचार होगा।

मेवाराम जैन

(बाड़मेर)

बामनवास के 33/11 केवी ग्रिड सब-स्टेशन के सहायक अभियन्ता कार्यालय भवन का निर्माण

महोदय,

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बामनवास में 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बामनवास पट्टीखुर्द पर ढाई वर्ष पूर्व स्वीकृत सहायक अभियन्ता कार्यालय का निर्माण कार्य आज दिनांक तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। जबकि राज्य सरकार द्वारा 22 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। वर्तमान में कार्यालय किराये के मकान में चल रहा है जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। आम जनता को अपनी विद्युत सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु गंगापुर जाना पड़ता है। जिससे आम जनता में राज्य सरकार के प्रति आक्रोष उत्पन्न हो रहा है। विभाग द्वारा इस कार्यालय में नाम मात्र का स्टाफ बैठा रखा है जिससे जनता का किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है और क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है। मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से मा. उर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार अविलम्ब सहायक अभियन्ता कार्यालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही करावे, एवं उक्त कार्यालय को किराये के मकान के बजाय 33/11 के.वी. जी.एस.एस. पर पूर्व में निर्मित तीन कमरों में ही शिफ्ट करावे ताकि मेरे क्षेत्र की आम जनता को अपनी विद्युत संबंधी समस्याओं से राहत मिल सके।

नवलकिशोर मीणा

(बामनवास)

सी.आर.एफ. नियमों की अस्पष्टता के चलते आदान-अनुदान के लाभ से वंचित काश्तकार

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा सम्वत् 2066 फसल खरीफ के दौरान हुये खराबे को लेकर आपदा प्रबन्धन विभाग ने ऐसे कृषकों को आदान अनुदान वितरण

किया जा रहा है जिसमें कृषक द्वारा बोये गये रकबे का 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराब हुई वो काश्तकार लघु एवं सीमान्त जिसकी सीमा 2 हैक्टेयर भूमि तक है को अनुदान देने की कार्यवाही तहसील स्तर पर चल रही है।

मेरा इस संबंध में सदन के माध्यम से निवेदन है कि सी.आर.एफ. नियमों की स्थिति स्पष्ट नहीं होने ये बहुत भूमि की गणना में सिंचित भूमि की गणना में सिंचित भूमि को दुगना करके लघु एवं सीमान्त कृषक निर्धारित कर रहे है जबकि मेरा निवेदन है कि इस गणना में सिंचित भूमि को दुगना नहीं गिनना चाहिए क्योंकि तालाबों एवं बांधों में पानी बिलकुल ही नहीं आया अत: यह भूमियां बारानी की श्रेणी की तरह ही है न कि बन्दोबस्त की श्रेणी के आाधार पर सिंचित माना जावे, ताकि सभी कृषकों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। कुछ तहसीलों में गैरखातेदार को अनुदान की राशि दी जा रही है ऐसे ही भूदान बोर्ड के खातेदार कृषक जो राजस्व रेकार्ड में स्थाई गैर खातेदार है उन्हें यह अनुदान की राशि कुछ जगह दे रहे है कुछ जगह नहीं दे रहे है।

अत: मेरा निवेदन है कि नियमों में एक रूपता बनी रहे इस हेतु आपदा प्रबंन्धन विभाग इसमें आवश्यक संशोधन करा सभी प्रदेश की तहसीलों में निर्देश जारी करे ताकि इस आदान अनुदान का लाभ सभी पात्र काश्तकारों को मिल सके।

महावीर प्रसाद जीनगर

(शाहपुरा)